

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

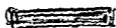
KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

इंग्लैंड, जापान एवं रूस का आर्थिक विकास

Landmarks in Economic Development of U. K.,
Japan and U. S. S. R.



संख्या १८ राजवाड़ रूसी साधन के माध्यम से
किया जाता है।

न केवल अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों वरन् सभी रुचियों और
विषयों के पाठकों के लिए यह वांछनीय है कि ये इन दोनों महान्
अर्थ-व्यवस्थाओं के अन्विष्टि में महिप्त

Dr K. A. CHOPRA
Department of Economics
University of Rajasthan, JAIPUR

AND

Prof P. N. MATHUR
Department of Economics
Govt. Girls College, KOTA

Prof M. L. MEHTA
Department of Economics
Government College, BHILWARA

COLLEGE BOOK DEPOT
TRIPOLIA ★ JAIPUR-2

Japan

Development of the Japanese economy during the Meiji Restoration
Agricultural development A few important facts about principal modern
industries Role of small scale industries Salient features of Japanese
foreign trade Role of State in Economic development Factors causing
Post World War II economic expansion

USSR

New Economic policy Economic conditions on the eve of the First
Five Year Plan. Collectivisation Soviet agricultural development since 1954
Problems of rapid industrialisation Recent trends in planning and economic
development

All Rights Reserved with the Publishers

Published by College Book Depot Tripolia Bazar Jaipur 2

Printed at Oriental Printers Jaipur

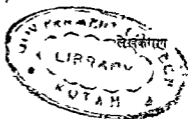
भूमिका



राजनीतिक द्वि-ध्रुवीय व्यवस्था के अनुरूप ही आधुनिक आर्थिक जगत् मुख्यतः दो अर्थ-व्यवस्थाओं द्वारा शासित है—एक है पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था और दूसरी है समाजवादी अर्थ-व्यवस्था। साम्यवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था का ही एक परिष्कृत रूप है। साध्य साम्यवाद है जिसे समाजवाद रूपी साधन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

न केवल अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों वरन् सभी रुचियों और विषयों के पाठकों के लिए यह वांछनीय है कि वे इन दोनों महान् अर्थ-व्यवस्थाओं के प्रतिनिधि राष्ट्रों के आर्थिक विकास का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करें। इसी उद्देश्य से, प्रस्तुत पृष्ठ अर्धे कलेवर में ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत रूस और जापान के आर्थिक विकास के इतिहास का समेटे हुए है। उपर्युक्त दोनों अर्थ-व्यवस्थाओं के प्रतिनिधि राष्ट्र होने के साथ ही वे अपनी कुछ और भी विशेषताएँ रखते हैं। ब्रिटेन औद्योगिक विकास का प्रयुक्त रहा है, रूस नियोजन के चमत्कारिक परिणामों का नमूना है और जापान लघु-कूटीर-उद्योगों और बृहद् उद्योगों का सुन्दर तालमेल है। भारत ने अपनी मिश्रित अर्थ व्यवस्था में नियोजन, लघु एव कूटीर उद्योगों तथा बृहद् उद्योगों—सभी को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। वह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थ-व्यवस्थाओं के तत्त्वों को लेकर चला है। अतः भारतीय छात्रों के लिए तो इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास के ज्ञान का विशेष महत्त्व है।

भाषा है उपर्युक्त राष्ट्रों के आर्थिक विकास के प्रमुख मील-स्तम्भों को इंगित करने वाली यह पुस्तक छात्रों व सभी प्रबुद्ध पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।



अनुक्रमणिका

इङ्ग्लैण्ड का आर्थिक विकास (Economic Development of U. K.)

1 औद्योगिक क्रांति और उसके प्रभाव (Industrial Revolution & Its Effects)	3
2 औपनिवेशिक विस्तार के आर्थिक पहलू (Economic Aspects of Colonial Expansion)	21
3 तीखा में आर्थिक स्थिरता की नीतियाँ (Policies for Economic Stabilization During 1930s)	38
4 पूर्ण रोजगार के लिए नियोजन (Planning for Full Employment)	48
प्रश्नावली (University Questions)	54

जापान का आर्थिक विकास (Economic Development of Japan)

1 मेजी पुनर्स्थापन के दौरान जापानी भय-व्यवस्था का विकास (Development of the Japanese Economy During the Meiji Restoration)	...	3
2 कृषि विकास (Agricultural Development)	19
3 प्रमुख आधुनिक उद्योगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य (A few Important Facts about Principal Modern Industries)	34
4 लघु-स्तरीय उद्योग-धन्धों का योगदान (Role of Small Scale Industries)	63
5 जापानी विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of Japanese Foreign Trade)	74

ii अनुक्रमणिका

6 आर्थिक विकास में राज्य का योगदान (Role of State in Economic Development)	85
7 द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में आर्थिक विस्तार के कारक (Factors causing Post World War II Economic Expansion)	94
प्रश्नावली (University Questions)	104
Suggested Readings	...	108

सोवियत रूस का आर्थिक विकास (Economic Development of USSR)

1 नवीन आर्थिक नीति (New Economic Policy)	3
2 प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था (Economic Condition on the Eve of the First Five Year Plan)	25
3 सामूहीकरण (Collectivisation)	31
4 सन् 1954 से सोवियत कृषि-विकास (Soviet Agricultural Development Since 1954)	46
5 तीव्र औद्योगीकरण की समस्याएँ (Problems of Rapid Industrialisation)	56
6 नियोजन और आर्थिक विकास की आधुनिक प्रवृत्तियाँ (Recent Trends in Planning and Economic Development)	65
प्रश्नावली (University Questions)	88
Suggested Readings	...	92

इंग्लैण्ड के आर्थिक-विकास में सोमा-चिन्ह

(LANDMARKS IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF U. K.)

- 1 औद्योगिक क्रान्ति और उसके प्रभाव
(*Industrial Revolution and its Effects*)
- 2 औपनिवेशिक विस्तार के आर्थिक पहलू
(*Economic Aspects of Colonial Expansion*)
- 3 सोमा में आर्थिक स्थिरता की नीतियाँ
(*Policies for Economic
Stabilisation during 1930s*)
- 4 पूर्ण रोजगार के लिए नियोजन
(*Planning for Full Employment*)

‘ ब्रिटेन के दो भौगोलिक गुण हैं—एक
सतार से पृथक्ता और दूसरा
पृथ्वी से सम्पर्क ।’

—मैकिण्डर

4 इंग्लैण्ड का आर्थिक विकास

सामान्यतः अर्थ किसी रक्तरजित विद्रोह अथवा हिंसात्मक विस्फोट से लिया जाता है, जैसे 1789 की फ्रैन्च क्रान्ति अथवा 1917 की रूसी क्रान्ति। लेकिन आर्थिक परिवर्तनों के सम्बन्ध में “क्रान्ति” शब्द का यह अर्थ प्रायः नहीं है। इस क्षेत्र में औद्योगिक क्रान्ति का आशय उद्योगों में हुए उन परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप दस्तकारी के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम होने लगा और उत्पादन-विधियों में आमूल-चूल परिवर्तन हो गए। दूसरे शब्दों में औद्योगिक क्रान्ति का तात्पर्य है निर्माण-कार्य, खनिक कर्म, परिवहन, संचार-साधन, कृषि आदि में मशीनों और वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग और फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि में परिवर्तन।

जब औद्योगिक क्रान्ति के परिणामस्वरूप पुरातन सीमित गृह उद्योगों की अपेक्षा वाष्प या विद्युत् यंत्रों की सहायता से बड़े-बड़े कारखानों में बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा तो न केवल ब्रिटेन ने बल्कि सम्पूर्ण विश्व में आर्थिक विकास के एक नए युग में प्रवेश किया। आर्थिक जगत में परिवर्तन प्रायः धीरे-धीरे होते हैं, किन्तु 18वीं शताब्दी के परिवर्तन इतने शीघ्रतापूर्वक हुए और साथ ही वे इतने मौलिक थे कि उनसे उत्पादन विधियाँ पूर्णतया बदल गईं व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन हो गया तथा अनेक नवीन व्यापारिक समस्याएँ अस्तित्व में आईं। औद्योगिक क्षेत्र में हुए इन परिवर्तनों के परिणाम इतने महत्वपूर्ण थे कि इंग्लैण्ड के और तत्पश्चात् विश्व के अनेक देशों के आर्थिक क्षेत्र के प्रत्येक अंग में एक प्रकार की क्रान्ति उत्पन्न हो गई। प्रोफेसर ए. बर्नी के शब्दों में—“इसके (औद्योगिक क्रान्ति के) अन्तर्गत हुए परिवर्तन इतने व्यापक और गहन थे गुणों और दोषों के प्रतीक्षे सम्मिश्रण को अपने में छिपाए इतने दुलदाई थे तथा एक और सामाजिक ऋणो एव दूसरी ओर भौतिक प्रगति के संयोग में इतने नाटकीय थे कि उन्हें क्रान्तिकारी परिवर्तन कहना ही अधिक उपयुक्त होगा।” वस्तुतः आर्थिक क्षेत्र में हुए इन अभूतपूर्व परिवर्तनों से सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक संगठन क्रान्तिकारी ढंग से बदल गए।

औद्योगिक क्रान्ति की निश्चित अवधि क्या थी कहना कठिन है। पर परिवर्तनों का क्रम 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से प्रारम्भ होकर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक तेजी से चलता रहा। जैसे इस औद्योगिक क्रान्ति की अवधि 1760 से लेकर प्रथम महायुद्ध से पूर्व तक मानी जा सकती है, जिसमें न केवल ब्रिटेन ने बल्कि सम्पूर्ण विश्व ने आर्थिक समस्याओं के एक नए युग में प्रवेश किया।

औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व इंग्लैण्ड की आर्थिक अवस्था (Economic Condition of England before Industrial Revolution)

यहाँ हमारे अध्ययन का विषय औद्योगिक क्रान्ति के समय से इंग्लैण्ड का आर्थिक विकास है, अतः औद्योगिक क्रान्ति और उसके प्रभावों का विवेचन करने से पूर्व यह जान लेना अपेक्षित है कि इस महान क्रान्ति से पहले इंग्लैण्ड की आर्थिक अवस्था क्या और कैसी थी ?

ग्रामीण जनसंख्या की बहुलता—19वीं शताब्दी के मध्य तक इंग्लैंड मुख्यतः एक कृषि-प्रधान देश था जिसकी अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण थी। ग्रेगरी किंग के अनुसार, 1696 में इंग्लैंड की लगभग 77 प्रतिशत जनसंख्या कृषि में और 5 प्रतिशत उद्योगों में लगी थी। लगभग 41 लाख व्यक्ति गांवों में निवास करते थे और 14 लाख व्यक्ति नगरों में। गांवों की तुलना में नगरों की संख्या बहुत कम थी। 1881 में अर्थात् औद्योगिक क्रान्ति के बाद इंग्लैंड की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात क्रमशः 66.7 तथा 33.3 हो गया और आज तो 80 प्रतिशत लोग नगर-निवासी हैं।

कृषि की प्रधानता—औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व इंग्लैंड एक कृषि-प्रधान राष्ट्र था जिसके उद्योग अ विकसित किन्तु विकासोन्मुख स्थिति में थे। कृषि-प्रधान देश होते हुए भी कृषि-कार्य के तरीके पुराने और घिसे-पिटे थे। कृषि का यन्त्रीकरण नहीं हुआ था। खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में बिकरे थे। खुले-खेत-पद्धति (Open Field System) का प्रचलन था। त्रि-खेत पद्धति (Three-Field System) के आधार पर कृषि होती थी जिसमें प्रति 3 वर्ष में एक बार खेत को विश्राम दिया जाता था। भूमि की चकवन्दी और बेराबन्दी के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई थी, किन्तु कुल मिलाकर कृषि का सपठन प्राचीन और अविकसित था। फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति घटती जा रही थी और किसानों में निर्धनता और निराशा बढ़ रही थी।

कृषि के सहायक धन्धे के रूप में पशु-पालन-व्यवसाय भी बड़ा पिछड़ा हुआ था। चरागाहों की स्थिति भी सन्तोषजनक नहीं थी। चरागाह सार्वजनिक होते थे जिन पर सभी लोगों को पशु चराने का अधिकार होता था। छोटे स्तर पर भेड़-पालन का कार्य होता था, लेकिन भेड़ें निर्बल और मरियल-सी थीं।

उद्योग-धन्धे—औद्योगिक स्थिति भी उत्साहजनक नहीं थी। सूती-वस्त्र, ऊन, इस्पात, धातु और मिट्टी के बर्तन, काँच जैसे अधिकांश निर्माणकारी उद्योग धारण नहीं हुए थे, और यदि हुए भी वे तो बड़े छोटे पैमाने पर केवल गांवों में ही पाए जाते थे। देश की जनसंख्या का लगभग 5 प्रतिशत ही उद्योगों में लगा हुआ था। सूती एवं ऊनी वस्त्र का उत्पादन-कार्य कुटीर उद्योग के रूप में किसानों द्वारा सहायक पेशे के रूप में किया जाता था। ऊन उद्योग की स्थिति अच्छी थी और वह उस समय इंग्लैंड की समृद्धि का आधार बना हुआ था। कुछ अन्य उद्योग भी विकसित हो चुके थे, जैसे लोह-उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, शीशा एवं ताम्बा उद्योग, कागज उद्योग तथा छपाई उद्योग। औद्योगिक क्रान्ति के समय यद्यपि सूती वस्त्र उद्योग महत्त्वपूर्ण नहीं था, तथापि इसका निर्यात-व्यापार बढ़ रहा था। फिर भी 1764 में सूती वस्त्र उद्योग का कुल निर्यात ऊन उद्योग के कुल निर्यात के 1/20 भाग से अधिक नहीं था। हौजरी उद्योग पतन चुका था, यद्यपि नार्य हाथों द्वारा ही किया जाता था। सिल्क उद्योग भी विकासोन्मुख था। लिनन (Linen) उद्योग इंग्लैंड का प्राचीन उद्योग था। इंग्लैंड के यार्कशायर, नारफोक तथा दक्षिण-पश्चिमी भाग उद्योगों की दृष्टि से उन्नत और प्रसिद्ध थे। कुल मिलाकर स्थिति यह

6 इंग्लैंड का आर्थिक-विकास

थी कि इंग्लैंड 1750 तक औद्योगिक दृष्टि से समृद्धि और विविधता की सीढियाँ चढ़ने लगा था। अन्य यूरोपीय राष्ट्रों के मुकाबले ब्रिटिश उद्योग बहुरूपी और उन्नत थे।

औद्योगिक क्रान्ति के ठीक पूर्व ब्रिटिश उद्योगों की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ थी—

(1) उत्पादन-कार्य हस्तशिल्प-प्रणाली के आधार पर किया जाता था। उत्पाद-कार्य बड़ा सरल था और वाष्प शक्ति का प्रयोग नहीं था।

(2) औद्योगिक संगठन की इकाई के रूप में परिवार ही प्रमुख था। परिवार ही उत्पादन की इकाई का कार्य करता था। कारखाना-पद्धति प्रचलन में नहीं थी।

(3) श्रम-विभाजन एकदम सरल था। मजदूरी तकदी में न चुकाकर प्रायः वस्तुओं के रूप में चुकाई जाती थी जिसे 'Truck System' कहते थे। इस पद्धति के फलस्वरूप श्रमिकों का शोषण होता था।

(4) यातायात एवं संचार साधनों के अभाव में बाजारों का विस्तृत होना सम्भव नहीं था और स्थानीय तौर पर ही कच्चे माल की पूर्ति की जाती थी।

(5) औद्योगिक व्यवस्था में गिल्ड-प्रणाली का प्रचलन था। व्यापारियों के संगठन "Merchant Guilds" और शिल्पियों के संगठन 'Craft Guilds' बृहद होते थे।

व्यापार—व्यापार की मात्रा सीमित थी। आन्तरिक व्यापार विदेशी व्यापार से अधिक था, तथापि विदेशी व्यापार में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही थी। विशेष बात यह थी कि फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड जैसे यूरोपीय देशों के साथ तो ब्रिटिश व्यापार घट रहा था, लेकिन उपनिवेशों के साथ व्यापार में प्रगति हो रही थी। 17वीं शताब्दी के आरम्भ में इंग्लैंड का निर्यात व्यापार केवल 17 लाख पौण्ड था जो बढ़कर 1760 में लगभग 145 लाख पौण्ड हो गया। निर्यात व्यापार में वृद्धि के फलस्वरूप जहाजरानी का भी विकास हो रहा था। ब्रिटेन की तत्कालीन व्यापार नीति "व्यापारवादी सिद्धान्तों" (Merchantilist Policy) पर आधारित थी। उस समय की परिस्थितियों की दृष्टि से इंग्लैंड की यह नीति उचित ही थी।

यातायात—औद्योगिक क्रान्ति से पूर्व यातायात के साधन अविश्वसित थे। सड़कों की दशा शोचनीय थी। स्थल यातायात खर्चीला, धीमा और खतरे से भरा था। देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाने में काफी समय लगता था। आन्तरिक जल यातायात के विकास पर ध्यान अग्रव्यक्त किया गया था और नदियों को गहरा करने के लिए अधिनियम भी पारित किए गए थे तथा 1755 में लिवरपूल में एक 10 मील लम्बी नहर भी बनाई जा चुकी थी, पर कुल मिलाकर कोई ठोस विकास नहीं हो पाया था। यात्राएँ बड़ी असुविधाजनक और असुरक्षित थीं।

आर्थिक विकास के प्रति तत्कालीन सरकारी नीति—जैसा कि कहा जा चुका है, इंग्लैंड में आर्थिक विकास के प्रति उस समय व्यापारवादी नीति की प्रमुखता थी

जिसका उद्देश्य देन-केन-प्रकारेण "अनुकूल व्यापार सन्तुलन" (Favourable Balance of Trade) प्राप्त करना था। सरकार को विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त था, लेकिन आर्थिक क्रियाओं की जटिलता के फलस्वरूप नियन्त्रण सम्बन्धी विधान लागू करना बड़ा कठिन था। श्रमिक निराश और हताश थे। कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जाती थी। वास्तव में 18वीं शताब्दी का इंग्लैंड पूँजीवादी प्रणाली से दूर था। गृह-प्रणाली का प्रचलन था जिसके अन्तर्गत कारीगर बहुधा अपने घरों में ही उत्पादन-कार्य करते थे।

श्रीद्योगिक ज्ञान्ति से पूर्व की अर्थ-व्यवस्था के इस विवेचन से स्पष्ट है कि तत्कालीन इंग्लैंड एक ऐसा देश था जो कृषि-प्रधान था, लेकिन जिसके उद्योग विकासोन्मुख थे। विदेशी व्यापार बढ रहा था और कृषि में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे थे। जहाजरानी उद्योग प्रगति पर था और देश साधारणों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर था। वैकिंग व्यवस्था भी विकसित हो रही थी। इस प्रकार सन् 1760 तक इंग्लैंड में श्रीद्योगिक ज्ञान्ति के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था।

इंग्लैंड में श्रीद्योगिक ज्ञान्ति के सर्वप्रथम आने के कारण

(Why the Industrial Revolution First came in England ?)

यद्यपि श्रीद्योगिक ज्ञान्ति की प्रक्रिया, जो दो-तीन सौ वर्ष पहले आरम्भ हुई थी, अब भी जारी है क्योंकि अब भी नये-नये श्रीद्योगिक आविष्कार हो रहे हैं, तथापि इंग्लैंड में सन् 1760 ई० के बाद लगभग आधी शताब्दी में और यूरोप में सन् 1815 ई० के बाद के वर्षों में इतने नान्तिकारी परिवर्तन हुए कि कृषि-प्रधान देश श्रीद्योगिक देश हो गए और इसीलिए इन वर्षों को श्रीद्योगिक ज्ञान्ति का युग कहते हैं। यह श्रीद्योगिक ज्ञान्ति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई और तब अन्य देशों में फैली। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से इंग्लैंड तत्कालीन यूरोप में कोई विशेष शक्तिशाली देश नहीं था और फ्रांस ब्रिटेन की तुलना में अधिक समृद्ध था, फिर भी ज्ञान्ति का सूत्रपात सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही हुआ। अवश्य ही इसके कुछ विशेष कारण थे—

(1) अन्य देशों के मुकाबले आवश्यक पृष्ठभूमि का अस्तित्व—इंग्लैंड में उस आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण हो चुका था जिसके आधार पर कोई भी श्रीद्योगिक ज्ञान्ति सफल हो सकती थी। किसी भी देश में श्रीद्योगिक ज्ञान्ति होने के लिए 4 बातें आवश्यक होती हैं—पूँजी और कुशलता, विस्तृत बाजार क्षेत्र, विकासोन्मुख उद्योग एवं आन्तरिक तथा राजनीतिक शान्ति। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के इंग्लैंड में सौभाग्यवश ये सभी बातें उपलब्ध थीं। सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में थे, पूँजीवाद की शुरुआत हो गई थी, यूरोपीय देशों तथा उपनिवेशों के साथ निर्यात व्यापार उन्नत था, वैकिंग व्यवस्था पनप रही थी, ब्रिटिश व्यापारियों को विशाल उत्पादन तथा विदेशी व्यापार का अच्छा अनुभव था और

देश में राजनीतिक शान्ति विद्यमान थी। इतने परिस्थितियों में स्वाभाविक था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रान्ति का श्रीगणेश होता।

औद्योगिक क्रान्ति के लिए आवश्यक उपर्युक्त परिस्थितियाँ फ्रांस, जर्मनी, रूस तथा यूरोप के अन्य राष्ट्रों में विद्यमान नहीं थी। फ्रांस 18वीं शताब्दी में एक शक्तिशाली और समृद्ध देश था, लेकिन वहाँ आन्तरिक शान्ति नहीं थी, बैंकिंग व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई थी वित्तियोग व्यवस्था भी ठीक नहीं थी, व्यापार सघों का सर्वथा अभाव था, फ्रैन्च सम्राट अपनी वशानुगत समस्याओं से इतने ग्रस्त थे कि देश के आर्थिक विकास की ओर उनका ध्यान केन्द्रित ही नहीं हो पाता था, सामन्तशाही का बोलबाला था, व्यापारिक क्षेत्र में विविध नियन्त्रण थे, प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से इंग्लैंड जैसी समृद्धि नहीं थी और जनसंख्या की अधिकता के फलस्वरूप आविष्कारों की तीव्र आवश्यकता भी अनुभव नहीं हुई थी। फ्रांस में जो राज्य-क्रान्ति हुई उसने देश के औद्योगिक विकास को न केवल पीछे धकेल दिया बल्कि उसकी गति भी अवरुद्ध कर दी। श्रीमती नोल्स के शब्दों में, "यदि फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने फ्रांस के औद्योगिक तथा आर्थिक जीवन को अस्त-व्यस्त न कर दिया होता, तो इंग्लैंड की जगह फ्रांस ही औद्योगिक क्रान्ति का प्रयुता होता।"

जर्मनी में भी औद्योगिक क्रान्ति अपेक्षाकृत बहुत बाद में आरम्भ हुई, क्योंकि 1870 तक जर्मनी का पुनर्गठन ही नहीं हो पाया था। औद्योगिक क्रान्ति के लिए आवश्यक पूँजी का भी जर्मनी में अभाव था। जर्मनी एक कृषि-प्रधान देश था और वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। इसके अतिरिक्त जर्मनी ने बड़े पैमाने पर सैनिकीकरण किया था, अतः औद्योगिक विकास के लिए धन जुटाना उसके लिए प्रायः असम्भव था। जर्मनी के पास औपनिवेशिक साम्राज्य भी नहीं था, अतः औद्योगिक कच्चे माल और विस्तृत बाजारों की दृष्टि से इंग्लैंड के मुकाबले वह बहुत कमजोर था।

रूस बहुत पिछड़ा हुआ और निर्धन राष्ट्र था, हॉलैंड के पास पर्याप्त पूँजी नहीं थी और बैंकिंग तथा व्यापार-व्यवस्था भी क्षीण थी और स्पेन भी विभिन्न समस्याओं में उलझा हुआ ऐसा राष्ट्र था जो औद्योगिक क्रान्ति की दिशा में सोच भी नहीं सकता था। तत्कालीन भारत व्यापार और उद्योग में उन्नति के शिखर पर था, अतः वहाँ के लोगों को अपना माल बेचने के लिए विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता था। कुटीर उद्योग पतने हुए थे और भारतीय अपने वर्तमान से इतने सन्तुष्ट थे कि नई मशीनों आविष्कृत करने की ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। भारतीयों में यह विश्वास गहरा बैठा हुआ था कि परम्परागत विधियों से बनाई गई वस्तु अधिक अच्छी होती है।

इस प्रकार कुल मिलाकर इंग्लैंड ही एक ऐसा देश था जहाँ औद्योगिक क्रान्ति के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ अन्य सभी देशों के मुकाबले अधिक अच्छी तरह विद्यमान थी। इंग्लैंड निवासी भी अन्य देशवासियों की तुलना में, औद्योगिक

(14) पूँजीपतियों के प्रभाव में वृद्धि—औद्योगीकरण के लिए भारी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता थी, अतः पूँजीपति वर्ग के प्रभाव में तेजी से वृद्धि हुई। उत्पादन और वितरण दोनों प्रक्रियाओं पर उद्योगपति छा गए। व्यापार का अधिकांश कार्य उद्योगपतियों के हाथों में केन्द्रित होने लगा। उद्योगपति वर्ग संगठित भी होने लगा अतः उसमें सरकारी नीति को प्रभावित करने की क्षमता आ गई।

(15) सरकारी नीति में परिवर्तन—क्रान्ति से पहले इंग्लैंड में व्यापार-वादी नीति का महत्त्व था जिसके अन्तर्गत ब्रिटिश उद्योगों को पूर्ण सुरक्षण दिया जाता था। लेकिन औद्योगिक क्रान्ति के उपरान्त इंग्लैंड का व्यापारिक प्रभुत्व कायम हो गया और ब्रिटिश उद्योगपतियों को किसी भी देश से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ा। अतः मुक्त व्यापार-नीति की माँग जोर पकटने लगी। सरकार ने अनुकूल रख अपनाते हुए व्यापारवादी नीति का परित्याग करके स्वतन्त्र व्यापार नीति (Laissez Fair Policy) अपनाई।

(16) श्रमिक वर्ग पर प्रभाव—औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप श्रमिक वर्ग पर लाभकारी और हानिकारक दोनों ही प्रभाव विशेष रूप से पड़े। औद्योगीकरण होने से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलने लगा तथा श्रमिक परिवारों की आय में वृद्धि हुई। वस्तुएँ सस्ती हो गईं और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति पूर्वपिछा काफी सुधर गई। श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के लिए संगठित हुआ और उसे सामन्तवादी शोषण से मुक्ति मिली। धरेलू-प्रणाली के अन्तर्गत श्रमिकों को बड़े ही अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करना पड़ता था, लेकिन उद्योगों का आधुनिकीकरण होने पर उन्हें बानानुकूलित और सुविधापूर्ण कारखानों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। पर दूसरी ओर अनेक दृष्टियों से श्रमिक वर्ग पर हानिकारक प्रभाव भी पड़ा। श्रमिकों की उत्पादन-कार्य सम्बन्धी स्वतन्त्रता नष्ट हो गई, अतः कलात्मक प्रदर्शन और रचनात्मक दृष्टिकोण को भारी क्षति पहुँची। नगरों में अस्वास्थ्यकर वस्तियों से श्रमिकों को रहना पड़ा जिससे बीमारी और मृत्यु सत्या में वृद्धि हुई। पूँजीपतियों के साथ उनके हित भी टकराने लगे।

सामाजिक प्रभाव

(1) वर्ग संघर्ष का जन्म—औद्योगिक क्रान्ति के कारण ब्रिटिश समाज दो विरोधी वर्गों में विभाजित हो गया—श्रमिक वर्ग और पूँजीपति वर्ग। धन का असमान वितरण बटने जाने से दोनों वर्गों के बीच मतभेदों और संघर्ष की खाई चौड़ी होती गई। धनिक वर्ग द्वारा शोषण किए जाने से श्रमिक निर्धन होते गए जिससे उनमें अमान्यता की भावना पनपने लगी और मार्क्स द्वारा घोषित वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन मिला।

(2) मध्यम वर्ग का उदय—बड़े-बड़े उद्योगों के विकास के साथ ही सहायक और पूरक उद्योग-धन्धे पनपने से मध्यम वर्ग के लोगो को बड़ा लाभ हुआ। मध्यम वर्ग ने इन सहायक और पूरक धन्धों को अपनाया क्योंकि वे न तो मजदूरों

कर सकते थे और न ही बड़े उद्योग-धन्वों की स्थापना ही कर सकते थे। इसके अतिरिक्त दलाली, ठेकेदारी और इसी प्रकार के अन्य व्यापारिक कार्यों में भी वृद्धि हुई। इस प्रकार के कार्य विशेषतः मध्यम वर्ग ने ही अपनाए।

(3) श्रम के नियोजन की समस्या—हाथों के स्थान पर मशीनों द्वारा उत्पादन-कार्य होने से श्रमिकों का महत्त्व घटता गया और कालान्तर में उनकी नियोजन की समस्या उठ खड़ी हुई।

(4) जनसंख्या में वृद्धि—औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप इंग्लैण्ड की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। जीविकोपार्जन के साधन बढ़ने से और विदेशों से आयात किए गए खाद्यान्न उपलब्ध होने से जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि 19वीं शताब्दी के अन्त तक वह पिछले 100 वर्षों में चार गुनी हो गई।

(5) ग्रामीण जनसंख्या में कमी—औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप नगरीकरण की प्रक्रिया तेज हुई और गाँवों के लोग शहरों तथा औद्योगिक केन्द्रों में आकर बसने लगे। इससे जहाँ नगरों की जनसंख्या बढ़ी वहाँ गाँवों की जनसंख्या घटी। आज तो स्थिति यह है कि इंग्लैण्ड की कुल जनसंख्या का केवल 20 प्रतिशत ही गाँवों में रहता है।

(6) स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार तथा नैतिकता की समस्या—जनसंख्या बढ़ने से स्वास्थ्य की समस्या उपस्थित हो गई। अव्यवस्थित तरीके से विकसित होने के कारण नगर बीमारी और गंदगी के केन्द्र बन गए। नगरों तथा औद्योगिक स्थानों का वातावरण गम्भीर रूप से दूषित हो गया। साथ ही व्याभ्रष्टाचार और अनैतिकता का भी प्रसार होने लगा। नगरों में जनसंख्या की अतिशय वृद्धि से मकानों की समस्या ने भीपण रूप धारण कर लिया।

(7) सामाजिक उत्पीड़न—औद्योगिक क्रान्ति ने सामाजिक उत्पीड़न की स्थिति भी पैदा की। प्रारम्भिक वर्षों में पूँजीपति वर्ग ने समाज में जन-साधारण को सिर उठाने का अवसर ही नहीं दिया। सरकार भी निरपेक्ष बनी रही, अतः जन-साधारण की दशा अधिकाधिक शोचनीय हो गई। कारखानों में श्रमिक वर्ग कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसे मजदूरी बहुत कम मिलती थी जिससे परिवार का भली प्रकार पेट पलना भी मुश्किल था। श्रमिक धीरे-धीरे पूरी तरह पूँजीपतियों के शिकजे में कस गए और कारखाने से निकाले जाने का भय उन्हें हमेशा सताने लगा। लम्बे अर्से तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के उपरान्त ही श्रमजीवी वर्ग की दशा सुधर सकी। औद्योगिक क्रान्ति के कारण स्त्री और बच्चों का सर्वाधिक शोषण हुआ। कारखानों में उनसे भी काम लिया जाने लगा। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी कारखानों में प्रतिदिन 18-18 घण्टे कार्य करना पड़ता था और उन्हें खाना खाने तक की छुट्टी तक नहीं मिलती थी। काम करते-करते बच्चे थक कर सो जाते थे और कभी-कभी इस हालत में मशीनों से उनके शरीर के अंग बट जाते थे। मन्दी के दिनों में कारखानों में तालाबन्दी हो जाने पर भारी संख्या में

वेकारी फैल जाती थी। कहने का आशय यह है कि औद्योगिक शक्ति ने अनेक विपन्न सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया जिनमें आज भी समाज का एक बड़ा वर्ग पीड़ित है।

(8) श्रमिकों की कुशलता पर प्रभाव—औद्योगिक क्रान्ति से बहुत से श्रमिकों की कुशलता में ह्रास हुआ। उनके उत्पादन-शक्ति में कमी आई। पहले वे सम्पूर्ण वस्तु स्वयं बनाते थे, लेकिन अब श्रम-विभाजन के कारण वस्तु का एक भाग ही बनाने लगे। अतः उनकी कुशलता पहले जैसी नहीं रही।

(9) ट्रक-प्रणय—औद्योगिक शक्ति ने ट्रक-प्रणय (Truck System) को भी प्रोत्साहन दिया। प्रायः श्रमिकों को उनके बतन का भुगतान वस्तुओं के रूप में किया जाने लगा जो कुछ बचता भी था उससे उन्हें उद्योगपतियों द्वारा खोली गई दूकानों से ही सामान खरीदना पड़ता था। पूँजीपतियों की नीति ऐसी थी जिसके फलस्वरूप श्रमिकों की सम्पूर्ण आय व्यय हो जाती थी और उन पर कर्जा चढ़ जाता था। इस स्थिति में बहुत आगे चलकर मुघार होने लगा।

(10) पारिवारिक जीवन में ह्रास—औद्योगिक शक्ति ने श्रमिकों के पारिवारिक जीवन को नारकीय बना दिया। श्रमिक अधिकांश समय कारखानों में बिताने लगे और इस प्रकार अपने परिवार से बहुत अधिक समय तक दूर रहने लगे। घर छोड़ने पर भी अतिशय पकान के कारण उन्हें मोने के अतिरिक्त कुछ नहीं सुभता था। इन सब बातों ने श्रमिकों का पारिवारिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। कुछ नेतृकों का मत है कि कारखाना-प्रणाली का पारिवारिक जीवन पर अस्वाभाविक प्रभाव पड़ा क्योंकि श्रमिक नियमित रूप से काम करने के अभ्यस्त हो गए जिससे उनका नैतिक उत्थान हुआ।

(11) सामाजिक चेतना का विकास—श्रीमती नोल्ल की मान्यता है कि 'यदि फ्रान्च राज्य शक्ति ने वैयक्तिक स्वतन्त्रता और समानता का पाठ पढ़ाया तो ब्रिटिश औद्योगिक शक्ति ने वैयक्तिक स्वतन्त्रता का क्रियात्मक उपयोग सम्भव बना दिया।' औद्योगिक शक्ति ने कालान्तर में श्रमिकों में सफ़ल-शक्ति का विकास किया जिससे अन्तर्गत एसी सामाजिक चेतना पैदा हुई जिसने व्यक्ति के सम्मान और मुसलमूत अधिकारों की सफलतापूर्वक मांग की।

राजनीतिक प्रभाव

इंग्लैंड के लिए औद्योगिक शक्ति के राजनीतिक प्रभाव अत्यन्त महत्वपूर्ण और दूरगामी हुए। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश संसद में केवल भूमिपतियों का ही प्रभाव था, लेकिन औद्योगिक शक्ति के कारण छोटे नगरों और शहियों द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधि भेजने तथा बड़े नगरों को प्रतिनिधित्व देने की मांग जोर पकड़ने लगी। आगे चलकर संसदीय मुघार को इस मांग की उपेक्षा नहीं की जा सकी।

औद्योगिक शक्ति ने ऐसा अतावरण तैयार कर दिया कि ब्रिटिश सरकार

को मुक्त व्यापार नीति अपनायी पडी और कारखाना-प्रणाली के दोषो को दूर करने के लिए विभिन्न कारखाना अधिनियम बनाने पडे। इस क्रान्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम यह निकला कि फ्रांस और नेपोलियन पर इंग्लैण्ड को विजय प्राप्त हुई। क्रान्ति के फलस्वरूप उत्पादन बढा और इंग्लैण्ड ने विपुल धन कमाया। धन क बल पर वह लम्बे अरसे तक फ्रांस और नेपोलियन से लडकर अन्त मे उन्हें हराने मे सफल हुआ। औद्योगिक क्रान्ति के फलस्वरूप ही मध्य वर्ग का न केवल विकास हुआ बल्कि यह वर्ग बहुत प्रभावशाली बन गया। राजनीतिक शक्ति मध्य वर्ग के हाथो मे सिकटती गई। कॉर्न काठून (Corn Law) को रद्द करने तथा चाटिस्ट आन्दोलन को दबाने मे मध्य वर्ग का ही हाथ था।

औद्योगिक क्रान्ति का एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि उद्योगो पर सैनिक शक्ति निर्भर करने लगी। उद्योग प्रधान देशो-इंग्लैण्ड फ्रांस, जर्मनी आदि की सैनिक शक्ति बहुत बढ गई।

इस सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि औद्योगिक क्रान्ति ने इंग्लैण्ड के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन मे क्रान्तिकारी परिवर्तन किए। मेरीडिथ के अनुसार— 'यद्यपि औद्योगिक क्रान्ति मे अनेक बुराइयाँ थी फिर भी वे लाभप्रद थी इस क्रान्ति के कारण इंग्लैण्ड की वित्त और आर्थिक व्यवस्था में काफी सुधार हुआ।' औद्योगिक क्रान्ति के प्रभाव अच्छे और बुरे दोनो प्रकार के थे, लेकिन बुराइयाँ सर्वथा औद्योगिक क्रान्ति की उपज नहीं थी क्योंकि वे तो पहले से ही चली आ रही थी। वास्तविकता यह थी कि कारखाना प्रणाली ने उन बुराइयो को अधिक उजागर कर दिया। औद्योगिक क्रान्ति का बस्तुतः इस दृष्टि से सुपरिणाम ही निकला कि बुराइयो को दूर करने के प्रयत्न हुए और ऐसे कानून बने जिनसे श्रमिको के हितो की रक्षा सम्भव हुई और कारखानो की काय-प्रणाली पर नियन्त्रण रखा गया। क्रान्ति के फलस्वरूप औद्योगिक श्रमिको के श्रेष्ठ वर्ग का उदय हुआ जिसने अपने अधिकारो की सफल लडाई लडी। औद्योगिक क्रान्ति से राष्ट्र की आय मे वृद्धि हुई और व्यापारी, उद्योगपति आदि अत्रिक धनवान और सम्पन्न हो गए। इससे देश के बाह्य व्यापार मे आशातीत वृद्धि हुई और इंग्लैण्ड एक महत्वपूर्ण उत्पादक राष्ट्र बन गया। लेकिन साथ ही औद्योगिक क्रान्ति ने अनेक नई समस्याएँ भी पैदा की जैसे वर्ग-सम्पर्क, नगरो मे जनसंख्या की वृद्धि और उससे उत्पन्न कठिनाइयाँ आदि।



औपनिवेशिक विस्तार के आर्थिक पहलू

(Economic Aspects of Colonial Expansion)

“उपनिवेशों की स्थापना ने ब्रिटेन को वह साधन उपलब्ध किया जिससे विदेशी वस्तुएँ अपनी बन जाएँ। इसने आर्थिक सम्बन्धों से जुड़े हुए एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना कराई जिसमें प्रत्येक अंग सम्पूर्ण साम्राज्य को सभाले उसका पोषण करे तथा मातृ-राष्ट्र एवं उपनिवेश एक-दूसरे के पूरक बन जाएँ।”

—लिप्सन

इंग्लैण्ड का औपनिवेशिक वैभव एक परम्परागत नीति थी, किन्तु 19वीं सदी के आरम्भ में उसका महत्त्व अधिक बढ़ गया और शताब्दी के अन्त तक इंग्लैण्ड विश्व की महान औपनिवेशिक शक्ति बन गया जिसके साम्राज्य में “सूर्य कभी अस्त नहीं होता था।” इंग्लैण्ड के औपनिवेशिक विस्तार के क्षेत्र में फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल डेनमार्क, हॉलैण्ड आदि विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों की तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा और अनेक रक्त-राजत सङ्घर्षों लड़नी पड़ी, लेकिन वह सबसे आगे निकल गया। औपनिवेशिक विस्तार की प्रतिद्वन्द्विता का ही यह आवश्यक परिणाम निकला कि विश्व राजनीति का युग आरम्भ हुआ। अभी तक यूरोपीय राज्यों की प्रतियोगिता यूरोप तक ही सीमित थी लेकिन अब सम्पूर्ण सत्तार, मुख्यतः एशिया और अफ्रीका, उनका रण-भू-मन्थ बन गया। अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड आदि में ब्रिटिश प्रभुत्व तथा औपनिवेशिक शक्ति का दोलबाला हो गया। भारत इंग्लैण्ड का सबसे बड़ा राज्य बना। उपनिवेशों के विस्तार के साथ-साथ ब्रिटिश आर्थिक पहलू परिवर्तित और विकसित होते गए जिन्होंने ब्रिटेन को धन-धान्य से भर दिया। अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में जो ब्रिटेन उपनिवेशों को भार-स्वल्प मानता था वही उन्नीसवीं शताब्दी के आते-आते उन्हें अपनी अमूल्य सम्पत्ति मानने लगा।

औपनिवेशिक विस्तार के कारण एवं उद्देश्य

(Causes and Objectives of Colonial Expansion)

इंग्लैण्ड विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक कारणों तथा उद्देश्यों से प्रेरित होकर औपनिवेशिक विस्तार की ओर अग्रसर हुआ।

आर्थिक कारण एव उद्देश्य

(1) इंग्लैण्ड के निवासियों में प्रारम्भ से ही वाणिज्यवादी प्रवृत्ति प्रवल थी। वे अपने मन में यह उद्देश्य सजोये हुए थे कि विदेशी व्यापार द्वारा अतुल सोना चाँदी कमा कर अपने देश को समृद्ध और शक्तिशाली बनाएँ। विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए आवश्यक था कि इंग्लैण्ड अपने उपनिवेशों की स्थापना करता।

(2) एक ओर तो इंग्लैण्ड की जनसंख्या बढ़ रही थी और दूसरी ओर खाद्यान्नों का अभाव तथा अकालों का प्रकोप था। खाद्यान्नों के अभाव की पूर्ति के लिए विदेशों में इंग्लैण्ड के प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार आवश्यक था। इसलिए इंग्लैण्ड के लोग ऐसे क्षेत्रों में अपने उपनिवेश स्थापित करने को आकर्षित हुए जहाँ से उन्हें खाद्यान्न तथा कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सके।

(3) देश की आर्थिक समृद्धि के लिए इंग्लैण्ड वालों ने यह उपयुक्त समझा कि दूसरे राष्ट्रों के प्राकृतिक साधनों के विदोहन का मार्ग प्रशस्त किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति तभी सम्भव थी जब इंग्लैण्ड का अपना उपनिवेशीय विस्तार करे। प्राकृतिक साधनों और बहुमूल्य खनिज के शोषण के लिए ही इंग्लैण्ड निवासी अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा, न्यूजीलैण्ड आदि में अपने प्रभुत्व क्षेत्र कायम करने के लिए आगे बढ़े।

(4) अंग्रेजों के मन में यह बात घर कर गई कि उपनिवेशों में जाकर वे वैशुमार धन कमा कर श्रेष्ठ जीवन-स्तर का भ्रानन्द उठा सकेंगे। केवल इंग्लैण्ड में ही रहते हुए यह सम्भव नहीं था। ब्रिटिश पूँजीपति अपनी पूँजी पर अधिक लाभ तभी कमा सकते थे जब वे उपनिवेशों में पूँजी विनियोग करते।

उपर्युक्त आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर ब्रिटन ने अपना आपनिवेशिक विस्तार लिया और उपनिवेशों के पूर्ण शोषण अथवा विदोहन की नीति अपनाई। उपनिवेशों को ब्रिटिश हित-साधन का माध्यम बनाया गया तथा उनके साथ व्यापार करने का एकाधिकार केवल ब्रिटिश व्यापारिक कम्पनियों को दिया गया। विविध कानून बना कर उपनिवेशों से तथा अन्य देशों से उन वस्तुओं का आयात प्रतिबन्धित कर दिया गया जो ब्रिटिश वृत्ति एव उद्योगों से प्रतियोगिता करते थे। उपनिवेशों को ब्रिटिश कारखानों के लिए कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाया गया। ब्रिटेन अपने निरमित माल को उपनिवेशों में खपाने लगा और वहाँ के कच्चे माल का अतिरिक्त आयात करके अपने औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने में जुट गया। उपनिवेशों से खाद्यान्न तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओं को इंग्लैण्ड में सस्ते मूल्यों पर आयात करने की नीति अपनाई गई। उपनिवेशों का बहुमूल्य खनिज पदार्थ इंग्लैण्ड की ओर प्रवाहित किया गया।

राजनीतिक कारण एव उद्देश्य

उपनिवेशों को बटाना उस युग में राष्ट्रीय गौरव माना जाता था। जितने अधिक उपनिवेश एव राज्य के पास होते थे उतनी ही प्रतिष्ठा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उस राज्य की होती थी। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैण्ड आदि यूरोपीय दश अपनी

राजनीतिक शक्ति के विस्तार के लिए उपनिवेशों की स्थापना कर रहे थे। स्वाभाविक था कि इंग्लैंड भी इस दौड़ में शामिल हो गया। इस कार्य में यूरोपीय राज्यों में आसपस से टूटकर होड़ चली और इंग्लैंड को फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों से युद्ध भी करना पड़ा। स्थानीय जनता से भी सघर्ष करने पड़े। लेकिन अपनी कुशल और शक्तिशाली सामुद्रिक सैन्य-शक्ति तथा व्यावहारिक कूटनीति के बल पर इंग्लैंड ने श्रीपनिवेशिक विस्तार में सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। नेपोलियन के युद्धों का अन्त होने के समय तक इंग्लैंड सबसे बड़ी श्रीपनिवेशिक शक्ति बन गया और अगली कुछ दशकधियों में एशिया, अफ्रीका तथा विश्व के अन्य भागों में ब्रिटेन के उपनिवेश स्थापित हो गए। बड़े-बड़े जल-मार्गों के महत्त्वपूर्ण केन्द्रों पर ब्रिटिश नाकाबन्दी करली गई। सैनिक महत्त्व के ठिकानों पर उसका राजनीतिक प्रभाव स्थापित हो गया। अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर तथा हिन्द महासागर में ब्रिटिश व्यापारिक जहाजरानी का आवागमन पूर्ण सुरक्षित हो गया। ब्रिटेन का उपनिवेशीय प्रसार नए राजनीतिक उद्देश्य आर्थिक उद्देश्यों का पूरक सिद्ध हुआ।

धार्मिक, सामाजिक तथा अन्य कारण एव उद्देश्य

(1) पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में इंग्लैंड निवासी धार्मिक उत्पीड़न से परेशान हो गए और इससे लुटकारा पाने के लिए उपनिवेशों की ओर आकर्षित हुए। चर्च के दबाव से स्वतन्त्र रहने के आकांक्षी अंग्रेजों ने उपनिवेशों में अरण्य तेना अधिक उपयुक्त मनना।

(2) इंग्लैंड का पादरी वर्ग धार्मिक "जेहाद" के जोश से प्रेरित होकर उपनिवेशों में धर्म-प्रचार में जुट गया। इंग्लैंड के पादरी एशिया, अफ्रीका और विश्व के कुछ दूसरे भागों में दूर-दूर तक जाकर ईसाई धर्म की ध्वजा फहराने लगे। उन्होंने दूरस्थ तथा पिछड़े प्रदेशों में जनता पर अपना प्रभाव जमा कर ब्रिटिश राजनीतिज्ञों और सैन्य विचारकों के लिए श्रीपनिवेशिक विस्तार की पृष्ठभूमि तैयार कर दी।

(3) अंग्रेज यह समझने लगे कि उपनिवेशों के आचार पर वे अपनी सस्कृति और अपने साहित्य का विश्व व्यापी प्रसार कर सकेंगे।

(4) नवीन साहित्यिक कार्यों का प्रलोभन भी श्रीपनिवेशिक विस्तार के लिए उत्तरदायी बना। अफराधियों तथा दोषी व्यक्तियों को उपनिवेशों में भेजने अथवा उनके बाहर भाग जाने की प्रवृत्ति से भी कुछ उपनिवेशों का विस्तार सम्भव हुआ।

उपर्युक्त विभिन्न कारणों एव उद्देश्यों से प्रेरित होकर इंग्लैंड ने भरपूर शक्ति से अपना श्रीपनिवेशिक विस्तार किया और अमेरिका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया तथा अफ्रीका के विभिन्न भागों में इंग्लैंड के उपनिवेश स्थापित हो गए। इंग्लैंड का सबसे बड़ा राज्य भारतवर्ष बना जो सन्धे सघर्ष के बाद 1947 में जाकर ब्रिटिश शासन से मुक्ति पा सका। 19वीं शताब्दी के अन्त तक इंग्लैंड का साम्राज्य ससार के विभिन्न भागों में इतना फैल गया कि यह कहावत परितार्थ हो गई कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज कभी नहीं डूबता।

ब्रिटिश उपनिवेशवाद का इतिहास तथा उसके आर्थिक पहलू (History of British Colonialism and its Economic Aspects)

ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के साथ साथ जो विभिन्न आर्थिक पहलू प्रकट हुए, उनके क्रमानुसार अध्ययन के लिए यह उचित होगा कि हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इतिहास के साथ-साथ आर्थिक पहलुओं को लेकर आगे बढ़ें। इस दृष्टि से ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार अथवा इतिहास को हम मुख्यतः निम्नलिखित चार भागों में बाँट सकते हैं—

- (1) 1603 से 1776 तक पुरातन औपनिवेशिक पद्धति का काल,
- (2) 1776 से 1870 तक औपनिवेशिक निर्वाह व्यापार का काल,
- (3) 1870 से 1895 तक विदेशी प्रतिस्पर्धा की प्रतिक्रिया का काल,
- (4) 1895 से 1920 तक रचनात्मक साम्राज्यवाद का काल।

1603 से 1776 तक पुरातन औपनिवेशिक पद्धति का काल

17वीं व 18वीं शताब्दी को ब्रिटिश इतिहास में मुख्यतः पुरातन औपनिवेशिक पद्धति का युग कहा जाता है। इस समय उपनिवेशों के सम्बन्ध में, आर्थिक दृष्टिकोण से ब्रिटेन की नीति यह रही—

(1) उपनिवेशों को ब्रिटेन ने अपनी निजी सम्पत्ति मानते हुए उनका उपयोग ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए किया। मूल उद्देश्य यही रहा कि उपनिवेशों के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य को आत्म निर्भर बनाया जाए।

(2) यह प्रयास किया गया कि उपनिवेश ब्रिटिश फैक्ट्रियों के लिए औद्योगिक कच्चे माल की पूर्ति के साधन बनें। इस दृष्टि से उपनिवेशों को कपास, रेशम, टिम्बर, प्लेक्स तथा अन्य माल उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा इसके लिए आवश्यक आर्थिक सहायता भी दी गई।

(3) ब्रिटेन ने यह सदैव ध्यान रखा कि उपनिवेश कहीं अपना औद्योगिक विकास करके ब्रिटिश उद्योगों के प्रतिस्पर्धी न बन जाएँ। अतः उसने उपनिवेशों को ऐसी किसी वस्तु का निर्माण नहीं करने दिया जिससे ब्रिटिश उद्योगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुँचने की सम्भावना हो।

(4) उपनिवेशों पर यह भार डाला गया कि वे ब्रिटेन के औद्योगिक सस्థानों के लिए न केवल कच्चे माल व कृषि वस्तुओं का उत्पादन करें बल्कि उन उद्योगों द्वारा निर्मित माल की खरीद भी करें।

(5) ब्रिटेन ने उपनिवेशों पर यह पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए रखा कि वे अन्य राष्ट्रों से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध न रखें। ब्रिटेन को भय था कि अन्य देश इन उपनिवेशों में अपना माल बेचने की ओर इन उपनिवेशों से आवश्यक कच्चा माल खरीदने की कोशिश करेंगे। इस तरह ब्रिटेन को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा और साथ ही उसके राजनीतिक प्रभुत्व को भी खतरा पैदा हो जाएगा। यही मकसद कुछ समझते हुए ब्रिटेन ने उपनिवेशों को पूर्ण नियन्त्रण में रखा। उपनिवेशों को व्यापार ब्रिटिश जहाजों से और इंग्लैण्ड के माध्यम से ही करना पड़ता था।

स्पष्ट है कि ब्रिटिश नीति उपनिवेशों का हर प्रकार से आर्थिक शोथण करने की थी। इस पुरातन पद्धति में मुख्यतः दो प्रकार के उपनिवेश थे। भारत, पश्चिमी अफ्रीका तथा कुछ वेस्ट इंडीज-द्वीप ऐसे उपनिवेश थे जो व्यापारिक दृष्टि से विशेष महत्त्व के थे। बर्जोनिया, पश्चिमी अफ्रीका आदि उपनिवेश ऐसे थे जिनका आर्थिक विदोहन अभी पूरी तरह नहीं होने लगा था वरन् इनकी स्थापना नए व निर्जीव क्षेत्रों में अपने लोगों का विस्तार करने के लिए हुई थी।

1776 से 1870 तक श्रीपनिवेशिक निर्वाह व्यापार का काल

कॉलम्बस द्वारा अमेरिका महाद्वीप की खोज की जाने के बाद यूरोप की जातियाँ ने इस नई दुनिया में अपने उपनिवेश स्थापित करना आरम्भ कर दिया था जिसमें सर्वाधिक और निर्णायक सफलता ब्रिटेन को ही मिल सकी थी। सन् 1776 तक अमेरिका में मूलग मूलग 13 उपनिवेशों की स्थापना हो चुकी थी जो आन्तरिक मामलों में स्वशासित होते हुए भी इंग्लैण्ड के आधिपत्य में थे। व्यापारवाद की नीति पर चलते हुए इंग्लैण्ड अपने उपनिवेशों का प्रयोग अपने लाभ के लिए कर रहा था, अतः उपनिवेशों के आर्थिक हितों को ब्रिटेन के हितों के बाद द्वितीय स्थान दिया जाता था। उन उद्योगों को, जो ब्रिटेन के उद्योगों के साथ प्रतिभोगिता कर सकते थे, उपनिवेशों में हतोत्साहित किया जाता था और जिन वस्तुओं की इंग्लैण्ड में माँग होती थी उन्हें प्रोत्साहित किया जाता था। वस्तुतः उपनिवेशों के व्यापार का सम्पूर्ण ढाँचा ब्रिटेन के आर्थिक हित में ही तैयार किया जाता था।

श्रीपनिवेशिक विस्तार और अन्य राजनीतिक मतभेद के कारण इंग्लैण्ड और फ्रांस में लम्बे अर्से से शत्रुता चली आ रही थी। 1763 में इंग्लैण्ड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध में विजयी होने के बाद इंग्लैण्ड की सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया कि अधीनस्थ उपनिवेश होने के कारण अमेरिका के उपनिवेश भी इस युद्ध के व्यय का भार वहन करें। ब्रिटिश सरकार की इच्छा थी कि उपनिवेशों की रक्षा और शासन-प्रबन्ध पर होने वाले व्यय का कुछ भाग उन्हें (उपनिवेशों को) स्वयं उठाना चाहिए। अतः ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकन उपनिवेशों पर व्यापार सम्बन्धी कानूनों को कठोर कर दिया और ब्रिटिश व्यापारियों के हितों की दृष्टि से उपनिवेशवासियों पर नए-नए कर बोये। परिणाम यह हुआ कि उपनिवेश निवासियों में विद्रोह की भावना भड़क उठी। उन्होंने ब्रिटिश संसद द्वारा लगाए गए करों को देना अस्वीकार कर दिया।

जब उपनिवेशों ने इंग्लैण्ड द्वारा आरोपित कानूनों व आज्ञाओं का खुला उल्लंघन करना शुरू कर दिया तो ब्रिटिश सरकार ने अधिकधिक दमनकारी उपायों का आश्रय लिया। अन्त में सभी 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घुसघात बरते हुए जुलाई, 1776 में ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी स्वामी-भक्ति समाप्त कर दी। स्वाधीनता सत्राण में उपनिवेश विजयी हुए। 1783 में एक सन्धि पर हस्ताक्षर हो गए जिसमें यह बात मानली गई कि सभी 13 उपनिवेश पूर्णतः स्वतन्त्र और प्रभुतासम्पन्न राज्य होंगे।

अमेरिका के इन उपनिवेशों के सफल विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को अपनी औपनिवेशिक नीति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। उपनिवेशों के प्रति अब ब्रिटेन में अविश्वास की भावना पैदा हो गई। ऐसे विचार भी पनपने लगे कि इंग्लैंड उपनिवेशों के बिना ही अधिक अच्छा है और अपनी एकाधिकारी शक्ति के बल पर वह बिना उपनिवेशों के समृद्धि की ओर बढ़ सकेगा। दास-प्रथा की समाप्ति के लिए होने वाले आन्दोलनों से पश्चिमी अफ्रीका भी निराशा पैदा करने लगा और दक्षिणी अफ्रीका के उपनिवेश भी ब्रिटेन के लिए सिर-दर्द बन गए। 1807 में दास-व्यापार तथा 1833 में दास-प्रथा के समाप्त होने से उपनिवेशों के लोगों के विरोध को बल मिला। 1865 में रॉयल कमीशन ने यह सिफारिश की कि पश्चिमी अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशों का विस्तार करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। पर जहाँ एक ओर उपनिवेशों के समापन की विचारधारा पनप रही थी वहाँ दूसरी ओर अनेक प्रमुख राजनीतिक उपनिवेशों के महत्त्व में अटूट विश्वास रखे हुए थे।

इस असमजसपूर्ण स्थिति में यह विचार बल पकड़ने लगा कि उपनिवेशवाद की सकीर्ण सीमाओं में बरीयता (Preference) की नीति का परित्याग कर देना चाहिए। धीरे-धीरे ये बरीयताएँ एक-एक करके मिटती गईं और निर्बाध व्यापार की नीति का अनुसरण औपनिवेशिक नीति का मुख्य आधार बन गया। 1842 से 1870 तक ब्रिटेन में स्वतन्त्र अथवा निर्बाध व्यापार नीति का ही बोलबाला रहा। इस अधिधि में उपनिवेश भार स्वरूप गिने जाने लगे। उन्हें स्वशासन का अधिकार दिया जाने लगा ताकि वे अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए आधार-भूमि बना सकें।

यद्यपि स्वतन्त्र व्यापार नीति के अन्तर्गत बाणिज्य के क्षेत्र में ब्रिटेन और उपनिवेशों में समानता की नीति पर बल दिया गया, तथापि इस बात पर पूरा ध्यान रखा गया कि उपनिवेशों के हितों की कीमत पर ब्रिटेन के हितों की बलि न चढ़ जाए। छोटे पिट (Pitt the Younger) का दृष्टिकोण था कि सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य की दशा में सुधार और बाणिज्य के क्षेत्र में इंग्लैंड व उपनिवेशों में समानता की नीति अपनाई जाए, लेकिन ब्रिटिश संसद को यह विचार पसन्द नहीं आया। फिर भी पिट ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न जारी रखा। पिट के बाद विलियम हसकिंसन ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति को प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। 1825 में नौबहन कानून (Navigation Act) में संशोधन किया गया। इसके अनुसार ब्रिटेन को यद्यपि अपने उपनिवेशों व यूरोप के बाहर के देशों के साथ व्यापार में अधिकार रहा, तथापि उन देशों को अधिक सुविधाएँ प्रदान की गईं जो ब्रिटेन को बदले में समान सुविधाएँ देते थे। साम्राज्य अधिमान या बरीयता (Imperial Preference) की नीति में भी सुधार किया गया। इसे अधिक उदारवादी बनाया गया जिससे उपनिवेशों को लाभ पहुँचा। इंग्लैंड ने उपनिवेशों को भी अधिमान स्वीकृत किया। उपनिवेशों से आने वाली विभिन्न वस्तुओं पर, जैसे— चीनी, तम्बाकू, सिप्रट, शराब आदि पर आयात कर हटा दिया गया। अब उपनिवेशों

मे अन्य देशों से भी आयात करने की छूट दी गई, तथापि ब्रिटिश हितों का पूरा ध्यान रखा गया। विलियम ह्यूक्ससन के बाद सर रॉबर्ट पील तथा ग्लेडस्टन के समय श्रीपनिवेशिक निर्बाध व्यापार को और अधिक प्रोत्साहन मिला। उपनिवेशों से आने वाली चीनी पर से अधिमान समाप्त कर दिया गया। सैकड़ों वस्तुओं पर से तट कर हटा लिया गया। उन वस्तुओं के सम्बन्ध से जिन पर उपनिवेशों को अधिमान दिया जाता था, ग्लेडस्टन ने यह नीति निश्चित की कि अन्य देशों की वस्तुओं पर भी उतना ही तट कर लगाया जाए जितना उपनिवेशों पर आयात कर लगाया जाता है। सन् 1854 में विदेशों व उपनिवेशों से आने वाली चीनी पर तट कर की दर समान कर दी गई।

1870 से 1895 तक विदेशी प्रतिस्पर्धा की प्रतिक्रिया का काल

स्वतन्त्र व्यापार की नीति के कारण इंग्लैंड की समृद्धि में आशातीत वृद्धि हुई, किन्तु 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में इसके विरुद्ध एक भयंकर प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई जिसने अन्त में इस नीति को दफना दिया। 1870 के बाद से ही सरक्षणवादियों का पक्ष प्रबल होता गया। इस वर्ग ने साम्राज्य-अधिमान (Imperial Preference) लगाए जाने की नीति का प्रतिपादन किया। जोसफ चैम्बरलैण्ड ने यह मत प्रकट किया कि एक 'ब्रिटिश साम्राज्य चुगी सघ' (British Imperial Customs Union) संगठित किया जाए तथा ब्रिटेन और उसके सभी उपनिवेशों को एक इकाई समझा जाए। अन्य देशों की वस्तुओं पर सरक्षण कर लगाए जाएँ। सरक्षणवादियों ने कहा कि ऐसा करने से ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों में एकता बढ़ेगी तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सकेगा। स्वतन्त्र व्यापार-नीति के आकर्षण और सरक्षणवाद की मांग के तर्क-वितर्क के बीच 1870 से 1895 की अवधि में उपनिवेशवाद के प्रति निराशाजनक अनोवृत्ति का हाव होता गया।

स्वतन्त्र व्यापार-नीति के विरुद्ध जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई, उसके फलस्वरूप यद्यपि सरक्षणवादी नीति को पूरी तरह अपनाया नहीं गया तथापि उपचारात्मक उपाय अवश्य लिए गए। इस दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए गए—

(1) सन् 1886 के बाद इंग्लैंड ने साम्राज्य अधिमान (Imperial Preference) की नीति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। 1887 में उपनिवेशों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया ताकि ब्रिटेन व उपनिवेशों के मध्य चुगीसघ बनाकर बरीयता के आधार पर सरक्षणवादी राष्ट्रों के विरुद्ध मोर्चा तैयार किया जा सके।

(2) उपनिवेशों का विकास करने के लिए विभिन्न कम्पनियों का निर्माण किया गया। उदाहरणार्थ, सन् 1881 में ब्रिटिश नार्थ-वोर्नियो कम्पनी, 1886 में रायल नाइजर कम्पनी, 1888 में ब्रिटिश अफ्रीका कम्पनी तथा 1889 में ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कम्पनी की स्थापना की गई। इन कम्पनियों के निर्माण से रचनात्मक साम्राज्यवाद (Constructive Imperialism) का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिस समय

अमेरिका के इन उपनिवेशों के सफल विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को अपनी औपनिवेशिक नीति पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य कर दिया। उपनिवेशों के प्रति अब ब्रिटेन में अविश्वास की भावना पैदा हो गई। ऐसे विचार भी पनपने लगे कि इंग्लैण्ड उपनिवेशों के बिना ही अधिक अच्छा है और अपनी एकाधिकारी शक्ति के बल पर वह बिना उपनिवेशों के समृद्धि की ओर बढ़ सकेगा। दास-प्रथा की समाप्ति के लिए होने वाले आन्दोलनों से पश्चिमी अफ्रीका भी निराशा पैदा करने लगा और दक्षिणी अफ्रीका के उपनिवेश भी ब्रिटेन के लिए सिर-दर्द बन गए। 1807 में दास-व्यापार तथा 1833 में दास-प्रथा के समाप्त होने से उपनिवेशों के लोगों के विरोध को बल मिला। 1865 में रॉयल कमीशन ने यह सिफारिश की कि पश्चिमी अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेशों का विस्तार करना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा। पर जहाँ एक ओर उपनिवेशों के समापन की विचारधारा पनप रही थी वहाँ दूसरी ओर अनेक प्रमुख राजनीतिक उपनिवेशों के महत्त्व में अटूट विश्वास रखे हुए थे।

इस असमंजसपूर्ण स्थिति में यह विचार बल पकड़ने लगा कि उपनिवेशवाद की सकीर्ण सीमाओं में वरीयता (Preference) की नीति का परित्याग कर देना चाहिए। धीरे-धीरे ये वरीयताएँ एक-एक करके मिटती गईं और निर्बाध व्यापार की नीति का अनुसरण औपनिवेशिक नीति का मुख्य आधार बन गया। 1842 से 1870 तक ब्रिटेन में स्वतन्त्र अथवा निर्बाध व्यापार नीति का ही बोलबाला रहा। इस अवधि में उपनिवेश भार-स्वरूप गिने जाने लगे। उन्हें स्वशासन का अधिकार दिया जाने लगा ताकि वे अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए आधार-भूमि बना सकें।

यद्यपि स्वतन्त्र व्यापार नीति के अन्तर्गत वाणिज्य के क्षेत्र में ब्रिटेन और उपनिवेशों में समानता की नीति पर बल दिया गया, तथापि इस बात पर पूरा ध्यान रखा गया कि उपनिवेशों के हितों की कीमत पर ब्रिटेन के हितों की बलि न चढ़ जाए। छोटे पिट (Pitt the Younger) का दृष्टिकोण था कि सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य की दशा में सुधार और वाणिज्य के क्षेत्र में इंग्लैण्ड व उपनिवेशों में समानता की नीति अपनाई जाए, लेकिन ब्रिटिश संसद को यह विचार पसन्द नहीं आया। फिर भी पिट ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न जारी रखा। पिट के बाद विलियम हसकिंसन ने स्वतन्त्र व्यापार की नीति को प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। 1825 में नौवहन कानून (Navigation Act) में संशोधन किया गया। इसके अनुसार ब्रिटेन को यद्यपि अपने उपनिवेशों व यूरोप के बाहर के देशों के साथ व्यापार में अधिकार रहा, तथापि उन देशों को अधिक सुविधाएँ प्रदान की गईं जो ब्रिटेन को बदले में समान सुविधाएँ देते थे। साम्राज्य-अधिमान या वरीयता (Imperial Preference) की नीति में भी सुधार किया गया। इसे अधिक उदारवादी बनाया गया जिससे उपनिवेशों को लाभ पहुँचा। इंग्लैण्ड ने उपनिवेशों को भी अधिमान स्वीकृत किया। उपनिवेशों से आने वाली विभिन्न वस्तुओं पर, जैसे—चीनी, तम्बाकू, स्प्रिट, शराब आदि पर आयात कर हटा दिया गया। अब उपनिवेशों

मे अन्य देशों से भी आयात करने की छूट दी गई, तथापि ब्रिटिश हितों का पूरा ध्यान रखा गया। विलियम हसकिन्सन के बाद सर रॉबर्ट पील तथा ग्लेडस्टन के समय औपनिवेशिक निर्वाह व्यापार को और अधिक प्रोत्साहन मिला। उपनिवेशों से आने वाली चीनी पर से अधिमान समाप्त कर दिया गया। सैंडवो वस्तुओं पर से तट कर हटा लिया गया। उन वस्तुओं के सम्बन्ध में जिन पर उपनिवेशों को अधिमान दिया जाता था, ग्लेडस्टन ने यह नीति निश्चित की कि अन्य देशों की वस्तुओं पर भी उतना ही तट कर लगाया जाए जितना उपनिवेशों पर आयात कर लगाया जाता है। सन् 1854 में विदेशों व उपनिवेशों से आने वाली चीनी पर तट कर की दर समान करदी गई।

1870 से 1895 तक विदेशी प्रतिस्पर्धा की प्रतिक्रिया का काल

स्वतन्त्र व्यापार की नीति के कारण इंग्लैंड की समृद्धि में आशातित वृद्धि हुई, किन्तु 19वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में इसके विरुद्ध एक भयंकर प्रतिक्रिया प्रारम्भ हुई जिसने अन्त में इस नीति को दफना दिया। 1870 के बाद से ही सरक्षणवादियों का पथ प्रबल होता गया। इस वर्ग ने साम्राज्य-अधिमान (Imperial Preference) लगाए जाने की नीति का प्रतिपादन किया। जोसफ चेम्बरलैण्ड ने यह मत प्रकट किया कि एक 'ब्रिटिश साम्राज्य युगी संध' (British Imperial Customs Union) संगठित किया जाए तथा ब्रिटेन और उसके सभी उपनिवेशों को एक इकाई समझा जाए। अन्य देशों की वस्तुओं पर सरक्षण कर लगाए जाएँ। सरक्षणवादियों ने कहा कि ऐसा करने से ब्रिटेन और उसके उपनिवेशों में एकता बढ़ेगी तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सकेगा। स्वतन्त्र व्यापार-नीति के आकर्षण और सरक्षणवाद की माँग के तर्क वितर्क के बीच 1870 से 1895 की अवधि में उपनिवेशवाद के प्रति निराशाजनक मनोवृत्ति का ह्रास होता गया।

स्वतन्त्र व्यापार-नीति के विरुद्ध जो तीव्र प्रतिक्रिया हुई, उसके फलस्वरूप यद्यपि सरक्षणवादी नीति को पूरी तरह अपनाया नहीं गया तथापि उपचारात्मक उपाय अवश्य किए गए। इस दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए गए—

(1) सन् 1886 के बाद इंग्लैंड ने साम्राज्य अधिमान (Imperial Preference) की नीति को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। 1887 में उपनिवेशों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया ताकि ब्रिटेन व उपनिवेशों के मध्य युगीसंध बनाकर वरीयता के आधार पर सरक्षणवादी राष्ट्रों के विरुद्ध मोर्चा तैयार किया जा सके।

(2) उपनिवेशों का विकास करने के लिए विभिन्न कम्पनियों का निर्माण किया गया। उदाहरणार्थ, सन् 1881 में ब्रिटिश नार्थ-वोनियो कम्पनी, 1886 में रॉयल नाइजर कम्पनी, 1888 में ब्रिटिश अफ्रीका कम्पनी तथा 1889 में ब्रिटिश साउथ अफ्रीका कम्पनी की स्थापना की गई। इन कम्पनियों के निर्माण से रचनात्मक साम्राज्यवाद (Constructive Imperialism) का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिस समय

ब्रिटिश सरकार उपनिवेशवाद की नीति के बारे में असमजसपूर्ण स्थिति में थी, उस समय इन कम्पनियों ने विभिन्न क्षेत्रों में इंग्लैण्ड के प्रभुत्व की स्थापना करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इन कम्पनियों के कारण ही ये क्षेत्र ब्रिटेन के आर्थिक हितों का पोषण करने के साधन बने रहे और विदेशियों के एकाधिकार में नहीं जा सके।

(3) औपनिवेशिक व्यापार की उन्नति के लिए उपनिवेशों में रेलों, सड़कों और बन्दरगाहों के विकास के प्रयास किए गए। रेलों तथा सामुद्रिक जहाजों ने ब्रिटेन को उसके उपनिवेशों के अधिक नजदीक ला दिया। इनके कारण निर्मित माल के लिए बाजार के रूप में उपनिवेशों का महत्व बढ़ता गया।

(4) उपनिवेशों में फैल रही विभिन्न प्रकार की बीमारियों को रोकने के लिए चिकित्सालय खोले गए जिनका अपरोक्ष रूप में उपनिवेशों के साथ ब्रिटेन के आर्थिक सम्बन्धों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा।

ब्रिटेन की इस औपनिवेशिक नीति का परिणाम यह हुआ कि उसे बहुत ही कम लागत पर आर्थिक विद्वेषण के लिए विशाल बाजार और कच्चे माल तथा खाद्यान्न के भण्डार प्राप्त हो गए। जो व्यापारिक कम्पनियाँ अस्तित्व में आईं वे नए-नए उपनिवेश स्थापित करने और उनका विस्तार करने तथा ब्रिटेन के आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने की दिशा में अमूल्य सेवा करती रही। साथ ही ब्रिटिश सरकार पर प्रशासन सम्बन्धी कोई विशेष आर्थिक बोझा भी नहीं पड़ता था। ये कम्पनियाँ महाद्वीपों के भीतरी भागों में पहुँचने और उपनिवेशों से अधिकाधिक आर्थिक लाभ कमाने के लिए रेलों और सड़कों के निर्माण में सलग्न रही। इन कम्पनियों के योग्य संचालकों ने अफ्रीका में ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने का सराहनीय प्रयत्न किया। 1895 से 1920 तक रचनात्मक साम्राज्यवाद का काल

सन् 1895 में जोसफ चेम्बरलैण्ड उपनिवेश सचिव नियुक्त हुए। तभी से ब्रिटेन ने विस्तारवादी नीति के स्थान पर जिस नई औपनिवेशिक नीति को अपनाया उसे नया रचनात्मक साम्राज्यवाद (New Constructive Imperialism) कहा जाता है। यह नीति मुख्यतः इसलिए अपनाई गई कि औपनिवेशिक व्यापार की उन्नति की जाए तथा साम्राज्य के साधनों का विकास करके उसके देशों में एकता लाई जाए। 1895 से 1920 की इस अवधि में ब्रिटेन और उपनिवेशों के आर्थिक सम्बन्धों को विकसित करने की दृष्टि से ये कदम विशेष उल्लेखनीय रहे हैं—

(1) 1887 में प्रथम औपनिवेशिक सम्मेलन के बाद 1894, 1897, 1907, 1911, 1917 और 1920 में औपनिवेशिक सम्मेलन आयोजित किए गए। 1907 के सम्मेलन में औपनिवेशिक अधिमान (Colonial Preference) का नाम बदल कर स्थाई रूप से साम्राज्य अधिमान (Imperial Preference) रख दिया गया तथा यह निश्चय किया गया कि प्रत्येक सदस्य देश को दूसरे सदस्य देश के निर्मित माल को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन सम्मेलनों से ब्रिटेन तथा उपनिवेशों के बीच आर्थिक सम्पर्क का बहुत अधिक विकास हुआ।

(2) सन् 1899 में एक औपनिवेशिक ऋण विधान स्वीकृत किया गया। ब्रिटिश कोष को यह अधिकार मिला कि शुद्ध उपनिवेशों को उसमें से ऋण दिया जा सके। ऋण को 50 वर्षों में लौटाने की व्यवस्था की गई। उपनिवेशों को यह भी छूट दी गई कि वे लंदन के खुले बाजार में भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

(3) उपनिवेशों में व्यापार सम्बन्धी सूचनाओं के प्रसार की योजना बनाई गई। इसके लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड के प्रयत्नों से एक विशेष समिति नियुक्त की गई जिसकी सिफारिश पर बोर्ड ऑफ ट्रेड की 'व्यापार सूचना विभाग' नामक एक विशेष शाखा अस्तित्व में आई। सन् 1908 में दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में ब्रिटिश व्यापार आयुक्त नियुक्त किए गए। प्रथम महायुद्ध काल में भारत वेस्ट इंडीज आदि में भी वाणिज्य दूतों की नियुक्ति हुई।

(4) सन् 1918 में एक खनिज पदार्थ ब्यूरो खोला गया जिसका कार्य खनिज पदार्थ सम्बन्धी सूचना देना था। उपनिवेशों में कृषि विभाग खोलने की ओर भी ध्यान दिया गया क्योंकि उपनिवेशों के कच्चे माल की ब्रिटेन को बहुत जरूरत थी। वेस्ट इंडीज में सर्वप्रथम उष्ण प्रदेशीय कृषि विभाग स्थापित किया गया।

(5) उपनिवेशों में यातायात के साधनों के विकास को प्रोत्साहन दिया गया था। औपनिवेशिक व्यापार व अन्य विदेशी व्यापार की वृद्धि के लिए जहाजरानी को अधिक विकसित किया गया।

व्यापारिक क्षेत्र में विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों से निकट सम्पर्क स्थापित कर उन्हें एकता के सूत्र में बाँधने की जो नीति अपनाई वह पर्याप्त सफल रही। इससे ब्रिटेन के आर्थिक हित अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ हुए। रचनात्मक साम्राज्यवाद की नीति के कारण सामुद्रिक मनोवृत्ति (Sea Psychology) के स्थान पर भूमि-मनोवृत्ति (Land Psychology) में प्रमुखता ग्रहण की।

ब्रिटेन की वह नई औपनिवेशिक नीति पुरातन औपनिवेशिक नीति से बहुत भिन्न थी। इस समय उपनिवेशों में भेद-भाव करने की नीति अपनाई गई। अतः यह उचित होगा कि हम रचनात्मक साम्राज्यवाद के काल का वर्णन उपनिवेशों के सम्बन्ध में अपनाई गई इस भेद-नीति के आधार पर भी करें। इनसे इस युग के औपनिवेशिक विस्तार के आर्थिक पहलुओं पर ज्यादा अच्छा प्रकाश डाला जा सकेगा।

नई औपनिवेशिक नीति के क्रियान्वयन के अनुरूप कुछ समय के लिए उपनिवेश मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किए गए—

(क) एम्पायर इन ट्रस्ट (Empire in Trust), तथा

(ख) एम्पायर इन अलायन्स (Empire in Alliance)।

(क) एम्पायर इन ट्रस्ट

(Empire in Trust)

"एम्पायर इन ट्रस्ट" के अन्तर्गत वे ब्रिटिश उपनिवेश शामिल थे जिनमें, अश्वेत लोग (Coloured People) रहते थे। अफ्रीका और एशिया के उपनिवेश

ऐसे ही थे। इन उपनिवेशों में जनसंख्या घनी थी। उपनिवेश-वासियों को स्वशासन का अधिकार प्राप्त न था। शासन सूत्र ब्रिटेन के हाथ में था। 'एम्पायर इन ट्रस्ट' को इसलिए 'दी एम्पायर ऑफ रूल' (The Empire of Rule) भी कहा जाता था। चेम्बरलेन के अनुसार ये उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्य की अविकसित सम्पत्ति (Undeveloped Estates) थे जिनके विकास के लिए पूँजी विनियोग आवश्यक था।

ब्रिटिश सरकार ने इन सब उपनिवेशों के विकास की ऐसी नीति अपनाई जिससे ब्रिटेन के हितों को पूरा संरक्षण मिलता, ब्रिटिश व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपनिवेशों का आर्थिक विदोहन अधिक सुगम हो जाता और उपनिवेशों में वे ही उद्योग पनपते जो ब्रिटेन के लिए किसी भी रूप में प्रतियोगी सिद्ध न होते। दूसरे शब्दों में यह कहा जाना चाहिए कि विकास के नाम पर उपनिवेशों के अविकास की नीति पर ही चला गया। उपनिवेशों में औद्योगिक प्रगति को कुण्ठित रखा गया। इन्हें कृषि प्रधान बनाए रखने का प्रयत्न किया गया ताकि ये ब्रिटेन के लिए कच्चे माल की पूर्ति का साधन बने रहे। उद्योगों को इसलिए नहीं पनपने दिया गया कि ब्रिटिश उद्योगों द्वारा निर्मित माल उपनिवेशों के बाजारों में खप सके। ब्रिटेन की यह नीति भी रही कि ब्रिटिश उद्योगों के लिए उपनिवेश खनिज-उत्पादन में लगे रहे। जब कभी ब्रिटेन को यह महसूस हुआ कि उपनिवेशों का किसी क्षेत्र में विकास ब्रिटिश उद्योगों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा, तो उस अविलम्ब रोक दिया गया।

'एम्पायर इन ट्रस्ट' (Empire in Trust) वाले उपनिवेशों के विकास की ऐसी नीति अपनाई गई जिससे उनका आर्थिक अवशोषण हो सके। इस दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए—

(1) यातायात के साधनों का विकास किया गया। रेलों के विकास में प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी गई। बन्दरगाह आदि के निर्माण के लिए भी धन व्यय किया गया। उपनिवेशों में रेलों के विकास, बन्दरगाहों के निर्माण से व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ी तथा निर्यात व्यापार में वृद्धि हुई। उदाहरणार्थ, जहाँ 1891 में गोल्डकोस्ट से कोको (Cocoa) का निर्यात केवल 4 लाख पौण्ड होता था वहाँ 1916 में यह लगभग 38 लाख पौण्ड होने लगा। यातायात के साधनों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिशीलता बढ़ी। पश्चिमी अफ्रीका ब्रिटेन को कोको, मू गफली आदि का निर्यात करने लगा तथा ब्रिटिश माल का प्रमुख आयातक बन गया। उपनिवेशों में रेलों का विकास करने से ब्रिटिश सरकार को भारी आर्थिक लाभ हुआ।

(2) स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य सस्थाओं का विस्तार किया गया ताकि उपनिवेश महामारियों के प्रकोप से बच सकें और उनमें श्वेत लोगों को अधिकाधिक बसाया जा सके जो वहाँ अर्थ-तन्त्र पर अपना पूरा कब्जा जमा लें।

(3) उपनिवेशों में कृषि के वैज्ञानिकरण को प्रोत्साहन दिया गया। कृषि-क्षेत्र और कृषि ज्ञान के विस्तार के प्रयास किए गए ताकि अधिकाधिक कच्चा माल उत्पादित किया जाकर ब्रिटेन की भेजा जा सके। कृषि शिक्षा के प्रसार से किसानों को

अधिकाधिक लाभ उठाने के अवसर दिए जाने लगे। फसलों को नष्ट करने वाले रोगों और जीव जंतुओं पर नियन्त्रण की नीति अपनाई गई। उपनिवेशों में कृषि विभाग खोले जाने लगे जिनसे नई-नई कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन मिला। उदाहरणार्थ, बेस्ट इंडीज में कृषि विभाग खोला गया जिसने नई पद्धति से गन्ना-उत्पादन बढ़ाया। नई पद्धति के कारण गन्ने के उत्पादन में पूर्वपिछा 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई। इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास के आयात को बहुत अधिक आवश्यकता थी। अतः उपनिवेशों में कपास की फसलों को बहुत अधिक प्रोत्साहन दिया गया। ब्रिटिश-भाग की पूति के लिए कपास की उत्तम-कोटि की फसलें उगाई जाने लगीं। मिस्र और अमेरिका में कपास का सद्योग एक तिहाई भाग बीटो व रोपों से नष्ट हो जाता था, अतः इस दिशा में सुधार के आवश्यक कदम उठाए गए। ब्रिटिश सरकार ने इस क्षति को रोकने के लिए काफी धन-राशि व्यय की। कपास से उत्पादन के विकास के लिए उपनिवेशों में रेलों और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि की गई। फलस्वरूप कपास का उत्पादन काफी घट गया। उदाहरणार्थ—नाइजीरिया में जहाँ प्रथम महायुद्ध के विस्फोट के समय अर्थात् 1914 में कपास का उत्पादन केवल 11 गाँठ होता था वहाँ 1921 में यह उत्पादन लगभग 31,500 गाँठ होने लगा। कपास की माँति ही गेहूँ, गन्ना, जूट, रेशम, सरसों, तम्बाकू आदि में भी वृद्धि के लिए वैज्ञानिक प्रयास किए जाने लगे।

अपने आर्थिक हितों की दृष्टि से ब्रिटेन ने उपनिवेशों में यातायात के साधनों, बन्दरगाहों, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि सस्त्राओं आदि का जो विकास किया उसके फलस्वरूप उपनिवेशों की अतिक्रमिता सम्पत्तियों का तेजी से विद्योहन किया जाने लगा। यद्यपि उपनिवेशों को भी लाभ हुआ क्योंकि उनमें उद्योग व कृषि के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार हुआ और आधुनिक यातायात के साधन विकसित हुए, तथापि ब्रिटेन की आर्थिक समृद्धि दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ने लगी। ब्रिटेन के सम्पर्क से उपनिवेशों में पत्त-शर्त जागरण की लहर पैदा होने लगी और अन्त में एक दिन वह प्राया अब उपनिवेशों की सम्पत्ति लूटने के दरवाजे बन्द हो गए।

उल्लेखनीय है कि 'एम्पायर इन ट्रस्ट' में भी स्वयं की अधिमान पद्धति (Preference System) का विकास हुआ। उदाहरणार्थ, 1919 में ब्रिटेन द्वारा अधिमान अपनाए जाने पर माल्टा व साइप्रस ने ब्रिटिश माल के आयात में अधिमान-नीति का अनुसरण किया। इसी प्रकार जामियाका ने भी साम्राज्य में उत्पादित सूती माल पर अधिमान देने की नीति अपनाई।

(ख) एम्पायर इन अलायन्स (Empire in Alliance)

"एम्पायर इन अलायन्स" के अन्तर्गत वे उपनिवेश सम्मिलित थे जिनमें श्वेत लोग रहते थे अथवा जहाँ श्वेत लोग बस-कर उन्हें अधिकाधिक आवाद कर सकते थे। 'इनमें कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका आदि थे। इन देशों को स्वशासन का अधिकार प्राप्त था और उन्हें कुछ आर्थिक स्वतन्त्रताएँ मिली हुई थी। इन उपनिवेशों को "डोमिनियन्स" (Dominions) कहा जाता था।

ब्रिटिश सरकार ने इन डोमिनियनों के साथ आर्थिक सहयोग की नीति अपनाई और उन्हें परस्पर एक-दूसरे के साथ व्यवहार के सम्बन्धों में विभिन्न व्यापारिक सुविधाएँ प्रदान कीं। ब्रिटिश सरकार द्वारा इन उपनिवेशों के प्रति अपनाई गई यह नीति ही वास्तव में "साम्राज्य अधिमान" (Imperial Preference) की नीति के आविर्भाव का कारण थी।

'एम्पायर इन अलायेन्स' के उपनिवेशों को आन्तरिक स्वतन्त्रता 1875 तक मिल चुकी थी। इन्हें "एम्पायर ऑफ सैटलमेंट" (Empire of Settlement) अथवा "ब्रिटिश कॉमनवैलथ ऑफ नेशन्स" (British Commonwealth of Nations) भी कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार के प्रयासों ने इन उपनिवेशों अथवा डोमिनियनों में यातायात के साधनों का बहुत अधिक विकास हुआ जिससे इनके आपसी सम्बन्ध विकसित हुए तथा "साम्राज्यीय सघ" (Imperial Federation) की धारणा बल पकड़ने लगी।

डोमिनियनों में "साम्राज्यीय सघ" की विचारधारा के जोर पकड़ने पर ब्रिटेन ने सन् 1887 में एक उपनिवेशीय सम्मेलन का आयोजन किया ताकि प्रदेशों के साथ राजनीतिक व आर्थिक दृष्टि से निकटतम सम्पर्क बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त हो। अगले सम्मेलन क्रमशः 1894, 1897, 1907, 1911, 1917, तथा 1920 में आयोजित हुए। 1917 में आयोजित सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया। यह निश्चय भी हुआ कि भविष्य में होने वाले सभी सम्मेलनों में भारत को प्रतिनिधित्व मिलेगा। यह वास्तव में एक महत्त्वपूर्ण निश्चय था क्योंकि इसके फलस्वरूप "एम्पायर इन अलायेन्स" की श्वेत लोगों की दपौती समाप्त हो गई। 1918 में साम्राज्यीय युद्ध कैबिनेट (Imperial War Cabinet) द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि साम्राज्य के विभिन्न उपनिवेश कच्चे माल को बेचने के सम्बन्ध में साम्राज्यीय देशों को प्राथमिकता देंगे।

सारांशतः ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति में समयानुसार परिवर्तन होता गया और 19वीं शताब्दी के अन्त में इस बात पर अधिकाधिक बल दिया जाने लगा कि परस्पर व्यापार में वृद्धि की जाए। जैसा कि कहा जा चुका है, साम्राज्य अधिमान इसी परिवर्तित नीति का परिणाम था। यद्यपि इसकी अर्थात् साम्राज्य अधिमान की चर्चा पूर्व पक्षियों में जगह-जगह की जा चुकी है, तथापि विषय की स्पष्टता की दृष्टि से यह उचित होगा कि अलग से इस पर कुछ लिख दिया जाए।

साम्राज्य अधिमान का इतिहास

साम्राज्य अधिमान के अन्तर्गत उपनिवेश ब्रिटेन को विभिन्न व्यापारिक सुविधाएँ देते थे और ब्रिटेन भी उन्हें आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करता था। ये देश आपस में एक-दूसरे की वस्तुओं पर या तो तटकर लगाते ही नहीं थे अथवा तटकर की दर घटा देते थे। इसके विपरीत ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर के देशों की वस्तुओं पर प्रायः ऊँची दर से तटकर लगाया जाता था।

साम्राज्य अधिमान का आरम्भ 1897 में तब हुआ जब कनाडा में ब्रिटिश वस्तुओं पर करों में 12½ प्रतिशत की छूट दी गई। 1918 में यह अधिमान बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया। यह अधिमान केवल ब्रिटिश वस्तुओं पर ही दिया जाता था। अन्य उपनिवेशों की वस्तुओं को यह अधिमान तभी मिल सकता था जब कनाडा की वस्तुओं को भी उन उपनिवेशों में अधिमान दिया जाता।

सन् 1902 में जो श्रीपनिवेशिक सम्मेलन हुआ, उसमें साम्राज्य अधिमान की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। यद्यपि रूपरेखा साम्राज्य के अधिकांश देशों में लागू की गई तथापि ब्रिटेन इसे पूरी तरह अपना नहीं सका। क्योंकि अभी तक वह स्वतन्त्र व्यापार नीति और संरक्षणवाद के तर्क वितर्क में बुरी तरह फँसा हुआ था। 'व्यवहार' अभी स्वतन्त्र व्यापार-नीति की ही प्रधानता थी। चूँकि उपनिवेशों को यह आशा थी कि ब्रिटेन निकट भविष्य में अधिमान देगा, अतः उन्होंने इस नीति को जारी रखा तथा 1922 तक कुल 26 देशों ने इस नीति को अपना लिया। फलस्वरूप ब्रिटेन को काफी आर्थिक लाभ पहुँचा। सन् 1915 के बाद ब्रिटेन संरक्षणवाद की ओर प्रसरण हुआ। अथ उपनिवेशों को कुछ अंशों में अधिमान दिया जाने लगा। सन् 1919 में साम्राज्यीय देशों से आयातित वस्तुओं पर कर की दर भी कम की गई। 1921 में एक अधिनियम के अन्तर्गत यद्यपि कुछ ब्रिटिश उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया, किन्तु उपनिवेशों की वस्तुओं पर तटकर में छूट दी गई।

वास्तव में 1915 से सन् 1931 तक ब्रिटेन पूरी तरह संरक्षणवाद नहीं अपना सका। व्यवहार में काफी सीमा तक आयात पर प्रतिबन्ध और कर लगाए जाने से स्वतन्त्र व्यापार नीति में बाधा पटने लगी थी और संरक्षणवाद को अपनाया जा चुका था, तो भी सैद्धान्तिक रूप से ब्रिटेन अभी स्वतन्त्र व्यापारवादी राष्ट्रों की श्रेणी में बने रहना चाहता था। लेकिन अन्ततः परिस्थितियों ने बाध्य कर दिया कि ब्रिटेन स्वतन्त्र व्यापार नीति का पूर्ण परित्याग कर दे। अक्टूबर, 1931 में ब्रिटेन में ऐसी सरकार बनी जो संरक्षणवादी नीति की समर्थक थी। इस नई सरकार के सत्ताह्व होते ही ब्रिटिश आर्थिक नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए और इंग्लैंड पूर्ण रूप से एक संरक्षणवादी राष्ट्र बन गया।

सन् 1932 में ओटावा (Ottawa) में साम्राज्यीय देशों का एक आर्थिक सम्मेलन (Economic Conference) हुआ जिसमें साम्राज्यवादी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से ब्रिटेन ने उनके आयात पर निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की—

- (1) सभी साम्राज्य के देशों की वस्तुओं पर ब्रिटेन में कोई तटकर नहीं लगाया जाएगा।
- (2) कुछ ब्रिटिश विदेशी वस्तुओं पर तत्कालीन अधिमान की सीमा 10 प्रतिशत रखा गई, तथा
- (3) साम्राज्य के देशों की अन्य वस्तुओं पर अधिक अधिमान की सुविधा दी गई। इन सुविधाओं के बदले में साम्राज्यीय देशों ने भी रासायनिक पदार्थ, सूती वस्त्र तथा ऊन आदि की निर्मित वस्तुओं को अधिमान देना स्वीकार किया।

साम्राज्यीय अधिमान (Imperial Preference) के उक्त समझौते से ब्रिटिश व्यापार में तो वृद्धि हुई, लेकिन उपनिवेशों को विशेष लाभ नहीं हुआ। इसी कारण भारत आदि देशों में श्रोटावा समझौते का विरोध किया गया, लेकिन फिर भी साम्राज्य अधिमान की नीति जारी रखी गई। वर्तमान समय में भी अपने परिवर्तित रूप में यह नीति जारी है, किन्तु अब इसे साम्राज्यीय (साम्राज्यीय अधिमान) न कह कर राष्ट्र-मण्डलीय अधिमान कहते हैं।

ब्रिटेन द्वितीय महायुद्ध के पूर्व तक संरक्षण नीति (Protection Policy) के मार्ग पर चलता रहा और साम्राज्य अधिमान की शर्तों को भी मानता रहा फिर भी आवश्यकतानुसार समय समय पर सन् 1932 से 1939 के मध्य कई देशों से द्विपक्षीय समझौते करके संरक्षण नीति में सुधार किया जाता रहा। उदाहरणार्थ, सन् 1938 में संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता किया गया।

1939 से 1945 तक द्वितीय महायुद्ध चलता रहा। इस युद्ध ने ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था को बिलबुल अस्त-व्यस्त कर दिया। उसके विदेशी बाजार संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे औद्योगिक देश के हाथों में खिसकने लगे। एक-एक करके उसके रहे सहे उपनिवेश भी हाथ से निकल गए और आज उसका साम्राज्य एक अतीत की कहानी बन चुका है।

श्रीपनिवेशिक-विस्तार से ब्रिटेन व उपनिवेशों को आर्थिक हानि-लान
अथवा

ब्रिटिश श्रीपनिवेशिक नीति के आर्थिक परिणाम

श्रीपनिवेशिक नीति के कारण ब्रिटेन को कितने विस्तृत आर्थिक लाभ हुए और उपनिवेशों की क्या दशा रही, इसका विस्तृत चित्र पूर्ववर्ती पृष्ठों में मिल जाता है, तथापि संक्षेप में इन आर्थिक परिणामों को एक-एक करके गिनाना अधिक उचित होगा—

(1) ब्रिटेन में उपनिवेशों को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाया। उपनिवेशों को प्रोत्साहित किया गया कि वे कपास, रेशम, टिम्बर प्लेक्स आदि का अधिकाधिक उत्पादन करके इन वस्तुओं का ब्रिटेन को निर्यात करें। उपनिवेशों को किसी भी ऐसी वस्तु का निर्माण करने से यथा-साध्य रोका गया जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए प्रतिस्पर्द्धा का कारण बन सकती थी।

(2) उपनिवेशों को ब्रिटिश उद्योगों द्वारा निर्मित माल के विक्रय का बाजार बनाया गया। उन्हें किसी भी अन्य राष्ट्र से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखने का अधिकार नहीं दिया गया। उपनिवेशों के औद्योगिक विकास पर अकुश रखा गया। उनकी अर्थ-व्यवस्था को इस तरह विखंडित करने का प्रयत्न किया गया कि ब्रिटिश उद्योगों को वहाँ निर्बाध व्यापार मिल सके।

(3) उपनिवेशों के कुटीर और लघु उद्योगों के विकास की तरफ भी कोई

ध्यान नहीं दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों के पुराने घरेलू उद्योग-धन्धों को नष्ट कर दिया और उनके स्थान पर आधुनिक ढंग के कारखानों का भी विकास नहीं किया। फलस्वरूप उपनिवेशों में बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप में हमेशा बनी रही। यदि आगे चलकर कुछ उद्योगों को स्थापित भी किया गया तो भी इस तरह किया गया कि ब्रिटिश हितों को कोई भी गम्भीर खतरा पैदा न हो सके।

(4) ब्रिटिश सरकार की नीति मूलतः यही बनी रही कि उपनिवेश आर्थिक जड़ता की स्थिति में फँसे रहे।

(5) कच्चे माल की प्राप्ति के लिए उपनिवेशों में कृषि को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई गई, लेकिन ब्रिटिश सरकार का प्रयत्न सदा यही रहा कि उपनिवेशों की कृषि केवल इतनी ही उन्नत बने जिससे ब्रिटेन की आवश्यकताओं की पूर्ति को सहारा मिले। इसीलिए कृषि विकास के लिए आधुनिकतम सिंचाई व्यवस्था और यान्त्रिक साज-सज्जा की पूर्ति नहीं की गई। फलस्वरूप उपनिवेशों की कृषि मानसून का जुधा इन गई। वहाँ की अस्थिर कृषि देश के औद्योगिक विकास का कोई सहयोग प्रदान नहीं कर सकी।

(6) उपनिवेशों में यातायात के साधनों का विकास किया गया, किन्तु इसके मूल में भी ब्रिटिश सरकार का इरादा अपने आर्थिक हितों की पूर्ति का था। उपनिवेशों के भीतरी भागों में ब्रिटेन में निर्मित माल को पहुँचाने के लिए तथा वहाँ से कच्चे माल को बाहरगाहों पर लाने के लिए ही मुख्यतः रेलों व सबको का विकास किया गया। ब्रिटिश सरकार की इस नीति से उपनिवेशों द्वारा निर्मित वस्तुओं की माँग समाप्त हो गई। वास्तव में ब्रिटिश नीति इंग्लैंड के औद्योगिक हित में उपनिवेशों की अर्थ-व्यवस्था का विशिष्टीकरण करने की रही। ज्यों-ज्यों ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग विकसित होता गया, ब्रिटिश-नीति कपास के कृषि क्षेत्र का विस्तार करने में ही गई। जिन उपनिवेशों की घरेली कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त थी, वहाँ कपास की खेती को अर्थविकासिक बढ़ाया गया।

(7) उपनिवेशों की परम्परागत अर्थ-व्यवस्था तहस-नहस हो गई। स्वदेशी शिल्पकारों ने बिना सोचे-समझे पश्चिमी पैटर्न की तकली जिससे स्वदेशी वस्तुओं की ख्याति को धक्का पहुँचा। स्वदेशी कारीगरों को बृहत् स्तरीय निर्माणा-उत्पादन में प्रशिक्षण पाने से वंचित रखा गया। आगे चलकर जब भारत जैसे उपनिवेशों में बड़े-बड़े उद्योगों के विकास की ओर पूँजीपतियों ने ध्यान देना प्रारम्भ किया तो घरेलू छोटे उद्योगों की अवनति एकदम चरम सीमा पर पहुँच गई।

(8) ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों में रेलों के विकास के माध्यम से विदेशी पूँजी के विनियोग को प्रोत्साहन दिया जिससे वहाँ अनेक बुराईयाँ उत्पन्न हो गईं। देश के उद्योगों में विदेशी पूँजी का विनियोग होने से स्वार्थी तत्त्व पनपने लगे और उपनिवेशों की राजनीतिक उन्नति में बड़ी बाधा पहुँची। वस्तुतः ब्रिटिश शासन में रेल-व्यवस्था का एक बड़ा उद्देश्य उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करना ही था। यदि उस समय उपनिवेशों के घरेलू उद्योगों और अन्य उत्पादन स्रोतों का साथ-साथ

ही विकास किया जाता तो रेलवे निर्माण और विस्तार से उन्हें काफी लाभ हो सकता था। लेकिन ब्रिटेन की नीति तो हर प्रकार से उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करने की थी। अतः रेलों द्वारा उपनिवेशों के कच्चे माल और खाद्यान्नों का निर्यात किया गया। रेलों के निर्माण पर जो व्यय किया गया उसका भार भी उपनिवेशों की जनता पर करो के रूप में डाला गया।

(9) ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति का मूल उद्देश्य यही रहा कि उपनिवेशों से ब्रिटेन की ओर सम्पत्ति का निष्कासन (Economic Drain) रहे। सम्पत्ति के निष्कासन से उपनिवेशों का कितना शोषण हुआ, इसका अनुमान हम अकेले भारत के उदाहरण से ही लगा सकते हैं। सन् 1867 में दादाभाई नौरोजी ने कहा कि “भारत में एकत्र की गई आय का लगभग $\frac{1}{4}$ भाग भारत में शासन करने का मूल्य है जो देश के बाहर चला जाता है और इंग्लैण्ड के साधनों में जोड़ दिया जाता है।” सन् 1872 में जस्टिस रानाडे ने बताया कि—“भारतीय राष्ट्रीय आय का एक तिहाई से भी अधिक भाग किसी न किसी रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा ले जाया जाता है।” विदेशी राजनीतियों और अर्थ-शास्त्रियों ने इस बात से सहमति प्रकट दी है कि सम्पत्ति-निष्कासन भारत की तथा अन्य उपनिवेशों की दरिद्रता का एक प्रमुख कारण था।

(10) ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों के उद्योगों के प्रति घातक नीति अपनाकर वहाँ आर्थिक जड़ता की प्रत्येक स्थिति पैदा कर दी है। उदाहरणार्थ, भारत में बड़े-बड़े उद्योगों पर ब्रिटिश पूँजीपतियों ने ही अधिकार रखा। बड़े पैमाने पर स्थापित किए गए अन्य उद्योगों पर सरकार का प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहा। भारतीय वस्त्र उद्योग को हर सम्भव उपाय से हतोत्साहित किया गया। ब्रिटेन को भेजे जाने वाले भारतीय सूत और रेशमी माल पर 40 से 60 प्रतिशत आय-कर लगाया गया जबकि ब्रिटिश सूती माल पर भारत में मूलानुसार केवल 3½ प्रतिशत आय-कर आरोपित किया गया। वास्तव में ब्रिटेन की कपड़ा मिलें भारतीय हितों की बलि देकर चलाई गईं। भारतीय जहाजरानी उद्योग को भी इसी तरह की भेदपूर्ण नीति अपनाकर नष्ट कर दिया गया। भारत और इंग्लैण्ड के बीच होने वाले व्यापार में भारतीय जहाजों के उपयोग को निरुत्साहित किया गया। भारत में कच्चे सोहे की बहुलता रही, लेकिन अंग्रेजों ने देश के सोहा उत्पादन पर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत में ब्रिटिश शासन की यही नीति रही कि भारतीय उद्योगों के विस्तार के लिए आवश्यक पूँजी, कच्चे माल, तकनीकी सहायता, कल-मुर्जें व मशीन आदि की सुविधाएँ ब्रिटिश पूँजीपतियों के सहयोग-से व संचालन पर उनके एकाधिकार देने पर ही प्राप्त की जा सकती थी। सन् 1923 से देश के उद्योगों के विकास में विभेदात्मक सरक्षण नीति अपनाई गई, किन्तु बहुत देर से और अपर्याप्त ढंग से अपनाई जाने के कारण यह भारतीय हितों को भागे बढ़ाने में अधिक समर्थ न हो सकी।

(11) ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशों में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का

आवश्यक प्रसार नहीं किया। फलस्वरूप विदेशों की तरह यहाँ प्राधुनिक उद्योग-धन्धे स्थापित नहीं किए जा सके।

(12) उपनिवेशों के श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने के कोई प्रयास नहीं किए गए जिससे उनकी उत्पादकता में वृद्धि नहीं हुई और न ही उनके जीवन-स्तर में सुधार हो सका। ब्रिटिश नीति केवल श्रमिकों का शोषण करने की ही रही।

(13) रचनात्मक साम्राज्यवाद के सिद्धान्त के अन्तर्गत साम्राज्यीय अधिमान की जो नीति विकसित की गई वह ब्रिटेन के लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई क्योंकि इसके आघार पर वह विश्व में अपनी व्यापारिक स्थिति कायम रख सका। पर दूसरी ओर विकासशील उपनिवेशों को भी इससे लाभ हुआ क्योंकि वे अपने मास के निर्यात को ब्रिटेन में बढ़ा सके। उदाहरणार्थ भारत उस नीति के कारण ही ब्रिटेन में अपने रपड़े का निर्यात बाजार बढ़ा सका।

(14) ब्रिटेन ने उपनिवेशों का आर्थिक विदोहन करने के लिए जिन विभिन्न साधनों का विकास किया, उनसे कालान्तर में उपनिवेशों को काफी लाभ भी पहुँचा। उपनिवेशों में वैज्ञानिक साधनों के विकास की आघार-भूमि तैयार हो गई। फलस्वरूप राजनीतिक चेतना के विकास के साथ-साथ उनमें अपने आर्थिक साधनों का खुद ही उपयोग करने और लाभ उठाने की बलवती भावना जाग्रत हुई। कालान्तर में यह स्थिति पैदा हो गई कि ब्रिटेन तेन-देन की भावना से काम करे और भी भागे चलकर उपनिवेश अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो गए। कृषि, खनिज, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में विकास की जो आघारशिला ब्रिटिश प्रयामों से बन चुकी थी, उसके बल पर वे अपने भावी औद्योगिक प्रगति का महल खड़ा करने में अपने आपको समर्थ महसूस करने लगे। इसी कारण स्वतन्त्र होने के उपरान्त उनकी प्रगति जारी रह सकी।

स्पष्ट है कि ब्रिटेन की भौपनिवेशिक नीति के कारण जहाँ प्रारम्भ में केवल ब्रिटेन ही लाभान्वित हुआ वहाँ भागे चलकर उपनिवेशों को भी लाभ पहुँचा। फिर भी ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशों का आर्थिक शोषण पहले ही इतना कर लिया गया कि बाद में उपनिवेशों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और आज भी वे अपनी आर्थिक प्रवृत्ति के लिए सघर्ष कर रहे हैं।



तीसा में आर्थिक स्थिरता की नीतियाँ

(Policies for Economic Stabilization During 1930s)

प्रथम महायुद्ध के बाद का काल यूरोप के देशों के लिए आर्थिक-पुनर्निर्माण का काल था। यूरोप के सभी क्षतिग्रस्त राष्ट्रों ने तेजी से आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्यक्रम अपनाए और 1925 तक वहाँ परिस्थितियाँ प्रायः सामान्य हो गईं। दुर्भाग्य-वश ब्रिटेन इस क्षेत्र में विभिन्न कारणोंवश पिछड़ा रहा। 1929 से पूर्व तक सभी राष्ट्रों ने भारी आर्थिक प्रगति की पर ब्रिटेन की दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ। इसके बाद ही 1929 में प्रारम्भ होने वाली महान आर्थिक मन्दी ने सभी देशों को अचानक ही घराशाही कर दिया। सम्पूर्ण विश्व घोर आर्थिक सकटों में फँस गया। ब्रिटेन ने अपनी आर्थिक दशा सुधारने के लिए जो भी प्रयत्न किए थे, वे आर्थिक मन्दी की एक ही चपेट में अस्त-व्यस्त हो गए। इसके बाद आर्थिक मन्दी के भयानक दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए 1930 वाले दशक में ब्रिटेन ने अनेक उपाय किए और महत्त्वपूर्ण आर्थिक नीतियाँ अपनाईं। इन विभिन्न नीतियों और उपायों के फलस्वरूप 1935 के बाद आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई पड़ने लगे, किन्तु 1937 में ब्रिटेन पुनः मन्दी के चक्कर में आने लगा और इसके बाद ही द्वितीय महायुद्ध सम्बन्धी तैयारियों तथा महायुद्ध के विस्फोट ने ब्रिटेन के पुनरुत्थान को रोक दिया।

महान मन्दी से पूर्व ब्रिटेन की आर्थिक दशा का एक चित्र

प्रथम महायुद्ध काल के बाद ब्रिटेन ने अपने आर्थिक पुनर्निर्माण के जो भी प्रयत्न किए वे विशेष सफल नहीं हुए। तब 1925 में ब्रिटेन ने अपनी आर्थिक दशा सुधारने और व्यापारिक परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए स्वर्णमान अपनाया, लेकिन आशाजनक परिणाम नहीं निवला। अन्य देशों के मुकाबले ब्रिटिश उत्पादन में बहुत कम वृद्धि हुई। दूरी और बेरोजगारी बहुत ही अधिक बढ़ गई। ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन अनेक कारणों से निराशाजनक रहा, जैसे निर्माण व्यय में वृद्धि, दोषपूर्ण संगठन, पुरानी मशीनें, नियोजकों का परम्परागत दृष्टिकोण, औद्योगिक भगड़े व श्रमिकों का असहयोग, सरकार की मौद्रिक नीति आदि। ब्रिटेन का निर्यात-व्यापार काफी कम हो गया। उदाहरणार्थ 1913 से 1929 के बीच सूती-वस्त्र के निर्यात में 37 प्रतिशत की, लोहा व इस्पात के निर्यात में 12 प्रतिशत की, कीयले के निर्यात में 18 प्रतिशत की और जहाज निर्यात उद्योगों के निर्माण में 19 प्रतिशत की कमी हुई। इसी तरह जहाँ 1860 में इन उद्योगों में कुल श्रम शक्ति

का लगभग 44 प्रतिशत भाग लगा था वहाँ 1929 तक यह 25 प्रतिशत के आस-पास रह गया। 1925 से 1929 के बीच जहाँ सोवियत रूस के अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्व के उत्पादन में घासत वृद्धि लगभग 26 प्रतिशत रही वहाँ ब्रिटेन में यह 16 प्रतिशत से भी कम रही। जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 तक बेरोजगारी केवल 2 प्रतिशत थी वहाँ ब्रिटेन में लगभग 11 प्रतिशत थी।

साराशत ब्रिटेन की आर्थिक दशा महान आर्थिक मन्दी से पूर्व विशेष अच्छी न थी। अन्य अनेक यूरोपीयन देशों तथा संयुक्त राज्य अमेरिका आदि के मुकाबले ब्रिटेन की दशा गिरी हुई थी।

महान् आर्थिक मन्दी के दुःप्रभाव और तीसरा में अपनाई गई ब्रिटिश नीतियाँ

सन् 1929 में अमेरिका के वास्तु स्ट्रीट के महान आर्थिक विस्फोट के साथ ही जो भयानक आर्थिक मन्दी चारों ओर फैली उसने ब्रिटेन की आर्थिक दशा को सम्भलने का मौका नहीं दिया। आर्थिक मन्दी ने सभी देशों में औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, विनियोग स्तर, विदेशी व्यापार आदि को भारी आघात पहुँचाया। ब्रिटेन पर भी इस मन्दी का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। जहाँ 1929 के मध्य तक ब्रिटेन में बेरोजगारी 11 प्रतिशत के आस-पास थी वहाँ 1932 में वार्षिक जनसंख्या का 22 प्रतिशत से भी अधिक भाग बेकार हो गया, औद्योगिक उत्पादन तैजों से गिर गया। मूल्य-स्तर, निर्यात-व्यापार, रोजगार-आदि सभी में तीव्र गति से ह्रास हुआ। 1931 में ब्रिटेन की आर्थिक दुरावस्था अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। इस समय तक ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था का जो पतन हुआ उसका आभास ब्रिटेन के प्रमुख आर्थिक तत्वों में निम्नांकित निर्देशांकों से मिलता है—

ब्रिटेन में प्रमुख आर्थिक तत्वों के निर्देशांक (1923=100)

	1929	1930	1931
औद्योगिक उत्पादन	106	98	89
रोजगार	102	98	94
घोक मूल्य-स्तर	97	85	74
निर्यात-मूल्य	103	89	74

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि महान मन्दी के समय ब्रिटेन के आर्थिक क्षेत्र के सभी पक्षों की दुरावस्था हुई। ब्रिटेन का भुगतान संतुलन भी बहुत बिगड़ गया। यह 1926 में 103 करोड़ पाँड पक्ष में था जो 1930 में 56 करोड़ पाँड विपक्ष में हो गया। विश्व-व्यापार में भी ब्रिटेन का भाग 11 प्रतिशत से घटकर 1930 में 10 प्रतिशत ही रह गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड को स्वर्ण-भुगतान की विकट समस्या का सामना करना पड़ा और पाँड के गिरते हुए मूल्य के फलस्वरूप स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा। पाँड का भवमूल्य भी किरा गया। ब्रिटिश-कृषि की दशा भी गिरती गई और सन् 1931 तक वह मन्दी के चक्कर में बुरी तरह फस गई।

तीसा में अपनाई गई ब्रिटिश नीतियाँ (British Policies Adopted during 1930s)

मन्दी के भीषण दुष्प्रभावों को दूर करने और आर्थिक स्थिरता लाने के लिए ब्रिटेन ने 1930 के दशक में विभिन्न प्रभावशाली उपाय किए जो संक्षेप में निम्नलिखित थे—

(1) स्वर्णमान का परित्याग और पौण्ड-स्टर्लिंग का अवमूल्यन

ब्रिटिश सरकार ने सन् 1931 में स्वर्णमान का परित्याग कर दिया। फलस्वरूप पौण्ड के मूल्य में शीघ्र ही 20 प्रतिशत की कमी आ गई। वर्षों के अन्त तक पौण्ड का मूल्य लगभग 10 प्रतिशत और गिर गया। स्वर्णमान के परित्याग तथा पौण्ड के अवमूल्यन के कारण ब्रिटेन को प्रारम्भ में लाभ हुआ, लेकिन जब कुछ ही समय बाद अधिकांश देशों ने भी इस नीति को अपनाया तो ब्रिटेन के तुलनात्मक लाभ शून्य शून्य कम अथवा समाप्त हो गए। इस प्रकार स्वर्णमान के परित्याग और पौण्ड के अवमूल्यन की नीति विशेष फलदायक सिद्ध नहीं हुई।

(2) संरक्षणवादी नीति

सन् 1875 के बाद से ही ब्रिटेन की स्वतन्त्र व्यापार-नीति का विरोध बढ़ता जा रहा था। फिर भी सन् 1931 तक ब्रिटेन में यह नीति प्रचलित रही। 1931 में ब्रिटेन को स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ा। इस समय ब्रिटेन का भुगतान शेष अत्यधिक प्रतिकूल हो गया और इन परिस्थितियों में संरक्षण की तीव्र आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। संरक्षणवादियों ने इस बात का जोरदार प्रचार किया कि आयात-कर लगाकर भुगतान-शेष की समस्या सुधारी जा सकती है और इस नीति पर चलने से ही ब्रिटिश उद्योगों का विकास तथा बेरोजगारी की समाप्ति सम्भव है। साथ ही अन्य देशों से भी सुविधाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।

इस वातावरण में अक्टूबर, सन् 1931 में ऐसी सरकार बनी जो संरक्षणवादी नीति की समर्थक थी। इस नई सरकार ने सत्तारूढ़ होते ही आर्थिक नीतियों में आमूल परिवर्तन किए। सितम्बर 1931 में स्वर्णमान के परित्याग के लगभग 6 माह के अन्दर ही मुक्त व्यापार की नीति का परित्याग कर दिया गया और संरक्षण व साम्राज्यीय अधिमान की नीति को अपना लिया गया।

मन्दी के कुप्रभाव को दूर करने के लिए विदेशी व्यापार पर तरह-तरह के नियन्त्रण की नीति अपनाई गई। सन् 1931 में इसी उद्देश्य से "Abnormal Importations (Customs Duties) Act" पारित किया गया जिसके अनुसार 6 माह के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर एक आयात कर लगाया गया। बाद में 1931 में "Horticultural Products (Emergency Customs Duties) Act" स्वीकृत हुआ जो 12 माह के लिए बनाया गया। इन दोनों विधानों में कुछ वस्तुओं पर 100 प्रतिशत तक आयात कर लगाने की व्यवस्था की गई।

उक्त दोनों ही अल्पकालीन विधान सन् 1932 में समाप्त कर दिए गए जबकि आयात कर अधिनियम 1932 (Import Duties Act, 1932) स्वीकृत हुआ।

इस अधिनियम के अनुसार, जो मार्च, 1932 से लागू हुआ, सभी विदेशी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत आयात कर लगाया गया जिसे बाद में बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया। कुछ खाद्य पदार्थों और कच्चे माल पर आयात कर नहीं लगाया गया। आयात कर के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए एक 'आयात कर परामर्शदाता समिति' (Import Duties Advisory Committee) बनाई गई। इस समिति के सुझावों पर कई वस्तुओं पर कर बढ़ाए गए। सरक्षण प्रदान करने के लिए एक स्थाई प्रशुल्क आयोग (Tariff Commission) संगठित किया गया।

अप्रैल, 1932 में आयातकर परामर्शदाता समिति को किसी भी वस्तु को कर मुक्त वस्तुओं की सूची में से सरक्षित वस्तुओं की सूची में सम्मिलित करने तथा उस पर कर लगाने का अधिकार दिया गया।

(3) साम्राज्य अधिमान की नीति

सन् 1932 में ओटावा (Ottawa) में साम्राज्यीय देशों का एक आर्थिक सम्मेलन (Economic Conference) हुआ जिसमें साम्राज्य के देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से ब्रिटेन ने उनके आयात पर निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान की—

(1) सभी साम्राज्य के देशों की वस्तुओं पर ब्रिटेन में कोई तटकर नहीं लगाया जाएगा,

(2) कुछ विशिष्ट विदेशी वस्तुओं पर तत्कालीन अधिमान की सीमा 10 प्रतिशत रखी गई, तथा

(3) साम्राज्यीय देशों को अन्य वस्तुओं पर अधिक अधिमान की सुविधा दी गई। इन सुविधाओं के बदले में साम्राज्यीय देशों ने भी रासायनिक पदार्थ, सूती वस्त्र तथा ऊन आदि की निम्न वस्तुओं को अधिमान देना स्वीकार किया।

साम्राज्यीय अधिमान (Imperial Preference) के उक्त समझौते से ब्रिटिश व्यापार में तो वृद्धि हुई, लेकिन उपनिवेशों को विशेष लाभ नहीं हुआ। इसी कारण भारत आदि देशों में ओटावा समझौते का विरोध किया गया, लेकिन फिर भी साम्राज्यीय अधिमान की नीति जारी रखी गई। वर्तमान समय में भी अपने परिवर्तित रूप में यह नीति जारी है, किन्तु अब इसे साम्राज्यीय अधिमान (Imperial Preference) न कह कर राष्ट्र-मण्डलीय अधिमान कहते हैं।

ब्रिटेन तृतीय महायुद्ध के पूर्व तक सरक्षण नीति (Protection Policy) के मार्ग पर चलता रहा और साम्राज्य अधिमान की शर्तों को भी मानता रहा। फिर भी आवश्यकतानुसार समय-समय पर सन् 1932 से 1939 के मध्य कई देशों में द्विपक्षीय समझौते करके सरक्षण नीति में सुधार किया जाता रहा। उदाहरणार्थ, सन 1938 में संयुक्तराज्य अमेरिका और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता किया गया।

(4) मौद्रिक नीति में परिवर्तन

ब्रिटिश सरकार ने आर्थिक मन्दी के कुप्रभावों को दूर करने के लिए अपनी

मौद्रिक नीति में भी कुछ परिवर्तन किए। राजकीय व्यय और घाटे की वित्त व्यवस्था को महत्व देते हुए सरकार ने सर्वप्रथम 'सस्ती मुद्रा नीति' (Cheap Money Policy) अपनाई। इस नीति के अनुपालन में बैंक दर घटा कर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी गई। युद्ध सम्बन्धी ऋण की व्याज दर भी 5 प्रतिशत से कम करके $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी गई। इस कदम से दीर्घकालीन विनियोगों पर व्याज-दर कम हो गई।

सस्ती मुद्रा नीति अपनाने और बैंक दर में इतनी कमी कर देने के बावजूद व्यक्तिगत विनियोग में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई। फिर भी निम्न व्याज दर के कारण राष्ट्रीय ऋण के व्याज में भारी कमी हो गई। सरकार ने कुछ करो में भी कमी की और महत्वपूर्ण उद्योगों को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। फलस्वरूप सूती वस्त्र, कोयला, जलपोत निर्माण आदि के उद्योगों के पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन मिला।

(5) विनिमय समानीकरण कोष की स्थापना

विदेशी विनिमय की स्थिरता की मात्रा को न्यूनतम बनाए रखने के लिए सन् 1932 में एक विनिमय समानीकरण कोष की स्थापना की गई। साउथगेट के अनुसार—“इस कोष का कार्य अस्थायी परिवर्तनों में स्थिरता लाने तक सीमित था वृहत्तर परिवर्तनों से सम्बद्ध कार्य का दायित्व इस पर नहीं था।” सन् 1933 में इस कोष की धनराशि 3,500 लाख पौण्ड तक और 1937 में 5,500 लाख पौण्ड तक बढ़ा दी गई। 1938 में कोष को भारी हानि उठानी पड़ी। सन् 1939 में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के सचिव से 2,000 लाख पौण्ड स्वर्ण की वृद्धि करके इसकी स्थिति सुदृढ़ की गई।

(6) कृषि नीति

प्रथम महायुद्ध के बाद ब्रिटिश कृषि क्षेत्र में मन्दी आ गई। कृषि की दशा बिगड़ने लगी। स्थिति को सुधारने के लिए सन् 1923 में लगान में कमी कर दी गई। सन् 1924 में कृषि मजदूरी नियमन अधिनियम (Agricultural Wages Act, 1924) पारित किया गया जिसका उद्देश्य कृषि श्रमिकों का वेतन निश्चित करना था। सन् 1925 से सरकार गन्ना उत्पादन पर भी वित्तीय सहायता देने लगी, लेकिन यह सभी सरकारी कदम कृषि क्षेत्र में विशेष सहायक नहीं हो सके। सन् 1928 में एक दूसरा कृषि साख नियम पास हुआ जिसके द्वारा उचित व्याज पर लम्बी अवधि के लिए ऋण देने की व्यवस्था की गई। कृषि उपज के लिए विपणन (Marketing) को समुचित व्यवस्था के लिए भी अनेक कदम उठाए गए, किन्तु ब्रिटिश कृषि की दशा फिर भी नहीं और सन् 1931 में जो यह विश्व-व्यापी मन्दी के संकट में बुरी तरह फँस गई।

सरकार द्वारा सन् 1931 में कृषि विपणन अधिनियम (Agricultural Marketing Act, 1931) बनाया गया जिसके अनुसार विभिन्न पदार्थों के अन्व-विक्रय, उत्पादन और मूल्य निश्चित करने के लिए विपणन बोर्डों के स्थापित किए जाने की व्यवस्था की गई। कृषि अवस्था को समालने के लिए सन् 1931 से ही सरकार ने स्वतन्त्र व्यापार नीति का परित्याग करके संरक्षण की नीति ग्रहण की।

सरक्षणवादी नीति के अन्तर्गत दो प्रकार के अधिनियम स्वीकार किए गए—
विशिष्ट प्रकार की एवं साधारण कृषि उत्पादन से सम्बन्धित। विशिष्ट अधिनियमों में 1932 का गेहूँ अधिनियम (Wheat Act 1932) उल्लेखनीय है। इसके अनुसार गेहूँ आयाग की नियुक्ति की गई। गेहूँ को सरक्षण देने के लिए आटे पर कर लगाकर रकम प्राप्त की जाने लगी। यह अधिनियम अत्यधिक धालीबना का पात्र बना। साधारण नियमों के अन्तर्गत 1931 का कृषि बाजार अधिनियम उल्लेखनीय है जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। 1931 के इस अधिनियम को 1933 में पुनः संशोधित किया गया।

इन दोनों विपरण अथवा बाजार अधिनियमों (Marketing Acts) ने जो सरक्षण किसानों को प्रदान किया वह 1932 के आयात कर अधिनियम द्वारा पुष्ट किया गया। इस आयात कर अधिनियम द्वारा—(क) आयातों पर प्रतिबन्ध लगाया गया (ख) विदेशों द्वारा ब्रिटिश माल के प्रति भेदभाव करने का समाधान बताया गया, एवं (ग) सरकारी धाय में वृद्धि कर दी गई। इस अधिनियम से किसानों को यद्यपि बहुत अधिक लाभ हुआ तथापि उन्हें कृषि यन्त्र और रासायनिक खाद पर अधिक कर भी देने पड़े।

कृषि पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषकों को सरकार द्वारा धन के रूप में सहायता भी दी जाने लगी। सन 1937 में एक कृषि अधिनियम पारित हुआ जिसके अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त गेहूँ की राशि को 27 मि० क्वार्टर से बढ़ाकर 36 मि० क्वार्टर कर दिया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत जो के उत्पादन को भी एक प्रामाणिक मूल्य की सहायता का आश्वासन दिया गया।

उपरोक्त सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप ब्रिटिश कृषि की दशा में पर्याप्त सुधार हो गए और कृषि पदार्थों के मूल्य कुछ बढ़ गए। बेकार पड़ी जमीन भी पर्याप्त रूप से कृषि के अन्तर्गत आ गई।

(7) औद्योगिक नीति

सरक्षणवादी नीति द्वारा तो उद्योगों को कुछ राहत ही गई, निर्यात-उद्योगों को भी सरकार ने प्रत्यक्ष अनुदान देकर तथा उनके कच्चे माल की पूर्ति की समुचित व्यवस्था करके प्रोत्साहित किया। छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयों के संयोजककरण (Combination) की नीति अपनाई गई। 1927 में फ्रांस जर्मनी, बेल्जियम और लक्जमबर्ग ने एक अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात कार्टेल (International Steel Cartel) की स्थापना करके ब्रिटिश इस्पात उद्योग को सकट में डाल दिया। अतः 1932 में ब्रिटिश लोहा एवं इस्पात उद्योग को संरक्षण देना पड़ा। लोहे के आयात पर कर लगाया गया तथा छोटे-छोटे इस्पात-उत्पादकों को मिलाकर 12 बड़े निगम स्थापित किए गए। इन प्रयत्नों का उद्देश्य इस्पात उद्योगों का पुनर्संगठन करके उसके हितों की रक्षा करना था। लेकिन कोई विशेष सफलता न मिलने पर 1935 में यूरोपीय इस्पात कार्टेल से समझौता करना पड़ा ताकि कठोर प्रतियोगिता से बचाव का रास्ता निकाला जा सके। कोयला उद्योग की दशा सुधारने के लिए 1930 में

एक अधिनियम के अन्तर्गत इसके पुनर्संगठन का मार्ग प्रशस्त किया गया। छोटी-छोटी खानों को मिलाकर बड़े आकार की कोयला कम्पनियाँ स्थापित करने के उद्देश्य से एक विशेष आयोग की भी स्थापना की गई जिसे विरोध के कारण 1935 में अपना काम बन्द कर देना पड़ा। 1937 में द्वितीय कोयला खान अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के आधार पर ही कोयला उद्योग का पुनर्गठन सम्भव हुआ। एक हजार से भी अधिक कोयला उत्पादक इकाइयों को लगभग 159 इकाइयों में संगठित कर दिया गया। कोयला खानों में तकनीकी सुधार लाने के भी प्रयत्न किए गए। वस्त्रों के उत्पादन में ब्रिटेन विशिष्टीकरण प्राप्त करके उत्तम किस्म के वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि के प्रयत्नों में जुट गया जिसके सुपरिणाम भी निकले।

(8) यातायात-नीति

महान आर्थिक मन्दी के दौरान यातायात के सभी साधनों को घाटे और सकट का सामना करना पड़ा। केवल रेलों की आय में ही 1931-32 में लगभग 142 लाख पाउण्ड की कमी हुई। रेल-सड़क प्रतिस्पर्धा के कारण रेलों को नुकसान पहुँचने लगा। अतः 1933 में सड़क एवं रेल ट्रैफिक एक्ट पास किया गया जिससे उचित किराया दर-निर्धारण सम्भव हुआ। एक अन्य कानून द्वारा सड़क-माल-परिवहन के साधनों पर प्रतिबन्ध लगाया गया। फलस्वरूप रेलों और सड़कों के बीच प्रतियोगिता कुछ कम हुई। 1936 में ट्रक-रोड-अधिनियम के अन्तर्गत प्रमुख सड़क मार्गों को सरकारी नियन्त्रण में ले लिया गया। इन सब उपायों से यातायात की स्थिति में सुधार होने लगा। आर्थिक मन्दी के कारण जहाजी कम्पनियों की आय गिर गई और जहाज-निर्माण-उद्योग पर प्रतिफल प्रभाव पड़ने से इसमें लगे मजदूरों की छोटनी की जाने लगी जिससे बेरोजगारी बढ़ी। अतः इस स्थिति को सम्भालने के लिए 1935 में सरकार ने जहाजी कम्पनियों को आर्थिक अनुदान देने की नीति अपनाई।

(9) बेरोजगारी बीमा-योजना

ब्रिटेन में बेरोजगारी के सम्बन्ध में विचार 1873 के बाद मन्दी के समय से ही होता रहा था। पर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम 1911 में उठाया गया जब कि राष्ट्रीय बीमा अधिनियम के अन्तर्गत स्वास्थ्य और बेकारी सम्बन्धी योजनाएँ लागू की गईं। इस बेरोजगारी बीमा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों और नियोजकों को समान रूप से दान देना पड़ता था और राज्य कुल व्यय का $\frac{1}{3}$ भाग वहन करता था। प्रथम महायुद्ध काल में बेकारी घटने से इस योजना को काफी सफलता मिली और बीमा-कोष में अर्थात् धन-राशि जमा हो गई। बेकारी बीमा-योजना के अन्तर्गत धीरे-धीरे विस्तृत कर दिया गया और आश्रित लोगों पर भी इसे लागू किया गया। लाभ की मात्रा भी बढ़ा दी गई।

महान आर्थिक मन्दी के समय इस योजना की प्रगति रुक गई और बेकारी बढ़ने से लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ती गई। फलस्वरूप आर्थिक सहायता ऋण लेकर दी गई। साथ ही अतिरिक्त चन्दे की दरें बढ़ा दी गईं और लाभ की मात्रा घटा दी गई। सन् 1931 में योजना की जाँच के लिए एक शाही आयोग

(Royal Commission) नियुक्त किया गया। इस आयोग की सिफारिशों पर सन् 1934 में इस योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। सहायता देने के लिए एक "बेरोजगार सहायता मण्डल" (Unemployment Assistance Board) संगठित किया गया जिसका आर्थिक दायित्व सरकार पर था। लाभ की कमी को पूरा किया गया और बन्दे की दरें भी घटा कर पहले के समान कर दी गईं। सन् 1936 में इस योजना को कृषि श्रमिकों पर भी लागू कर दिया गया। 1939 में वीमाकृत व्यक्तियों की संख्या बढ़ कर लगभग 140 लाख हो गई। अगले वर्ष बृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन बेकार व्यक्तियों के क्षेत्र तक बढ़ा दी गईं। द्वितीय महायुद्ध काल में बेरोजगारी सहायता मण्डल (Unemployment Assistance Board) का नाम बदल कर 'सहायता मण्डल' कर दिया गया।

आर्थिक मन्दी से उद्धार पाने और पुनरुत्थान की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए ब्रिटेन ने और भी अनेक छोटे-मोटे उपायों का सहारा लिया। देश की भीतरी परिस्थितियाँ भी अनुकूल सिद्ध हुईं। फलस्वरूप ब्रिटेन में धीरे-धीरे मन्दी समाप्त होने लगी।

आर्थिक स्थिरीकरण की नीतियों के प्रभाव

(Effects of the Policies of Economic Stabilization)

ब्रिटिश सरकार ने 1930 की भीषण आर्थिक मन्दी के दुष्प्रभावों को मिटाने के लिए आर्थिक स्थिरता सम्बन्धी जो नीति अपनाई, वे 1935 के बाद अपना वांछित फल दिखाने लगी। ब्रिटेन में आर्थिक पुनरुद्धार के लक्षण प्रकट होने लगे। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1932 में 88 से बढ़कर 1935 में 112, निर्यात के सूचकांक 50 से बढ़कर लगभग 59, रोजगार के सूचकांक 94 से बढ़कर 104, थोक मूल्यों में सूचकांक 72 से बढ़कर 76 और सामान्य लाभ के सूचकांक 65.2 से बढ़कर 81.4 हो गए। 1936 में इन सबके सूचकांक क्रमशः 121, 69, 108, 80, 98.8 हो गए। इन दुने हुए आर्थिक तत्वों के ये सूचकांक अग्रलिखित तालिका से अधिक स्पष्ट हो सकेंगे।

दुने हुए आर्थिक तत्वों के सूचकांक (1928=100)

	1932	1933	1934	1935	1936
औद्योगिक उत्पादन	88	94	115	112	121
रोजगार	94	97	100	104	108
शुद्ध निर्यात	50	51	55	59	69
थोक मूल्य	72	72	75	76	80
सामान्य लाभ	56.2	60.9	68.2	81.4	98.8

इन सूचकांकों से प्रकट है कि ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ। औद्योगिक उत्पादन और रोजगार की स्थिति तो मन्दी-पूर्व के स्तर पर पहुँच गई। निर्यात के क्षेत्र में वांछित वृद्धि नहीं हुई और पहले की अपेक्षा 1936 में

भी निर्यात लगभग 21 प्रतिशत कम रहा। इसी प्रकार थोक मूल्य भी 1928 के मुकाबले लगभग 18 से 20 प्रतिशत कम रहे। सन् 1937 में ब्रिटेन में आर्थिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ गईं। प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ा और गृहों का काफी निर्माण हुआ। बिजली उद्योग भी तेजी से पनपा तथा अनेक नये उद्योगों का विकास हुआ। किन्तु यह सब कुछ होते हुए भी ब्रिटेन की पुनरुत्थान प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई। 1937 में पुन मंदी के लक्षण प्रकट होने लगे। इसके बाद ही द्वितीय महायुद्ध से सम्बन्धित तैयारियाँ की और तब द्वितीय महायुद्ध के विस्फोट ने ब्रिटेन को दबोच लिया।

यद्यपि तीसरे दशक में अपनाई गई आर्थिक नीतियों से ब्रिटेन का पुनरुत्थान पूर्ण नहीं हो सका, फिर भी अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार निश्चित रूप से हुआ। सुधार की स्थिति का अनुमान उपर्युक्त सूचकांकों से लग जाता है, तथापि अधिक भ्रुसासा रूप में इसे हम यों प्रकट कर सकते हैं—

औद्योगिक क्षेत्रों में सुधार—आर्थिक स्थिरीकरण की नीतियों के फलस्वरूप ब्रिटेन की औद्योगिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ। आधारभूत उद्योगों का विकास हुआ और मूल्यों में वृद्धि होने से उत्पादन को प्रोत्साहन मिला। 1928 में उत्पादन-सूचकांक को 100 मानते हुए 1932 में जो सूचकांक केवल 88 रह गया था वह। 1934 में अपने आधार वर्ष को पार कर गया और 1936 में 121 तक जा पहुँचा। इस प्रकार केवल चार वर्षों की अल्प अवधि में ही कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

निर्यात व्यापार का विकास—स्वर्णमान के परित्याग, पौंड-स्टर्लिंग के अवनमन, संरक्षण और साम्राज्यीय अधिमान की नीति अपनाने के फलस्वरूप ब्रिटिश निर्यात में सुधार हुआ। ब्रिटेन राष्ट्र मंडलीय देशों और उपनिवेशों में विदेशी प्रतियोगिता को दूर करने में बहुत कुछ सफल हुआ जिससे ब्रिटेन का व्यापारिक संतुलन उसके पक्ष में होने लगा। 1928 के आधार वर्ष पर 1932 में जहाँ शुद्ध निर्यात का सूचकांक 50 तक पहुँच गया था, वहाँ यह बढ़कर 1934 में 55, 1935 में 59 में और 1936 69 हो गया। यद्यपि मंदी-पूर्व स्थिति की तुलना में निर्यात लगभग 31 प्रतिशत कम था, तो भी मंदी के उपरान्त की गई यह वृद्धि निराशाजनक नहीं थी।

रोजगार की स्थिति में सुधार—मंदी के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए जो कदम उठाए गए उनसे रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हुई। नए उद्योगों के विकसित होने और पुराने उद्योगों के पुनः समृद्ध होने से बेरोजगारों को बड़ी सख्या में काम मिला। फलस्वरूप 1932 में रोजगार का सूचकांक 94 से बढ़कर 1936 में 108 हो गया अर्थात् 1928 के आधार-वर्ष से भी 18 अँचा पहुँच गया। रोजगार की स्थिति में यह सुधार उत्साहजनक था। प्राविधिक सुधारों के कारण श्रम की कुशलता भी बढ़ी। राष्ट्रीय उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से जो सस्ती मुद्रा नीति अपनाई गई, उसका वस्तुतः बड़ा अच्छा परिणाम निकला।

कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन—कृषि क्षेत्र में भी सुधार हुआ तथा कृषि उत्पादन बढ़ा। किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा कृषि उत्पादकों के लिए

न्यूनतम मूल्य की गारंटी दी गई जिसके अन्तर्गत विदेशी आयात के कारण बाजार मूल्य कम होने पर किसानों को थतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गई । इस कदम से ब्रिटिश कृषि-उत्पादन को प्रोत्साहन मिला ।

मूल्य-स्तर में सुधार—आर्थिक नीतियाँ मूल्य स्तर के क्षेत्र में ना सुपरिणाम लाईं । 1928 के आधार-वर्ष पर 1932 में थोक मूल्यों का सूचकांक केवल 72 रह गया था जो सुधारते हुए 1934 में 75, 1935 में 76, और 1936 में 80 पर जा पहुँचा । यद्यपि मूल्य-स्तर पर यह प्रभाव बहुत मद् था, तथापि इससे अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुधार की गति को बल प्रवण्य मिला ।

सामान्य लाभ का ऊँचा होना—आर्थिक मन्दी में व्यापारियों उद्योगपतियों आदि को भारी हानि उठानी पड़ी क्योंकि उत्पादित वस्तुओं के मूल्य बहुत गिर गए । 1928 के आधार वर्ष पर ब्रिटेन में सामान्य लाभ का सूचकांक केवल 65 रह गया । यह स्थिति बहुत चिन्ताजनक थी । 1933 में हालत तब और बिगड़ गई जब यह सूचकांक निम्नतम स्तर 60.9 पर आ गया । सरकार द्वारा मोद्रिक नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप और अन्य अनुकूल परिस्थितियों के प्रभाव-स्वरूप लाभ के सूचकांकों में वृद्धि होने लगी । 1934 में सामान्य लाभ का सूचकांक 68.2, 1935 में 81.4 और 1936 में 98.8 पर पहुँच गया । इस प्रकार सामान्य लाभ का स्तर लगभग वही हो गया जो मन्दी से पहले था ।

अन्य प्रभाव—मन्दी काल में अग्रभाई गई नवीन नीतियों के कुछ और भी अनुकूल प्रभाव पड़े—(1) ब्रिटिश कारखानों के उत्पादन को प्राथमिकता मिलने से उनकी दशा में सुधार हुआ, (2) ब्रिटिश सार्वजनिक क्षेत्र को कुछ मान्यता मिली क्योंकि 1926 के बार्ड केन्द्रीय विद्युत बोर्ड, दी लन्दन ट्रांसपोर्ट बोर्ड और ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का सार्वजनिक क्षेत्र में गठन किया गया, (3) लगभग 30 लाख भवनों और आवास गृहों का निर्माण-कार्य चलाया गया जिससे रोजगार को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, (4) उद्योगों के एकीकरण और संयोगीकरण की नीति से एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ प्रोत्साहित हुईं, (5) राजकीय संरक्षण तथा उचित नियन्त्रण एवं हस्तक्षेप की नीति की उपमोषितों बढ गईं (6) कार्मिकों के जनसंख्या की क्षेत्रीय गतिशीलता बढी, एवं (7) कुछ नवीन उद्योग अस्तित्व में आए, जैसे विद्युत उपकरण, कृषि में रेखा उद्योग, स्टेशनरी-वस्तु उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग आदि ।

आर्थिक मन्दी के दुष्प्रभावों को दूर करने और देश में आर्थिक स्थिरता लाने के लिए सरकार ने जिन विभिन्न नीतियों का आश्रय लिया उनसे ब्रिटेन की अर्थ-व्यवस्था पतन के गड्ढे से ऊपर निकल आई । यदि द्वितीय महायुद्ध की तैयारियों में ब्रिटेन को न फँसना पड़ता और बाद में महायुद्ध के काल में जर्मनी की पराजयकारी वम धरों से हुए भीषण विनाश को न झेलना पड़ता तो ब्रिटेन आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ जाता । दुर्भाग्यवश महायुद्ध के विस्फोट ने ब्रिटेन की अधिक स्थिरकरण की नीतियों के प्रभाव को धूमिल बना दिया ।

4

पूर्ण रोजगार के लिए नियोजन (Planning for Full Employment)

“युद्धोत्तर अवधि में उच्च एवं स्थायी रोजगार-स्तर कायम रखना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य और उत्तरदायित्व है।”

—ब्रिटिश व्हाइट पेपर

बेरोजगार पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का एक बहुत बड़ा अभिशाप है। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था शान्तिकाल में प्रायः सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने में असमर्थ रहती है जबकि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था शान्तिपूर्ण समय में भी सभी लोगों को रोजगार प्रदान कर सकती है। मुख्यतः द्वितीय महायुद्ध के बाद से ब्रिटेन, अमेरिका आदि पूँजीवादी देशों में भी इसलिए आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया जाने लगा है ताकि पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त की जा सके।

पूर्ण रोजगार का अर्थ

प्रश्न उठता है कि पूर्ण रोजगार से वास्तविक आशय क्या है? पूर्ण रोजगार का अभिप्राय उस अवस्था से नहीं होता जिसमें देश के सभी स्वस्थ और क्षमतावान व्यक्तियों को रोजगार मिल जाए। पूर्ण रोजगार का आशय देश में अनर्च्छक बेरोजगारी के अभाव से होता है, क्योंकि स्वेच्छक बेरोजगारी तो कुछ अंश में रहती ही है। प्रत्येक देश में कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वेच्छा या आलस्य के कारण प्रचलित भ्रष्टाचारी की दूरी पर काम करना पसन्द नहीं करते। इसके अतिरिक्त कुछ अंश तक सघर्षात्मक बेरोजगारी (Frictional Unemployment) भी सम्भव है। अर्थ-शास्त्रियों का विचार है कि प्रायः हर एक अर्थ-व्यवस्था में 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक सघर्षात्मक बेरोजगारी अवश्य होती है।

अभिप्राय यह हुआ कि पूर्ण रोजगार का मतलब देशवासियों को शतप्रतिशत रोजगार से नहीं होता। पूर्ण रोजगार की दशा में भी 95 से 97 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्थाओं में पूर्ण रोजगार के लिए आर्थिक नियोजन का उद्देश्य रोजगार के क्षेत्र में इसी लक्ष्य को प्राप्त करना है। पूर्ण रोजगार की दशा प्राप्त करने के लिए देश में प्रभावपूर्ण मार्ग में वृद्धि करना आवश्यक माना गया है। इसके लिए मुख्यतः दो उपायों का आश्रम लिया जाता है— देश के उपभोग को प्रोत्साहित किया जाय तथा देश के निवेश की मात्रा को बढ़ाया जाए।

पूर्ण रोजगार का अर्थ समझने के उपरान्त अब हम ब्रिटेन में पूर्ण रोजगार के लिए जो नियोजन अपनाया गया है उसकी चर्चा करेंगे।

ब्रिटेन में पूर्ण रोजगार के लिए नियोजन (Planning for Full Employment in Britain)

ब्रिटेन में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था है। वहाँ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। द्वितीय महायुद्ध के बाद से ही ब्रिटेन में यह अनुभव किया जाने लगा है कि देश की आर्थिक प्रगति का सही मूल्यांकन करने, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने तथा पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त करने के उद्देश्य से आर्थिक नियोजन का सहारा लेना देश के लिए हितकर होगा। यह अनुभूति विशेषतः ब्रिटेन के आर्थिक दल में हुई, किन्तु अब ब्रिटेन के अधिकांश राजनीतिक क्षेत्रों में इस विचार ने अपनी जड़ जमा ली है।

ब्रिटिश आर्थिक नियोजन का वर्णन करने से पूर्व यह बात ध्यान में रखनी होगी कि ब्रिटेन में आर्थिक नियोजन किन्हीं गम्भीर सिद्धान्तों पर आधारित नहीं है बल्कि युद्धोत्तर आर्थिक कठिनाइयों का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए इसे अपनाया गया है। अभी इसका उपयोग अधिकांशतः श्रमोत्पन्नक ही है। प्रो० लेविट के अनुसार—“विभिन्नता, विरोधाभास, सराय, बठोरता अन्धकार आदि के रूप में यह ब्रिटिश नियोजन अमेरिका के न्यू डील से मेल खाता है। यहाँ समाजवादी रूपरेखा की कोई सुविचारित और सुनिर्मित योजना नहीं है बल्कि यह नियोजन तो एक प्रकार से उच्च-स्तर का प्रजातान्त्रिक तालमेल है।” युद्ध की विपन्न आर्थिक परिस्थितियों ने ही ब्रिटेन में सरकार द्वारा नियन्त्रण और नियमन की नीति को प्रोत्साहित किया है। 70988

इंग्लैण्ड में पूर्ण रोजगार नीति का सूत्रपात और रोजगार नीति पर श्वेत पत्र (1944) की मुख्य विशेषताएँ

यद्यपि अमेरिका के समान ही इंग्लैण्ड में भी तीसरी आर्थिक मन्दी के समय से ही बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए कदम उठाए जाने लगे, लेकिन रोजगार नीति का वास्तविक सूत्रपात द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के लगभग ही हुआ। युद्धोत्तरकालीन मन्दी और गम्भीर बेरोजगारी के खतरे का सामना करने के लिए तत्कालीन संयुक्त सरकार (Coalition Govt) ने 1944 में ही एक रोजगार नीति सम्बन्धी श्वेत पत्र (White Paper on Employment Policy 1944) जारी किया, जिसमें इस बात का संकेत दिया गया कि सरकार सम्भावित बेरोजगारी और मन्दी की समस्या का समाधान करने के लिए तथा दीर्घकालीन रोजगार-स्थायित्व के लिए किन नीतियों और प्रयत्नों का आश्रय लेगी। इस प्रकार वास्तव में रोजगार सम्बन्धी आर्थिक नियोजन की शुरुआत तो इस श्वेत-पत्र से ही हो गई, यद्यपि क्रियान्वयन आगे चलकर हुआ।

रोजगार नीति पर जो श्वेत पत्र 1944 में प्रकाशित किया गया उसमें रोजगार-नीति के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों पर बल दिया गया—

- (1) युद्धोत्तरकालीन बेरोजगारी की समस्या का समाधान,
- (2) उत्पादन तथा उत्पादकता के उच्चस्तर की प्राप्ति के लिए सगठन और साधनों में समन्वयात्मक कुशलता की वृद्धि,
- (3) आर्थिक मन्दी के दुष्प्रभावों से छुटकारा पाने के लिए समाज में व्याप्त आर्थिक विषमताओं को दूर करने की दिशा में प्रयत्न और आर्थिक समानता के मार्ग को प्रशस्त करना,
- (4) राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से आर्थिक एवं राजनीतिक सुदृढता और स्थिरता की समुचित व्यवस्था, एवं
- (5) दार्ढकालीन रोजगार-स्थायित्व तथा आर्थिक स्थायित्व के लिए प्रयत्न करना ताकि कल्याणकारी राज्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

ब्रिटिश सरकार ने रोजगार-नीति के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्वेत पत्र में रोजगार नीति के कुछ मूल तत्त्वों का समावेश किया। ये मूल तत्त्व संक्षेप में इस प्रकार थे—

(1) चूंकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था काफी सीमा तक निर्यात व्यापार पर निर्भर है अतः रोजगार के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए देश की आन्तरिक माँग के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय माँग में वृद्धि का प्रयत्न किया जावे। निर्यात के नये बाजार खोजे जाएँ, विदेशी व्यापार का विकास किया जाए और विभिन्न देशों से सक्रिय आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाए।

(2) रोजगार के उच्च एवं स्थाई स्तर को बनाए रखने के लिए सुदृढ औद्योगिक पृष्ठभूमि का निर्माण किया जाए। इसके लिए उद्योगों का तेजी से विकास किया जाए और उत्पादन में विविधता लाई जाए। उत्पादन को इस रूप में सुधारा जाए कि विदेशी बाजारों में खपत बटे, देश की प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का विकास हो। श्रमिकों की उत्पादकता और कुशलता को बढ़ाया जाए। देश की आन्तरिक माँग में वृद्धि द्वारा रोजगार के स्तर को उठाने का प्रयत्न किया जाए।

(3) उद्योगों और श्रमिकों का सन्तुलित वितरण हो सके—इस दिशा में प्रयास किए जाएँ। इसके लिए श्रमिकों की गतिशीलता में वृद्धि की जाए। उनकी गतिशीलता में बाधक तत्त्वों को दूर किया जाए, श्रमिकों के प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया जाए, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर किया जाए और नये उद्योगों की स्थापना इस रूप में की जाए कि अर्थ व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक संरचना का विविधीकरण हो सके।

(4) रोजगार में उच्च और स्थाई स्तर की सामान्य शर्तों की पूर्ति के प्रयास किए जाएँ। इस दृष्टि से कुल व्यय का उच्च-स्तर कायम रखा जाए, मूल्य और मजदूरी में स्थायित्व लाया जाए, श्रम को अधिकाधिक गतिशील बनाया जाए और इसी प्रकार के अन्य आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

युद्धोत्तरकाल में रोजगार नीति आर्थिक नियोजन की अपनाना

1945 में युद्ध समाप्त होने पर इंग्लैण्ड में भन्दी और बेरोजगारी की समस्याएँ तो पैदा नहीं हुईं यल्कि आशा के विपरीत मुद्रा-स्फीति, मूल्य-वृद्धि और वस्तुओं की असाधारण कमी देश को परेशान करने लगी। इन समस्याओं से अर्थ-व्यवस्था में गम्भीर संकट पैदा हो गया। ऐसे समय ब्रिटन में मजदूर दल की सरकार बनी जिनसे ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था में नियोजन के तत्त्वों को सक्रिय होने का मौका मिला। प्रारम्भ में मजदूर दलीय सरकार ने प्रभावी नियन्त्रणों की नीति अपनाई। लेकिन 1946 तथा 1947 के प्रारम्भ तक उपर्युक्त आर्थिक समस्याओं का प्रयोग बड़ता ही गया।

नियन्त्रणों की नीति का कोई वांछित फल न निकलते देखकर मजदूर दलीय सरकार ने देश की आर्थिक सन्तुष्टि सीमित साधनों के समुचित उपयोग, बाजार तन्त्र पर नियन्त्रण तथा आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया। 1947 में प्रथम आर्थिक सर्वेक्षण (Economic Survey) जारी किया जिसके अनुसार आर्थिक नियोजन का उद्देश्य ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था में पिछित उपायों से सन्तुलन स्थापित करना रखा गया। यह कहा गया कि सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे उपलब्ध साधनों को राष्ट्र के अधिकतम हित के लिए उपयोग में लाया जा सके तथा साधनों व आवश्यकताओं के अन्तराल को पाटा जा सके। यह भी निश्चय किया गया कि साधनों के वितरण को बाजार तन्त्र पर न छोड़कर उनके उपयोग में साम्य लाया जाए। इसके अतिरिक्त नियोजन का उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि, पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थायित्व तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करना था।

सन् 1951 तक मजदूर दलीय सरकार ने पूर्ण आर्थिक नियोजन न अपनाकर आर्थिक नियोजन-पद्धति को ही अपनाया। इस प्रकार ब्रिटिश नियोजन साम्यवादी रस के नियोजन की तरह नहीं बरन् एक प्रकार से मौद्रिक, प्रशासनिक तथा राजकीय नियन्त्रण मात्र था जिसमें कुछ आर्थिक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप बढ गया था। आर्थिक नियोजन के मार्ग पर चलते हुए 1946 व 1947 में कुछ उद्योगों और सेवाओं का राष्ट्रीयकरण भी किया गया। वास्तव में यह कहना उपयुक्त होगा कि ब्रिटन में प्रोत्साहन नियोजन (Planning by Inducement) अपनाया गया। 1945 से 1951 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया तथा मौद्रिक और राजकीय नियन्त्रण की अधिक प्रभावशाली स्थापना की गई। सामाजिक सुरक्षा कानूनों को अधिक प्रोत्साहन दिया गया।

आलोचकों के अनुसार धन-दलीय सरकार द्वारा अपनाया गया यह नियोजन वास्तव में कोई नियोजन न होकर एक दिखावा था। यह नियोजन का एक बहाना मात्र था। जो भी नियन्त्रण स्थापित किया गया वह सीमित और असम्भावित था तथा अल्पकालीन उद्देश्यों से प्रेरित था। सरकारी हस्तक्षेप का रूप और उद्देश्य इस प्रकार का था कि अर्थ-व्यवस्था को वांछित दिशाओं में प्रभावित करने में राज्य निजी व्यक्तियों को प्रोत्साहित कर सके। सर्वे (Survey) एक प्रकार का अनुमान पत्रक था जिसमें

वांछित कठोरता और परिपालन की अनिवार्यता का अभाव था। कोई निश्चित और सुनियोजित नीति नहीं थी और सरकार आंशिक नियोजन के क्षेत्र में भी शिथिल थी। सर्वे कोई ब्ल्यू-प्रिन्ट नहीं था बल्कि सरकार और निजी उद्योगों के भावी विकास का मार्ग-निर्देशक पट्ट मात्र था। इस नियोजन के कार्यक्रम सन्दिग्ध थे जिनमें निश्चयता और दृढ़ता नहीं थी। कुछ भाषाएँ की गई थी जिनकी पूर्ति का ठोस निश्चय नहीं था।

अनुदार दल (1951-64) द्वारा नियोजन के प्रति उपेक्षा

सन् 1951 के चुनावों में श्रमिक दल पराजित हुआ और नवम्बर में अनुदार दल (Conservative Party) ने सत्ता सम्भाली। नई सरकार ने आर्थिक नियोजन को तिलाजलि दे दी। अर्थ-व्यवस्था मन्द गति से आगे बढ़ती रही और आगे चलकर विभिन्न आर्थिक समस्याओं ने सम्पूर्ण ब्रिटिश अर्थतन्त्र को बिगाड़ दिया। भुगतान-सन्तुलन की समस्या बिकट हो गई। औद्योगिक प्रवन्ध में नये दोष घुस गए। श्रमिक-सघों की संरचना दोषपूर्ण होती गई, मूल्य में काफी वृद्धि हो गई और क्षेत्रीय बेरोजगारी की समस्या विषम होती गई। 1963 में इंग्लैंड में लगभग 4½ प्रतिशत से लेकर 7 प्रतिशत तक व्यक्ति बेरोजगारी से पीड़ित हो गए। कुछ स्थानों में तो बेरोजगारी का प्रतिशत सम्भवतः और भी अधिक था।

देश की बिगड़ती हुई आर्थिक परिस्थितियों ने अनुदार दलीय सरकार को चिन्तित कर दिया और अर्थ-व्यवस्था व विभिन्न अङ्गों के विकास के लिए अल्पकालीन विभागीय योजनाएँ बनाई जाने लगीं।

राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद् (National Economic Development Council)—सर्वप्रथम जुलाई, 1961 में सरकारी स्तर पर अर्थ मन्त्री लॉयड ने एक केन्द्रीय नियोजन सगठन बनाने का सुभाष दिया। अतः फरवरी सन् 1962 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद् की स्थापना की गई जिसकी प्रथम बैठक 7 मार्च, 1962 को हुई। स्थापना के समय परिषद् के निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए—

- (i) राष्ट्र के आर्थिक विकास की प्रगति का निरीक्षण करना
- (ii) निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के भावी विकास में बाधक तत्वों पर विचार करना तथा कार्य क्षमता वृद्धि और प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग के लिए सुझाव देना।
- (iii) आर्थिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करना।

राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद् आज भी सक्रिय है। इसमें सरकार के, श्रमिक सघों के, उद्योगपतियों के और राष्ट्रीयकरण किए हुए उद्योगों के प्रतिनिधियों व अर्थ-शास्त्रियों को सदस्यता दी गई है। इस प्रकार वह वास्तव में एक राष्ट्रीय परिषद् है। यह परिषद् समय-समय पर अपनी रिपोर्टें प्रकाशित करती रहती है। जिसके अन्तर्गत ब्रिटेन की विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है। 1963 में इसने एक प्रतिवेदन ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था के 1966 तक के विकास के सम्बन्ध में और दूसरा प्रतिवेदन तीव्र-विकास की अनुकूल दशाओं के सम्बन्ध में प्रकाशित किया था। प्रथम प्रतिवेदन में 17 प्रमुख ब्रिटिश उद्योगों के 1966 तक के लक्ष्य निर्धारित

किए गए थे और यह निश्चय व्यक्त किया गया था कि ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था 4% वार्षिक दर से विकास की ओर अग्रसर हो। द्वितीय प्रतिवेदन में ब्रिटेन की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन तथा सुधार के सुझावों का उल्लेख था।

पुन श्रमिक सरकार (1964) और आर्थिक नियोजन

लगभग 13 वर्षों के बाद अक्टूबर, 1964 में ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार पुन बनी। मजदूर दलीय सरकार ने पुन आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई और 1964-65 से 1969-70 तक की ब्रिटेन की प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया गया। मजदूर सरकार ने सत्ताह्व होने के 15 दिन बाद ही आयात को हतोत्साहित करने की दृष्टि से 15% का अतिरिक्त कर लगा दिया। इसके प्रत्यक्ष निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जाने लगे। दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था की गई तथा विदेशी बाजारों के अनुसन्धान के लिए एव व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डलों को भेजने के लिए वित्तीय सहायता का प्रबन्ध किया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना से अब तक रोजगार व्यवस्था

मजदूर सरकार के अखीन राष्ट्रीय विकास परिषद् ने ब्रिटेन की प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार की जिसे सरकार द्वारा 16 सितम्बर, 1965 को श्वेत-पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया। इसमें राष्ट्रीय योजना के विभिन्न कार्यक्रमों, उद्देश्यों आदि का उल्लेख किया गया। यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि भावी पांच वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि की जाएगी तथा प्रति व्यक्ति आय में वार्षिक वृद्धि की दर 30% होगी। योजना का प्रमुख लक्ष्य पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त करना था। अतः यह प्रावधान किया गया कि योजना की समाप्ति तक देश में बेरोजगारी की समस्या का पूरी तरह समाधान कर दिया जाएगा। इससे भी आगे बढ़कर यह आशंका व्यक्त की गई कि योजना के अन्त तक सम्भवतः दो लाख कुशल श्रमिकों की कमी पड़ जाएगी।

यह अनुमान लगाया गया कि योजना के आर्थिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण योजना काल में लगभग 8 लाख श्रमिकों की माँग होगी जिसमें से 4 लाख श्रमिक तो जनसङ्ख्या की सामान्य वृद्धि में उपलब्ध हो जाएँगे, 2 लाख बेरोजगारों को काम देना होगा और शेष दो लाख की पूर्ति उत्पादकता में वृद्धि करके की जाएगी।

ब्रिटेन की प्रथम पंचवर्षीय योजना यद्यपि काफी सफल रही और बेरोजगारी औसत रूप में कुल कार्यशील जनसङ्ख्या के 2-3 प्रतिशत भाग से भी कम हो गई, तथापि ब्रिटेन आर्थिक संकटों में युक्त नहीं हो सका। मुद्रा स्फीति, भुगतान-असन्तुलन, औद्योगिक क्षेत्रों के पूर्ण आधुनिकीकरण आदि की समस्याएँ ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था की गतिशीलता में बाधक बने रहे।

प्रश्नावली

(University Questions)

अध्याय 1

1 "इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति ने इसके आर्थिक जीवन के हर पहलू को दूर तक प्रभावित किया।" समीक्षा कीजिए। (1978)

'The Industrial Revolution in England had far reaching effects on every aspect of her economic life. Discuss

✓ औद्योगिक क्रान्ति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बताइए कि यह क्रान्ति सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में ही क्या हुई? 1980 (1977)

Describe the main features of Industrial Revolution and discuss why did it occur first in England

3 19वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड की औद्योगिक और व्यापारिक सर्वोच्चता के क्या कारण थे? (1978)

What were the reasons responsible for the industrial and commercial supremacy of Great Britain during 19th century?

4 "औद्योगिक क्रान्ति शब्द का उपयोग इसलिए नहीं किया जाता कि इन परिवर्तनों की प्रक्रिया तीव्र थी, अपितु इसलिए किया जाता है कि यह परिवर्तन सम्पन्न होने के बाद मौलिक थे।' समझाइए और क्रान्ति के कारणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। (1977)

"The term Industrial Revolution is used, not because the process of change was quick, but because when accomplished, the change was fundamental." Explain and briefly discuss the causes of Industrial Revolution

5 इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति सर्व प्रथम क्या हुई? इससे वहाँ की जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुए? (1978)

Why did Industrial Revolution first take place in England? Describe the changes in the social and economic life of Great Britain which took place as a result of this

6 "ग्रेट ब्रिटेन में उद्योग क्रान्ति ने आर्थिक समृद्धि तथा व्यापारिक वृद्धि का द्वार खोला और आर्थिक क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात किया।' इस कथन को स्पष्ट करते हुए उद्योग क्रान्ति के आर्थिक एवं राजनैतिक प्रभावों का विवचन कीजिए। (1977)

"Industrial Revolution in U.K. opened the flood gates of economic prosperity and commercial development and inaugurated a new age in the economic field." Explaining the statement discuss the economic and political effects of Industrial Revolution

- 7 ग्रेट ब्रिटेन में हुई उद्योग क्रांति के कारणों का विवेचन कीजिए और बताइए कि यह क्रांति ग्रेट ब्रिटेन में ही पहले क्यों हुई ? (1977)
 Discuss the Causes of Industrial evolution in UK and show why did this revolution came about in UK first

अध्याय 2

- 8 ग्रेट ब्रिटेन की उपनिवेशीय विस्तार नीति के उद्देश्यों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (1978)
 Critically discuss the objectives of the policy of Colonial expansion of Great Britain
- 9 इंग्लैंड में उपनिवेशीय विस्तार की मुख्य विशेषताओं तथा उनके ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था पर प्रभावों का परीक्षण कीजिए। (1978)
 Examine the main characteristics of Colonial expansion by England and its effect on British economy
- 10 ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति में किस प्रकार से ब्रिटिश आर्थिक हितों के अनुरूप परिवर्तन हुए ? (1977)
 How the Colonial Policy of Britain underwent changes to suit the British economic interest ?
- 11 ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आर्थिक पहलू क्या थे ? विवेचना कीजिए। (1977)
 What were the economic aspects of British Colonialism ? Explain
- 12 आंग्ल औपनिवेशीय विस्तार के कारणों का परीक्षण कीजिए एवं औपनिवेशिक नीति पर अपने विचार प्रकट कीजिए। (1978)
 Examine the causes of colonial expansion and give your view regarding the British Colonial Policy
- 13 ग्रेट ब्रिटेन के औपनिवेशिक विस्तार के आर्थिक पहलुओं का उल्लेख कीजिए। उपनिवेशों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का विवेचन कीजिए। (1977)
 Explain the economic aspect of the Colonial expansion of UK and discuss its bad effects on Colonies
- 14 औपनिवेशिक नीति के कारणों को बताकर उसके दोषों (आलोचनाओं) विवेचन कीजिए तथा आधुनिक आर्थिक साम्राज्यवाद का स्वरूप बताइए। (1977)
 Explain the causes of Colonial policy and discuss the demerits of this policy Also throw light on the forms of Modern Economic Imperialism

अध्याय 3

- 15 सन् 1930 की महान् मन्दी के दौरान ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को जिन कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनकी समीक्षा कीजिए। (1978)

Discuss the main difficulties of the British economy had to face during the Great Depression of 1930s

- 16 ग्रेट ब्रिटेन में 1930 की महान मन्दी के समय आर्थिक स्थिरीकरण के लिए अपनाई गई नीतियों का विश्लेषण करते हुए उनके प्रभावों का विवेचन कीजिए। (1977)

Analysing the policies adopted for the economic stability in U K during Great Depression of 1930s, discuss their effects

- 17 इंग्लैण्ड द्वारा महान मन्दी काल में अपनाई गई आर्थिक नीति का मूल्यांकन कीजिए। यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहीं तक सफल रही? (1978)

Evaluate the economic policy adopted by England during the Great Depression How far was it successful in its objectives?

- 18 तीसरी विश्वव्यापी मन्दी का मुकाबला करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या ये नीतियाँ अपने उद्देश्यों में सफल रही? (1977)

Describe in brief the steps taken by British Government to counter the effects of the world wide Economic Depression of thirties Did the policies succeed in their object?

अध्याय 4

ग्रेट ब्रिटेन में पूर्ण रोजगार के लिए नियोजन नीति के उद्देश्य एवं मूल तत्वों को बताकर इस नीति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। (1977)

Critically examine the objects and main features of Planning for full employment in U K

- 20 ब्रिटेन में पूर्ण रोजगार नीति अपनाने के लिए क्या प्रयास किए गए। (1978)
What efforts were made for adopting full employment policy in England?

- 21 द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् इंग्लैण्ड की पूर्ण रोजगार की नीति की विवेचना कीजिए। (1977)

Discuss critically the full employment policy of England after the Second World War

जापान के आर्थिक विकास में सीमा-चिन्ह

(Landmarks in Economic
Development of Japan)

- 1 मेजीपुनर्संस्थापन के दौरान जापानी अर्थ-व्यवस्था
(Development of the Japanese Economy during the Meiji Restoration)
- 2 कृषि विकास
(Agricultural Development)
- 3 मुख्य आधुनिक उद्योगों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
(A few important facts about Principal Modern Industries)
- 4 लघु-स्तरीय उद्योगों की भूमिका
(Role of Small Scale Industries)
- 5 जापान के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ
(Salient Features of Japanese Foreign Trade)
- 6 आर्थिक विकास में राज्य का योगदान
(Role of State in Economic Development)
- 7 द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में आर्थिक विस्तार के कारक
(Factors causing Post-World War II Economic Expansion)

“द्वितीय महायुद्ध के दौरान और बाद में अमेरिकन सैनिक प्रशासन के अन्तर्गत कुचल कर रख दिया गया जापान आज अमेरिका और सोवियत संघ के बाद बड़ी ताकतों में नाम लिखाने का हकदार बन चुका है। यह आशा की जाती है कि 1980 तक वह रूस व अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सम्पन्न देश बन जायेगा। 10 करोड़ की आबादी का टापुभू पर बसा यह देश दुनिया के आधे तेलवाहक जहाज बनाता है, ब्रिटेन से प्रति-व्यक्ति ज्यादा इस्पात तैयार करता है और समरणको के उपयोग में यह केवल अमेरिका के पीछे है।”

—डॉ एम एल शर्मा

मेजी पुनर्संस्थापन के दौरान जापानी अर्थ-व्यवस्था का विकास

(Development of the Japanese Economy
During the Meiji Restoration)

“मेजी-काल (1867-1912) विश्व-इतिहास के सबसे उल्लेखनीय युगों में से है। सम्राट मेजी के शासन काल में देश ने कुछ ही दशकों में वह सब-कुछ पाने का प्रयत्न किया जिसे पाने में पश्चिम को सदियों लगी थी।”

—सार्वजनिक सूचना ब्यूरो, जापान

जापान प्रशान्त सागर में स्थित एक द्वीप-समूह है जिसमें चार प्रमुख द्वीप होकेडो, होशू, शिकोकू तथा क्यूशू और लगभग तीन हजार छोटे द्वीप सम्मिलित हैं। इन सबकी कुल लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1,400 मील है। जापान का वर्तमान क्षेत्रफल लगभग 1,35,000 वर्ग मील है और यहाँ की जनसंख्या अनुमानतः 10 करोड़ है। पर्वतीय प्रदेश होने के कारण यहाँ कृषि योग्य भूमि कम है, लेकिन व्यापक वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग से कृषि को इतना उन्नत बना दिया गया है कि प्रति एकड़ पंचावार की दृष्टि से जापान का स्थान विश्व में अग्रणीय है। जल-शक्ति ने जापान को औद्योगिक विकास में महान् सहायता दी है। खनिज पदार्थों और प्राकृतिक साधनों का यहाँ अभाव-सा है। व्यापारिक मार्गों की दृष्टि से यह देश महत्वपूर्ण केन्द्र है। इसके बन्दरगाह सर्वत्र खुले रहते हैं। ज्वालामुखियों का तो यह घर ही है। वर्ष में लगभग 500 ज्वालामुखी और 1500 भूकम्प जापानी जीवन को अस्थिर बनाए रखते हैं। जापान की वर्तमान शासन पद्धति ससदीय है, लेकिन औपचारिक रूप से सम्राट की सत्ता भी है।

राजनीतिक, प्राथिक क्रांति की दृष्टि से जापान का अध्ययन मेजी पुनर्संस्थापन (The Meiji Restoration) के समय से महत्वपूर्ण है। इसके पूर्व जापान में लगभग 1600 से 1867 तक तोकुगावा घराने का शासन था। 1868 में, विभिन्न कारणोंवश, तोकुगावा घराने के विरुद्ध विद्रोह हुआ और उसे समाप्त करके पुनः

सम्राट को जापान के राज्य सिंहासन पर पदारूढ किया गया। जापान के इतिहास में यह एक महानतम घटना थी क्योंकि लगभग 800 वर्षों के बाद जापान में पुन-सम्राट के हाथों में वास्तविक सत्ता आई थी। मेजी पुनर्संस्थापन के समय से ही जापान में सामाजिक, आर्थिक, वैधानिक सभी क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए और सदियों से एकत्र शक्ति का प्रवाह खुल गया। तभी से जापान कभी धीरे और कभी तेजी से प्रगति की दिशा में छलांगें भरता हुआ आज दुनिया का तीसरा सम्पन्न देश बनने के निकट है।

मेजी पुनर्संस्थापन

(The Meiji Restoration)

सन् 1868 में मेजी पुनर्संस्थापन ने जापान की सोई हुई शक्तियों को जगा दिया। केन्द्रीय शासन का नियन्त्रण प्रत्यक्ष रूप से सम्राट के हाथों में आ गया। तोकुगावा शासन की समाप्ति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उठने वाले छोटे-मोटे विद्रोहों को 1877 तक समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार जापान की राजनीतिक क्रान्ति वस्तुतः 1877 में पूर्ण हुई और अब जापानी प्रगति के द्वार खुल गए।

सम्राट मेजी और उसका शासन प्रगतिशील था। नये शासन के नेतृत्व में जापान की आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था की नींव पड़ी। प्रो. जी. सी. एलन के अनुसार, "नये शासन को यह पता लग गया कि जापान की सैनिक कमजोरी और उसका आर्थिक पिछड़ापन उसे पश्चिमी शक्तियों के लिए सहज ही लूट का सामान बना सकते हैं, अतः उसने निर्णय लिया कि युद्ध और उद्योग में पश्चिमी प्रणालियों को शीघ्रता से अपनाया जाना ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे जापान अपनी स्वतन्त्रता बनाए रख सकता है।" कहने का आशय यह हुआ कि मेजी पुनर्संस्थापन के बाद जापानी नेताओं ने पश्चिमी प्रणालियों को अपनाते हुए (क) सैनिक शक्ति में वृद्धि, तथा (ख) तीव्र आर्थिक विकास का निश्चय किया। जापानियों ने 'समृद्ध राष्ट्र, सुदृढ़ सेना' (Rich Nation, Strong Army) का नारा बुलन्द कर दिया।

मेजी पुनर्संस्थापन काल में जापानी अर्थ-व्यवस्था ने जो बहुमुखी विकास किया, उसका अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों में करना उपयुक्त होगा—

- (1) आर्थिक परिवर्तन और प्रगति, तथा
- (2) वित्तीय परिवर्तन व प्रगति

आर्थिक परिवर्तन व प्रगति

(Economic Changes and Development)

तोकुगावा शासन की समाप्ति के बाद यद्यपि सत्ता सम्राट के हाथों में आ गई, तथापि राजनीतिक सघर्षों का अन्त नहीं हुआ। 1870 में जाकर नये शासन का विरोध अन्तिम रूप से शान्त किया जा सका। 1874 में और फिर 1877 में जो विद्रोह हुए, जिसे एलन के अनुसार, "दम तीडती हुई सामन्तशाही की अन्तिम लड़ाई थी" इन विद्रोहों को दबा दिये जाने पर 1868 की राजनीतिक क्रान्ति पूर्ण हो गई।

राजनीतिक सवर्षों के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार की प्रशासनिक क्षमता और उसके वित्तीय ससाधनों पर काफी वीरता पडा। नई आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई। पर इन सब परिस्थितियों के बावजूद नये शासन ने आर्थिक व वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हाँसिल की और देश को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। उदार और महत्वाकांक्षी सम्राट मेजी ने 1868 से 1911 तक शासन किया और इस अवधि में जापान के आर्थिक जीवन व इतिहास में एक नया अध्याय खोल दिया। लगभग 44-45 वर्षों की यह अवधि जापान के लिए 'विन्दोरिया युग' था। इस समय जापानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुर्ननिर्माण और सुधारों का प्रकाश फैला। आर्थिक क्षेत्र न जो प्रगति हुई और जो परिवर्तन किए गए, वे इस प्रकार थे—

1. सामन्तशाही की समाप्ति

नए शासन ने 1869 में सामन्त-शाही प्रथा को समाप्त कर दिया। इस प्रथा ने 'तोकुगावा' शासन-काय' ने जापान के आर्थिक विकास को एकदम अवरुद्ध कर दिया था। नयी सरकार ने सामन्तशाही के प्रति कोई रियायत नहीं बरती। सरदारों ने अपने अधिकार सरकार के हाथ यह कहते हुए सुपुर्द कर दिए कि "सारी भूमि सम्राट की है, अतः सम्पूर्ण अधिकारों को लौटाते हैं।" बिना किसी रक्तपात के शान्तिपूर्ण ढंग से सामन्तशाही की यह समाप्ति बहुत ही आश्चर्यजनक और प्रशंसनीय थी। नई सरकार ने सामन्तों को उदारतापूर्वक पेशान देने की व्यवस्था की। सन् 1871 में हान (Han) की जगह मांडलिको (Prefectures) की स्थापना की गई। एसन के शब्दों में, "सामन्तशाही से सम्बद्ध प्राचीन वित्तीय तथा शासकीय प्रणाली का लोप हो गया।" सन् 1878 में मांडलिको (Prefectures) के लिए असेम्बली की व्यवस्था की गई। अक्टूबर 1881 में यह प्रशासकीय घोषणा निकाली गई कि 1890 से राष्ट्र के लिए एक प्रतिनिधि एसेम्बली की स्थापना की जाएगी।

सामन्तशाही प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप भूमि की नई व्यवस्था हुई। इस नई व्यवस्था में खेत जोतने वाले किसान भूमि के स्वामी हो गए और किसानों को फसल बोने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई। यह स्वतन्त्रता उन्हें पहले नहीं थी।

2. आवागमन, व्यापार व उद्योग एवं कृषि की स्वतन्त्रता

मेजी युग में अनेक प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गईं जिनसे आर्थिक विकास का दातावरण बना। आवागमन और व्यापार व उद्योग की स्वतन्त्रता पर लगाए गए अधिकांश प्रतिबन्ध समाप्त कर दिए गए। पहले व्यापार व उद्योग के द्वार केवल गिल्डों (Guilds) के सदस्यों के लिए ही खुले थे और यह सदस्यता कुछ ही विदेशी सुविधा प्राप्त लोगों को उपलब्ध थी, लेकिन मेजी पुनर्संस्थापना से इस प्रकार का पक्षपात दूर हो गया। अतः प्रत्येक वर्ग के सदस्य व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में बढन बढ़ा सकते थे। 1869 में कानूनी रूप से विभिन्न सामाजिक वर्गों की समानता घोषित कर दी गई और लोगों को किसी भी व्यापार में प्रवेश

करने की छूट दे दी गई। सत्तार की स्थानीय श्रद्धाओं समाप्त कर दी गई। कृषि क्षेत्र में भी फसले काटने तथा बोनो की स्वतन्त्रता दे दी गई और जैसा कि कहा जा चुका है, व्यक्तियों को भूमि के स्वामित्व-विषयक अधिकार प्राप्त करने की इजाजत दे दी गई।

3. विदेशी व्यापार व औद्योगिक उपक्रमों को प्रोत्साहन

मेजी शासन में विदेशी व्यापार पर से सभी प्रकार के प्रतिबन्धों को समाप्त कर दिया गया। सरकार ने विदेशी व्यापार के क्षेत्र में विशेष रुचि लेना शुरू कर दिया तथा जापान ने पश्चिमीकरण का मार्ग अपनाया। पश्चिमीकरण के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए व्यापारी जहाजों, युद्ध-पोतों, मशीनों आदि उपकरणों का आयात जरूरी हो गया जिनके बढ़ते में जापान को विदेशी मुद्रा में बड़े-बड़े भुगतान करने पड़े। इस विदेशी भुगतान की समस्या को सुलझाने के लिए मेजी शासन ने निर्यात को हर प्रकार से प्रोत्साहित किया। कई बार स्वयं सरकार ने देशवासियों से चावल, चाय, रेशम आदि खरीद कर विदेशों में इन वस्तुओं को स्वयं ने बेचा। विदेशी व्यापार को अपने अनुकूल बनाने के लिए अनावश्यक वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित किया गया। इसके अतिरिक्त सीमेंट, ग्लास व अन्य प्रकार के कारखानों की स्थापना के लिए राज्य ने सक्रिय कदम उठाये। सरकार की आशा थी कि वह ये कारखाने खोलकर देश में बनाये गए माल के सभरण से आयात बन्द कर सकेगी।

उपर्युक्त विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप, जापान के विदेशी व्यापार में आशातीत वृद्धि होती गई और 75 वर्षों के अल्प समय में ही जापान ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रमुखता प्राप्त कर ली। 1880 से 1913 के मध्य जापान के विदेशी व्यापार में लगभग आठ गुनी वृद्धि हुई। इसके पूर्व 1868 में विदेशी व्यापार लगभग 260 लाख येन (चाँदी का तत्कालीन जापानी सिक्का) का होता था जो 1873 तक बढ़कर लगभग 500 लाख येन और 1881 तक 620 लाख येन का हो गया किन्तु इस वृद्धि के बावजूद भी विदेशी व्यापार में 1868 से 1881 के बीच जापान को लगभग 790 लाख का घाटा उठाना पड़ा क्योंकि देश के पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में उसे आयातित मशीनों आदि के लिए और विदेशी व्यापारियों व बैंकों की वित्तीय सेवाओं के लिए काफी बड़ी रकमें विदेश भेजनी पड़ी। 1881 के बाद यह असंतुलन कम होता गया। 19वीं शताब्दी के अन्त तक आयात और निर्यात कुल राष्ट्रीय उपज का लगभग 10 प्रतिशत भाग हो गया और आगे चलकर दोनों महायुद्धों की बीच की अवधि में यह कुल राष्ट्रीय उपज के 15 से 20 प्रतिशत के बीच रहने लगा। यदि डॉलरों में नापें तो 1910 में जापान का कुल निर्यात 2,230 लाख डॉलर का हुआ जबकि 1870 में 75 लाख डॉलर से भी कुछ कम था। 1920 में यह निर्यात बढ़कर 9,450 लाख डॉलर तक जा पहुँचा। 1900 से 1913 के बीच सूती वस्त्र और रेशम उद्योग के विकास के

कारण इनके निर्माता में बहुत अधिक वृद्धि हुई। दूसरी ओर निमित्त वस्तुओं के आयात में काफी घटी आ गई।

4 पाश्चात्य आर्थिक प्रणालियों को प्रोत्साहन

मेजी सरकार ने जापान के आर्थिक विकास के लिए पश्चिमी व्यापार की प्रणालियों और तकनीकी के विकास को प्रोत्साहन दिया। तोकुगावा शासन-काल से ही खनिज-कर्म और उत्पादन के पाश्चात्य तरीकों को सिखाने के लिए विदेशी विशेषज्ञ रखे जाने लगे थे। मेजी शासन ने अपने प्रारम्भिक वर्षों में इस नीति का और अधिक विस्तार किया। सन् 1875 में केन्द्रीय व मांडलिक सरकारों के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक थी। एलन के अनुसार, "इस समय 527 विदेशी इन सरकारों के अधीन काम कर रहे थे। इनमें 205 तकनीकी सलाहकार, 144 शिक्षक, 69 प्रबन्धक और प्रशासक तथा 36 कुशल कारीगर थे।"

मेजी शासन ने तकनीकी प्रशिक्षण के विकास के लिए केवल विशेषज्ञों की सेवाएँ ही प्राप्त नहीं की बल्कि जापानियों को प्रेरित किया कि वे विदेश जाकर पाश्चात्य ज्ञान अर्जित करें और स्वदेश लौटकर उस ज्ञान का उपयोग अपने देश के विकास में करें। राज्य द्वारा बड़ पैमाने पर स्कूलों, कॉलेजों और महाविद्यालयों की स्थापना की गई। इसमें इंजीनियरिंग, मार्निंग व कृषि विद्यालयों को प्रधानता दी गई। देश के आर्थिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा को इतना प्रोत्साहित किया गया कि 19वीं शताब्दी के अन्त तक इस दिशा में जापान लगभग आत्मनिर्भर हो गया। 1869 में सरकार द्वारा विदेशी व्यापार को देखरेख और प्रेरणा के लिए एक वाणिज्यिक ब्यूरो भी स्थापित किया और इसके द्वारा कलात्मक उत्पादनों के निर्यात का विकास करने के लिए एक संगठन की भी नींव डाली गई। सन् 1877 में इस ब्यूरो द्वारा टोकियो में एक औद्योगिक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई जिसमें नवीन तकनीकी, मशीनरियों आदि का प्रदर्शन किया गया।

पाश्चात्य आर्थिक प्रणालियों को प्रोत्साहन देने की नीति का फलस्वरूप जापान शीघ्र ही इस अवस्था में पहुँच गया कि वह व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में पश्चिमी देशों से प्रतिस्पर्धा ले सके।

5 राज्य द्वारा औद्योगीकरण में सहयोग और देश की औद्योगिक प्रगति

मेजी सरकार ने देश के औद्योगीकरण में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। सरकारी प्रयत्नों से जापान में पूँजीवादी विकास के लिए आवश्यक राजनीतिक और आर्थिक वातावरण पैदा हो गया तथा औद्योगीकरण की मजबूत आधारशिला रखी गई। मेजी शासन काल के प्रारम्भिक 15-20 वर्षों में तेजी से जापानी औद्योगीकरण की पृष्ठभूमि के निर्माण का कार्य किया जिसके फलस्वरूप आगामी 75 वर्षों में जापान अत्यन्त विकसित और उन्नत श्रेणी का औद्योगिक राष्ट्र बन गया जो प्रायः सभी औद्योगिक वस्तुओं का निर्माण करने लगा।

सरकार ने सबसे पहले राज्य में शोगुन-शासन तथा दायमियों द्वारा प्रारम्भ किए गए बहुत से कारखानों की व्यवस्था स्वयं अपने हाथ में ले ली और उनका

आधुनिक तरीके से पुनर्गठन किया। राज्य ने और भी अनेक वस्तुओं के निर्माण के लिए आधुनिक ढंग के नए-नए कारखानों की स्थापना की। आठवें दशक में राज्य ने आइची तथा हिरोशिमा के मण्डलों में पाश्चात्य ढंग की कताई की सूती मिलें खोली। गैर सरकारी उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य द्वारा कताई की विदेशी मशीनों का आयात किया गया और उन्हें आसान किशतों पर उद्यम-कर्ताओं को बेच दिया गया। 1870 में मेबाशी (Maebashi) और टोमिको (Tomiko) में फ्रांसीसी और इटालियन नमूनों पर रेशम के कारखाने खोले गए। आठवें दशक में, पश्चिमी तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य नमूनों के विभिन्न कारखाने खोले गए जिनमें शिराकावा ह्याइट टाइल वर्क्स, दि फुकुगावा सीमेंट वर्क्स, सेनजा बुलन वेव फैक्ट्री और सोडियम सल्फेट तथा ब्लीचिंग पाउडर के कारखाने उल्लेखनीय थे। कुछ विशेष कारखाने खास क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से खोले गए थे, उदाहरणार्थ, होकेडो के विकास आयोग ने सप्पोरो (Sapporo) में किण्वासवन और चीनी के कारखाने इसी उद्देश्य से खोले थे।

राज्य द्वारा अस्त्र-शस्त्र के निर्माण के लिए भी कारखानों की स्थापना की गई। सर्वप्रथम शोगुन शासन के अधीन आने वाले अस्त्र शस्त्र सम्बन्धी कारखानों को लेकर उनका विकास किया गया। डायमियो के लिए हथियार बनाने वाले कारखानों पर भी कब्जा कर लिया गया और उनमें नए सिरे से उपकरण लगवाए गए। नागासाकी का लोहा ढलाईघर (Nagasaki Iron Foundries) नई सरकार तोपखाने का प्रथम निर्माण केन्द्र बना। कोगोशिमा का पोत-निर्माण याड (Kogoshima Ship-building Yard) युद्धपोतों के निर्माण के अनुकूल बना गया। सेना को वर्दी का कपड़ा देने के लिए सरकार ने 1876 में एक ऊनी मिल स्थापित की। 1879 में एक इंजीनियरिंग कारखाना खोला गया। विभिन्न पुराने कारखानों को लेकर राज्य द्वारा उनका पुनर्गठन किया गया।

राज्य ने यह भी घोषणा की कि सारी खनिज सम्पत्ति सरकार की है जिसके हनन का अधिकार उन लोगों को पट्टे पर दिया जा सकेगा जो उनकी खुदाई करने से के इच्छुक हों। श्री जी सी एलन के अनुसार, "सातवें दशक के उत्तरार्द्ध और आठवें दशक के पूर्वार्द्ध में सरकार आदर्श उपकरणों के रूप में ५ बड़ी-बड़ी खानी (सोना, चाँदी, ताँबा, लौह अयस्क एवं कोयला) को चला रही थी।"

सरकार ने व्यापारिक जहाजों के विकास की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया। सन् 1874 में राज्य द्वारा विदेशों से सामुद्रिक जहाज खरीदे गए जिन्हें बाद में मित्रसुबिशी फर्म को सौंप दिया गया। यह फर्म सरकार की सहायता से नौ-बहन का संचालन किया करती थी। जहाजों को चलाने और नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी कप्तान रखे गए। एलन के अनुसार, "सच तो यह है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के दशकों में पश्चिमी ढंग का ऐसा एक भी महत्वपूर्ण जापानी जहाज नहीं था जिसकी स्थापना का श्रेय राज्य को न हो।" सन् 1880 में दिए गए एक विवरण के अनुसार उस वर्ष तक राज्य द्वारा स्थापित कारखानों और

सम्पत्ति में तीन जहाज निर्माता के कारखाने, 51 व्यापारिक जहाज, 5 अस्त्र-शस्त्र निर्माण के कारखाने, 52 अन्य कारखाने, 10 स्नान, 79 भील रेलवे लाइन और सभी प्रमुख नगरों को मिलाने वाली एक टेलीग्राफ व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, सरकार विभिन्न पोत-निर्माण यार्डों को महापता दे रही थी और टाक नौ-बहन सेवा को भी उससे अर्थ-सहायता मिल रही थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नए शासन ने इन सब कार्यों को उस समय किया था जब उसके सामने विपन्न वित्तीय कठिनाइयाँ थी और उसे राजनीतिक दबावों व विद्रोहों का सामना करना पड़ रहा था।

सन् 1882 के बाद सरकार ने अपनी नीति को एक मोड़ दिया। उसने अब व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में स्वयं कार्य करने की नीति का परिष्कार कर दिया और सरकारी औद्योगिक संस्थाओं को निजी उद्योगपतियों के हाथ वजी रियायती व सुविधाजनक दरों पर बेचना शुरू कर दिया। सरकार को इस नीति को "पुनः निजीकरण की नीति" (Policy of Re-privatisation) कहा जाता है। सरकार के इस नीति-परिवर्तन के लिए मुख्यतः निम्नलिखित कारण उत्तरदाई थे—

(i) सरकार ने अब तक जो उद्योग स्थापित किए थे, वे सुदृढ़ता प्राप्त कर चुके थे। वे अब इस स्थिति में आ चुके थे कि निजी उद्यमकर्ताओं द्वारा उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक चलाया जा सकता था।

(ii) विभिन्न सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप निजी उपक्रम भी काफी विकसित हो चुके थे। अतः यह आवश्यक हो गया था कि इनके विनियोग के लिए नई सुविधाओं की व्यवस्था की जाए।

(iii) राज्य जिन उद्योगों का संचालन कर रहा था, उनसे लाभ बहुत ही कम हो रहा था। यह एक माना हुआ तथ्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निजी क्षेत्र के उपक्रम अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। अतः सरकार ने यह उचित समझा कि सरकारी उद्योग व्यवस्थित रूप से निजी उद्यमकर्ताओं को अनुकूल गतों व दरों पर हस्तांतरित कर दिए जाएँ।

उपरोक्त सभी कारणों का यह सम्मिलित परिणाम हुआ कि राज्य ने स्वयं को व्यापार व उद्योग के क्षेत्र से हटाना और निजी उद्योगियों को अधिकधिक भाग देना शुरू कर दिया। पर साथ ही देश के समुचित आर्थिक विकास की दृष्टि से सरकार ने औद्योगिक विकास के संचालन में अपना महत्वपूर्ण हाथ भी बनाए रखा।

सन् 1890 के उपरान्त औद्योगिक क्षेत्र में जापान बहुत ही तेजी से भागे बटने लगा। इस समय तक देश में पारंपारिक तकनीक विकसित हो चुकी थी और व्यापार व यन्त्रों का प्रचुर उपयोग होने लगा था। बैंकिंग गृहों का विकास हो चला था उत्पादित व निर्यात वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से मुनाफा अधिक होने लगा था और विश्व सृष्टि की ओर बढ़ रहा था। इन सब अनुकूल परिस्थितियों में यह स्वाभाविक

था कि मेहनतकश और निपुण जापानी जनता द्रुत गति से व्यापारिक व औद्योगिक प्रगति करती ।

सन् 1894-95 में जापान और चीन के बीच युद्ध में जापान की विजय से भी इसके औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्र का विकास हुआ । इस विजय के कारण जापान पश्चिमी राष्ट्रों के साथ पहले किए गए असम्मानजनक समझौतों से मुक्त हो गया और विश्व राजनीति के क्षेत्र में उसने नया गौरव अर्जित किया । इस युद्ध में विजय के फलस्वरूप जापान को क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि प्राप्त हुई । इस धनराशि के बल पर वह सप्तराज्य के अन्य देशों की भाँति स्वयं-प्रमाण अपना सका । जापान ने जहाज निर्माण व रासायनिक उद्योगों के विकास पर भारी बल दिया । अपने निर्यात को अधिकाधिक बढ़ाया और कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए । सन् 1904-5 में रूस व जापान के बीच युद्ध हुआ जिसमें जापानियों ने रूसियों को बुरी तरह हराकर विश्व को आश्चर्य में डाल दिया । इस विजय के फलस्वरूप जापान के व्यापारिक व औद्योगिक विकास को पुनः प्रोत्साहन मिला । वित्तीय समस्याओं, सामुद्रिक और यातायात औद्योगिक तकनीकी को भारी प्रेरणा मिली और निर्यात व्यापार तजी से बढ़ा ।

6 प्रथम महायुद्ध के पूर्व बड़े पैमाने के जापानी उद्योग-धन्धों का चित्र

मेजी युग में जापान न उद्योग धन्धों के क्षेत्र में कितनी प्रगति की, इसकी एक झाँकी प्रथम महायुद्ध के पूर्व के बड़े पैमाने के जापानी उद्योग-धन्धों के निम्नलिखित संक्षिप्त चित्रण से मिल सकेगी—

लोहा व इस्पात उद्योग—जापान ने लोहा व इस्पात उद्योग में भारी प्रगति की । सन् 1896 में आन्तरिक माँग का लगभग 40 प्रतिशत लोहा उत्पादन किया गया । 1913 के आने आने जापान लोहे व इस्पात की क्रमशः 48 व 34 प्रतिशत आन्तरिक माँग की पूर्ति करने लग गया । शेष माँग की पूर्ति के लिए अभी वह विदेशों के आयात पर निर्भर था ।

कोयला उद्योग—इस उद्योग में कोयला खानों की खुदाई के आधुनिक तरीके अपनाए गए । ज्यों ज्यों जापान का औद्योगीकरण तेज होता गया त्यों त्यों कोयले की माँग बढ़ती गई और कोयला उद्योग फलता-फूलता गया । सन् 1913 के आते-आते कोयले की खानें बढ़कर सराया में 100 हो गईं जिनमें लगभग 2 लाख श्रमिक लगे हुए थे ।

जहाज-निर्माण उद्योग—इस उद्योग का विकास धीरे-धीरे किन्तु मजबूती से हुआ । जो जहाजी कारखाने सरकार के नियन्त्रण में थे, वे 1880 में निजी पूँजीपतियों को दे दिए गए । नए निजी निर्माण गृह भी स्थापित हुए । यद्यपि जलपोतों का निर्माण क्रमशः बढ़ता गया तथापि 1896 से पूर्व तक एक हजार टन से अधिक का कोई जहाज नहीं बनाया गया । इनके बाद पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलने से यह उद्योग तेजी से बढ़ा और जहाजी इजिन भी बनाए जाने लगे । 1899 में सामुद्रिक सहायता कायान बनाने में व्यापारिक जहाजी बेड़े के निर्माण को

श्रोत्राहन मिला। सन् 1913 में जलपोत निर्माण उद्योग की दृष्टि से जापान में एक हजार टन से अधिक के जहाजों का निर्माण करने वाले 6 कारखाने थे।

पेट्रोल उद्योग—इस महत्वपूर्ण उद्योग का विकास सन् 1881 के बाद हुआ। इस क्षेत्र में विदेशी पूँजी का ही महत्वपूर्ण भाग रहा, जापानी पूँजी व साहस के उपयोग में कमी रही। प्रथम महायुद्ध के पूर्व स्थिति यह थी कि तेल की कुल जापानी माँग का 65 प्रतिशत भाग विदेशी कम्पनियों द्वारा ही पूरा किया जाना था।

इजीनियरिंग उद्योग—यह उद्योग भी धीरे-धीरे विकसित हुआ। 1887 में शिकाउरा इजीनियरिंग कारखाना खोला गया जिससे 1892 में विद्युत् सामग्री का उत्पादन होने लगा। कुछ कम्पनियाँ बल्बों, टेलीफोन व तार सामग्री आदि का निर्माण करती थीं। 1892 में जापान में पहला रेल इंजन बनाया गया। सन् 1906 में रेलों के राष्ट्रीयकरण के बाद जापान में रेल-सामग्रियों के निर्माण की गति बढ़ाई गई। 1910 के बाद विद्युत् शक्ति उत्पादन केन्द्रों की संख्या बढ़ी। अर्थ देश में जल विद्युत् शक्ति का उपयोग होने लगा। इसी वर्ष कुछ कारखाने और भी खोले गए व कुछ का आकार बढ़ाया गया।

कागज, चीनी, शीशा, साइकिल व अन्य उद्योग—जापान में और भी विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ। इनमें शीशा, कागज, चीनी, रासायनिक उद्योग, खाद व साइकिल उद्योग आदि उल्लेखनीय हैं। कागज उद्योग की स्थापना से लगभग 50 करोड़ पाँड कागज का उत्पादन होने लगा, किन्तु जापान जिस विरोध किस्म के कागज के लिए विख्यात था वह भ्रव भी छोटे कारखानों व किसान परिवारों में ही बगामा जाता रहा। चीनी उद्योग मेजी काल से पहले भी था पर इसका विकास फारमोसा को जापानी उपनिवेश बना लेने के बाद हुआ। सन् 1902 के बाद यह उद्योग तेजी से पनपा। जापान के मिश्राई तथा मित्सुबिशी रोड परिवारों ने इस उद्योग के विकास में तेजी से हाथ बटाया। शीशा उद्योग का विकास भी मित्सुबिशी घराने से ही हुआ। साइकिल उद्योग ने रूस-जापान युद्ध की समाप्ति के बाद भारी प्रगति की। बड़े कारखानों में साइकिलों के पुर्जे बनाए जाने लगे जिन्हें व्यापारी खरीद कर छोटे उत्पादकों को बेचने लगे जो अपने छोटे कारखानों में इन पुर्जों को मिलाकर अधिकाधिक संख्या में साइकिलें बनाने लगे। सीमेंट, रबर, रासायनिक उद्योगों का भी अच्छा विकास हुआ।

7. आवागमन के साधनों के विस्तार द्वारा आर्थिक प्रगति

पाश्चात्य देशों की भाँति बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण की नीति ने मेजी सरकार को इस बात के लिए प्रेरित किया कि आवागमन के साधनों का विस्तार किया जाए। फलस्वरूप सन् 1871 में वाक-तार प्रणाली का आरम्भ हुआ और 7 वर्ष बाद ही जापान विश्व डाक संघ में शामिल हो गया। सन् 1869 में शोसाका एच टोकियो के बीच एक नौ-यह्न मार्ग बनाया गया। इसके शीघ्र बाद ही टोकियो व याकोहामा को मिलाने के लिए पहली रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। इनके अनिश्चित, अब तक जो माल परम्परागत तरीकों से बनाया जाता था, उनके बदले

नए उत्पादनों को तैयार करने के लिए ऐसे निर्माण संस्थान खोले गए जिनमें पश्चिमी मशीनें लगाई गईं ।

रेलवे और जहाज यातायात साधनों के विकास से जापान की औद्योगिक प्रगति को भारी प्रेरणा मिली । रेल मार्गों की सम्बाई सरकारी रेल मार्गों को मिलाकर सन् 1881 तक लगभग 122 मील हो गईं । इस प्रकार-व्यापारिक पोतों का टन-भार सन् 1873 के 26 हजार टनों से बढ़कर नवें दशक में लगभग 50 हजार टन हो गया । पोतों की सख्या में क्रमशः काफी वृद्धि हुई । जापान के मुख्य शहरों में धीरे-धीरे सार्वजनिक सेवाओं का प्रसार होता गया जिनमें गैस का दिया जाना और ट्रामों का चलाया जाना भी शामिल था ।

1912-13 तक राजकीय रेलवे लगभग 8,396 किलोमीटर और निजी रेलवे 5,289 किलोमीटर हो गईं । 1913 तक जापान अपने कुल निर्यात का लगभग 51 प्रतिशत भाग अपने जहाजों में भेजने लगा जबकि 1893 में वह केवल 7 प्रतिशत भाग ही अपने जहाजों से बाहर भेजता था । जापान का जहाजी बेड़ा 1875 में लगभग 26 हजार टन था जो 1913 के अन्त तक लगभग 15 लाख टन हो गया ।

यातायात और संचार व्यवस्था के साधनों के विकास ने जापान को तीव्र आर्थिक प्रगति दी । श्री जी सी एलन के शब्दों में, "नई संचार व्यवस्था-विशेषकर रेलमार्गों और जहाजों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण योग रहा । बाजार बढ गए और स्थानीय विशेषज्ञता को बढ़ावा मिला । अपने देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राजकुमार मन्सुकाता का यह सुझाव निश्चित रूप से ठीक ही था कि विश्व के विभिन्न भागों की आर्थिक प्रगति और रेलमार्गों के विकास का पारस्परिक सम्बन्ध है तथापि यह कहना शायद ठीक हो कि मेजी काल के प्रारम्भिक वर्षों में यथोक्त परिवहन जापान के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि वे नई प्रक्रियाएँ जो तकनीकी दृष्टि से विलकुल पुरानी थीं । यह ठीक ही कहा गया है कि मिट्टी की सड़कों के निर्माण और लहू, घोड़ों और बोझा ढोने वाले मजदूरों के स्थान पर रिक्शों, घोड़ा गाड़ियों, बैल-गाड़ियों, कुत्तों और आदमियों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों के प्रयोग का नई अर्थ-व्यवस्था के विकास में रेलमार्गों की अपेक्षा शायद अधिक जोरदार प्रभाव पड़ा ।"

8. कृषि की उन्नति

मेजी शासनकाल में कृषि-क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुए जिनसे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था को बल मिला । कृषि में विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए गए तथा औद्योगिक उन्नति के फलस्वरूप कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात घट गया ।

मेजी शासन काल में सरकार ने किसानों को सामन्तवादी प्रतिबन्धों से मुक्त करके उन्हें खेती के सुधरे हुए तरीके प्रयोग में लाने को प्रोत्साहित किया । देश में कृषि विद्यालय खोले गए और विदेशों में कृषि के तरीकों की शिक्षा के लिए विद्वानों

को भेजा गया। किसानों को प्रशिक्षण देने के विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए। कृषि के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र में वृद्धि हुई और साथ ही खेती के सुपारे हुए तरीकों, सिंचाई की अधिकाधिक सुविधाओं आदि का विस्तार हुआ। कीड़े-मकोड़ों और विभिन्न प्रकार की कृषि-बीमारियों पर नियंत्रण आदि से कृषि उत्पादन को बढ़ाया गया। जहाँ 1878 में लगभग 25,79,000 चो (Cho) क्षेत्र में खेती होती थी वहाँ 1908 में लगभग 29,22,000 चो क्षेत्र में खेती होने लगी। जापान के व्यापारिक क्षेत्रों में बिजली के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापारिक कृषि पदार्थ उत्पन्न किए जाने लगे। फलस्वरूप ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में उत्ती तरह सुधार होने लगा जिस तरह इंग्लैंड में 14वीं शताब्दी में होने लगा था।

मेजी युग में कृषि उत्पादन और भी तेजी से बढ़ा। जहाँ 1879-83 में चावल, जौ और गेहूँ का उत्पादन क्रमशः 30,874, 5,506 एवं 2,219 हजार कोकू (एक कोकू बराबर 4.96 बुशल) हुआ था वहाँ 1909-13 की अवधि में 50,242, 9,677 एवं 4,907 हजार कोकू हुआ। यद्यपि मेजी-युग में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई, तथापि किसानों का जीवन अधिक नहीं सुधर सका।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मेजी शासन काल में जापान के आर्थिक इतिहास में एक क्रांतिकारी करवट ली। जापानी अर्थ व्यवस्था जाग गई और तेजी से विकास पथ की ओर बढ़ने लगी। अर्थ-व्यवस्था की यह रचनात्मक पृष्ठभूमि बहुत कुछ तैयार हो गई जिसके आधार पर भावी आर्थिक विकास कामहल खड़ा किया जा सका।

वित्तीय परिवर्तन व प्रगति (Financial Changes and Progress)

मेजी शासन को प्रारम्भ से ही अनेक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फलस्वरूप आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, नई सरकार ने अनेक वित्तीय परिवर्तन किए और इन क्षेत्र में प्रगति करके उसने वित्तीय समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया।

पत्र-मुद्रा प्रवाहान तथा मुद्रा क्षेत्र की अराजकता मिटाने के प्रयत्न

मेजी सरकार के सामने वित्तीय कठिनाइयाँ प्रमुख रूप से तीन कारणों से प्रकट हुईं—(i) शोगुन द्वारा प्राप्त कुल आय केन्द्रीय सरकार को प्राप्त नहीं हो सकी, (ii) हान को भी वरों के क्षेत्र में अभी तक स्वायत्तता प्राप्त थी, एवं (iii) राजनीतिक संधियों व आन्तरिक विद्रोहों का सामना करने में मेजी सरकार को काफी धन राशि व्यय करनी पड़ी। देश की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति इस प्रकार की थी कि सरकार के लिए नए कर लगाना उचित था। इसके अतिरिक्त विदेशी शक्तियों से करारों के कारण सीमा शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली आय भी बहुत ही सीमित थी। कुल मिलाकर बजट की स्थिति सरकार के बहुत ही प्रतिभूल थी। एम टकावै के अनुसार, "सन् 1868 में जहाँ जापानी सरकार का खर्च 250 लाख

येन था वहाँ सरकार को सामान्य स्रोतों से प्राप्त होने वाले राजस्व की राशि 37 लाख येन से अधिक नहीं थी। यह स्थिति वास्तव में बड़ी निराशाजनक थी।

इस गम्भीर वित्तीय समस्या से निपटने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए—

(1) सरकार ने अपने समर्थक व्यापारियों से और स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाओं से अल्पकालीन ऋण लिए। इन स्रोतों से प्राप्त होने वाली कुल राशि केवल 54 लाख येन ही रही और फलस्वरूप 1868 में सरकार को लगभग 160 लाख येन घाटा रहा। सन् 1869 में भी स्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ क्योंकि जहाँ खर्च 208 लाख येन हुआ वहाँ करो, अल्पकालीन ऋणों, जुर्मानों आदि से आमदनी केवल 105 लाख येन की हुई।

(ii) इन प्रतिकूल परिस्थितियों में मेजी सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह छापेखाने का आश्रय ले अर्थात् पत्र-मुद्रा निकाले। सरकार ने 1868 और 1869 में लगभग 480 लाख येन की कीमत के नोट जारी किए। जी. सी. एलन के अनुसार “इनमें से कुछ नोट उन पुरानी विनिमय कम्पनियों या (कावसे-गुमी) के माध्यम से जारी किए गए जिन्होंने इस लेन-देन में बहुत लाभ उठाया।” पत्र-मुद्रा प्रकाशन का डायमियों ने काफी विरोध किया क्योंकि उन्हें भय था कि सरकारी नोटों के प्रकाशन से उनकी अपनी कागजी मुद्रा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

यद्यपि सरकार ने नोट जारी करके वित्तीय समस्या का सामना करने की कोशिश की तथापि सरकार की आर्थिक स्थिति जन-साधारण से छिपी नहीं थी। सरकार की स्थिति में लोगों को अविश्वास होने से नोटों का मूल्य बहुत अधिक गिर गया और 1868 में ही एक समय ऐसा आया जब ये नोट लगभग 55 प्रतिशत के बट्टे पर सोने-चाँदी में बदले जा सकते थे।

कुल मिलाकर आर्थिक क्षेत्र में बड़ी अराजकता की स्थिति थी। पत्र-मुद्रा जारी करने का कोई प्रामाणिक तरीका नहीं था और देश में विभिन्न प्रकार की पत्र-मुद्राएँ प्रचलित थीं। साथ ही सोने चाँदी के सिक्के भी चलन में थे। एलन के शब्दों में, “मुद्रा की स्थिति वास्तव में बहुत भयानक थी क्योंकि उस समय जिस मुद्रा का चलन था उसमें जारी किए गए न केवल ये अपरिवर्तनीय नोट ही थे, अपितु व सोने व चाँदी के सिक्के भी थे जिनमें विभिन्न मात्रा में मिलावट थी। इस मुद्रा में कुला द्वारा जारी किए गए नोटों की लगभग पन्द्रह सौ किस्में भी थीं। ये सब शोगुन शासन के विरासत में मिले थे।”

मेजी शासन ने धैर्य और बुद्धि से काम लिया तथा मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था के क्षेत्र में व्याप्त अराजकता धीरे-धीरे दूर होने लगी। 1869 के अन्त तक मेजी विरोधी शक्तियों का बहुत कुछ दमन कर दिया गया जिससे सरकारी खर्च घट गए और 1870 में बहुत कम नोट जारी करने पड़े। मुद्रा स्फीति के बन्द अथवा कम हो जाने से और साथ ही नए शासन में जनता का विश्वास बढ़ने से नोटों के गिर हुए मूल्य फिर ऊँचे हो गये। 1871 में हान की समाप्ति से मेजी सरकार

के राजस्व खोन पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक हो गए। इसी वर्ष मुद्रा में भी सुधार के प्रयत्न किए गए।

(iii) सोने के येन में धातु की मात्रा निर्धारित करने और उसे प्रामाणिक सिक्का करार देने के लिए सरकार ने एक कानून पास किया। चांदी वाला येन भी वैय मुद्रा घोषित किया गया। सरकार ने ओसाका में एक टकसाल खोली जिसमें आधुनिक मशीन लगाई गई तथा विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किए गए।

(iv) यद्यपि वित्तीय समस्याओं का बहुत कुछ सामना किया गया, तथापि गम्भीर कठिनाइयाँ बनी रही। हान शासन की समाप्ति से स्थानीय प्रशासन का उत्तरदायित्व भी केन्द्रीय सरकार पर आ पड़ा। सरदारों व सामन्तों को वार्षिक पेन्शनों की व्यवस्था करनी पड़ी। इन सब कारणों से बजट की कठिनाइयाँ फिर बढ़ गईं और 1872 में खर्चा तो 580 लाख येन हुआ—बकि राजस्व 330 लाख येन ही हो सका। इस कमी को पूरा करने के लिए नई कागजी मुद्रा जारी की गई। इस वर्ष सरकारी नोटों की राशि 730 लाख येन से भी अधिक हो गई। 1872 के अन्त तक कुल कागजी मुद्रा की मात्रा लगभग 10 करोड़ येन थी।

(v) 1873 में सरकार ने कागजी मुद्रा के बदले 6 प्रतिशत व्याज वाले बाँड देने का प्रस्ताव रखा। पर बाँड आना से बहुत कम खरीदे गये क्योंकि व्याज की वर्तमान दर बाँडों पर मिलने वाले व्याज की दर से कहीं अधिक थी और साथ ही नोटों का मूल्य भी पूर्वापेक्षा बढ़ गया था। फिर भी पत्र मुद्रा प्रकाशन की स्थिति में काफी सुधार हुआ और जून, 1876 तक जारी नोटों की कुल रकम केवल 940 लाख येन के आसपास रह गई। इस समय नोटों का मूल्य लगभग सोने—चांदी के मूल्य के बराबर ही गया। एलन के अनुसार, “वास्तव में इस समय यूरोप में रेशम की फसल खराब हो जान से जापानी रेशम की विदेशों में माग बढ़ गई, अतः सन् 1876 के उत्तरार्द्ध में इन नोटों का मूल्य यथार्थ रूप से मेक्सिकन डॉलर और चांदी के येन से भी अधिक हो गया।”

इस प्रकार 1876 का वर्ष समाप्त होते-होते मेजी सरकार ने अपनी गम्भीर मुद्रा—कठिनाई को हल कर लिया। अल्पकालीन ऋणों को चुका दिया गया और अन्य ऋण भी बहुत कम हो गये।

कर-व्यवस्था में सुधार

एक और तो फेरी सरकार ने वित्तीय समस्याओं का समाधान नोट जारी करके और ऋण लेकर पूरा करने का प्रयत्न किया और दूसरी और कर-व्यवस्था में भी सुधार के प्रयास जारी रहे। शोगुन शासन के समय स्थानीय और केन्द्रीय सरकारों के राजस्व का मुख्य स्रोत लगान होना था। लगान की कोई निश्चित राशि नहीं थी और इसे चावल के रूप में अदा किया जाता था। सन् 1872 में करों की व्यवस्था दिलकुल नए तरीकों से की गई। इस कर-निर्धारण का उद्देश्य ऐसा राजस्व बसूना करना था जो व्यापक रूप से पहले जैसा ही हो, किन्तु राशि की दृष्टि से उगमे बहुत कम घट बढ़ होने की सम्भावना रहे।

केवल भूमिकर में ही वृद्धि की गई वल्कि अन्य करों को भी वैज्ञानिक आधार पर निर्धारित किया गया। पुरानी शासन व्यवस्था में जनता पर अनेक कर लगे हुए थे उनसे धाय होता तो दूर रहा, उनकी बसूली का खर्च भी पूरा नहीं होता था। सन् 1875 में सम्पूर्ण कर-प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर दिया गया और आगामी पांच वर्षों में लगभग सोलह सौ करों के स्थान पर केवल 74 कर ही रह गए। लगान राजस्व का महत्त्वपूर्ण साधन बना रहा 1879-80 में लगान से होने वाली आय सम्पूर्ण राजस्व का लगभग 4/5 भाग थी।

करों की वैज्ञानिक व्यवस्था के कारण सरकार की आमदनी बहुत अधिक बढ़ी। सन् 1870 में सरकार की कुल आय लगभग 20,959 (हजार येन में) थी जिसमें करों से प्राप्त आय 9,323 (हजार येन में) थी। इसकी तुलना में 1876 में ही सरकार की आय 69,482 (हजार येन में) रही जिसमें से कर-आय 59,194 (हजार येन में) थी। इस वर्ष भूमिकर कुल करों की आय का 58 प्रतिशत था। बैंकिंग प्रणाली का संगठन

नई सरकार ने व्यापार और उद्योग का जो विस्तार किया उसके फलस्वरूप जापान में एक व्यापारिक कम्पनी (Trading Company) का निर्माण हुआ जिसने 1870 में काम करना शुरू किया। यह कम्पनी आधुनिक ढंग पर संचालित की गई। इसके बाद ही बैंकिंग कॉरपोरेशन (Banking Corporation) का संगठन किया गया। बैंकिंग के क्षेत्र में उस प्राचीन व्यवस्था को जो डायमियों के अन्तर्गत प्रचलित थी त्याग दिया गया और उसके स्थान पर नई व्यवस्था जारी की गई। अमेरिकन बैंकिंग प्रणाली के आधार पर देश में बैंकिंग व्यवस्था संगठित की गई। इसके अनुसार केन्द्रीय बैंकिंग प्रणाली को नहीं अपनाकर नेशनल बैंक की स्थापना की गई जिन्हे खास-खास क्षेत्रों के अन्तर्गत नोट जारी करने का अधिकार दिया गया। शीघ्र ही बैंक जापान की स्थापना हुई जिसे नोट जारी करने का एकाधिकार दिया गया। 1887 में विदेशी व्यापार की वित्तीय आवश्यकताओं को दृष्टि से, योकोहामा स्पेशी बैंक (Yokohama Specie Bank) स्थापित किया गया। 1893 में स्टॉक एक्सचेंज अधिनियम और बैंक अधिनियम (Stock Exchange Act and the Bank Act) के द्वारा मुद्रा बाजार को नियमित करने के प्रयत्न किए गए।

मेजी सरकार ने इन सभी प्रयासों द्वारा आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयत्न किया, फिर भी उतार-चढ़ाव होते रहे और 1880 के आसपास मुद्रा स्फीति ने जापानियों को काफी परेशान कर दिया। प्रारम्भ में ऋणों को चुकाया अवश्य गया, लेकिन इस समय तक कुल मिलाकर राज्य पर कर्जा बढ़ गया। जून, 1878 में यह कर्जा लगभग 25 करोड़ 40 लाख येन था। सरकार मुद्रा स्फीति के खतरों से अनभिज्ञ नहीं थी। इस शोचनीय स्थिति को मिटाने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए गए। सरकार ने कर बढ़ाकर भी अपनी बजट की स्थिति को सुधारने की चेष्टा की। अक्टूबर, 1881 में काउंट मत्सुकाता को वित्त मंत्री नियुक्ति करने के बाद वित्तीय स्थिति पर बहुत कुछ काबू पाया जा सका।

वास्तव में मेजी पुनर्संस्थापन के समय जो वित्तीय कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं वे नीति की गलतियों के कारण नहीं थी, बल्कि उन घटनाओं के फलस्वरूप हुईं थी जो सरकार के नियन्त्रण के बाहर थी। लेकिन वित्तीय संकटों के दौरान मेजी सरकार ने काफी साहस, धैर्य और दृढ़ता का परिचय दिया जिससे निराश जापानियों में आशा का संचार होता रहा।

मेजी पुनर्संस्थापन काल में विभिन्न परिवर्तनों के तात्कालिक परिणाम (Immediate Effects of the Changes made during the Meiji Restoration)

मेजी पुनर्संस्थापन काल में जो विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और वित्तीय परिवर्तन हुए, उनके तात्कालिक परिणाम मुख्यतः ये निकले—

(1) आर्थिक जीवन में नई चेतना आई। जापान की आर्थिक समृद्धि के प्रेरक वातावरण की रचना हुई।

(2) जापान के उद्योग, वाणिज्य, कृषि, परिवहन आदि सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति हुई।

(3) शिक्षा के प्रसार को बल मिला। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जापान तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा। पाठ्यपुस्तक प्राविधिकों के प्रोत्साहन से देश के भावी आर्थिक विकास की नींव पड़ने में भारी सहायता मिली।

(4) उद्योग-धन्वों के क्षेत्र में बृहद और लघु दोनों ही प्रकार के उद्योगों का संगठन हुआ। बड़े पैमाने पर आधारभूत उद्योगों की नींव रखी गई।

(5) सामन्तशाही की समाप्ति से किसानों को भारी राहत मिली। कृषि क्षेत्र में नवीन प्रयोगों से कृषि की दशा सुधरने लगी।

(6) कर-व्यवस्था वैज्ञानिक आधार पर संगठित हुई और जनता पर से सैकड़ों अनावश्यक करों का बोझ हट गया।

सारंभत मेजी पुनर्संस्थापन-काल में जो विभिन्न परिवर्तन किए गए उनसे जापान की भावी आर्थिक व राजनीतिक प्रगति की नींव पड़ गई और धीरे-धीरे 19वीं शताब्दी के अन्त तक जापान की गरुना विश्व की महान् शक्तियों में की जाने लगी। वस्तुतः मेजी शासन ने जापान को एक आधुनिक राष्ट्र में बदल दिया। उसने पूँजीवादी विस्तार की आवश्यक रूप रेखा बना दी। मेजी काल में जो प्रयास हुए उन्हीं के कारण आधुनिक जापान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

मेजी काल में जापान के औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक (Factors Promoting Industrialisation of Japan during the Meiji Restoration)

मेजी युग में जिन परिस्थितियों और कारकों ने जापान के औद्योगीकरण को प्रोत्साहित किया, उनका सविस्तार उल्लेख पूर्ववर्ती पृष्ठों में हो चुका है। अतः

यहाँ सैकितिक रूप में उन कारकों व परिस्थितियों को अलग-अलग गिनाना ही पर्याप्त होगा—

(1) सरकार ने व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में सत्रिय रुचि ली। सरकारी सहायता और सहयोग से देश तेजी से औद्योगिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा। सरकार ने स्वयं निर्माण उद्योगों के विकास में भाग लिया और विभिन्न उद्योगों को अपने हाथ में लेकर पुनर्गठित किया।

(2) देश के औद्योगिक विकास के लिए पाश्चात्य प्रणालियों और प्रविधियों को अपनाया गया। विदेशी विशेषज्ञ देश में बुलाए गए और जापानियों को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया। देश में प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का अधिकारधिक विस्तार किया गया।

(3) विदेशों से आधुनिक ढंग की बनी वस्तुओं को जापानी श्रमिकों व कारीगरों के सामने नमूने के लिए पेश किया गया ताकि वे उनकी तकल कर सकें और स्वदेशी वस्तुओं को सुधार सकें।

(4) यातायात और सदेशवाहन क साधनों का तेजी से विकास करने की दशा में प्रभावशाली कदम उठाए गए।

(5) पूँजी निर्माण ही समन्या का समाधान सरकार और बड़े-बड़े व्यापारियों के प्रयासों द्वारा किया गया। मेजी शासन में नियोजित रूप में स्पीति-जनक नीति का अनुसरण किया गया। फलस्वरूप आय बढी और आय के पुनर्वितरण से पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिला।

(6) सरकार ने बर-व्यवस्था को पुनर्गठित करके राजस्व में वृद्धि की तथा पत्र-मुद्रा जारी करके वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया।

(7) प्रारम्भिक वर्षों में सरकार ने ऐसी मजदूरी की नीति अपनाई जिसमें मजदूरी में वृद्धि की रूट नहीं दी जाती थी।

(8) सामन्तशाही की समाप्ति करके सामन्तों को मुआवजा ऋण-पत्रों के रूप में दिया गया। सामन्तों ने इन ऋण-पत्रों का प्रयोग नए-नए उद्योग-धन्वों व बैंक आदि में लगाने तथा शेयरों को खरीदने में किया।

(9) बैंकिंग व्यवस्था का संगठन किया गया जिससे मुद्रा बाजार व्यवस्थित हो सका।

(10) विदेशी व्यापार व अन्य उद्योग-धन्वों पर से सभी प्रतिबन्ध उठा लिए गए। पश्चिमी देशों के सम्पर्क में आने से विदेशी व्यापार बढ़ा जिसका देश के निर्माणकारी उद्योगों के विकास पर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा।

(11) चीन और रूस के साथ हुए युद्धों में विजय प्राप्त करने से जापान को अनेक राजनीतिक व आर्थिक लाभ हुए।

संक्षेप में, मेजी सरकार ने औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने वाली प्रत्येक सम्भव नीति का अनुसरण किया। सरकार की सक्रियता और जापानियों के परिश्रम से आर्थिक शक्तियों का प्रवाह बल गया।

2

कृषि विकास

(Agricultural Development)

एक उद्योग प्रधान देश होते हुए भी कृषि के क्षेत्र में जापान का महत्त्व कम नहीं है। कृषि कार्य प्रधानत छोटे पैमाने पर किया जाता है किन्तु पर्याप्त उन्नत है और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग है। कृषि से ही सम्बन्धित पशु-उद्योग भी जापान में बड़ा उन्नत है। फलस्वरूप दुग्धशालाओं का तेजी से विकास हो रहा है।

जापानी कृषि का विकास

(Agricultural Development in Japan)

जापानी की कृषि व्यवस्था राजनीतिक इतिहास में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होती रही है। इसके ऐतिहासिक विकास का अध्ययन हम निम्नलिखित भागों में कर सकते हैं—

- (1) तोकुगावा शासन काल में कृषि,
- (2) मेजी शासन काल में कृषि,
- (3) 1914 से 1932 के बीच कृषि,
- (4) महान् मदी काल में कृषि,
- (5) द्वितीय महायुद्ध काल में कृषि,
- (6) सैनिक शासन काल में कृषि, एवं
- (7) वर्तमान समय में कृषि।

तोकुगावा शासन काल में कृषि

सन् 1868 में मेजी पुनर्स्थापना (The Meiji Restoration) से पूर्व जापान में लगभग 1600 से 1867 तक महान् शक्तिशाली तोकुगावा परिवार का प्रभुत्व रहा। तोकुगावा युग में कृषकों की प्रधानता थी। देश की कुल जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई भाग किसानों का ही था। तोकुगावा घराने की समाप्ति के समय जापान की कुल कार्यशील जनसंख्या लगभग 195 लाख थी जिसमें से 80 प्रतिशत क करीब लोग कृषि, वन और मछली उद्योगों में लगे हुए थे।

तोकुगावा शासन काल में जापानी कृषक वर्ग की स्थिति यूरोपीय दासों की तरह थी। उनकी स्वतन्त्रता पर कठोर प्रतिबन्ध लगे हुए थे। सामन्तवादी प्रथा ने

अपने चारों ओर नियन्त्रणा और प्रतिबन्धों का एक जाल-सा बिछा रखा था। भूमि पर उनका जबरन कब्जा था और किसानों को धूमने-फिरने की आजादी नहीं थी। कृषक वर्ग प्रगतिशील नहीं बन सकता था। उसका रहन-सहन पम्परागत नियमों के अनुसार होना आवश्यक था।

तोकुगावा युग में लगान की मात्रा इतनी अधिक थी कि किसानों को कुल उपज का 40 से 50 प्रतिशत भाग तक लगान के रूप में देना होता था। जापानी अर्थ-व्यवस्था कृषि प्रधान थी, किन्तु कृषि की उत्पादकता बहुत कम थी। कृषि-फसलों में चावल, जौ, गेहूँ और सोयाबीन की प्रधानता थी। पर्वतीय प्रदेश होने से जापान के कुल क्षेत्र के लगभग 16 प्रतिशत भाग पर ही कृषि की जाती थी। कृषि की दशा बहुत पिछड़ी हुई थी और औसत जोत का आकार प्रायः 12 एकड़ था। देहाती क्षेत्रों के सिंचित प्रदेशों में चावल की फसल सबसे प्रमुख थी। दूसरे क्षेत्रों में कपास, नील, सन आदि व्यापारिक फसलों की खेती भी की जाती थी। रेशम उद्योग कृषि के पूरक के रूप में था। यह संभवतः सभी देहाती इलाकों में विद्यमान था। तटवर्ती गाँवों के निवासी मछली पारने का धन्धा भी एक पूरक उद्योग के रूप में अपनाए हुए थे। कृषि आय कम होने के कारण किसानों द्वारा कोई न कोई पूरक व्यवसाय अवश्य अपनाया जाता था।

कृषि की ही नहीं, किसानों की दशा भी बहुत खराब थी। सामन्तों के शिकार तो थे ही, ग्रामीण साहूकारों द्वारा भी उनका तरह-तरह से शोषण किया जाता था। कृषि-उपज बहुत कम होने से देश को अकालों का मुँह भी देखना पड़ता था। कृषि वर्ग में इन अकालों का सामना करने की शक्ति नहीं थी।

मेजी शासन काल में कृषि

तोकुगावा घराने के शोषण और दोषपूर्ण नीति के कारण उसका पतन हो गया तथा 1868 में मेजी पुनर्संस्थापन हुआ अर्थात् सम्राट को जापान का राजसिंहासन मिल गया। मेजी शासन-व्यवस्था स्थापित होने से जापान में आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन आरम्भ हुए।

मेजी पुनर्संस्थापन युग में जापान में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। कृषि में विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को अपनाने का प्रयास किया गया और कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात घट गया। जहाँ 1868 में जापान की कार्यशील जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित था वहाँ 1930 के आते-आते कृषि पर आश्रित जनसंख्या का प्रतिशत 48 के आसपास और 1940 में 41 के लगभग हो गया। इस दौरान जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई, लेकिन कृषि पर आश्रित अनुपात घटता गया।

मेजी शासन काल में सरकार ने किसानों को सामन्तवादी प्रतिबन्धों से मुक्त करके उन्हें खेती-के सुधरे हुए तरीके प्रयोग में लाने को प्रोत्साहित किया। देश में कृषि विद्यालय खोले गए और विदेशों में कृषि के तरीकों की शिक्षा के लिए विद्वानों को भेजा गया। किसानों की प्रशिक्षण देने के विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए। कृषि

के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र में वृद्धि हुई और साथ ही खेती के सुघरे हुए तरीकों, सिंचाई की अधिकारिक सुविधाओं आदि का विस्तार हुआ। कीडे-मकोड़ों और विभिन्न प्रकार की कृषि बीमारियों पर नियन्त्रण आदि से कृषि उत्पादन बढ़ाया गया। जहाँ 1868 में लगभग 2,579,000 चो (Cho) क्षेत्र में खेती होती थी वहाँ 1908 में लगभग 2,922,000 चो क्षेत्र में खेती होने लगी। जापान के व्यापारिक क्षेत्रों में खेती के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापारिक कृषि पदार्थ उत्पन्न किए जाने लगे। फलस्वरूप ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में उसी तरह सुधार होने लगा जिस तरह इंग्लैंड में 15वीं शताब्दी में होने लगा था।

मेजी शासन-काल में कृषि क्षेत्र के विस्तार के साथ ही कृषि उत्पादन भी तेजी से बढ़ा। जहाँ 1879-83 में चावल, जौ और गेहूँ का उत्पादन क्रमशः 30,874 5,506 एवं 2,219 हजार कोकू (एक कोकू बराबर 4 96 बुगल) हुआ था वहाँ 1909 13 को अर्धघंटे में 50,242,9 677 एवं 4 907 हजार कोकू हुआ।

यद्यपि मेजी शासन काल में कृषि के तरीकों में पर्याप्त सुधार हुआ और उत्पादन में भी वृद्धि हुई, किन्तु किसानों का जीवन अधिक नहीं सुधर सका। खेती का आकार अभी भी अत्यन्त छोटा था। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण चावल की खेती केवल छोटे प्रदेशों में ही की जाती थी। मेजी शासन काल में कृषि की दृष्टि से जो सुधार किए गए उनका उद्देश्य यह था कि सरकार अपने औद्योगिक एवं सैनिक उद्देश्यों के लिए कर आदि के रूप में अधिक रकम बसूल करे। मेजी शासन काल में कृषि के सम्मुख अनेक समस्याएँ थीं। यातायात के पर्याप्त साधनों का अभाव होने के कारण किसान अपनी उपज दूर के बाजारों में नहीं ले जा सकते थे। राजकीय व्यय में वृद्धि होने के कारण किसानों पर कर का बोझ बढ़ गया। फलतः जापानी किसान अपनी जीविका निर्वाह करने में भी असमर्थ रहा और इसलिए महाजनों को अपनी भूमि को बेचने लगा। महाजनों द्वारा ऊँचा लगान वसूल किया जाता था। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि पर भार बढ़ता जा रहा था और कृषि का उत्पादन घट रहा था।

1914 से 1932 के बीच कृषि

मेजी शासन काल के बाद जापानी कृषि में महान् आर्थिक मन्दी काल तक विशेष परिवर्तन नहीं हुए। प्रथम महायुद्ध के दौरान कृषि की स्थिति असंतोषजनक रही। प्रथम महायुद्ध के प्रारम्भ से 1932 के बीच किसान परिवारों की संख्या 55 लाख के लगभग बनी रही। जोतों का आकार भी बहुत कम बढ़ता। जो मानुली परिवर्तन हुए वे बहुत छोटे और बहुत बड़े फार्मों से सम्बन्धित रहे। भूमि-व्यवस्था के क्षेत्र में भी बहुत कम परिवर्तन हुए।

1914 से 1932 की अवधि में भोजन और कृषि के क्षेत्र में चावल की प्रधानता बनी रही। कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 55 प्रतिशत भाग में चावल की खेती की जा रही। 1920 तक तो चावल की खेती का क्षेत्र अधिक बढ़ता रहा, लेकिन इसके बाद बहुत कम बढ़ोत्तरी हुई। चावल की औसत उपज यथापूर्व

रही। चावल के बाद खाद्यान्नों के उत्पादन में गेहूँ और जौ का मुख्य स्थान रहा। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में कृषि उपज में वृद्धि न हो पाने से जापान को खाद्यान्नों की पूर्ति के लिए अपने उपनिवेशों पर, विशेषतः कोरिया और फारमोसा पर आश्रित रहना पड़ा। अन्य कृषि पदार्थों में 1914 से 1932 के दौरान काफी वृद्धि हुई। विभिन्न प्रकार की तरकारियों और फलों की खेती भी की जाने लगी।

महायुद्ध से आर्थिक मन्दी प्रारम्भ होने की अवधि में कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन खाद और उर्वरकों के प्रयोग में हुए। विदेशी व्यापार के कारण किसानों की खाद तथा उर्वरकों सम्बन्धी आवश्यकताएँ सुगमता से पूरी होती रही। महायुद्ध के बाद जापान ने भी अपने रासायनिक उद्योग का विकास किया।

इस काल में यद्यपि कृषि उपज की मात्रा बढ़ी, तथापि कृषि पदार्थों के मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन होने से किसानों की आर्थिक दशा अधिक नहीं सुधर सकी। महायुद्ध के दौरान चावल के मूल्य बढ़े, किन्तु बाद में तेजी से गिरते गए। फलस्वरूप सरकार को इस मूल्य-ह्रास को रोकने के लिए स्वयं क्रय-नीति का आश्रय लेना पड़ा। 1927 के बाद चावल की उपज काफी अच्छी होने से सरकारी प्रयत्नों के बावजूद इसके मूल्य में और अधिक गिरावट आ गई जिसका किसानों की आर्थिक दशा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा।

कच्चे रेशम की खेती की प्रमुखता भी बनी रही। 1924 के बाद तो कच्चे रेशम का उत्पादन इतना अधिक बढ़ा कि 1929 तक वह पहले की अपेक्षा लगभग तिगुना हो गया। चावल की भांति ही युद्ध काल के बाद कच्चे रेशम के मूल्य में गिरावट आई लेकिन यह स्थिति शीघ्र ही सुधर गई। पर यह सुधार अस्थायी ही था क्योंकि महान मन्दी के समय लगने वाले भीषण भूटके ने किसानों को भूकम्प दिया। मछली उद्योग ने कृषि के पूरक व्यवसाय के रूप में अच्छी उन्नति की।

महान मन्दी काल में कृषि

महान मन्दी काल में अन्य देशों की अर्थ-व्यवस्था के समान ही जापानी अर्थ-व्यवस्था को गहरा घक्का लगा। कृषि क्षेत्र मन्दी के भूटके से अस्त-व्यस्त-सा हो गया। कच्चे रेशम का मूल्य बहुत अधिक गिर गया और उसके निर्यात में भी भारी कमी आ गई। चावल के मूल्य में भी भारी गिरावट आ गई। फलस्वरूप किसानों की आय पर्याप्त घट गई। जापानी सरकार ने कृषि क्षेत्र में मन्दी के प्रभाव को दूर करने का भरसक प्रयास किया। रेशम के उत्पादकों को प्रोत्साहन देने और उनके घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने एक बड़ी रकम खर्च की। इसके मूल्य में गिरावट को रोकने के लिए 1929 में एक अधिनियम (The Silk Stabilisation and Indemnification Act) भी पारित किया गया। चावल के मूल्य को उचित स्तर पर स्थिर बनाए रखने के लिए 1933 में एक कानून (The Comprehensive Rice Law) पारित किया गया। इसके अतिरिक्त 1932 में दो अन्य कानून भी

बनाए जा चुके हैं जिनके अनुसार किसानों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की सुविधाएँ प्रदान की गईं। करो में परिवर्तन किए गए और किसानों की सहायता के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए गए।

इन समस्त व्यवसायों और सरकारी प्रयासों के बावजूद किसान सन्तुष्ट नहीं हो सके। उनका आरोप था कि उद्योग और सैनिक भावश्यकताओं की दृष्टि से उनकी अवहेलना की जा रही है। यद्यपि सरकार ने किसानों की स्थिति स्थायी रूप में सुधारने के लिए 1932 में कृषि आर्थिक पुनरुद्धार ब्यूरो (The Agricultural Economic Recovery Bureau) की स्थापना भी की लेकिन किसानों में असन्तोष जारी रहा। वे कृषि क्षेत्र में सरकारी नीति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों पर जोर देते रहे ताकि देश के आर्थिक विकास के लाभ का एक समुचित भाग उन्हें मिल सके।

द्वितीय महायुद्ध काल में कृषि

महान मन्दी के दुष्प्रभावों ने जापानी कृषक वर्ग को बहुत झटके दिये थे। महान मन्दी के बाद उन्हें अपनी दशा में सुधार होने की कुछ आशा हुई और तभी द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका ने आ घेरा। सैनिक तैयारियों के कारण कृषि क्षेत्र पर सरकार समुचित ध्यान न दे सकी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान जापानी कृषि और भी बुरी तरह प्रभावित हुई। प्रथम तो किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या को सैनिकों के रूप में अपना जीवन खपा देना पड़ा और दूसरे कृषि के मायने रासायनिक खाद तथा उर्वरकों की भारी कमी आ गई। इसके अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का काफी भाग गैर कृषि उपयोगों में प्रयुक्त किया गया। कृषि धमिकों की इतनी कमी आ गई कि यन्त्रीकरण द्वारा उसे तत्काल पूरा करना सम्भव नहीं था। महायुद्ध की समाप्ति तक किसानों को साधारण कृषि यन्त्र मिलना भी कठिन हो गया।

महायुद्ध जनित परिस्थितियों का यह स्वाभाविक परिणाम हुआ कि 1942 से ही कृषि कुशलता और कृषि उत्पादन में भारी गिरावट आती गई। जहाँ 1937 में फार्म उत्पादन का सूचकांक (1933-35=100) 110.6 था वहाँ 1944 में यह केवल 77.6 रह गया। 1944 तक कुल जोते गये क्षेत्र में भी लगभग 3% की गिरावट आ गई। 1945 में जापान की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के विनाश के साथ ही कृषि की दशा और भी अवनत हो गई तथा उत्पादन का सूचकांक 60% तक गिर गया।

महायुद्ध के बाद जापानी कृषि और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए यह आवश्यक हो गया कि कुछ नास्तिकारी परिवर्तन लाए जाएँ। इस दिशा में अमेरिकन अधिकारियों ने, जिन्होंने 1945 के बाद जापान का शासन चलाया कुछ महत्त्वपूर्ण कदम उठाए और फलस्वरूप युद्धोत्तरकाल में जापानी कृषि को एक नया जीवन मिला।

सैनिक शासन काल में कृषि

द्वितीय विश्व-युद्ध में जापान को हार और भारत-समर्पण के बाद अमेरिका

के जनरल मैकार्थर को शासन की बागडोर सौंपी गई। उनके सैनिक शासन काल में जापान की कृषि में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। सैनिक शासन ने अनुभव किया कि देश में कृषि की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सुधार किए जाएँ। सैनिक शासन यह भी जानता था कि सेना का मुख्य आधार देहाती जमींदार हैं। कृषि की स्थिति को सुधारने के लिए अनेक भूमि-सुधार किए गए। बड़े-बड़े किसानों को समाप्त कर दिया गया। सभी जमींदारों से एक निश्चित मात्रा में अधिक भूमि सरकार द्वारा ले ली गई और सरकार ने इसे जनता के हाथों देच दिया। जमींदारों को उनकी भूमि के बदले पत्र-मुद्रा के रूप में मुआवजा दिया गया था, किन्तु अवमूल्यन के कारण इसकी मात्रा बहुत थोड़ी रह गई। इस नीति में किसानों का ऋण कम हो गया और इनको अधिक गहन खेती के लिए प्रोत्साहित किया गया। युद्ध के बाद खाद्यान्न का अभाव था और इसलिए कृषकों को उत्पादन बढ़ाने से अधिक लाभ प्राप्त हो सका। युद्ध के बाद जापान कृषक स्वामियों का देश बन गया। 1949 तक जमींदारों से अतिरिक्त भूमि लेने और रेंटों को उसे देच देने का काम पूरा हो गया। इस समय तक कुल जोती जाने वाली भूमि में रेंटनी भूमि या प्रतिशत 46 से घटकर 8 तक पहुँच गया।

जापान में कृषि की वर्तमान अवस्था

(Present Position of Agriculture in Japan)

यों समूची अर्थ-व्यवस्था के सन्दर्भ में देखें तो जापान में कृषि का महत्त्व बड़ी तेजी से घटा है, फिर भी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का वह एक महत्त्वपूर्ण अंग है। जहाँ 1950 में कृषि से जापान की लगभग 34 करोड़ जनसंख्या आजीविका कमाती थी वहाँ सन् 1970 में यह संख्या घटकर केवल 27 करोड़ रह गई अर्थात् कुल जनसंख्या का लगभग 18 प्रतिशत। जापान पर्वतों और द्वीपों का राष्ट्र है, अतः यहाँ कृषि योग्य भूमि कुल भूमि की केवल 15% है।

जापान के सरकारी प्रकाशन के अनुसार जापानी किसान आज स्वयं ही अपनी जमीन का मालिक हैं। कृषि योग्य भूमि के चप्पे-चप्पे पर सपन खेती होती है। यहाँ की पहाड़ियों और छोटे-छोटे पहाड़ों के ढलानों को काट-काट कर बड़े-बड़े जंगलों की तरह से चौरस भूमि निकाली जाती है और उसमें खेती की जाती है। जापानी फर्मों के छोटे आकार के कारण उनमें ट्रैक्टरों और दूसरी बड़ी-बड़ी फार्म-मशीनों का इस्तेमाल करना कठिन हो जाता था। केवल होक्कोइदो इसका अपवाद है जहाँ कृष्य भूमि खूब है। किन्तु फिर भी मशीनीकरण का विकास बड़ी तेजी से हुआ है और अनेक जापानी किसान अब अपनी भूमि में यान्त्रिक हलों से खेती करते हैं। लगभग 85 से 90 प्रतिशत कृषक परिवार धान की खेती में बिजली के हलों और अन्य मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही, धान की खेती वाली 80 प्रतिशत से भी अधिक भूमि पर इस प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। खेती में श्रम की उत्पादकता प्रति व्यक्ति लगभग 40 प्रतिशत बढ़ी है।

यहाँ की मुख्य फसल चावल है जो जापानियों का असली भोजन है। उसके

बाद गेहूँ और जौ का स्थान आता है। उन्नत तकनीको, सुघरे किस्म के बीजों और रासायनिक खादों के भारी उपयोग के कारण जापानी खेत सस्यार के सबसे अधिक उत्पादकता वाले खेतों में आते हैं। प्रति एकड़ चावल की उपज का अनुपात जापान में लगभग चीन, महाद्वीपीय चीन में दो तथा अन्य एशियाई देशों में एक है। पिछले दशक में जापान में चावल की फसलें बराबर इतनी प्रचुर रही हैं कि लगभग 120 लाख टन की उपज को किसी समय भरपूर फसल माना जाता था पर आज सामान्य माना जाता है। चावल के उत्पादन में कृषि भूमि का लगभग 37.54 प्रतिशत भाग लगा हुआ है तथा चावल उत्पादन से होने वाली आय कुल कृषि आय की लगभग 57 प्रतिशत है। कृषि का देश की राष्ट्रीय आय में कुल योगदान 1964 में 8.9 प्रतिशत था और 1970 तथा बाद के वर्षों में भी लगभग यही प्रतिशत है।

जापान में अच्छे चरागाहों का अभाव है, इसलिए पशुओं का पालन-पोषण अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर ही हो पाता है। फिर भी पशुपालन जापानी अर्थ-व्यवस्था का प्रमुख व्यवसाय है। लोगों की खान-पान की आदतें बदलती जा रही हैं। आज उनमें मांस की और दूध की चीजों की खपत पहले से कहीं अधिक हो गई है। नतीजा यह हुआ कि हाल ही के वर्षों में पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। खाद्य-पदार्थों की आवश्यकता की दृष्टि से जापान 80 प्रतिशत आत्म-निर्भर रहा है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उपयोगों के लिए खेती की अन्य उपज का भी आयात होता है जैसे कच्चा खड, सूत और ऊन। ये सब चीजें मिलाकर जापान के कुल आयात के लगभग 35 प्रतिशत के बराबर हो जाती है। कुछ वर्ष पूर्व दुनिया के कुल कृषि आयात में जापान का हिस्सा 8 प्रतिशत था।

इसके वर्षों में खेती के ढाँचे में एक जो अन्य परिवर्तन आया है वह है रेशम के कीड़े पालने के उद्योग में निरन्तर कमी होते जाना। इसके साथ ही फसलों जैसे नारंगी सेब और बेर आदि की उपज में काफी वृद्धि हुई। सब तो यह है कि जापान में तरह-तरह के फलों की उपज होती है जिनमें से कुछ का तो बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होता है खासतौर से नारंगियों और आड़ुओं का।

कृषि में मशीनीकरण एवं औद्योगिक विकास के कारण कृषि पर भार निरन्तर कम होता जा रहा है। 1950 में कृषि में लगभग 360 लाख श्रमिक नियोजित थे जो घटकर 1970 में लगभग 110 लाख और 1977 में लगभग 80 लाख रह गये। इस प्रकार वर्तमान में कृषि में केवल श्रम शक्ति का लगभग 14 प्रतिशत भाग ही नियोजित है।

जापान में कृषि की सफलता मुख्यतया गहन कृषि पर आधारित है। जापानी कृषि में जहाँ प्रति एकड़ लगभग 2352 पाँड चावल उत्पन्न होता है वहाँ अमेरिका में लगभग 1390 पाँड और भारत में लगभग 770 पाँड उत्पन्न होता है। 1977 में जापान में लगभग 35 लाख हैक्टेयर में केवल चावल की खेती की गई जबकि 25 लाख हैक्टेयर भूमि में चाय, सन, सोयाबीन आदि की औद्योगिक फसलें उगाई

गई। चावल ही जापान की मुख्य कृषि उपज है। 1977 में लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि में लगभग 10 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उत्पन्न हुआ।

जापान में, जो कि एक औद्योगिक राष्ट्र है, खाद्यान्न के अभाव की पूर्ति के लिए प्रायः प्रतिवर्ष खाद्यान्न आयात करना पड़ता है। 1960 के पूर्व जापान में खाद्यान्न का आयात कुल लगभग 80 करोड़ डॉलर था जो बढ़कर 1970 में लगभग 150 करोड़ डॉलर और 1977 में लगभग 800 करोड़ डॉलर हो गया। जापान को अपने चीनी उद्योग के लिए लगभग 70 से 80 प्रतिशत कच्चा माल विदेशों से आयात करना पड़ता है। जापान में रेशम का उत्पादन औसतन 1 लाख टन सालाना है।

जापान की गणना विश्व के मुख्य औद्योगिक राष्ट्रों में की जाती है तथापि व्यवसाय की दृष्टि से आज भी वह एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। जापान के आर्थिक विकास की यह एक मुख्य विशेषता रही है कि वहाँ कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य किया है। कृषि ने औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है तथा आधुनिक औद्योगिक विकास को सम्भव बनाया है।

जापान में भूमि-सुधार (Land Reforms in Japan)

जापान में कृषि की स्थिति उस समय भारत से अधिक अच्छी नहीं थी जब वह मिन राष्ट्रों के सर्वोच्च कमाण्डर के हाथों में आया। उस समय अधिकतर भूमि बड़े जमींदारों के हाथ में थी और खेत जोतने वाला किसान गम्भीर गिनिता की स्थिति में था। फलस्वरूप वास्तविक जोतदार आसामी बन गए। सन् 1946 में लगभग 70 प्रतिशत कृषक जनता किसी न किसी रूप में लगान वाली भूमि पर निर्भर थी। किसानों की सख्या बढ़ने के कारण भूमि का मूल्य बहुत ऊँचा हो गया। गरीब आदिमियों को उन परिस्थितियों में भू स्वामियों से जमीन प्राप्त करने के लिए अनेक अनुपयुक्त और सर्वाधिक नुकसानपूर्ण शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। गरीब आसामी को जमींदारों के लिए अपनी मेहनत के फलों का आधे से अधिक भाग देना पड़ता था। मित्र-राष्ट्रों के सर्वोच्च सेनापति ने 9 दिसम्बर, 1945 को एक निर्देश जारी किया ताकि सामन्तवादी शोषण के आर्थिक दबाव को समाप्त किया जा सके। इसमें जापानी सरकार को ऐसे आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया ताकि जापान की भूमि में खेती करने वाले किसान अपने परिश्रम का फल प्राप्त करने का अधिक अवसर पा सकें। इस अधिनियम के अन्तर्गत किए गए भूमि-सुधारों को निम्नलिखित 4 बिंदुओं में विभाजित किया जा सकता है—

1. भूमि पर सीमा-निर्धारण—भूमि को काम में न लेने वाले जमींदारों को अपनी भूमि आवश्यक रूप से राज्य के लिए बेचनी पड़ेगी। खेत न जोतने वाले, किन्तु उसी स्थान पर रहने वाले जमींदार अपने पास केवल 2.45 एकड़ भूमि रख सकते थे। कुछ प्रदेशों जैसे होक्काइडो में भूमि की अधिकतम मात्रा 9.80 एकड़ रखी गई। इसके अतिरिक्त भूमि को राज्य के लिए बेचना अनिवार्य था। जो किसान अपनी भूमि स्वयं जोतते हैं उनको शिकोकू, कीशू और होन्शू प्रान्तों में

4 35 एकड़ और होक्वाइडो में 29 40 एकड़ से अधिक भूमि न रखने की बात कही गई। अनुमान था राज्य द्वारा इस प्रकार खरीदा जाने वाला क्षेत्र 4 90 मिलियन एकड़ से भी अधिक था।

2 भूमि की कीमत और भुगतान की शर्तें—भू-स्वामी और आसामी भूमि के स्वामित्व के परिवर्तन के बारे में प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं कर सकते थे। भूमि राज्य द्वारा खरीदी जाती थी और राज्य ही उसे इच्छुक आसामियों को बेच देता था। अधिनियम के पारित हो जाने के बाद आसामियों को बेदखल होने से बचाने के लिए यह व्यवस्था की गई थी। भूमि का स्वामित्व इस आधार पर निश्चित किया जाएगा कि 23 नवम्बर, 1945 को सम्बन्धित व्यक्ति भूमि पर अपना वास्तव में स्वामित्व रखता था।

इस प्रकार आसामियों को भूमि की अधिक कीमत देने से बचाया गया और साथ ही उनको अनुचित रूप से बेदखल करने के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान की गई। यह व्यवस्था की गई कि राज्य से जमीन खरीदने वाला आसामी या तो एक ही बार में कीमत का भुगतान कर सकता था अथवा उसका एक भाग पहली किश्त में देकर दूसरे भाग अन्य 30 किश्तों में देने का निर्णय ले सकता था। ली जाने वाली ब्याज की दर अधिक नहीं थी। वास्तविक व्यवहार में आसामियों ने भूमि खरीदने की पूरी कीमत एक या दो किश्तों में चुका दी क्योंकि उस समय कृषि उत्पादनों की कीमतें पर्याप्त ऊँची थीं ताकि वे शीघ्र ही भूमि की कीमत का भुगतान कर सकें। आसामियों द्वारा कृषि की पुनर्विक्री पर रोक लगा दी गई। केवल राज्य के अधिकारों के माध्यम से ही ऐसा किया जा सकता था।

3 भूमि सुधारों का प्रयत्न—भूमि सुधारों को प्रशासित करने के लिए 3 स्तरों वाले संगठन की स्थापना की गई।

(A) केन्द्रीय भूमि आयोग—केन्द्रीय भूमि आयोग को नीति-निर्माण का काम सौंपा गया। इसमें कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं जिनमें 8 जमींदार, 8 आसामी 4 विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और 2 राष्ट्रीय फार्म संस्था के प्रतिनिधि हात हैं। कृषि और वाणिज्य मन्त्री इस आयोग का सभापति होता है।

(B) प्रोफेक्टर भूमि आयोग—यह आयोग प्रोफेक्टर के स्तर पर कार्य करने के लिए बनाए गए। इनमें 9 जमींदार, 10 आसामी व 4 स्वामी किसान होते हैं। इन सबको अपने-अपने उन प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त किया जाता है जो स्थानीय भूमि आयोगों में रहते हैं। यह आयोग स्थानीय आयोगों के विरुद्ध अपील सुनता है और उनके निर्णयों को अस्वीकार कर सकता है।

(C) स्थानीय भूमि आयोग—इनमें भू-स्वामी, आसामी और दो स्वामी-कृषक होते हैं। इनके अतिरिक्त 4 शिक्षित और पड़े-लिखे व्यक्ति होते हैं जो स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं।

4 आसामी व्यवस्था में सुधार—इन सुधारों के द्वारा आसामियों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका वन् अभी भी 10 प्रतिशत भूमि इन्हीं के द्वारा

जोती जाती थी। कृषि भूमि समायोजन अधिनियम पारित हुआ। उसमें यह व्यवस्था की गई कि लगान का भुगतान वस्तु के रूप में नहीं किया जाएगा। यह भी कहा गया कि आसामी द्वारा भू-स्वामी को दिया गया लगान सूखी भूमि के कुल उत्पादन के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। जमींदार और आसामी के बीच किए जाने वाले मौखिक समझौते को अब बंध घोषित किया गया। कानून द्वारा यह भी व्यवस्था की गई कि यदि आसामी द्वारा भूमि पर कुछ स्थाई प्रकृति के सुधार किए गए हैं तो उनके बदले उन्हें मुआवजा दिया जाएगा।

इस प्रकार भूमि-सुधार के लिए दानो दिशाओं में प्रयास किए गए। एक ओर आसामियों की परिस्थितियों को सुधारा गया और दूसरी ओर बड़ी सख्या में आसामियों को भू-स्वामी बना दिया गया। इस सुधार के द्वारा 90 प्रतिशत जोती जाने वाली भूमि को भूमि के जोतदारों के स्वामित्व में ला दिया गया। इस प्रकार इस आश्वासन को पूरा करने की चेष्टा की गई कि भूमि उसे जोतने वाले की होती है।

जापानी कृषि की आधुनिक प्रवृत्तियाँ एवं समस्याएँ

1 जापान में छोटे-छोटे खेत बिखरे पड़े हैं जिनका औसत आकार 1 हेक्टर से भी कम है। अधिकांश खेती के उपभाजन और उपखण्डन के फलस्वरूप ऐसे खेतों के 15-16 टुकड़े तक हैं।

2 कृषि उन्नत रूप में वैज्ञानिकीकृत हो चुकी है। वर्तमान में छोटे आकार के आधुनिक यन्त्रों का उपयोग बढ़ रहा है।

3 कृषि-उत्पादन में निरन्तर वृद्धि के बावजूद राष्ट्रीय आय में कृषि का भाग घटा है। यह कुछ वर्ष पूर्व जहाँ 18 प्रतिशत था वहाँ अब लगभग 9 प्रतिशत ही रह गया है। इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास की तीव्र गति है।

4 जापानवासियों में अपनी भूमि से अत्यधिक प्रेम की प्रवृत्ति विद्यमान है, अतः निकट भविष्य में भी चकवन्दी की संभावना बहुत कम है।

5 जापान की कृषि की सफलता मुख्यतया गहन-कृषि पर आधारित है और जापानी कृषि में व्यवसायी दृष्टिकोण की प्रधानता है।

6 जापान में कृषि में उन्नत बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग निरन्तर बढ़ता जा रहा है। जापान प्रति एकड़ उत्पादन में नये कीर्तिमान स्थापित करता रहा है। 1952 को यदि आधार वर्ष मानें तो जहाँ 1955 में कृषि-उत्पादन का सूचकांक 125 था वहाँ 1977 में यह लगभग 170 हो गया।

7 जापान में कृषि ने औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। कृषि-जन्य खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि के फलस्वरूप जापानियों की खाने की आदत में परिवर्तन आता जा रहा है और वे दूध, मांस, फल, मछली का प्रयोग अधिक करने लगे हैं।

8 कृषि में भारी उन्नति के बावजूद जापान खाद्यान्नों की दृष्टि से आत्म

निर्भर नहीं है। खाद्यान्नों के अभाव की पूर्ति के लिए खाद्यान्नों का आयात निरन्तर बढ़ता जा रहा है। 1960 में यह आयात लगभग 80 करोड़ डॉलर था जो बढ़ कर 1977 तक 800 करोड़ डॉलर और वर्तमान में 900 डॉलर से भी अधिक का हो गया है।

9 जापान में कृषि-योग्य समतल भू-भाग की कमी है। मैदानी भाग बहुत छोटा और बिखरा हुआ है। इसलिए जापानी खेतों का आकार भी छोटा है।

10 कृषि के वैज्ञानिकरण के कारण इस क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों की संख्या निरन्तर घटती जा रही है।

11 जापानी कृषि में पूँजी-निर्माण की गति कम होती जा रही है और सस्ती कृषि-साख का अभाव बढ़ रहा है। इन सब कारणों से कृषकों की सीमान्त दक्षता कम है।

12 कृषि जापानी अर्थ-व्यवस्था की एक बहुत कमजोर कड़ी है और कृषि में लाभ-दर औद्योगिक क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम है। जापान में कृषि मुख्यतया सरकारी अनुदान और सरक्षण पर आधारित है। फिर भी जापानी कृषि का व्यावसायिक दृष्टिकोण विश्व की कृषि प्रदान अर्थ-व्यवस्थाओं के लिए एक "विकास मॉडल" प्रस्तुत करता है।

कृषि के लिए राज्य की सहायता

(State Aid to Agriculture)

जापान में प्रारम्भ से ही राज्य ने कृषि के विकास में रुचि ली है। मेजी शक्ति काल में भी राज्य कृषि के विकास के लिए सक्रिय योगदान करता था। 20वीं शताब्दी में यह प्रवृत्ति बढ़ गई। कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए और खेती-बाड़ी के तरीकों में सुधार लाने के लिए तथा विदेशी धाँजों को जापान की परिस्थितियों में अपनाते में सहायता करने के लिए कृषि प्रयोगात्मक स्टेशन स्थापित किए गए हैं। जापान की सरकार कृषि की सहायता के लिए हर दृष्टि से सामने आई। सरकार द्वारा फाम व्यवस्थापन किया गया, कृषि वित्त की व्यवस्था की गई, कीमत स्थायित्व लागू किया गया, भूमि नीति और गेहूँ नीति को क्रियान्वित किया गया, सरकार ने कृषि के विकास की दृष्टि से जो विभिन्न कार्य किए, उनमें उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं—

(1) कृषि-वित्त की व्यवस्था—सन् 1896 में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार 10 मिलियन येन की पूँजी से युक्त एक बैंक की स्थापना की गई जो किसानों को अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर ऋण दे सके। इन ऋणों का भुगतान वार्षिक किराने के रूप में 50 वर्ष तक किया जाता था। बैंक को यह भी शक्ति दी गई कि वह सरकारी सत्ताओं, सहकारी समाजों और मछली तटों को ऋण दे सके। इसके अतिरिक्त 46 कृषि और औद्योगिक बैंक भी स्थापित किए गए। वे हाईपोथिक बैंक से ऋण ले सकते थे और उन सभी कार्यों को सम्पन्न कर सकते थे जो हाईपोथिक बैंक को सौंपे गए। कुछ समय में बैंक की वित्तीय स्थिति

इतनी सुघर गई कि इसने 750 मिलियन येन का ऋण 1933 तक प्रदान किया। अचल सम्पत्ति पर दिए जाने वाले ऋणों की मात्रा 1921 और 1931 के बीच 15 प्रतिशत बढ़ गई। सरकारी वित्तीय सहायता सहकारी कार्यगृहों और खाद फ़ैक्ट्रियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान की गई। राज्य ने रीलिंग मिलों की स्थापना पर जोर दिया ताकि छोटे सिल्क उत्पादकों को बड़े रीलरो के वित्तीय नियन्त्रण से बचाए रखे।

1922 में राज्य ने आवश्यकता वाले किसानों को डाक घर के सुरक्षित कोष एव जीवन बीमा पॉलिसी में से ऋण प्रदान किया। 1925 तक लगभग 17 मिलियन येन का ऋण इस प्रकार दे दिया गया। 1916 में जब कृषि-कीमतें निरन्तर गिरने लगी तो सरकार ने उनको रोकने के लिए बेयर हार्जिसिंग व्यापार अधिनियम पारित किया। यह अधिनियम सरकारी बेयर हाउसों में रखे हुए माल पर साख प्रदान करने की अनुमति देता है। 1925 तक सहकारी समितियों ने 1741 बेयर हाउसों की रचना की। सन् 1920 में केन्द्रीय सहकारी बैंक स्थापित किया गया जिसने 1924 के बाद काम करना प्रारम्भ किया। सन् 1924 में एक थोक सहकारी समाज स्थापित किया गया। 1927 में जापान में 1400 सहकारी समितियाँ थीं। इनकी सख्या 1937 में 16000 हो गई जिसके सदस्य 61 लाख थे। सन् 1932 में विशेष ऋण और हानि मुआवजा कानून पारित किए गए ताकि केन्द्रीय सहकारी बैंक और बन्धन बैंक दोनों दीपकालीन और अल्पकालीन ऋण किसानों को प्रदान कर सकें। सरकार द्वारा किसानों की नकद आय को बढ़ाने के लिए राहत कार्य भी प्रारम्भ किए गए। मन्दी के समय रेशम की कीमत को बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इन सहायताओं का मुख्य भाग कृषि-भूमि के सुधार, देहाती नालियों और जल व्यवस्था में सुधार आदि के काम में लिया गया।

2 कीमत स्थायित्व—राज्य द्वारा किया गया दूसरा मौलिक प्रयास कीमत स्थायित्व में सम्बन्धित था। कृषि उत्पादनों की कीमतें बुरी तरह से हिल रही थी इसलिए राज्य को उन्हें बुद्धिपूर्वक स्तर पर स्थिर करना पड़ा। सन् 1921 में चावल नियन्त्रण अधिनियम पारित किया गया। इसके अनुसार सरकार को चावल की पूर्ति नियमित करने के लिए आवश्यकतानुसार चावल खरीदने, बेचने, बदलने और स्टोर करने की शक्ति दी गई। इस कार्य के लिए 200 मिलियन येन का प्रारम्भिक कोष प्रदान किया गया। चावल की घटती हुई कीमतों को केवल राज्य द्वारा चावल खरीद कर नहीं रोका जा सका। 1925 में एक कानून द्वारा राज्य को कीमतों पर नियन्त्रण लगाने की शक्ति मिल गई। इन प्रयासों के परिणाम-स्वरूप कुछ समय के लिए कीमतों में गिरावट पर रोक लग गई किन्तु आर्थिक मन्दी के बाद कीमतों में फिर से गिरावट आ गई। 1930 में राज्य ने अन्य चावल कानून पास किया। इसके अनुसार यह व्यवस्था की गई कि यदि कीमतें नियन्त्रण-स्तर से नीचे गिर जाएँगी तो राज्य खरीददारी कर लेगा और यदि अधिकतम स्तर से ऊपर उठ जाएँगी तो राज्य विक्री करेगा। 1933 के सशोधन ने सरकार को

न्यूनतम और अधिकतम कीमतें निश्चित करने और चावल नियमन तथा चावलों के आयात पर साइसेस लगाने के लिए एक चावल मण्डल की स्थापना की शक्ति दी। कीमतों के निम्नलिखित सूचकांक के आधार पर सरकार की सफलता स्पष्ट हो जाती है—

कीमत सूचकांक
(माघार वर्ष 1925=100)

वर्ष	कीमत सूचकांक
1929	80 4
1930	62 2
1931	44 6
1932	80'9
1933	51 9
1934	63 0
1935	71 5

3. रेशम या सिल्क नीति—मार्च 1930 में सिल्क की कीमतें स्थाई बनाने से सम्बन्धित अधिनियम पारित हुआ। इस समय 1932 की मन्दी के कारण सिल्क की कीमतें गिर रही थी। इस कानून के अनुसार सिल्क उत्पादकों के लिए क्षति-पूर्ति की व्यवस्था की गई। इनके परिणामस्वरूप सरकार के ऊपर लगभग 29 5 मिलियन येन का अतिरिक्त भार बट गया।

4. गेहूँ नीति—गेहूँ के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए और किसानों के कष्टों को दूर करने के लिए जापानी सरकार ने विभिन्न प्रयास किए। 1932 में सरकार ने पंचवर्षीय योजना घोषणाई। गेहूँ और आटे पर करों की मात्रा बढ़ाई गई। गेहूँ के उत्पादन के लिए सुघरे हुए साधनों और प्रणालियाँ को काम में लाया जाने लगा। बाजरे तथा जौ के स्थान पर गेहूँ का प्रयोग किया जाने लगा। पंचवर्षीय योजना द्वारा गेहूँ के उत्पादन को 1937 तक 50 मिलियन बुशेल बढ़ाने की योजना बनाई गई और किसानों की धाय 30 प्रतिशत बढ़ाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया।

5. भूमि कय-नीति—राज्य ने एक 25 वर्षीय कार्यक्रम निर्धारित किया जिसके अन्तर्गत आसामी को वह भूमि खरीदने की सुविधाएँ प्रदान की जानी थी जिसे वह जोतता है। कार्यक्रम ने 1 2 लाख किसानों को 1 3 लाख एकड़ भूमि खरीदने की व्यवस्था की। इस योजना से केवल 2 प्रतिशत ही किसान लाभ उठा सके।

6. भूमि-सुधार नीति—किसानों को अधिक से अधिक भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उनको खेती-बाड़ी के व्यापक तथा गहन दोनों तरीके बताए गए। इसके लिए अच्छे बीजों और अच्छी खाद को लोकप्रिय बनाया गया। खेती-बाड़ी के गहन तरीकों को लोकप्रिय बनाकर सरकार प्रति एकड़

अधिक उत्पादन कर सकती थी। यह 1870 में 94 16 या और 1924 में यह काफी बढ़ गया।

जापान के कृषि विकास में आसामी व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा थी। सरकार ने 20 जुलाई, 1946 को भूमि सुधार कार्यक्रम अपनाया ताकि आवश्यकता के अनुसार भूमि खरीदी और बेची जा सके तथा कृषक स्वामियों की स्थापना की जा सके। मित्र-राष्ट्रों के अधिकार के समय भूमि प्रशासन की दृष्टि से उल्लेखनीय सुधार हुए। भू-स्वामित्व की व्यवस्था को सुधार दिया गया और इस प्रकार 90% भूमि का स्वामित्व स्वयं किसानों के हाथों में आ गया।

7 कृषि-आर्थिक क्षति-पूर्ति ब्यूरो—उपर्युक्त प्रयासों के अनिश्चित जापानी सरकार ने 1932 में कृषि आर्थिक क्षति-पूर्ति ब्यूरो की स्थापना की ताकि किसानों की मुसीबतों को कम किया जा सके। किसानों की उत्पादन-लागतें बहुत ऊँची उठ गई थीं। ब्यूरो को यह काम भी सौंपा गया कि वह फार्म के नेताओं को प्रशिक्षित करे ताकि वे उत्पादन और वितरण को नियंत्रित कर सकें तथा भूमि पूँजी का समानतापूर्ण रूप से प्रयोग कर सकें।

8 सहकारी आन्दोलन—जापान में सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ एव प्रगति सरकार की पहल एव समर्थन के आघार पर हुई थी। सहकारी आघार पर बनाए गए स्टोर हाउसों और ज्वरकर फैक्ट्रियों को सरकारी सहायता प्रदान की गई।

इस प्रकार जापान की सरकार ने अपने देश की कृषि की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए अनेक सजग प्रयास किए हैं। भारत जापान के अनुभवों से पर्याप्त लाभ उठा सकता है। कीमत स्थायित्व, देहाती वित्त, फार्म-व्यवस्थापन आदि के क्षेत्र में जापान ने जो कदम उठाए हैं वे भारत के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं।

भारत के लिए उपयोगिता

(Utility for India)

जापान के अनुभवों की भारत के लिए क्या उपयोगिता है, इसका अध्ययन करना इस दृष्टि से उपयोगिता रखता है कि हम भी अपनी समान समस्याओं के लिए इन तरीकों को आना सकते हैं। भारतीय कृषि के लिए जापान की कृषि में जो सबक मिलते हैं वे निम्नलिखित हैं—

1 जापान ने साम्राज्यवादी उद्देश्यों के पीछे अपने देश की कृषि की अवहलना की। विभिन्न उपजबेशों की प्राप्ति करन और बनाए रखने का कामना में उसने कृषि की अपेक्षा अपने औद्योगिक प्रसार पर अधिक ध्यान दिया। भारत में पञ्चशील और तटस्थता की विदेश नीति को अपनाकर इस सम्भावना को ही निरस्त कर दिया है। कृषि के विकास को आगे बढ़ाने के लिए यह नीति अपनाना आवश्यक भी है।

2 जनसंख्या की वृद्धि जापान जैसे उन्नत देश में भी एक गम्भीर समस्या बन जाती है। इसके परिणामस्वरूप भूमि पर दबाव में वृद्धि हो जाती है। ऐसी

स्थिति में यह स्पष्ट है कि भारत को अपनी कृषि का विकास करने के लिए जनसंख्या-वृद्धि पर आवश्यक रूप से रोक लगानी चाहिए।

3. देहाती ऋणप्रस्तता की समस्या केवल तभी मुलभई जा सकती है जबकि राज्य उसमें पूरी तरह से रचि ले। जापान में देहाती साख की व्यवस्था के लिए बैंको का जाल बिछा दिया गया है। भारत में इसी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं।

4. किसानों को राहत प्रदान करने के लिए तथा उनके दुःखों को दूर करने के लिए कीमत स्थिरीकरण की नीति अपनाई जा सकती है मद्यपि यह नीति पर्याप्त महंगी होती है और हमेशा सफल भी नहीं हो पाती, फिर भी यह एक ठोस कदम है।

5. जापान की भाँति भारत में भी किसानों की अल्प आय को सहारा देने के लिए लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों का प्रसार किया जा सकता है।

6. भारत में कृषि की अर्द्ध-वेरोजगारी को दूर करने के लिए जापान की भाँति कृषि से सम्बद्ध उद्योगों का विकास किया जा सकता है। यहाँ गौ-पालन, दुग्धशालाएँ, चारागाह-पालन आदि व्यवसाय अपनाकर भूमि के भार को कम किया जा सकता है। भारतवर्ष फसल की खेती की अपेक्षा मिश्रित खेती का तरीका भी अपना सकता है। ये प्रयास देश की बढ़ती हुई वेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कुछ उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

जापान की कृषि जो 1850 में पर्याप्त पिछड़ी हुई थी आज वह उन्नत वैज्ञानिकीकृत हो चुकी है। जापान में यह परिवर्तन मुख्यतः इसलिए प्राया क्योंकि उसने इस परिवर्तन की चार न्यूनतम शर्तों को पूरा कर लिया। ये शर्तें हैं—(1) इस प्रकार की दूरदर्ष्टि वाला नेतृत्व होना चाहिए जो अतीत से पूर्णतः भिन्न भविष्य की परछाइयों को समझ सके। (2) इस नेतृत्व का सरकार की सत्ता पर निरन्तर एवं स्थायी रूप में अधिकार रहना चाहिए। ऐसा न होने पर आय को निवेश में नहीं बदला जा सकेगा तथा उन परम्परागत सत्याओं को नहीं बदला जा सकेगा जो परिवर्तन का विरोध करती हैं। (3) अर्थ-व्यवस्था इतनी सशक्त होनी चाहिए कि वह महत्त्वपूर्ण स्तर पर साधनों का निवेश कर सके। (4) उद्योग में अर्थ की पर्याप्त पूर्ति हो। जापान में इन सभी पूर्वं-शर्तों को पूरा किया जा सका और इसलिए उसने कृषि के क्षेत्र में इतनी प्रगति की।



प्रमुख आधुनिक उद्योगों के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

(A Few Important Facts About Principal
Modern Industries)

द्वितीय महायुद्ध में तहस-नहस हो गए जापान ने न केवल अपने घावों को भर ही लिया है बल्कि वह आधुनिक विश्व का एक महान औद्योगिक राष्ट्र बन गया है। रूस, अमेरिका और पश्चिमी जर्मनी के बाद आर्थिक समृद्धि और औद्योगिक प्रगति की दृष्टि से जापान की ही गणना की जाती है। जापान ने वृहद् और लघु दोनों ही प्रकार के उद्योगों में आश्चर्यजनक प्रगति की है।

जापान में उद्योग वर्तमान दशा

(Industry in Japan Present Position)

वर्तमान शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में जापानी अर्थ-व्यवस्था में अम-प्रधान उत्पादन का बोलबाला था और आज पूँजी-प्रधान उद्योगों के प्रति विशेष आग्रह है—यानी उत्पादन का क्रम हल्के से भारी उद्योग की ओर रहा है। अर्थ-व्यवस्था के इस परिवर्तन-चक्र के इद गिर्द ही आधुनिक जापान की कहानी घूमती है।

द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले जापान के उद्योग—विशेष रूप से हल्के औद्योगिक उत्पादन में लगे हुए उद्योग—काफी विकसित थे। चौथे दशक में भारी उद्योगों का द्रुत परिवर्तन शुरू हुआ और वेग धारण करता गया। युग की माँगों से इस परिवर्तन को और भी गति मिल गई। परन्तु अगस्त, 1945 में जब युद्ध का अन्त हुआ तब तक जापान का अग्रिष्ठतर औद्योगिक समय नष्ट हो चुका था।

पिछले दो दशकों में, मोटे तौर पर आर्थिक विकास के तीन दौर रहे हैं। पहला दौर 1945 से 1952 तक रहा। इस दौर को हम पुनर्निर्माण का युग कह सकते हैं। इस दौर में औद्योगिक क्षमता का तेजी से दुबारा निर्माण किया गया। 1953 के आरम्भ तक युद्धोत्तर पुनर्निर्माण की माँग प्रायः पूरी हो चुकी थी।

दूसरे दौर का प्रसार 1953 से 1959 के आरम्भ तक रहा। इसे हम अपनी स्थिति मजबूत करने का दौर कह सकते हैं।

जापान के मुद्रोत्तर आर्थिक निर्माण का तीसरा दौर अभी पूरा हुआ है। इस काल में, उद्योगों को फिर से व्यवस्थित किया गया और उनका विस्तार किया गया और राष्ट्र के औद्योगिक ढांचे का आधार निश्चित रूप से भारी उद्योग बन गए।

भव यह कहा जा सकता है कि अपने अनवरत विकास-क्रम में जापान ने एक नए दौर में प्रवेश किया है। यह दौर परिणाम के विस्तार का नहीं, गुण की वृद्धि का दौर है जबकि भव तक सबसे ज्यादा दौर परिणाम के विस्तार का रहा है। पूँजी के भरपूर उपयोग से ही देश की औद्योगिक सुविधाओं को द्रुत आधुनिकीकरण हुआ है। एक अध्ययन के अनुसार नए वैयक्तिक पूँजी निवेश की औसत जापान में अमेरिका के स्तर से हाल ही के वर्षों में प्रायः दुगुनी रही है।

जापान के आर्थिक पुनरुत्थान के व्यावहारिक प्रतीक रासायनिक और शैल-रासायनिक उद्योगों तथा भारी मशीन-उद्योग हैं। इन उद्योगों की हवा से ही आज जापान की गिनती दुनिया के सबसे ऊँचे औद्योगिक राष्ट्रों में होती है।

तकनीकी स्तरों का निरन्तर और क्रमशः ऊँचे उठना तथा उद्योगों में नई शिल्प वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के प्रयोग का इस आर्थिक विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जहाँ तक "पोत-निर्माण" का सम्बन्ध है, "प्लाक-पद्धति" का उपयोग करके जापानी याई दुनिया के सबसे बड़े टैंकरों का निर्माण कर रहे हैं? शैल-रासायनिक उद्योग के अन्तर्गत उद्योग और उपभोक्ता दोनों के लिए नई-नई चीजें पैदा की जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जापान घर और आकाश दोनों के लिए नए उपकरण तैयार कर रहा है। परिपहन के क्षेत्र में देखें तो न्यू तोकाइदो साइन की सुपर-एकप्रेशा गाड़ियाँ सत्तार की सबसे तेज रफ्तार वाली गाड़ियों में हैं। विदेश-व्यापार में भी जापान और शिल्प विज्ञान दूसरे देशों को भेज रहा है—विशेष रूप से संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक उत्पादनों के क्षेत्र में।

जापान की औद्योगिक प्रगति का एक अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 1959 से 1969 के मध्य ही औद्योगिक सूचकांक चार गुना बढ़ गया था और 1953 से 1959 की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में औसतन 10-9 प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। कुछ वर्षों पूर्व प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र सभ की एक विज्ञप्ति के अनुसार 1958-67 के दस वर्षों में जापान का औद्योगिक उत्पादन लगभग 245 प्रतिशत बढ़ा जबकि उसी अवधि में रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि क्रमशः 121 प्रतिशत, 71 प्रतिशत और 38 प्रतिशत हुई। यदि 1934-36 को आधार वर्ष मानें तो 1937 में जापानी औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 130 था जो गिरकर 1946 में केवल 31 रह गया। मुद्रोत्तर काल में जापान के औद्योगिक क्षेत्र में विस्फोटक प्रगति हुई और फलस्वरूप 1951 में यह सूचकांक 114 से बढ़कर 1970 में 1870 हो गया और 1977 में यह सूचकांक लगभग 3,000 हो जाना अनुमान था। इस प्रकार 1951 के सूचकांक की तुलना में 1977 तक 26 गुणा से भी अधिक वृद्धि हुई और यदि 1946 को लें तो 1977 तक लगभग 97 गुणा वृद्धि हुई। यदि 1960 को आधार

वर्ष (1960-100) मान कर औद्योगिक प्रगति पर रूटिपात करे तो 1935 के मुकाबले जापानी उद्योग में 1977 तक सामान्यतः 30 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई। 1935 में सामान्य उत्पादन सूचकांक 28.7 था जो बढ़कर 1977 में 850 से भी अधिक हो गया। जनोपयोगी औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 1935 में लगभग 22.4 था जो बढ़कर 1977 में लगभग 900 हो गया। खनिज उद्योग उत्पादन का सूचकांक 1935 में लगभग 65 था जो बढ़ कर 1977 में लगभग 20 हो गया। केवल औद्योगिक उत्पादन 1960 के मुकाबले 1979 तक 5 गुना से भी अधिक हो गया है। विश्व के अग्रणी राष्ट्रों के मुकाबले जापान ने औद्योगिक क्षेत्र में विस्फोटक प्रगति की है। यदि 1977 के आंकड़ों को लें तो 1913 के आधार वर्ष के अनुसार (1913=100) औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक इंग्लैंड में 460, अमेरिका में 1000 और रूस में 2500 था तो जापान में यह 3500 था। यदि 1870 के आंकड़ों को लें तो हम आश्चर्य चकित हो जायेंगे कि औद्योगिक उत्पादन इन देशों में कितना अधिक बढ़ा है। 1870 का औद्योगिक सूचकांक (1913 के आधार वर्ष के अनुसार) इंग्लैंड में 43, अमेरिका में 12-5, रूस में 11 और जापान में 12 था। दूसरे शब्दों में यह कहना होगा कि 1913 के आधार वर्ष के अनुसार 1870 से 1977 तक जापान के औद्योगिक सूचकांक में लगभग 292 गुना वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में रूस में लगभग 227 गुना, अमेरिका में लगभग 80 गुना और इंग्लैंड में लगभग 11 गुना वृद्धि हुई। जापान में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि निरस्तदेह चमत्कारपूर्ण रही। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जापानी औद्योगिक संरचना में छोटे पैमाने के तथा उपभोग उद्योगों की प्रधानता थी जबकि महायुद्धोत्तर काल में आधारभूत इंजीनियरिंग उद्योगों की प्रमुखता है। जहाज निर्माण के क्षेत्र में जापान विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश। लोहा-इस्पात के उत्पादन में विश्व में उसका तीसरा स्थान है तो मोटर-गाड़ी के उत्पादन में विश्व का बड़ा देश है।

जापान में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 1941 में जापान में लगभग 78 लाख औद्योगिक श्रमिक थे जो बढ़कर 1956 में लगभग 175 लाख और 1966 में 490 लाख हो गए। 1977 में औद्योगिक श्रमिकों की 70 लाख से भी अधिक होने का अनुमान था।

जापान में युद्धोत्तरकाल में तीव्र औद्योगिक प्रगति के कारण

जापान के औद्योगिक उत्पादन में पिछले लगभग तीन दशकों में विस्फोटक प्रगति हुई है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ 1939 के आधार वर्ष पर 1946 में औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 31 था वहाँ 1960 में यह 410, 1970 में 1870 और 1977 में अनुमानतः 3000 हो गया। औद्योगिक श्रमिकों की संख्या 1946 में लगभग 105 लाख से बढ़ कर वर्तमान में 1130 लाख से भी अधिक हो गई है। पिछले लगभग दस वर्षों में जापान ने औद्योगिक उत्पादन में पाँच गुना वृद्धि की है जिसका उदाहरण विश्व के किसी भी राष्ट्र में नहीं मिलता। द्वितीय महायुद्धकाल में जापान की सारी अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी, किन्तु

बाद में जापान ने जिस आश्चर्यजनक ढंग से पुद्द के पावो को भर दिया और अमत्कारिक गति से अपना पुनर्निर्माण किया, उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्तमान शताब्दी के अन्त तक जापान आसानी से प्रगति कर लेगा और 21वीं शताब्दी के कुछ ही दशकों में विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र बन जाएगा।

जापान की अमत्कारिक और विस्फोटक औद्योगिक प्रगति के मूल में मुख्यतः निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं

1 जापान का राष्ट्रीय धरित्र बहुत ऊँचा है, जापानी कर्मचरिण्ड हैं और राष्ट्रभक्ति की भावना से अतप्रोत हैं। उन्होंने अपने राष्ट्र के औद्योगिक विकास के अर्थो में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। जापान में अनुशासित धर्म का कोई प्रभाव नहीं पाया जाता।

2 जापान का तकनीकी कौशल बहुत ऊँचे दर्जे का है। जापानियों ने आधुनिकतम उपकरणों और विधियों को निरन्तर प्राथमिकता दी है। पश्चिमी राष्ट्रों से प्रभूत महायत्ता प्राप्त कर जापान ने अपने आधारभूत उद्योगों के लिए सुद्ध आधार-शिला तैयार की है।

3 जापान में धर्म अनुशासित, कुशल और परिश्रमी होने के साथ ही सस्ता भी है। फलस्वरूप उत्पादकता और उत्पादन दोनों में तीव्रगति से वृद्धि हुई है।

4 सरकार की सशक्त और यथार्थवादी मौद्रिक तथा राजकोपीय नीति में औद्योगिक प्रगति को बहूत ही अनुकूल रूप में प्रभावित किया है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं आदि के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए ऋणों की समुचित व्यवस्था उपलब्ध की गई है।

5 जापानी खाद्यो, पीओ और भोज उद्योगों के सिद्धान्त में विश्वास नहीं रखते। उनका विश्वास "कम उपभोग और अधिक बचत" में है। ब्रिटेन और अमेरिका में वैयक्तिक व्ययों का अनुपात राष्ट्रीय आय का क्रमशः लगभग 5 और 7 है जबकि जापान में यह 25 प्रतिशत है। अधिक बचत के कारण ही अधिक पूँजी-निर्माण सम्भव हुआ है और देश के औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में विशाल पूँजीनिवेश हो सका है।

6 उपभोग में कटौती के कारण विशाल मात्रा में पूँजी निवेश होने से विकास दर भी बढ़ गई है। पिछले दशक में अमेरिका में वार्षिक विकास-दर लगभग 4-5 प्रतिशत, जर्मनी में लगभग 6 से 7 प्रतिशत और इंग्लैण्ड में लगभग 3 प्रतिशत रही थी तबकि जापान में विकास दर लगभग 9 से 10 प्रतिशत रही।

7. जापान ने अपने सर्वाङ्गीण विकास के लिए पिछले दशकों में आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया है। नियोजन-कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वयन हुआ है जिससे औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा है। जापान ने आर्थिक विकास की दस वर्षीय योजना बनाई है। 1961-70 की दस वर्षीय योजना के बाद 1970-80 की योजना समाप्ति पर है।

8 जापान में बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ ही छोटे पैमाने के उद्योगों को भी निरन्तर प्रोत्साहन दिया गया है। दोनों औद्योगिक क्षेत्र परस्पर समन्वयपूर्ण

दृष्टिकोण रखते हैं तथा एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि और उद्योग में भी परस्पर घनिष्ठ अन्वयगतित सम्बन्ध है।

9 जापानी औद्योगिक विकास के प्रति गहन रुचि रखते हैं और सरकार का उन्हें पूर्ण सहयोग मिलता है। देश की लगभग समूची जनसंख्या (98 प्रतिशत से भी अधिक) शिक्षित है, और उसमें अपने राष्ट्र को विश्व का सिरमौर बनाने की महत्वाकांक्षा है।

इन सब कारणों से जापान अपना तीव्रगति से औद्योगीकरण करने में सफल हुआ है।

इस पृष्ठभूमि के उपरान्त अब हम जापान के कुछ बुने हुए प्रसिद्ध उद्योगों का विवरण देते हैं—

- (1) सूती वस्त्र उद्योग
- (2) रेशम उद्योग
- (3) लोहा एवं इस्पात उद्योग
- (4) कोयला उद्योग
- (5) जहाज निर्माण उद्योग
- (6) रासायनिक उद्योग
- (7) मोटर उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Textile Industry)

जापान के आर्थिक विकास में सूती वस्त्र उद्योग का जितना अधिक योगदान रहा है, उतना अन्य किसी उद्योग का नहीं। प्रारम्भ में यह उद्योग कृषि के सहायक रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता था किन्तु मेजी पुनर्संस्थापन के बाद इस उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की।

1868 से 1885 तक का काल—मेजी पुनर्संस्थापन के पहले जापानी हाथ से सूत कातते थे और हस्तचालित करघे से बुनने का कार्य करते थे। आधुनिक प्रकार का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना 1867 में स्थापित किया गया। 1870 में और फिर 1872 में सूती वस्त्र के कारखाने खोले गए। मेजी सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में स्वयं पदार्पण करने की नीति अपनाई जिसके फलस्वरूप पश्चिमी यन्त्रों से सुसज्जित दो सूत कातने के कारखाने स्थापित हुए।

विदेशों से सूती वस्त्र के यन्त्रों का आयात किया गया और फिर उन्हें उचित दर पर निजी व्यापारियों को दिया गया। किन्तु अभी तक सूती वस्त्र उद्योग के सभी कारखाने आकार में काफी छोटे थे और उनका संचालन भी जल शक्ति से होता था। सन् 1882 में एक आसाका स्पीनिंग मिल खोली गई जो उस समय के अन्य सूती वस्त्र कारखानों से बड़ी थी।

इन प्रयासों के बावजूद 1868 से 1885 के दौरान कुल मिलाकर सूती वस्त्र उद्योग में विकास बहुत ही कम हो सका था और यह उद्योग इस क्षेत्र में विदेशों का, विशेषतः ब्रिटेन का मुकाबला करने में असमर्थ था। सन् 1887 में भी जहाँ जापान

में कुल मिलाकर 77 हजार के आस-पास तकुवे थे वहाँ इंग्लैंड की एक ही मित में इतने तकुवे पाए जाते थे।

1886 से 1914 तक का काल—1886 के बाद सूती-वस्त्र उद्योग का तेजी से विकास प्रारम्भ हुआ। सरकार उद्योगों को अनुकूल शर्तों व दरों पर निजी उद्यमकर्ताओं को देने लगी। मूल्यों में वृद्धि हो जाने से उद्योगपतियों को इस उद्योग में विनियोग करने का बड़ा प्रोत्साहन मिला। 1896 के बाद जापान को भारत से सस्ती दर पर कपास मिलने लगी। 1894-95 में चीन के साथ होने वाले युद्ध में जापान की विजय हुई, फलस्वरूप उसे सूत के लिए कोरिया का बाजार हाथ लगा। सस्ते श्रमिकों की उपलब्धि के कारण भी इस उद्योग को बड़ी गति मिली। जहाँ 1887 में जापान में तकुवों की संख्या लगभग 77 हजार थी वहाँ 1913 में यह संख्या 2415 हजार तक पहुँच गई। इसी प्रकार जहाँ 1893 में सूत का उत्पादन लगभग 880 लाख पींड हुआ था वहाँ 1913 में यह उत्पादन लगभग 6070 लाख पींड तक जा पहुँचा। 1913 में सूत कातने वाले मिल्नों की संख्या भी लगभग 44 हो गई।

1914 से 1929 तक का काल—इस अवधि में जापानी सूती-वस्त्र उद्योग का पहले तो भी अधिक तेजी से विकास हुआ। यूरोपियन देश महायुद्ध में फसे रहने से अपना निर्यात नहीं कर सके। यूरोपियन जहाजी बंड युद्ध में उलझे रहे, अतः निर्यात की जो सामग्री उपलब्ध थी वह भी पूर्वी बाजारों में नहीं भेजी जा सकी। इस परिस्थिति से जापान ने पूरा-पूरा लाभ उठाया। जापानी जहाजों ने सभी पूर्वी देशों की गाना की और इस प्रकार युद्ध-काल में जापान को इन देशों के विशाल बाजार हाथ लग गए। जापान ने इन प्रदेशों में ब्रिटेन के एकाधिकार को समाप्त कर दिया।

महायुद्ध के बाद आने वाली मन्दी और 1923 के भूकम्प के कारण जापानी सूती-वस्त्र उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी प्रगति जारी रही। इस अवधि में सूती-वस्त्र-कारखानों के औसत आकार में वृद्धि हुई। एकीकरण की प्रवृत्तियाँ दिखाई देने लगी तथा 1929 तक लगभग 56 प्रतिशत तकुवे 17 बड़ी-बड़ी मिल्नों के हाथ में आ गए। अब एक ही कारखानों में कनाई और बुनाई के दोनों कार्य किए जाने लगे। जापानी सूती माल विश्व के बाजारों में छाने लगा। पापुविन, क्रैप, साटिन, ब्रिटिंग आदि का ऊँचे किस्म का माल अधिकधिक निर्यात किया जान लगा।

1929 से 1939 तक की अवधि—सन् 1929 में जापानी सूती-वस्त्र उद्योग काफी विकसित अवस्था में था, किन्तु शीघ्र ही विश्व-व्यापी मन्दी ने इस उद्योग को बड़ा धक्का पहुँचाया। महान मन्दी के कारण सूती वस्त्र के निर्यात पर भारी प्रतिफल प्रभाव पड़ा। लगभग दो वर्षों तक विपन्न कठिनाइयाँ भेलने के बाद जापान ने स्वयं-भार का परित्याग करके घेन का पुनर्मुल्यांकन किया। अब स्थिति में तेजी सुधार हुआ तथा सूती-वस्त्र उद्योग को भारी प्रोत्साहन मिला। जापान ने न केवल अपनी बिगड़ी हुई स्थिति को समाप्त किया बल्कि वह सूती माल के निर्यातक देशों में सबसे अग्रणी हो गया। 1931 के बाद जापान में सूती-वस्त्र का निर्माण और निर्यात इतना तेजी से होने लगा कि 1936 के आते-आते उसने इंग्लैंड को इस क्षेत्र

में पछाड़ दिया। अब विश्व बाजार में जापान ही सूती वस्त्र उद्योग का राजा (Textile King) कड़ा जाने लगा। 1934 में जापान के निर्यात के कुल मूल्य का लगभग 23.7 प्रतिशत केवल सूती माल से बना।

इस अवधि में सूती-वस्त्र उद्योग मुख्यतः तीन कारणों से इतना अधिक उन्नत हो सका—

(i) जापानी मुद्रा के पुनर्मूल्यन से जापानी वस्तुओं के निर्यात का मूल्य घट गया, अतः सूती माल का निर्यात बहुत अधिक बढ़ा।

(ii) सूती-वस्त्र कारखानों की वित्तीय स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ, जिससे इस उद्योग को तीव्र गति मिली।

(iii) सम्बन्धित उद्योगपतियों ने इस उद्योग के विकास में पूर्ण रुचि ली। सूती वस्त्र के निर्यात और कपास के आयात दोनों में इन्होंने महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया।

1939 से 1945 तक का काल—द्वितीय महायुद्ध काल में जापानी सूती-वस्त्र उद्योग को बड़ा भारी धक्का लगा। इसका निर्यात बाजार समाप्त हो गया। कपास के आयात में भारी कमी हो गई। मित्र राष्ट्रों के निरन्तर वायु आक्रमणों ने जापान के विभिन्न उद्योगों और कारखानों को तहस-नहस कर दिया। इस महा विनाश के कारण 1945 में जापानी वस्त्र उद्योग में तकुवो की संख्या 1937 के 12 मिलियन की तुलना में केवल 3 मिलियन ही रह गई। युद्ध काल में जापान ने अपना सम्पूर्ण ध्यान शस्त्रास्त्रों के उत्पादन में लगा दिया और उन्हीं उद्योगों में रुचि ली जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में सहायक होते। सामरिक आवश्यकताओं के कारण बहुत से सूती-वस्त्र कारखानों को युद्ध-सामग्री उत्पन्न करने वाले कारखानों में बदल दिया गया। जहाँ 1937 में सूती-वस्त्र मिलों की संख्या 285 थी वहाँ 1945 में यह संख्या केवल 38 रह गई। कर्मियों की संख्या भी 1937 में 1,16,276 से घटकर 1945 में केवल 23 हजार रह गई। स.स. में, द्वितीय महायुद्धकाल में जापान का सूती-वस्त्र उद्योग तहस-नहस हो गया।

युद्धोत्तर काल—महायुद्ध की समाप्ति पर जापान पर मित्र राष्ट्रीय नियन्त्रण स्थापित हो गया। सैनिक शासन के दौरान, विभिन्न परिस्थितियों वश, जापान के पुनरुत्थान के प्रयास किए जाने लगे। जापानी उद्योगों और अर्थ-व्यवस्था के पतन से अमेरिका व उसके साथी राष्ट्रों को यह चिन्ता हो गई कि पूर्वी एशियाई बाजारों पर कहीं रूस अथवा उसके गुट का कोई अन्य राज्य प्रभुत्व न जमा ले। मास्को द्वारा एशिया के निर्धन राज्यों में साम्यवाद के प्रचार का भी पूरा भय पैदा हो गया। अतः अमेरिकन सैनिक शासन का यह प्रयत्न रहा कि जापान को पुनः सम्मानजनक स्तर प्रदान कर दिया जाए और उसे पुनरुत्थान की दिशा में मोड़ा जाए।

सैनिक शासन ने सर्वप्रथम एक नौ-सूत्री आर्थिक स्थिरता कार्यक्रम बनाकर जापान के पुनरुत्थान की दिशा में कदम उठाया। सूती-वस्त्र उद्योग की दृष्टि से 1946 में एक अमेरिकी समिति ने 'सयुक्त राष्ट्र वस्तु साख कॉरपोरेशन' से सिफारिश की कि जापान को दो लाख गाँठ कपास दी जाए। इस समय जापान के निर्यात

बाजारों में मोटे किस्म की वस्तुओं की मांग महीन और बटिया किस्म की वस्तुओं की मांग होने लगी थी। अतः जापान ने अमेरिका और मिस्र से उत्तम कोटि की कपास खरीदी।

जापानी-वस्त्र-निर्माणा सघ द्वारा सैनिक शासन से अनुरोध किया गया कि वस्त्र उद्योग को कम से कम 30 प्रतिशत तक युद्ध पूर्व की प्रवस्था प्राप्त करने की छूट दी जाए। सैनिक शासन ने इतनी छूट तो नहीं दी, लेकिन इस उद्योग का विकास 40 लाख तंतुओं तक बढ़ाने की अनुमति दे दी। यह छूट बहुत ही कम थी, क्योंकि जापानी वस्त्रों की घरेलू और बाहरी मांग की पूर्ति के लिए इस उद्योग में 80 लाख तंतुओं का लगाना तो निरन्तर आवश्यक था। सैनिक शासन ने धीरे-धीरे और भी छूट दी जिससे 1952 तक तंतुओं की संख्या बढ़कर लगभग 64 लाख हो गई और लगभग 2,92,672 कर्बों काम करने लगे। 1953 में तंतुओं की संख्या 75 लाख तक पहुँच गई और युद्ध पूर्व के उत्पादन का लगभग 80% वस्त्र तैयार होने लग गया। सूती वस्त्रों का घरेलू बाजार बहुत ही विस्तृत हो गया। 1951 में सूती वस्त्रों की आन्तरिक खपत युद्ध-पूर्व स्तर तक पहुँच गई तथा 1952 में 50 प्रतिशत अधिक हो गई। 1953 में जापान के घरेलू बाजारों में ही वस्त्र उद्योग के सम्पूर्ण उत्पादन का 60 प्रतिशत से भी अधिक भाग खपने लगा जबकि युद्ध से पहले केवल 24 प्रतिशत भाग ही खपता था।

जापान सैनिक शासन के अन्तर्गत अथवा पराधीनता की प्रवस्था में 1945 से 1952 तक ही रहा। अतः 1952 के बाद सभी क्षेत्र में जापान उन्मुक्त रूप से प्रगति करने लगा। आज जापान का वस्त्र उद्योग बहुत ही उन्नत प्रवस्था में पहुँच चुका है। लगभग दस बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ इस उद्योग का प्रबन्ध सम्भाले हुए हैं और 8000 से भी अधिक इस उद्योग के स्वतन्त्र उत्पादन-कर्त्ता हैं। इन दस बड़ी कम्पनियों के पास 109 से भी अधिक मिलें हैं जिनमें लगभग डेढ़ लाख श्रमिक काम करते हैं। उल्लेखनीय है कि यद्यपि सूती-वस्त्र उद्योग का जापानी अर्थ-व्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है तथापि इसका सापेक्षिक महत्त्व क्रमशः घटता जा रहा है। महायुद्ध से पूर्व जापान के कुल निर्यात का लगभग आधे से भी अधिक भाग सूती वस्त्र का होता था जबकि 1963 में यह लगभग 22.9 प्रतिशत ही था। सूती-वस्त्र उद्योग के अत्यधिक वैज्ञानिकरण के कारण जापान आज भी विश्व का एक प्रमुख वस्त्र उत्पादक देश है। कृत्रिम वस्त्रों के उत्पादन में इतने बड़ी प्रगति की है। 1963 में स्थिति यह थी कि जापान विश्व के सम्पूर्ण वस्त्र उत्पादन का लगभग 31.5 प्रतिशत स्वयं उत्पन्न करता था। वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में आज भी जापान का पलड़ा भारी है, तथापि विश्वयुद्ध के पूर्व जापान के निर्यात में जहाँ 50 प्रतिशत भाग इस उद्योग का था वहाँ अब यह लगभग 13 प्रतिशत रह गया है। भारत के वस्त्र उद्योग को जापानी वस्त्र उद्योग से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। जापान कृत्रिम वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 1966 में जापानी मिलों ने लगभग 5 लाख टन सूती और लगभग 290 करोड़ से भी अधिक वर्गमीटर कपड़े

का उत्पादन किया था जबकि 1977 में 9 लाख टन सूत और 6 करोड़ वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन हुआ। सूती वस्त्र उत्पादन के आंकड़े 1979 तक और भी अधिक ऊँची सीमा छूने लगे हैं।

रेशम उद्योग (Silk Industry)

रेशम उद्योग जापान का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है, किन्तु पहले की अपेक्षा इसका सापेक्षिक महत्त्व कम हो गया है। सिल्क उद्योग की कहानी बड़ी लम्बी और प्राचीन है। जापान के ग्रामीण परिवारों में रेशम का उत्पादन अति प्राचीन काल में ही किया जाने लगा था। तोटुगावा शासन काल में भी रेशम के बीड़ों को पालना कृषक परिवारों का एक मुख्य घन्या था। सन् 1855 के लगभग रेशम की माँग में एकाएक वृद्धि होने में इससे उत्पादन को काफी प्रोत्साहन मिला। मेजी पुनर्संस्थापन के समय से यह उद्योग तेजी से पनपने लगा।

1868 से 1894 तक का काल—1868 में मेजी पुनर्संस्थापन के बाद रेशम उद्योग को सरकारी संरक्षण मिला। रेशम के बेचने के आधुनिक तरीके काम में लाए गए। पश्चिमी मशीनें उद्योग में लगाई गईं। इन सब उपायों के फलस्वरूप सन् 1868 से 1883 के बीच रेशम का उत्पादन पहले की अपेक्षा दुगुना और निर्यात ढाई गुना हो गया। आंकड़ों की दृष्टि से इस अवधि में कच्चे रेशम का उत्पादन 278 लाख क्वान (एक क्वान बराबर 8 22 पौण्ड) में 457 लाख क्वान तक बढ़ गया और निर्यात 175 लाख क्वान से 365 लाख क्वान तक हो गया। जापानी रेशम को फ्रांसीसी और इटालियन रेशम से मुकाबला करना पड़ा लेकिन उत्पादन के तरीकों में सुधार करके, कीमत घटाकर और 1893 में चाँदी में गिरावट आ जाने से जापानी रेशम सफलतापूर्वक प्रतियोगिता में ठहर सका। फिर भी 1881 के बाद रेशम का निर्यात गिरने अवश्य लग गया।

1894 से 1913 तक का काल—सन् 1881 के बाद जापानी रेशम के निर्यात में जो कमी आने लगी, वह बढ़ती ही गई। 19वीं शताब्दी के अन्त तक रेशम का निर्यात नगण्य हो गया, किन्तु आन्तरिक खपत में वृद्धि होती गई। अन्य देशों की अपेक्षा उत्पादन-व्यय कम होने से जापान में इसका बाजार बढ़ता गया। सन् 1893 के बाद रेशम का उत्पादन ग्रामीण परिवारों की जगह कुछ विशेष प्रकार के संस्थानों में होने लगा जिन्हें सरकार ने प्रोत्साहित किया। 1883 से 1913 के दौरान रेशम के उत्पादन और निर्यात की स्थिति इस प्रकार रही—

वर्ष	उत्पादन (मिलियन पौण्डों में)	निर्यात (मिलियन पौण्डों में)
1893	457	367
1889-1903	1924	1110
1902-13	3375	2583

1914 से 1939 तक का काल—1914 में प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। उस समय यह उद्योग छोटी-छोटी इकाइयों या सस्थाओं के हाथ में था। बिजली द्वारा चलने वाले कच्चे सीमित भागों में ही थे। 1914 से 1939 के बीच रेशमी वस्त्र उद्योग में भारी विकास हुआ। 1914 से 1939 के बीच ही कच्चे रेशम का उत्पादन लगभग दुगुना बढ़ गया। किसान अधिकधिक सख्या में रेशम के कीड़े पालने लगे। 1929 में स्थिति यह थी कि लगभग आधे कृषक परिवार इसे सहायक धन्धे के रूप में अपनाए हुए थे। काम करने वालों में लड़कियों की सख्या सबसे अधिक थी। जापान में यह उद्योग इतना लोकप्रिय हो गया कि जब 1930 में महान मंदी के कारण रेशम के बाजारों को धक्का लगा तो जापान की श्रामीण जनता को भारी दुखों और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा।

प्रथम महायुद्ध के समय से ही जापानी रेशम उद्योग ने इतनी उन्नति कुछ विशेष कारणोंवश की। प्रथम अमेरिका में रेशम की मांग बढ़ गई। द्वितीय जापानी रेशम में सुधार लाने के पूरे प्रयास किए गए। तृतीय, जापानी कृषि विभाग ने निरानों को आर्थिक व तकनीकी सहायता दी जिससे एक ओर तो वे कृषि का विकास कर सकें और दूसरी ओर रेशम के कीड़े पालने में अधिक रुचि ले सकें। चतुर्थ, आन्तरिक बाजार में भी रेशम की मांग बढ़ती गई। पंचम, शहृतों की सेती, कीड़ा के पालन पोषण, मशीनों आदि सभी में अद्यत् रेशम उद्योग के हर विभाग में वैज्ञानिक ढंग से सुधार किया गया तथा रेशम वस्त्र का मानदण्ड निर्धारित किया गया।

सरकार और जापानी जनता की सक्रियता के कारण रेशम उद्योग ने मंदी के भटके को सहन करने के बाद पुन तेजी से उन्नति की। उत्पादन विधियों में सुधार आदि के फलस्वरूप रेशम का उत्पादन क्रमश बढ़ता ही गया।

इस अवधि में रेशम बुनने के उद्योग दो विभागों में बँटे थे। पहला विभाग हाथ से संचालित करघों का था। घरों व छोटी छोटी दुकानों में घरेलू बाजार के लिए कम अर्ज के रेशमी वस्त्र इन करघों द्वारा तैयार किए जाते थे। दूसरा विभाग बड़े कारखानों का था जिनमें मशीनों द्वारा कच्चे चलाए जाते थे। इन कारखानों में चौड़े अर्ज के रेशमी वस्त्र निर्यात के लिए बनते थे।

द्वितीय महायुद्ध काल और बाद का समय—द्वितीय महायुद्ध काल में जापान ने सभी उद्योगों को धार विनाश का सामना करना पड़ा। यद्यपि महायुद्ध के बाद सैनिक शासन के अन्तर्गत और फिर स्वाधीनता काल में जापान ने काफी प्रगति की, लेकिन उसका रेशम उद्योग पहले की तरह पतन नहीं सका। महायुद्ध के बाद कच्चे रेशम के निर्यात में भारी कमी आ गई। 1954 के बाद से जापानी रेशम का सबसे बड़ा बाजार केवल समुक्त राज्य अमेरिका ही रहा है। कृत्रिम रेशम की खोज के बाद रेशम उद्योग का मौए हो जाना अस्वाभाविक भी नहीं है। भारी प्रयत्नों के बावजूद जापान का रेशम उद्योग अभी 1921-23 के वार्षिक स्तर पर ही पहुँचा है जो 1930-35 के वार्षिक उत्पादन के आधे से भी कम उत्पादन है। 1977 में

लगभग 60 लाख क्वान कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ था जबकि 1935-36 में लगभग 115 क्वान का उत्पादन किया गया था। 1945 से 1950 के पूर्व तक लगभग 19 लाख क्वान वार्षिक औसत था जो बढ़कर 1950-55 की अवधि में लगभग 36 लाख क्वान वार्षिक औसत हो गया। 1969 में लगभग 56 लाख क्वान कच्चे रेशम का उत्पादन हुआ था। निर्यात मूल्य की दृष्टि से ले तो जहाँ 1929 में लगभग 7800 लाख येन मूल्य का कच्चा रेशम निर्यात किया गया था वहाँ 1945-50 के बीच लगभग 12 लाख क्वान कच्चा रेशम का वार्षिक औसत निर्यात रहा। 1960 में लगभग 14 लाख येन का कच्चा रेशम निर्यात किया गया जबकि 1977 में केवल लगभग 3 लाख येन का ही निर्यात हो सका।

लोहा एवं इस्पात उद्योग (Iron and Steel Industry)

आज के युग में लोहा और इस्पात उद्योग किसी भी देश की आर्थिक शक्ति का मापक माना जाता है। आज इस क्षेत्र में जापान इतनी प्रगति कर चुका है कि अमेरिका और रूस के बाद उसकी ही गिनती है।

1868 से 1913 तक का काल—मेजी शासन काल के प्रारम्भ में जापान में लोहा व इस्पात का उत्पादन इतना कम था कि जापान को लगभग अपनी सम्पूर्ण आवश्यकता की पूर्ति विदेशों से आयात द्वारा करनी पड़ती थी। लेकिन मेजी सरकार इस उद्योग के प्रति उदासीन नहीं रह सकी। सन् 1887 में पहली वायु भट्टी (Blast Furnace) और सन् 1891 में पहली खुली भट्टी (Open Hearth Furnace) अस्तित्व में आई। पर आधुनिक ढंग का पहला लोहा व इस्पात कारखाना 'यावटा वर्क्स' (Yawta Works) सरकार द्वारा सन् 1911 में ही आकर स्थापित किया जा सका। सरकारी रुचि जाग्रत होना पर निजी उद्योगपति भी इस ओर आकर्षित हुए और उनके द्वारा भी कई छोटे-छोटे कारखाने स्थापित किए गए जो बहुत कुछ सरकारी सहायता पर आश्रित थे।

यद्यपि लोहा और इस्पात उद्योग की नींव पड़ चुकी थी, लेकिन प्रथम महायुद्ध के आरम्भ तक यह उद्योग काफी पिछड़ा हुआ ही था। लोहा और इस्पात का उत्पादन बहुत ही कम था।

1914 से 1929 तक का काल—प्रथम महायुद्ध ने जापान के लोहा व इस्पात उद्योग में प्राण फूँक दिए। युद्धकाल में और इसके बाद निजी उद्योगपतियों ने लोहा व इस्पात के अनेक कारखानों की स्थापना की तथा पुराने कारखानों का विस्तार किया। उद्योग के विकास में सरकार की पूर्ण रुचि और सजगता बनी रही। सन् 1929 तक देश में उत्पादित कुल इस्पात और पिंग आयरन का एक बहुत बड़ा भाग यावटा आयरन वर्क्स द्वारा ही उत्पन्न होता था जो राज्य द्वारा नियन्त्रित था। सन् 1914 से 1929 के बीच इस्पात का उत्पादन पूर्वपिछा लगभग 8 गुना बढ़ गया। जहाँ 1913 में तैयार इस्पात 255 हजार टन हुआ था वहाँ 1929 में यह बढ़ कर 2034 हजार टन हो गया।

1930 से 1939 तक का काल—महा मदी के समय जापान को तीव्र आर्थिक भटके लगे, किन्तु बाद में औद्योगिक क्षेत्र में उसने तेजी से प्रगति की। 1930 से 1939 के बीच लोहा व इस्पात का उद्योग काफी पनपा। 1930 से 1936 के बीच ही तैयार इस्पात का उत्पादन पहले की तुलना में दुगुने से भी अधिक हो गया। पिग आयरन का उत्पादन भी दुगुना हो गया। तैयार इस्पात में विभिन्न नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। 1936 तक इस्पात के उत्पादन में जापान ने इतनी उन्नति करली कि आयात के स्थान पर वह इसका निर्यात करने लगा। इस समय महायुद्ध के लक्षण प्रकट होने लग गए थे। अतः सैनिक तैयारियों की दृष्टि से, लोहा व इस्पात के उत्पादन के एकीकरण पर बल दिया गया। इस उद्देश्य से 1934 में एक जापान स्टील कम्पनी स्थापित हुई जिसमें लगभग तीन-चौथाई पूँजी सरकारी थी। सन् 1937 में चीन व जापान के बीच युद्ध छिड़ जाने से लोहा व इस्पात उद्योग की भारी प्रगति हुई। अब लोहा व इस्पात के उत्पादन पर अधिकाधिक ध्यान दिया जाने लगा। द्वितीय महायुद्ध के छिड़ने तक इस्पात के उत्पादन में काफी वृद्धि करली गई।

द्वितीय महायुद्ध काल और बाद का समय—महायुद्ध काल में जापान ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध किया। युद्ध के प्रारम्भिक तीन वर्षों में जापान और उसके साथी राष्ट्र निरन्तर विजयें प्राप्त करते गए। जापान में लोहा और इस्पात का उत्पादन तेजी से होने लगा। तैयार इस्पात की क्षमता अत्यधिक बढ़ गई। सारा उत्पादन देश ही में खपने लगा। 1944 में इस्पात का उत्पादन चरम सीमा पर पहुँच गया। लेकिन यह स्थिति बनी न रह सकी। मित्र राष्ट्रों की बम वर्षा कहर डालने लगी और जापान के उद्योग भू-भ्रष्ट होन लगे। 1945 में जापान द्वारा आत्मसमर्पण करने के समय तक उत्पादन बहुत ही कम हो गया। विदेशी विनिमय सम्बन्धी कठिनाइयों और कोयले के अभाव ने जापान की लोहा व इस्पात उत्पादन क्षमता को मुख्य रूप से घटका पहुँचाया।

अमेरिकन सैनिक नियन्त्रण के दौरान, अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और साम्यवाद के भूत के भय से, जापान का आर्थिक पुनरुद्धार आवश्यक समझा गया। अमेरिका ने कच्चे माल के आयात के लिए जापान को काफी आर्थिक सहायता दी। देश में ही उपलब्ध स्क्रैप माल को भी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए काम में लाया गया। उद्योग का पुनर्विकास 1947 के बाद ही होने लगा। 1950 में कच्चे लोहे का उत्पादन 22 लाख टन से कुछ अधिक था जो बढ़कर 1960 में 119 लाख टन, 1971 में 475 लाख टन, 1974 में लगभग 930 लाख टन और 1977 में लगभग 1150 लाख टन हो गया। तैयार इस्पात का उत्पादन 1950 में लगभग 48 लाख टन था जो बढ़कर 1960 में लगभग 221 लाख टन, 1971 में लगभग 575 लाख टन और 1977 में लगभग 1450 लाख टन हो गया।

जापान का लोहा और इस्पात उद्योग कच्चे लोहे तथा कोयला पर आधारित है

जिसका कि उसे विदेशों से आयात करना पड़ता है यह आयात मुख्यतः मत्तया, भारत, अमेरिका आदि देशों से किया जाता है। जापान आज ससार में रूस व अमेरिका के बाद सबसे बड़ा लोहा और इस्पात उत्पादक देश है। अमेरिका, रूस और भारत को भी वह अपने लोहे और इस्पात का निर्यात करता है। जापान की प्रथम-व्यवस्था में इस उद्योग का महत्त्व इसी तथ्य से स्पष्ट है कि कुल उत्पादन मूल्य में लोहा-इस्पात का मूल्य लगभग 9 प्रतिशत और कुल निर्यात में इसका लगभग 17 प्रतिशत भाग है। इस उद्योग की सफलता के लिए मुख्य उत्तरदायी कारण हैं—

(1) सस्ते जल-विद्युत का प्रयोग, (2) कुशल और सस्ते श्रम की उपलब्धि, (3) एशिया के दक्षिणी-पूर्वी देशों का बाजार उपलब्ध होना, (4) जल-परिवहन का विकसित और सस्ता होना, (5) वैज्ञानिक प्रगति, (6) कच्चे माल को विकसित जहाजरानी की सहायता से बाहर से मंगा लेना, एवं (7) सरकार का पूरा संरक्षण।

कोयला उद्योग

(Coal Industry)

मेजी पुनर्स्थापन काल से जापान में आर्थिक प्रगति के जो द्वार खुले, उसमें खनिज उद्योग भी अग्रगण्य न रहा। विशेषकर कोयला उद्योग में काफी प्रगति हुई। मेजी शासन काल में कोयले की खानें छोटी थीं और अधिकांश उत्पादन जैबत्सु के अन्तर्गत कुछ फर्मों द्वारा किया जाता था।

प्रारम्भ में कोयले का उत्पादन बहुत कम रहा, लेकिन औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ इस दिशा में उत्साहप्रद वातावरण बना। 1894 के बाद धरेनू बाजार के विस्तार के साथ कोयले की माँग तेजी से बढ़ी और उसके उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी। सन् 1913 में स्थिति यह थी कि जापान के कुल खनिज उत्पादन के मूल्य में आधे से अधिक भाग केवल कोयले का था।

1914 से 1937 तक का काल—प्रथम महायुद्ध के दौरान कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। लेकिन बाद में उत्पादन की दर ऊँची नहीं रह सकी। इसी बीच कोयले की आन्तरिक खपत में भारी वृद्धि हुई, किन्तु कोयले का उत्पादन इतना नहीं हो सका कि माँग को पूरा किया जा सके। फलस्वरूप अतिरिक्त खपत की पूर्ति विदेशों से कोयला मगाकर करनी पड़ी। तीसरे दशक में कोयले के उत्पादन में धीरे-धीरे मजबूती से वृद्धि होने लगी और 1937 तक उत्पादन 1913 के मुकाबले दुगुने से भी अधिक हो गया। थोड़ा बहुत कोयला निर्यात भी किया जाने लगा, फिर भी कोयले का आयात पूरी तरह बन्द नहीं हो सका। विशेषतः कोकिंग कोयला बाहर से मगाया जाता रहा क्योंकि इस प्रकार के कोयले का जापान में अभाव है। इस तरह, इस अवधि में कोयला उद्योग के सन्तुलन की दृष्टि से जापान में कोयले का आयात ही महत्त्वपूर्ण रहा।

द्वितीय महायुद्ध काल और बाद का समय—द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में कोयले का उत्पादन बढ़ता रहा। लेकिन बाद में मित्र राष्ट्रों की भीषण बम वर्षा ने जापान के सभी उद्योगों पर विनाशकारी चोट की। फलस्वरूप कोयले के

उत्पादन में कमी आ गई और खनिज श्रमिक भी तितर-बितर हो गए। महायुद्ध के अन्त में जापान द्वारा मिन राष्‍ट्रीय फौजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया गया।

प्रारम्भ में अमेरिकन सैन्य प्रशासन ने जापान के पुनरुत्थान में कोई विशेष रूचि नहीं ली। 1947 में कोयले का उत्पादन युद्ध पूर्व के स्तर से लगभग आधा था। 1947 के बाद, साम्‍यवाद के प्रसार के भय से और अन्य विभिन्न राजनीतिक कारणों से विवश होकर अमेरिकन सैन्य प्रशासन ने जापान के पुनरुत्थान का कार्यक्रम बनाया। फलस्वरूप सभी उद्योगों की धीरे-धीरे उन्नति होने लगी। 1952 में शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद जापान ने पुन स्वाधीनता की सांस ली। 1950 में कोयले का उत्पादन लगभग 385 लाख टन तक बढ़ाया गया और 1953 तक कोयले का उत्पादन युद्ध-पूर्व के स्तर से भी आगे निकल गया। 1955 में लगभग 425 लाख टन कोयला-उत्पादन हुआ। 1963 में कोयले का उत्पादन लगभग 510 लाख टन तक पहुँच गया। किन्तु खनिज यन्त्रों की कमी पड़ जाने से तथा अर्थव्यवस्था के कोयला खनिजों की समाप्ति के कारण कोयले का उत्पादन पुन घटने लगा। विभिन्न कठिनाइयों की वजह से जापानी कोयले की कीमतें भी विदेशों के मुकाबले अधिक ऊँची हो गईं। 1977 में कोयले का उत्पादन 1950 के स्तर से भी नीचे पहुँच गया। इस वर्ष उत्पादन लगभग 370 लाख टन रहा। जापान की 45 से भी अधिक खानें, तोकेदो हांसू और क्यूशू प्रदेश में फैली हुई हैं। क्यूशू क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें देश का लगभग एक-तिहाई भाग कोयला खोदा जाता है। जापान अपनी आवश्यकता का लगभग 25 प्रतिशत कोयला ही उत्पन्न कर पाता है। जापान ने काफी पहले से ही यह समझ लिया था कि कोयले की कमी नये उद्योगों की प्रगति के लिए खतरा पैदा करेगी, अतः वह जल-विद्युत के विकास पर ध्यान देने लगा। आज जल-विद्युत शक्ति का प्रयोग जापान में जितना अधिक किया जाता है उतना सम्भवतः इने-गिने देशों में ही होता है। जल-विद्युत शक्ति आधुनिक जापान की अर्थ-व्यवस्था का आधार है पर इसका आशय यह नहीं है कि कोयले पर जापान की निर्भरता समाप्त हो गई है। जब कभी वर्षा अपर्याप्त रहती है तो कोयले पर निर्भरता विशेष रूप से बढ़ जाती है। इसके अनिश्चित कोयले की ऊँची कीमत विद्युत-उत्पादन की लागत को भी प्रभावित करती है।

जहाज-निर्माण उद्योग

(Ship Building Industry)

जापान ने जहाज-निर्माण उद्योग में आश्चर्यजनक प्रगति की है। आज का जापान दुनिया के साथे तेलवाहक जहाज बनाता है। दस करोड़ की आबादी का टापुघो पर बसा यह देश विश्व के कुल जहाजों उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत भाग अथवा उत्पादन करता है। जहाज निर्माण का जापानी उद्योग सदियों प्राचीन है, किन्तु इसके वास्तविक विकास का युग मेजो पुनर्स्थापन के समय से ही शुरु होता है।

प्रारम्भिक इतिहास—तोकुगावा शासन से भी पहले जापान का जहाज उद्योग

उन्नत था और चीन तथा दक्षिणी एशिया के सामुद्रिक सम्बन्ध थे, लेकिन तोकुगावा शासकों ने जापानियों के सामुद्रिक सम्पर्कों को हतोत्साहित किया और जापान को शेष विश्व से अलग-थलग रखने की नीति अपनाई। यह प्रतिबन्ध लगा दिया कि 50 टन से अधिक की क्षमता वाला कोई जहाज न बनाया जाए। तोकुगावा शासन की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि जापानियों की जहाज निर्माण कला अवनत होने लगी और सामुद्रिक शक्ति के रूप में जापान की कमजोरी प्रकट होने लगी। अतः जहाज-निर्माण पर लगाए प्रतिबन्ध उठा लिए गए और बड़े जहाजों के निर्माण की आज्ञा दे दी गई। 1854 से 1859 के दौरान योकोसुके (Yokosuke) में प्रथम शिपयार्ड बनाया गया और नागामाकी मण्डल में एक नौ-बहन स्कूल आरम्भ किया गया। इस स्कूल में 22 डच लोगों को अध्यापकों के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार मेजी पुनर्स्थापन से पहले ही जापान में जहाज-निर्माण उद्योग की आधारशिला रख दी गई, यद्यपि वास्तविक विकास 1868 के बाद ही प्रारम्भ हुआ।

1868 से 1913 तक का काल—मेजी पुनर्स्थापन के तुरन्त बाद ही सुरक्षात्मक और व्यापारिक दृष्टि से जहाज-निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। सरकार ने इस दिशा में 1870 में मर्केन्टाइल मेराइन लाँ (Mercantile Marine Law) पास करके पहला प्रभावशाली कदम उठाया और 'कैशो-कैशा' (Kaiso-Kaisha) यातायात कम्पनी स्थापित हुई। इस पर सरकार का आंशिक नियन्त्रण था और इसे सरकारी सहायता भी प्राप्त थी। अगले कुछ वर्षों में अनेक छोटी निजी कम्पनियाँ भी अस्तित्व में आ गईं जो सरकारी समर्थन से कुछ बड़ी कम्पनियाँ के रूप में गठित कर दी गईं।

यद्यपि मेजी शासन के प्रारम्भिक वर्षों में सरकारी व निजी क्षेत्र ने जहाज निर्माण उद्योग में काफी रुचि ली, लेकिन शताब्दी का अन्त होने तक उत्पादन बहुत कम रहा। आधुनिक ढंग का पहला लोहे का जहाज तो 1871 में ही बना लिया गया, लेकिन इस्पात का पहला जलपोत 1890 में जाकर ही बनाया जा सका। 1895 में जाकर जापानी शिपयार्डों में ने पहला ऐसा जहाज समुद्र में उतारा गया जिसका भार एक हजार टन से अधिक था। इस समय तक भी जापान अपनी जहाजी आवश्यकताओं के लिए विदेशों से आयात पर ही निर्भर था वैसे इस समय तक अर्थात् 1895 में जापान के पास लगभग 147 वाण जहाज हो चुके थे जिनका कुल टनेज 164, 454 था।

जहाज निर्माण के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात 1896 के 'जहाज-निर्माण प्रोत्साहन अधिनियम' (Ship-building Encouragement Act) द्वारा हुआ। जी सी एलन के अनुसार, "इस अधिनियम में कुल सात सौ टन या इससे ऊपर के लोहे और इस्पात के जहाज बनाने के लिए सरकारी आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई।" इस अधिनियम के अस्तित्व में आने के फलस्वरूप अनेक नए सामुद्रिक जहाज-निर्माण केन्द्रों अथवा शिपयार्डों की स्थापना हुई और मौजूदा

शिपयार्डों का विस्तार किया गया। सन् 1899 में एक अन्य शोधन अधिनियम द्वारा जहाज निर्माण के कार्य को और अधिक प्रोत्साहन दिया गया। आगे चलकर 1909 में आर्थिक सहायता की दृष्टि में पुनः वृद्धि की गई।

इन सब प्रयासों के परिणामस्वरूप जापान ने जहाज निर्माण उद्योग में काफी प्रगति कर ली। प्रथम महायुद्ध के ठीक पहले के वर्षों में जापानी जहाज-निर्माण केन्द्र पुद्धपोनो का निर्माण करने में सक्षम हो गए। सन् 1913 तक ऐसे 6 जहाज-निर्माण केन्द्र अस्तित्व में आ गए जो एक हजार टन अथवा इससे अधिक वजन के जहाजों का निर्माण कर सकते थे। इनके अतिरिक्त और भी अनेक छोटी-छोटी निर्माण स्थापनाएँ थीं। जहाँ दशवें दशक के अन्त तक समुद्र में उतारे गए बाष्प पोतों का कुल वार्षिक औसत टन भार दस हजार से कम था वहीं 1909 से 1913 के बीच यह बढ़कर 50 हजार टन से भी अधिक हो गया। समुद्र में उतारे गए पाल-चालित पोतों के वार्षिक औसत टन भार में भी काफी वृद्धि हुई। यह 1913 तक लगभग 20 हजार टन हो गया।

1914 से 1936 तक का काल—प्रथम महायुद्ध से ठीक पूर्व जापान में लगभग 1,528,000 टन के 3,286 बाष्प जहाज थे। प्रथम महायुद्ध के दौरान जापान का जहाज-निर्माण उद्योग और विदेशी व्यापार बहुत फला फूला क्योंकि जापान को पूर्वी देशों में वृहद् बाजार हाथ लगा। युद्ध काल में जापानी माल की माँग तेजी से बढ़ती गई जबकि दूसरी ओर यूरोपीय राष्ट्रों के जहाज युद्ध में व्यस्त रहे। इन दोनों बातों का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि जापानी जहाजरानी की माँग काफी बढ़ गई। जी सी एलन के अनुसार, “जापान के ‘शिप-यार्डों’ (Ship-yards) से सन् 1914 में समुद्र में उतारे गए जहाजों का जो टन भार केवल 85 हजार टन था, वह सन् 1919 में कुल मिला कर 650 हजार टन हो गया।” जापानी जहाज सभार के सभी समुद्रों में दूर-दूर के देशों तक आने-जाने लगे। दुश्मन के छतरे का सामना उठाकर भी जापानी जहाज माल लाते, ले जाते रहे। घरेलू जहाज उद्योग भी काफी सुदृढ़ हुआ। एक अध्ययन के अनुसार, 1918 में युद्ध की समाप्ति तक जापान के पास कुल 2,337,000 टन के 4,755 बाष्प-चालित जहाज थे।

युद्धोत्तर काल में जापानी जहाज-निर्माण उद्योग की प्रगति मन्द पड़ गई। जापानी नव-वहन की लायत अन्य राष्ट्रों की तुलना में अधिक थी। मन्दी की गुरुभात हो जाने व सस्ती विदेशी प्रतियोगिता के कारण इस उद्योग को काफी धनि पहुँची। इस अवधि में एक हजार टन से अधिक टन के जहाजों का निर्माण कर सकने वाले जहाज निर्माण केन्द्रों में अधिकांश की संख्या लगभग दो तिहाई कम हो गई। सन् 1929 का वर्ष पूर्ववर्ती वर्षों से अच्छा था, किन्तु उस वर्ष भी समुद्र में उतारे गए व्यापारी जहाजों का टन भार केवल 165,000 ही था। जापानी जहाजों की किस्म भी बढ़िया नहीं रह सकी। महान मन्दी काल में इस उद्योग को काफी धक्का लगा।

मन्दी काल के घाव शीघ्र ही भर गए और सरकारी प्रोत्साहन के परिणाम-स्वरूप जहाज-निर्माण उद्योग में फिर तेजी से विकास होने लगा। 1931 से ही यह वृद्धि शुरू हो गई। जापान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की पुनः प्राप्ति और 'मिटावो तथा बनावो' योजना के कारण जहाजी उद्योग तेजी से पनपा। 'मिटावो व बनावो' योजना के अन्तर्गत पुराने जहाजों को नष्ट करने और नए व आधुनिक जहाजों का निर्माण करने की नीति अपनाई गई। यह योजना पूरी तरह सफल हुई। 1934 में एक नई योजना के अन्तर्गत जहाजों का निर्माण काफी तेज कर दिया गया। सरकार द्वारा उद्योग को काफी आर्थिक सहायता दी गई।

इन सब प्रयासों का यह स्वाभाविक परिणाम हुआ कि जापानी जहाज निर्माण उद्योग बहुत उन्नत हो गया। जी सी एलन के शब्दों में, "दिसम्बर 1931 में मुख्य पोत निर्माण प्रांगणों में श्रमिकों की संख्या 34,000 थी, वह सन् 1936 में बढ़कर 51,000 हो गई। सन् 1932 में समुद्र में उतार गए व्यापारी पोतों का टन भार कुल 54,000 था, जो सबसे कम था। इसकी तुलना में सन् 1937 में यही टन भार कुल 446,000 हो गया। सन् 1919 से लेकर अब तक समुद्र में उतारे गए पोतों के टन भार से बहुत अधिक था। इस उद्योग को नौ-पोत निर्माण के पुन आरम्भ से ही लाभ हुआ। सन् 1937 तक जापान के पास 8 व्यापारी पोतों का कुल टन भार 4,500,000 था। इस समय जापान का व्यापारी जहाजी बेड़ा संसार में तीसरी श्रेणी पर था और इस बेड़े में अधिकांश नए पोत ही थे।" ज्योज्यो द्वितीय महायुद्ध सत्रिकट होता गया, जापानी जहाजों की क्षमता बढ़ती गई।

द्वितीय महायुद्ध काल और बाद का समय—द्वितीय महायुद्ध काल के प्रारम्भिक वर्षों में जापानी जहाज निर्माण उद्योग की क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई। यौद्धिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जहाजरानों का अधिकाधिक विकसित और सुदृढ़ होना आवश्यक था, लेकिन बाद में शत्रु की कम वर्षों में जापानी औद्योगिक संस्थानों को तहस-नहस करना शुरू कर दिया। युद्ध के समाप्त होने तक जापान का जहाज-निर्माण उद्योग लगभग विनिष्ट हो चुका था। जापान के लगभग सभी सामुद्रिक जहाज मित्र राष्ट्रों की कारवाइयों द्वारा डूबो दिए गए थे। जापान की अधिकांश मशीनरी और उसके कारखाने मिट्टी में मिल चुके थे। उसकी सारी औद्योगिक प्रगति दर्दनाक मौत का शिकार बन चुकी थी।

महायुद्ध के बाद जापान प्रत्यक्ष रूप से अमेरिकन सैनिक प्रशासन की अधीनता में आ गया। उसका यह पराधीनता-काल 1945 से 1952 तक रहा। युद्धोत्तर काल के प्रारम्भिक वर्षों में जापान की दयनीय दशा और नियन्त्रणकारी शक्तियों के प्रतिबन्धों के कारण, अन्य उद्योगों के समान ही, जहाज-निर्माण उद्योग भी पुनरुद्धार की दिशा में आगे नहीं बढ़ सका।

1948 तक जापान को केवल छोटे तटीय जहाज बनाने की ही आज्ञा दी गई परन्तु शीघ्र ही जापान के प्रति मित्रराष्ट्रों की नीति में परिवर्तन आया और सन् 1950 के आते-आते जापान के आर्थिक पुनरुद्धार की नींव जमने लग गई। कोरिया-

युद्ध ने जापान के जहाज-निर्माण उद्योग को गति दी। अब बड़े-बड़े सामुद्रिक जहाज पुनः बनाए जाते लगे। 1952 में शान्ति-सन्धि पर हस्ताक्षर होने के बाद जापान पुनः एक स्वाधीन राष्ट्र बन गया। अब जापानी जहाज निर्माण उद्योग ने आश्चर्य-जनक तेजी से प्रगति की। 1956 तक जापान विश्व का सबसे बड़ा जहाज निर्माणा देश बन गया। जो जापान महायुद्ध काल में अविनाशित राष्ट्र का ढेर बन गया था, उसने हर क्षेत्र में अपना पुनर्निर्माण इतनी तेजी से किया कि दुनिया चकित रह गई। 1957 में जापान ने लगभग 24,33,000 टन भार के सामुद्रिक जहाजों का निर्माण किया जो विश्व के कुल उत्पादन का प्रायः 29 प्रतिशत भाग था। सन् 1965 में जापान ने 53,63,000 हज़ार टन-भार के सामुद्रिक जहाज बनाए। जापान का यह जहाजी उत्पादन उस समय विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 43.9 प्रतिशत था। जापान के शिपयार्ड में विश्व का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ जलयान तैयार किया गया है। जापान ही दुनिया का पहला राष्ट्र है जिसने अपने जलयान में औद्योगिक माल की प्रदर्शनी आरम्भ की। जापान की जहाज निर्माण क्षमता 1959 में 20 लाख टन से बढ़कर 1969 तक लगभग 90 लाख टन हो गई अर्थात् 10 वर्षों में ही जहाज उत्पादन में लगभग साढ़े चार गुना वृद्धि हुई। सन् 1971 तक जापानी जहाजरानी क्षमता लगभग 126 लाख (GRT) तक पहुँच गई जो भारत की वर्तमान क्षमता से भी लगभग चौगुनी थी। 1973-74 में जापान ने लगभग 162 लाख (GRT) क्षमता के जलयान तैयार किये और उनमें से 75 प्रतिशत से भी अधिक का निर्यात कर दिया गया। इसके पूर्व सन 1972 में जापान ने विश्व का सबसे बड़ा तेजवाहक जहाज ग्लोबटिक टोकियो (Globtic Tokiyo) समुद्र में उतारा। यह जहाज 4.77 लाख (DWT) का है। इसके बाद साढ़े पाँच-पाँच (GRT) क्षमता के दो और विशाल तेलवाहक जहाज बनाये गये। सन् 1977 में जापान ने लगभग 190 लाख (GRT) क्षमता के जलयान बनाये, जिनकी संख्या अनुमानितः लगभग 980 थी। जापान प्रतिवर्ष 900 से 1000 जलयानों का निर्माण करता है। अगस्त, 1977 में जापान ने 5-1 लाख (DWT) क्षमता के 406 मीटर लम्बे, 71 मीटर चौड़े और 68 मीटर ऊँचे तेलवाहक जहाज समुद्र में उतारा। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जलयान है। विश्व में जहाज-उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत भाग अकेला जापान उत्पन्न करता है। 1977 में सम्पूर्ण विश्व ने लगभग 380 लाख टन के जलयान अकेले जापान ने बनाये थे। संख्या की दृष्टि से 1977 में लगभग 2850 जहाज सम्पूर्ण विश्व में बने थे जिनमें से लगभग 980 जहाज अकेले जापान ने बनाये थे। जापानी जहाज निर्माण उद्योग की वर्तमान प्रवृत्ति तेलवाहक जहाज और बड़े जलयानों के बनाने की है।

जहाज-निर्माण की प्रगति के कारण

जापान में छोटे-बड़े कुल लगभग 300 शिपयार्ड हैं जिनमें से 40 शिपयार्ड तो बहुत विशाल आकार के हैं। नागासाकी, मीजी, याकोहावा, तोक्यो, ओसाका,

कोबे, शिमोनेसेकी, तामाशिया आदि अत्यन्त विशालकाय शिपयार्ड है और भी नये-नये शिपयार्ड विभिन्न स्थानों पर विकसित किये जा रहे हैं ।

जापान जहाज निर्माण के क्षेत्र में सबसे आगे इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि यहाँ इन उद्योग के लिए निम्नलिखित विशेष सुविधायें उपलब्ध हैं—

(1) जापान एक द्वीपीय देश है अतः यहाँ के निवासी नाविक कला में काफी दक्ष हैं । -

(2) जापान के तट बहुत अधिक कटे-फटे हैं । यहाँ विस्तृत आश्रय वाले बन्दरगाह हैं जहाँ जलपोत बनाने के यार्ड बनाए जा सकते हैं ।

(3) जापान की जलवायु यद्यपि शीतल है, किन्तु समुद्र के पास की गर्म जलधारा जापान के तटों को जमने नहीं देती ।

(4) जापान एक व्यापारिक और औद्योगिक देश है जिसे बहुत-सा कच्चा माल बाहर से मगाना और तैयार माल बाहर भेजना पड़ता है । व्यापारिक जलयान बेड़ की सदा से आवश्यकता रही है । फलस्वरूप इस बेड़ के विकास को निरन्तर प्रेरणा मिली है ।

(5) जापान में अपने निर्मित माल बाहर भेजने के लिए अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की महत्त्वाकांक्षा सदैव रही है । अतः शक्तिशाली नौ-सेना के विकास में आगे बढ़ने की सगन के कारण जहाज-निर्माण उद्योग का विकास अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुआ है ।

रासायनिक उद्योग (Chemical Industries)

जापान के इस महत्त्वपूर्ण उद्योग का विवरण कालक्रम की दृष्टि से निम्न-लिखित भागों में देना उपयुक्त होगा—

प्रारम्भिक इतिहास—जापान के इस उद्योग की आधारशिला भी मेजी शासन काल में पड़ी । प्रथम महायुद्ध से लगभग 30 वर्ष पूर्व जापान में इस उद्योग का विकास प्रारम्भ हुआ । उस समय रासायनिक उद्योगों में सीमेन्ट ग्लास एव उर्वरक उद्योग, सूगर रिफाइनिंग उद्योग आदि सम्मिलित थे । ये रासायनिक उद्योग जैबत्सु (Zaibatsu) (जापान के महान धनी सेठ परिवार) की प्रेरणास्वरूप अस्तित्व में आए । इन जैबत्सु अथवा जापान के धनी सेठ परिवारों को सरकारी सुरक्षण प्राप्त था । कुछ रासायनिक उद्योगों ने यद्यपि अल्पकाल में ही काफी प्रगति कर ली, जापान की रासायनिक वस्तुओं की माँग पूरी करने में ये उद्योग असफल रहे । वास्तव में 1930 तक रासायनिक उर्वरकों और अन्य रासायनिक उत्पादनों के सम्बन्ध में जापान को बहुत कुछ विदेशी आयातों पर निर्भर रहना पड़ा । फिर भी 1920 से 1930 की अवधि में रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । जहाँ 1914 में रासायनिक माल 176 मिलियन येन का हुआ वहाँ 1925 में 757 मिलियन येन और 1930 में 924 मिलियन येन का हुआ ।

1930 से 1939 तक का काल—इस अवधि में रासायनिक उद्योगों में सभी शाखाओं में उत्पादन तेजी से बढ़ा । औद्योगिक और शस्त्रास्त्र सम्बन्धी

क्षेत्र की अधिकाधिक प्रगति के कारण रासायनिक उत्पादनों की माँग में वृद्धि हुई। 1930 से 1939 के बीच रासायनिक उद्योग की कुछ शाखाओं ने उत्पादन में द्रुगुनी-त्रिगुनी वृद्धि कर दिखाई। मूल्य की दृष्टि से जहाँ 1930 में रासायनिक उत्पादन लगभग 924 मिलियन येन के हुए थे वहाँ 1933 में 1288 मिलियन येन के हुए। महायुद्ध से पूर्व रासायनिक उद्योग में तकनीकी और उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न सुधार किए गए। अमोनियम सल्फेट तथा अन्य रासायन व्यापारों के सयत्रों के मानों में वृद्धि हुई तथा लागते कार्फों घट गईं।

द्वितीय महायुद्ध काल और बाद का समय—महायुद्ध काल में रासायनिक उद्योग भी विनाश का शिकार बना, पर युद्धोत्तरकाल में जब जापान आर्थिक पुनरुद्धार की दिशा में आगे बढ़ा तो सबसे पहले अमोनियम सल्फेट उद्योग के भाग्य जागे। खाद्य उत्पादन सम्बन्धी हितों को ध्यान में रखते हुए इस उद्योग को प्राथमिकता और आवश्यक आर्थिक सहायता दी गई। सन् 1949 में इस उद्योग ने इतनी तरक्की कर ली कि यह युद्ध पूर्व स्तर से अधिक उत्पादन करने लगा। 1955 के आते-आते उर्वरकों के क्षेत्र में जापान एक निर्यातक देश बन गया।

रासायनिक उद्योग आज जानान की औद्योगिक गतिविधि का एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिछले कुछ वर्षों में, कुछ चीजों के अलग-अलग उत्पादन में प्रति वर्ष औसतन 14 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। मूल रासायनिक कच्ची सामग्री—जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोनाट सोडा—के क्षेत्र में जापान की गिनती आज दुनिया के चार सबसे बड़े उत्पादकों में होती है।

पेट्रोलियम, लवण, पोटेशियम लवण, फॉस्फेट अयस्क तथा तेलों और बसाओं जैसे अनिवार्य कच्चे माल के अभाव में भी इस उद्योग ने विलक्षण गति से अपना विकास किया है। ये सब चीजें उसे विदेशों से मगानी होती हैं।

पिछले दशक से इस उद्योग के ढाँचे में बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। एक तो शैल-रासायनिक उद्योग का विकास हुआ है दूसरे उत्पादन के क्षेत्र में अप्रहृ रासायनिक उर्वरकों तथा औद्योगिक सोडा रासायनों के बजाय सश्लिष्ट कार्बनिक-रासायनों पर हो गया है।

1955 में, शैल-रासायनिक उद्योग का निर्माण करने के लिए 8,20,000 लाख येन का एक पंचवर्षीय कार्यक्रम आरम्भ किया था। उत्पादन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई। 1957 में 17,390 लाख येन के मूल्य का उत्पादन हुआ था और 1964 में वह बढ़कर 16,56,300 लाख येन के मूल्य का हो गया। 1960 में दूसरा विकास-कार्यक्रम लागू किया गया और 1970 तक जापान के कुल रासायनिक उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन शैल-रासायनिक चीजों का हो गया। जहाँ तक बित्री का सवाल है 1969 तक शैल रासायनिक उद्योगों की चीजों की, बित्री बढ़कर लगभग 77,00,000 लाख येन हो गई।

जापान का रासायनिक उद्योग निरन्तर प्रगति करता रहा है। 1960 के आठार वर्ष के अनुसार रासायनिक उद्योग का उत्पादन सूचकांक 1965 में लगभग 208 से बढ़कर 1969 में लगभग 374 हो गया। 1977 में जापान में अनुमानित

180 लाख टन मीट्रिक टन रासायनिक पदार्थों का उत्पादन किया गया। जापान के रासायनिक उद्योग का भविष्य उज्वल है और वस्त्र एवं लोहा-इस्पात उद्योग के बाद रासायनिक उद्योग की गणना की जाती है। जापान के रासायनिक उद्योग देश की समग्र औद्योगिक पेट्री के समानान्तर फैला हुआ है तथापि केन्द्रीयकरण की दृष्टि से तोक्यो, ओसाका, कोबे आदि क्षेत्र अग्रणी हैं। जापान प्रतिवर्ष लगभग 60 से 70 करोड़ येन मूल्य के रासायनिक पदार्थों का निर्यात करता है। जापान के कुछ निर्यात में इस उद्योग के निर्यात का भाग लगभग 6 प्रतिशत है।

जापान में रासायनिक उद्योग की तीव्र प्रगति में जिन कारणों ने सहयोग दिया है उनमें कुछ मुख्य यह हैं—(1) सस्ती एवं पर्याप्त शक्ति का उपलब्ध होना, (2) जापानी उद्योगी और गहन कृषि के लिए उर्वरकों, पीच-संरक्षण औषधियों आदि के लिए आन्तरिक माँग में वृद्धि, (3) सरकार की उदार एवं सहयोगी नीति, (4) सरकार द्वारा वैज्ञानिक शोध एवं अनुसंधान का प्रदर्शन, (5) कच्चे माल की समुचित पूर्ति, यथा—समुद्र से नमक, ज्वालामुखी क्षेत्रों से गन्धक बनो से कोलतार, पानी, कोयला आदि।

मोटर उद्योग

(Automobile Industry)

संयुक्तराज्य अमेरिका यदि मोटर उद्योग का राजा है तो जापान उसका वजीर है। आज जापान का स्थान मोटर उत्पन्न की दृष्टि से अमेरिका के बाद दूसरा है। मोटर उद्योग के क्षेत्र में जापान ने जो आश्चर्यजनक प्रगति की है उसे देखते हुए यह असम्भव नहीं लगता कि निवट भविष्य में वह अमेरिका को टक्कर देने लगेगा।

जापानी मोटर उद्योग का प्रारम्भ 1907 में छोटे पैमाने पर हुआ। 1927 में जापान कुल 136 मोटरों बना सका। मोटरों के ढाँचों और इजिनो का आयात अमेरिका से होता था जबकि अन्य भागों (Parts) का निर्माण जापान में ही कर लिया जाता था। जापानी मोटर उद्योग को तब भारी प्रेरणा मिली जब 1936 में सरकार ने इसे संरक्षण प्रदान करते हुए उत्पादन शक्ति 500 मोटर प्रतिवर्ष निर्धारित कर दी। मोटर उद्योग प्रगति करता गया। सन् 1941 में लगभग 43 हजार मोटरें बनाई गईं। महायुद्ध काल में मोटरों के स्थान पर वायुयान निर्माण को अधिकाधिक प्राथमिकता दी जाने लगी और 1944 के आते-आते सवारी गाड़ियों का उत्पादन बन्द-सा हो गया। आरम्भसमय के बाद भी वर्षों तक जापान मोटर उद्योग का पुनरुद्धार नहीं कर सका। 1949 तक इस उद्योग की अवस्था शोचनीय बनी रही। सन् 1956 में छिड़ने वाले कोरिया युद्ध के फलस्वरूप मोटर उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला। इसके बाद यह उद्योग तेजी से पुनपता गया। सन् 1967 में जापान ने चार पहियों वाली लगभग 34 लाख गाड़ियों का उत्पादन किया। तीन पहियों वाली गाड़ियों का उत्पादन इससे अलग था। 1960 से 1965 के दौरान मोटर गाड़ियों के निर्यात में भी लगभग 15 गुनी वृद्धि हुई। उल्लेखनीय है कि

जापानी मोटरे छोटी होती हैं जिनमें प्रायः 10 अश्व शक्ति के इंजिन लगते हैं। तीन पहिये वाली गाड़ियाँ सामान्य ढाँच के काम आती हैं। इधर कुछ वर्षों की उपलब्धि यह भी है कि जापानी गाड़ियों के तकनीकी स्तर बराबर ऊपर उठते गए हैं। अब तक निर्माता कबल इस बात की ध्यान देते थे कि उनमें मार्ग योम्यना कितनी है और वे टिकाऊ कितनी हैं, किन्तु अब जापान की सड़कें पहले से बहुत अच्छी हो गई हैं इसलिए वे उनकी गति और त्वरण क्षमता पर ईंधन की बचत पर, आरामदेह ढाँच तथा बाहर और भीतर के डिजाइनों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। जापान में मोटर गाड़ियाँ बनाने की दृष्टि से कितनी प्रगति हुई है इसकी एक शानदार मिसाल यह है कि 1965 में मैक्सिको की ग्रैंड प्री में दौड़ने वाली कारों के मुकाबले में जापान की होंडा फामला प्रथम की जीत हुई थी। जापानी मोटर उत्पादन ने 1959 से 1969 की दस वार्षिक अवधि में मोटर-गाड़ी उत्पादन में लगभग चालीस गुना वृद्धि की है। 1959 में जहाँ दस लाख मोटर गाड़ियाँ बनाने की क्षमता थी वहाँ 1969 में चालीस लाख गाड़ियाँ प्रतिवर्ष बनाने की क्षमता हो गई। 1977 में लगभग 85 लाख मोटर गाड़ियों का उत्पादन किया गया। जापानी मोटर उद्योग का भविष्य बहुत उज्ज्वल है और यह जापान का प्रमुख उद्योग बन गया है। जहाँ 1966 में जापान ने लगभग 93 लाख मोटर गाड़ियाँ पजीकृत की थी वहाँ 1976-77 में पजीकृत मोटर वाहनों की संख्या 355 लाख तक पहुँच गई। जापान में प्रति 3-6 व्यक्तियों के पीछे एक कार है। जापान अपने मोटर उत्पादन का लगभग आधा भाग निर्यात कर देता है। 1977 में लगभग 85 लाख मोटर वाहनों का उत्पादन हुआ जिनमें से लगभग 40 लाख का निर्यात किया गया था।

इंजीनियरिंग उद्योग

(Engineering Industry)

जापान के इंजीनियरिंग उद्योग की नींव भी मेजी पुनसंस्थापन के समय ही पड़ी। अतः तभी से विभिन्न कालों में इसके विकास का बखूबी करना उपयुक्त होगा।

प्रथम महायुद्ध से पूर्व तक—मेजी सरकार ने राजनीतिक कारणों से इंजीनियरिंग उद्योग को बढ़ावा दिया, तथापि वह 1930 तक समुचित आकार ग्रहण नहीं कर सका। उद्योग की एक शाखा जहाज निर्माण की थी जिसने अपेक्षाकृत अधिक उन्नति की। आठवें दशक में शिबाउरा इंजीनियरिंग वर्क्स (Shibaura Engineering Works) की स्थापना हुई। इस संस्थान में—सामान्य इंजीनियरिंग के काम के अलावा विद्युत् मशीनरी और औजारों का उत्पादन भी किया जाने लगा। लगभग इसी समय और भी कई फर्मों ने इस उद्योग में प्रवेश किया। सन् 1906 में रेलवे के राष्ट्रीयकरण के बाद रेल सामग्री का उत्पादन काफी बढ़ा। 1908 में रेल कारखाने का निर्माण हुआ। 1910 के बाद विद्युत् शक्ति उत्पादन की संख्या बढ़ी और जल विद्युत् शक्ति का उपयोग किया जाने लगा। टोकियो विद्युत् कम्पनी का पुनर्गठन हुआ तथा 'माजदा' निर्मित किए जाने लगे। इन्सुलेटरो के लिए भी एक कम्पनी की स्थापना की गई। साइकिल उद्योग भी काफी पनप गया।

1914 से 1929 तक का काल—इजीनियरिंग उद्योग की जहाज निर्माण शाला ने प्रथम महायुद्ध के दौरान बहुत अधिक उन्नति की। इजीनियरिंग की अन्य शाखाओं ने भी इस अवधि में काफी प्रगति दिखाई। यह प्रगति मुख्यतः इसलिए हुई क्योंकि एक तो युद्ध के दौरान प्रतियोगिता का अभाव था, दूसरे सप्ताह में गोला बारूद व शस्त्रास्त्रों की अधिक मांग थी तथा तीसरे, जापान का आन्तरिक बाजार भी विस्तृत हो गया था। इन सब कारणों से विद्युत् सामग्री, टैक्सटाइल, मशीनरी और वैज्ञानिक यन्त्रों के अलावा इजीनियरिंग उद्योगों का काफी विस्तार हुआ और 1920 के समाप्त होते-होते जापान इन वस्तुओं का बहुत कम आयात करने लगा फिर भी सम्पूर्ण मशीनरी की दृष्टि से जापान अभी विदेशी स्रोतों पर निर्भर था, क्योंकि उसके औद्योगीकरण के लिए भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार की मशीनरी की आवश्यकता थी।

महायुद्ध के बाद जब मन्दी का दौर शुरू हुआ तो अनेक नये उत्पादक तवाह हो गये, किन्तु इस समय भी, एलन के शब्दों में, “इजीनियरिंग व्यापारों—खासतौर से शक्ति के प्रमुख संचालकों, विजली की मशीनों और यन्त्रों, वस्त्र मशीनरी तथा वैज्ञानिक औजारों से सम्बन्धित व्यापारों की प्रगति होती रही और तीसरे दशक के मध्य से बाद के जापान में ऐसे माल का आयात कम हो गया।”

इस अवधि में साइकिलों के निर्माण का उद्योग महत्वपूर्ण हो गया। सन् 1929 तक जापान ने साइकिलों के पुर्जों का आयात बन्द कर दिया। अपनी साइकिलों की सम्पूर्ण मांग की पूर्ति वह स्वयं करने लगा।

यद्यपि जापान ने इजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी प्रगति कर ली, किन्तु जैसे-जैसे उसका औद्योगीकरण बढ़ता गया, उसकी मशीनों और औजारों की पूर्ति के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भरता भी बढ़ती गई।

मन्दी के मटको को पार करने के बाद महायुद्ध के पूर्व तक इजीनियरिंग व्यापारों ने काफी प्रगति की। जापान में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, किस्म में सुधार और क्षेत्र में विस्तार किया। जहाँ 1929 से पहले दस हजार किलोवाट से अधिक क्षमता के टरबाइनों का आयात होता था वहाँ 1937 तक अधिकांश भाग की पूर्ति घरेलू संसाधनों द्वारा की जाने लगी। इस अवधि के प्रारम्भ में जापान सभी वायलर नलियों का आयात करता था वहाँ इस अवधि के अन्त में वह अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अच्छी किस्म की नलियों का उत्पादन करने लगा। ढलाई की तकनीक में काफी सुधार किया गया। सन् 1932 से पूर्व जापान में बड़ी-बड़ी इस्पात की ढली हुई वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो सकता था, लेकिन 1936 तक यह भली प्रकार सम्भव हो गया। अब इजीनियर इन वस्तुओं को स्थानीय पूर्ति के स्रोतों से ही बिना किसी कठिनाई से प्राप्त कर सकते थे। जापान की इजीनियरिंग श्रमिकों की कार्यकुशलता भी इतनी बढ़ गई कि जहाँ पहले विदेशी विशेषज्ञ उनकी कमियों की शिक्षा देते करते थे वहाँ अब उनके प्रशंसक बन गये।

महायुद्ध काल और बाद का समय—महायुद्ध काल में इजीनियरिंग उद्योग

और भी तेजी से बढ़ा। सन् 1944 में 1937 के मुकाबले तिगुने से अधिक इजीनियरिंग माल उत्पादित होने लगी। यद्यपि महायुद्ध काल में जापान ने कई बड़े इजीनियरिंग संस्थान नष्ट भ्रष्ट हो गये, तथापि युद्ध के बाद भी इस उद्योग में जापान की काफी क्षमता बनी रही। फिर भी कुछ विशेष कठिनाइयों के कारण इस उद्योग का तेजी से पुनरुद्धार कुछ समय के लिए रुक गया। प्रथम तो अमेरिकन सैनिक प्रशासन ने जापान के उन भारी इजीनियरिंग व्यापारों पर प्रतिबन्ध लगा दिए थे जिनसे जापान की सैनिक शक्ति में वृद्धि की सम्भावना थी। दूसरे कच्चे माल का आयात रुक गया। तीसरे आर्थिक अस्थिरता और अराजकता छाई हुई थी। चौथे, इसके संगठन के द्विज मित्र हो जाने से भी इजीनियरिंग उद्योग को धक्का लगा था।

किन्तु शीघ्र ही एक-एक करके सभी समस्याएँ मिटने लगीं। जापान के प्रति अमेरिकन साथी राष्ट्रों की नीति में भी परिवर्तन हुआ। फलस्वरूप इजीनियरिंग उद्योग पुनः चलने लगा। कोरिया युद्ध से इस उद्योग को विशेष गति मिली। जहाज निर्माण शाखा ने सबसे अधिक आश्चर्यजनक उन्नति की, अन्य इजीनियरिंग व्यापारों में भी काफी प्रगति हुई और 1951 में मशीनरी का उत्पादन 1937 के उत्पादन से भी अधिक होने लगा। 1955 तक इजीनियरिंग उद्योग का विस्तार इतना अधिक हो गया जितना 20 वर्ष पहले भी नहीं था।

1955 के बाद जापानी इजीनियरिंग उद्योग का असाधारण गति से विस्तार हुआ। 1955 से 1957 के बीच ही उत्पादन लगभग दुगुना हो गया और आगे भी प्रगति की रफ्तार जारी रही। सन् 1963 के 1955 के मुकाबले 5 गुना और युद्ध पूर्व के स्तर से दस गुना अधिक इजीनियरिंग माल बना। आज यह उद्योग जापान का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। वहाँ इस उद्योग से सम्बन्धित हर प्रकार की वस्तु का भारी मात्रा में उत्पादन होता है।

जापान के मन्त्र-उद्योग का कितना विकास हुआ है, उसमें कितनी विविधता है और उसका कितना ऊँचा तकनीकी स्तर है—इसका प्रमाण दुनिया के प्रायः हर कोने में मिल सकता है। जापानी यादों के बने जहाज आज सातों समुद्रों पर तैरते दिखाई पड़ते हैं। जापानी कैमरों, ट्रांजिस्टर, रेडियो और सिलाई मशीनों के बहुत अरुद्ध होने के बाद आज सभी जानते-मानते हैं और दुनिया के बाजारों में आज उनकी माँग है। जापानी कारें, बसें, सारिया और रेलों के डिब्बे पाँचों महाद्वीपों में परिवहन की आवश्यकताएँ पूरी करने में सहायता दे रहे हैं। जापान के बने बिजली के जनित्र एशिया, आस्ट्रेलिया तथा दक्षिण और उत्तरी अमेरिका के घरो और उद्योगों में बिजली और विद्युत-शक्ति का सम्प्रेषण करते हैं। कताई और बुनाई की जापानी मशीनें एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में कपड़ा-उद्योग के विकास में सहायता कर रही हैं।

कुछ अन्य उद्योग (Some Other Industries)

जापान के कुछ और भी प्रमुख उद्योग हैं जिनमें वह विश्व के अनेक देशों की तुलना में बहुत बड़ा हुआ है।

लकड़ी की लुग्दी और कागज उद्योग (Pulp and Paper Industry)

जापान सम्पूर्ण एशिया में लकड़ी की लुग्दी और कागज बनाने के उद्योग में अग्रणी है। यहाँ अनेक प्रकार का कागज बनाया जाता है क्योंकि कागज के अनेक उपभोगों का यहाँ काफी प्रचार है। उदाहरणार्थ, कागज से रुमाल, तौलिया, छाले, लालटेन, बोरे आदि बनाए जाते हैं। जापान भूकम्पों का देश है, अतः यहाँ भूकानों की भीतरी दीवारों मोटे कागज अथवा गत्ते से बनाई जाती हैं। इस देश में कागज को चमड़े की जगह प्रयोग में लाया जाता है। जापान में लगभग 11.5 लाख मीट्रिक टन बढिया कागज प्रतिवर्ष बनता है।

लुग्दी के उत्पादन में भी जापान काफी आगे है। प्रतिवर्ष लगभग 16 लाख मीट्रिक टन लुग्दी बनाई जाती है, इनमें 60 प्रतिशत रासायनिक लुग्दी होती है। जापान में लुग्दी कागज की अठ्ठाईस मीले होक्काइडो द्वीप में है। लुग्दी के अलावा घान के छिलको, शहतूत की पत्तियों, वनस्पति रेशों से भी कागज बनाया जाता है। यह कागज मोटा और मजबूत होता है तथा मुख्यतः कुटीर प्रणाली पर घरों में बनाया जाता है।

सीमेन्ट (Cement)

इमारतें बनाने के इस आधुनिक मसाले का एशियाई देशों में जापान सबसे बड़ा उत्पादक है। यह लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन से भी अधिक सीमेन्ट प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है। सीमेन्ट निर्माण के 40 से भी अधिक कारखाने हैं। चूँकि देश की माँग से अधिक सीमेन्ट तैयार किया जाता है अतः यहाँ से सीमेन्ट का निर्यात भी होता है।

काँच उद्योग (Glass Industry)

द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जापान का काँच उद्योग बहुत उन्नत था और यहाँ काँच की नाना वस्तुएँ बनाई जाती थीं। काँच की चादरो के उत्पादन में तो यह देश सबसे आगे था। महायुद्ध काल में अन्य उद्योगों के समान ही काँच उद्योग को भी भारी क्षति पहुँची। युद्ध के बाद इस उद्योग को पुनः सगठित किया गया है। जापान का काँच उद्योग आज काफी उन्नत दशा में है। इस उद्योग के मुख्य केन्द्र टोकियो, घाओया, आसोका, याकोहामा, मीजी और तोबाता हैं।

विमान उद्योग

जापान के विमान निर्माण उद्योग का इतिहास 1911 से आरम्भ होता है और विमान निर्माण के क्षेत्र में उसने दुनिया का नेतृत्व किया है। आज इस उद्योग में प्रमुखतः यात्री-विमानों का और निजी तथा सामूहिक उपयोग के लिए हल्के विमानों का उत्पादन हो रहा है।

प्रमुख आधुनिक उद्योगों के बारे में कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य 59

दो तरह के हवाई जहाजों को दुनिया भर में व्यापकता मिल चुकी है। YS-11 को जो 60 यात्रियों का लघु परिवार टर्बा प्राप उपयोगिता-यान है और MV-2 को, जो 6 से 9 यात्रियों तक का टर्बा प्राप उपयोगिता-यान है अमेरिका के फैंडरल विमान-एजेंसी ने दोनों को टाइप सर्टीफिकेट दिए हैं। इन दोनों में ही थोड़ी जगह में उड़ान भरने और उतरने वाले विमानों की दिशा में प्रगति की विदेशों में ज्यों-ज्यों अधिकाधिक प्रतिष्ठि होती जा रही है, त्यो-त्यो अधिकाधिक सख्या में उनका निर्यात हो रहा है।

उद्योग में दो और किस्मों के छोटे-छोटे जहाज भी बनाए जा रहे हैं—चार सवारियों वाला N-62 ईंग्लेट और चार ही सवारियों वाला F-200। इनके उड़ने के लिए थोड़ी दौड़ पर्याप्त होती है और इनको चलाने और रख-रखाव का काम बड़ा सरल होता है।

इस समय जापान के विमान-उद्योग में बी० स्टास (ऊर्ध्वाधर : थोड़ी जगह में उड़ान भरने और उतरने वाले) जहाज के बनाने के बारे में अनुसंधान हो रहा है।

जापान में औद्योगीकरण की वर्तमान विशेषताएँ

(Salient Features of Modern Industrialisation)

हम जापान के कतिपय प्रमुख उद्योगों का विवरण दे चुके हैं। यहाँ संक्षेप में जापानी औद्योगीकरण की कुछ विशेषताओं पर अलग से धृष्टिपात करना उपयुक्त होगा—

1. पूँजी-प्रधान उद्योगों के प्रति विशेष धारण—वर्तमान शताब्दी के आरम्भिक वर्षों में जापानी अर्थ-व्यवस्था में अम-प्रधान उत्पादन का बोलबाला था, पर आज पूँजी-प्रधान उद्योगों के प्रति विशेष धारण है अर्थात् उत्पादन का क्रम हल्के से भारी उद्योगों की ओर रहा है।

2. गुण-वृद्धि पर बल—महायुद्धोत्तर युग में जापानी उद्योगों के विकास क्रम में परिमाण के विस्तार का नहीं, गुण की वृद्धि का दौर है। इसके पूर्व सबसे ज्यादा जोर परिमाण के विस्तार पर रहा था।

3. पूँजी का नरपूर उपयोग—पूँजी के भरपूर उपयोग से ही जापान की औद्योगिक सुविधाओं का द्रुत आधुनिकीकरण हुआ है। एक अध्ययन के अनुसार नई वैयक्तिक पूँजी के निवेश की औसत प्रतिवर्ष समग्र राष्ट्रीय उत्पादन की 30 से 35 प्रतिशत है। यह औसत अमेरिका के स्तर से लगभग दुगुनी है।

4. औद्योगिक संरचना में परिवर्तन—जापानी औद्योगिक संरचना में भी परिवर्तन आया है। जहाँ पहले सूती एवं रेशमी उद्योगों की प्रमुखता थी वहाँ अब रासायनिक और जैत-रासायनिक उद्योग तथा भारी मशीन उद्योग प्रमुख हैं। इन उद्योगों के फलस्वरूप ही आज जापान की गणना विश्व के सबसे ऊँचे औद्योगिक राष्ट्रों में होती है।

5. तकनीकी विकास—जापानी उद्योग अपनी तकनीकी क्षमता के निरन्तर

विकास की ओर सजग हैं। तकनीकी स्तरों का निरन्तर और प्रमत्त उँचा उठना तथा उद्योगों में नई शिल्प वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग—इन बातों का जापान के आर्थिक विकास से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जापान अपना शिल्प-विज्ञान दूसरे देशों को भी भेज रहा है—विशेष रूप से संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा रासायनिक उत्पादनों के क्षेत्र में।

6. सरकारी नीति और सहयोग—जापान के औद्योगिक विकास में सरकारी सहयोग का विशेष महत्त्व है। सरकार इस क्षेत्र में मार्ग-दर्शक, वित्तीय प्रबन्धक, बुद्धिमान नियन्त्रक और समयानुकूल सरक्षक रही है। यह आश्चर्य की बात है कि एक साम्यवादी अथवा समाजवादी राष्ट्र न होते हुए भी जापान के औद्योगिक विकास में वहाँ के शासन का अन्य पूँजीवादी देशों के मुकाबले अधिक महत्त्वपूर्ण हाथ और नेतृत्व रहा है।

7. प्राकृतिक साधनों का अभाव—जापानी उद्योगों के सामने सबसे बड़ी समस्या देश में प्राकृतिक साधनों की कमी है। जापान में खनिज-साधन बहुत ही कम हैं और एक सम्पन्न राष्ट्र के लिए आवश्यक माने जाने वाले अधिकांश साधन यहाँ नहीं पाए जाते। उदाहरणार्थ बॉक्साइट, तेल, कच्चे लोहे, पत्थर के कोयले जैसी आधारभूत सामग्री जापान को बाहर से मगानी पड़ती है। पेट्रोलियम का उत्पादन नगण्य-सा है और इस दृष्टि से विदेशी आयात पर जापान का अस्तित्व निर्भर है। सीसा, जस्ता, गंधक, चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट आदि अनेक साधन कबल इतने पाए जाते हैं जिनसे घरेलू माँग पूरी हो सके।

8. व्यक्तिगत एवं निजी साहस—जापानी उद्योगों में निजी साहस का विशेष महत्त्व है। कतिपय राजकीय एकाधिकारों को छोड़कर अधिकांश उद्योग निजी साहसियों के हाथ में हैं जो देश की अर्थ-व्यवस्था की सम्पूर्ण इकाइयाँ हैं। हम कह चुके हैं कि जापान में पिछले कुछ वर्षों से निजी अथवा वैयक्तिक पूँजी-निवेश का औसत अमेरिकी औसत से भी लगभग दुगुना रहा है।

9. श्रमिक-सुविधाओं का विस्तार—जापानी औद्योगीकरण में श्रमिक सुविधाओं के विस्तार के प्रति विशेष रुचि पाई जाती है। जापान में श्रम-कल्याण अपनी चरम सीमा पर है। श्रमिकों के कार्य करने की दशाएँ बहुत ही उन्नत हैं। नई तकनीकों द्वारा उनकी कार्य-क्षमता का निरन्तर विकास किया जाता है। श्रमिकों में कर्तव्य और श्रम के प्रति जितनी निष्ठा जापान में पाई जाती है, उतनी अन्यत्र नहीं।

10. लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योग—जापान के औद्योगिक ढाँचे में लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों का जैसा बोलबाला है वैसा विश्व में और कहीं नहीं है। इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रतिष्ठा भी है। एक अध्ययन के अनुसार कुल उद्योगों का लगभग चौथाई भाग में भी कम बड़े उद्योग हैं और दो-तिहाई भाग से अधिक उत्पादन लघु-स्तरीय तथा मध्यमवर्गीय उद्योगों से होता है।

11. उच्च-वचत अनुपात—जापान में बचत की दर अथ देशों के मुकाबले

कही ऊँची है। राष्ट्रीय आय का लगभग 50 से 55 प्रतिशत वैयक्तिक उपभोग पर व्यय किया जाता है, शेष विनियोग-भाष्यम डूँड लेता है। इस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में पूँजी निरन्तर लगती रहती है।

12 लघु और बड़े उद्योगों में सहयोग—जापान में लघु एव कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों के पूरक और सहायक के रूप में कार्य करते हैं, प्रतियोगी के रूप में नहीं। दोनों में सहयोग और समन्वय का सुन्दर उदाहरण विश्व के दूसरे देशों के लिए अनुकरणीय है।

13 उच्च-राष्ट्रीय भावना जापानी औद्योगीकरण की सबसे बड़ी विशेषता वहाँ के हर नागरिक में उच्च राष्ट्रीय भावना का होना है जिससे वे अपने देश के विकास के लिए तन-मन-धन लगाकर कार्य करते हैं।

14 उच्च कोटि के समन्वय की उपलब्धि—वार्टेल एव ट्रस्ट द्वारा यहाँ संगठित उद्योगों में उच्च कोटि का समन्वय है और भी विभिन्न प्रकार के संगठन हैं। प्रायः सभी उद्योग अपने अलग-अलग संगठनों में आ जाते हैं। अतः वे एक समन्वित संगठन उपलब्ध कर सके हैं जो कि जापान के औद्योगिक विकास में अत्यन्त सहायक रहा है।

15 विदेश व्यापार-क्षमता—विदेश व्यापार जापान का प्राण है। जापानी अर्थ-व्यवस्था की गति, जापान के विदेश व्यापार पर निर्भर रहती है। चूँकि देश की आवादी निरन्तर बढ़ रही है, उसके पास प्राकृतिक साधनों का अभाव है और भूमि क्षेत्र भी सीमित है, अतः आर्थिक दृष्टि से जीवित रहने के लिए जापान विदेश व्यापार पर अत्यधिक निर्भर रहता है।

संक्षेप में, जापान का समूचा औद्योगिक सयत्र विकासशील और विवेकपूर्ण है। युद्धोत्तर काल में जापान न जो द्रुत औद्योगिक विकास किया है उसे देखते हुए यह भविष्यवाणी की जाती है कि अगले कुछ दशकों में जापान औद्योगिक उत्पादन में विश्व का सिरमौर राष्ट्र होगा।

जैबत्सु और उसके आर्थिक प्रभाव

(Zaibatsu and Their Economic Influences)

जापानी उद्योगों पर कुछ ही परिवारों का स्वामित्व है—ये सामन्तशाही घराने के हैं। इनमें मिट्सुबई, मिट्सुबोशी, सुमोतोमे और यद्युदा प्रमुख हैं। स्थानीय भाषा में इन्हें “जैबत्सु” कहते हैं।

जैबत्सु का जापान की आर्थिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। देश के अधिकांश वित्तीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में इनका एकाधिकार-सा है। निर्माणकारों, बैंकिंग, बीमा, सौदागरी तथा जहाजरानी के उद्योग इन्हीं के हाथ में हैं। एक अध्ययन के अनुसार कम्पनियों की चुकता पूँजी, सचिवी श्रेण पत्र तथा कुल विनियोग की तीन-चौथाई पूँजी पर जैबत्सु का ही अधिकार है और नए तथा लघु उद्योगों के कच्चे माल एव वित्त की पूर्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है। जैबत्सु के अठ पराने जापान की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था पर छाये हुए हैं।

मेजी पुनर्संस्थापन के बाद मेजी सरकार ने देश के आर्थिक-सामाजिक एवं औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त व्यक्तियों राजनीतिज्ञों तथा वित्तीय व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी। चूंकि मेजी शासन के आविर्भाव के पूर्व जैबत्सु इन सभी कार्यों को कर चुके थे, अतः स्वाभाविक था कि मेजी सरकार को इन्हें (जैबत्सु) को अपनाना पड़ा। जैबत्सु घरों ने शासन को औद्योगिक क्षेत्रों में अत्यधिक मदद पहुँचाई। सरकार का इन्हें वरद-हस्त प्राप्त हुआ। ठेकेदारी, सरकारी व्यापार, राजकीय सम्पत्ति के श्रय आदि में इन्हें प्राथमिकता दी गई। इन्हें हर क्षेत्र में काफी छूट और सुविधाएँ मिली। फलस्वरूप आर्थिक शक्ति का सकेन्द्रण इनके हाथ में होता गया। वे विदेशी व्यापार में भी घुस गए और आधुनिक शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में एक-परिवार छोटे उद्योगों में भी इन्होंने अपना आधिपत्य और प्रभाव जमाना शुरू कर दिया।

बैंकिंग व्यवस्था पर भी जैबत्सु का आधिपत्य था। 1972 के बैंकिंग सक्त में सभी छोटे बैंकों को पाँच बड़े बैंकों में सम्मिलित कर दिया गया जिसमें जैबत्सु परिवार ही प्रमुख था। जैबत्सु घराने वास्तव में जापान की समस्त अर्थ-व्यवस्था पर छा गए। विशेषता यह थी कि देश में तो वे आपस में प्रतियोगिता भी करते थे, पर विदेशी अथवा बाहरी प्रतियोगी का एक होकर सामना करते थे। देश में इन्होंने सम्मिलित ढंग से भी बहुत से उद्योगों में विनियोग किया। सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त प्रभाव, सरकार से अच्छे सम्बन्ध, देश के महत्त्वपूर्ण उद्योगों पर अधिकार और व्यापक औद्योगिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप सन् 1929 तक इनका जापान के आर्थिक क्षेत्र में विशेष स्थान रहा। वास्तव में अर्थ-व्यवस्था का कोई भी अंग ऐसा नहीं था जहाँ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जैबत्सु घराना की उपस्थिति न हो। स्थिति यहाँ तक थी कि सरकार एक प्रकार से इन्हीं के निर्देशानुसार संचालित हो जाती थी।

लेकिन 1929 के बाद महान आर्थिक मन्दी ने जैबत्सु की स्थिति पर घातक प्रहार किया। महान आर्थिक सन्क्रान्ति के फलस्वरूप मेजी सरकार की नीति बदनाम हो गई और जब नई सरकार आई तो जैबत्सु का प्रभाव समाप्त होने लगा। यह आरोप लगाया गया कि जैबत्सु घर अपने हितों के लिए शासन को खतरे में डालने से नहीं चूकते। इनके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया की लहर उठ खड़ी हुई और 1932 में इनके प्रमुख सचालक की हत्या कर दी गई। अब जैबत्सु सामान्य कृषि उत्पादनो स अपना हाथ खींचने लगे और आर्थिक क्षेत्र में इनकी स्थिति लडखडा गई। ये पुनः जमाने का प्रयत्न करने लगे। नई सरकार ने विभिन्न नियन्त्रण लगाकर उन्हें समाप्त करने का प्रयत्न किया, पर विभिन्न बाधाओं के बावजूद जैबत्सु अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सफ़ल हो गए, उन्हें समाप्त नहीं किया जा सका।

लघु-स्तरीय उद्योग-धन्धों का योगदान (ROLE OF SMALL SCALE INDUSTRIES)

लघु एव कुटीर उद्योग-धन्धों के क्षेत्र में जापान को जितना अनुभव है, उतना सम्भवतः विश्व के बहुत कम देशों को है। लघु-स्तरीय उद्योग-धन्धों में जापानियों की कुशलता तथा से विश्वविख्यात रही है। ये उद्योग-धन्धे प्राचीन काल में तो जापानी अर्थ-व्यवस्था के मुख्य आधार थे ही, किन्तु आज भी आर्थिक क्षेत्र में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है।

जापानी लघु एवं कुटीर उद्योग धन्धों का विकास (Development of Small Scale Industries in Japan)

जापान में आधुनिक तरीके के भारी उद्योगों के विकास की आधारशिला 1868 में मेजी पुनर्संस्थापन के बाद रखी गई, किन्तु लघु एव कुटीर उद्योग-धन्धे जापानी अर्थ-व्यवस्था पर सदियों पहले से छाए हुए थे। उस समय एक मात्र ये उद्योग धन्धे ही सम्पूर्ण जापानी अर्थ-व्यवस्था का आधार थे।

मेजी पुनर्संस्थापन काल में भारी उद्योगों की नींव पड़ी और धीरे-धीरे उनके विकास के साथ जापानी अर्थ-व्यवस्था के दो मुख्य आधार-स्तम्भ बन गये—भारी पैमाने के उद्योग तथा कुटीर एव लघु उद्योग। जापानी अर्थ-व्यवस्था की मुख्य विशेषता इस बात में रही कि वहाँ भारी पैमाने के उद्योगों ने लघु-स्तरीय उद्योगों को विनिष्ट करने अथवा उन्हें क्षति पहुँचाने की नीति नहीं अपनाई। इसके विपरीत लघु-उद्योग भारी उद्योगों के लिए सहायक और पूरक का काम करते रहे। एक-दूसरे के सम्बन्ध में जापान की अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ होने में बड़ी सहायता मिली।

एक ओर तो जापान पश्चिमी ढंग पर अपना औद्योगीकरण करता रहा और दूसरी ओर लघु तथा कुटीर उद्योग धन्धे भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाये रहे। इन लघु उद्योग-धन्धों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का विदेशों में भारी मात्रा में निर्यात होता रहा और इनसे प्राप्त होने वाली आय ने जापान के आधुनिक औद्योगीकरण को आगे बढ़ाया। जापानी किसान परिवार को पूरा पैदा करते थे और अपने बृद्धि-घटो में रेशम उत्पन्न करते थे। विभिन्न प्रकार की अन्य वस्तुएँ छोटे-छोटे स्थापनों अथवा लघु-स्तरीय औद्योगिक इकाइयों में बनती थीं। इन्होंने ही जापानी अर्थ-व्यवस्था की नींव डाली।

जापान में औद्योगिक ढाँचा एक क्षेत्र में बड़े पैमाने के स्थापनों और दूसरे क्षेत्र में लघु-स्तरीय इकाइयों का सम्मिश्रण बना रहा। सन् 1930 में भी यह

स्थिरता थी कि जापान के कुल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लगभग 54 प्रतिशत एक व्यक्ति सस्थान थे अर्थात् इन लघु औद्योगिक इकाइयों में केवल एक-एक व्यक्ति काम करता था। सन् 1938 में जापान के कुल कारखानों में से लगभग 96.2 प्रतिशत सस्थान ऐसे थे जिनमें 5 से 100 के बीच व्यक्ति लगे हुए थे। निर्यात के क्षेत्र में बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के उद्योगों का लगभग बराबर भाग था। सन् 1933 में जो कुल निर्यात किया गया उसमें मात्रा की दृष्टि से 60.6 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 57.1 प्रतिशत भाग लघु तथा मध्यम आकार के उद्योगों से प्राप्त हुआ था।

जापान के निजी निर्माण उद्योगों के क्षेत्र में लघु-स्तरीय उद्योगों की जो महत्त्वपूर्ण स्थिति थी, उसका एक अनुमान लोकवुड (Lockwood) द्वारा दिए गए सन् 1930 के वर्ष के निम्नलिखित आँकड़ों से लगता है—

सस्थानों का आकार	लगे हुए व्यक्तियों का प्रतिशत
स्वतन्त्र	14.0
1-4 तक कार्य करने वाले	44.3
5-99 तक कार्य करने वाले	20.8
100-499 तक कार्य करने वाले	10.6
500 अथवा अधिक कार्य करने वाले	6.00, 10.3

यद्यपि लोकवुड ने लिखा है कि उपर्युक्त आँकड़े जापानी अर्थ-व्यवस्था में लघु-उद्योगों के महत्त्व को बढा-चढा कर प्रस्तुत करते हैं तथापि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उस समय जापान की औद्योगिक व्यवस्था में इनका बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान था। गुन्थर स्टीन (Guenther Steen) के अनुसार, सन् 1932 में काम करने वाले श्रमिकों के आधार पर फैक्ट्रियों का जो वितरण था वह लघु-स्तरीय इकाइयों के महत्त्व का प्रमाण था। उनके अनुसार लगभग 97 प्रतिशत फैक्ट्रियाँ लघु अथवा मध्यम आकार की थीं। श्री स्टीन द्वारा दिए गए आँकड़े इस प्रकार हैं—

श्रमिकों की संख्या के आधार पर फैक्ट्रियों का वितरण (1932)

सस्थान	कुल काम करने वालों का प्रतिशत
5-9 लोगों को रखे हुए सस्थान	18
10-49 " " "	26
50-500 " " "	36
500 से अधिक " " "	25

इन आँकड़ों से प्रकट है कि लगभग 39 प्रतिशत लोग छोटी इकाइयों में 86 प्रतिशत मध्यम आकार की इकाइयों में और 25 प्रतिशत बड़ी फैक्ट्रियों में लगे हुए थे। कुल उत्पादन में छोटी फैक्ट्रियों का भाग 29 प्रतिशत, मध्यम आकार की फैक्ट्रियों का भाग 35 प्रतिशत और बड़े आकार की फैक्ट्रियों का भाग 25 प्रतिशत था। कहने का आशय यह हुआ कि उस समय कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 64

से उसका बड़ा महत्त्व है। जापानी लोग अपने स्वभाव से ही कुटीर व लघु उद्योगों के प्रेमी हैं। अतः इस उद्योग का बने रहना अस्वाभाविक नहीं है।

जापान के कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग

(Some Small Scale Industries of Japan)

जापानी सरकार के अनुसार लघु उद्योग उन्हें कहा जाता है जहाँ श्रमिकों की संख्या थोड़ी, प्रबन्ध एक व्यक्ति के हाथ में, पूँजी का विनियोग छोटा, आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र छोटा हो तथा उद्योग के विनियोग-सम्बन्ध किसी निगम के साथ न हो। जापान में बहुत से लघु उद्योग सरकार द्वारा लाभ प्राप्त कर अपनी प्रगति कर रहे हैं। वस्त्र-उद्योग में कपास, ऊन, हीजरी, टॉवल, रुमाल, टेबिल-क्वर, तैयार बने वस्त्र, मछली पकड़ने के जाल आदि लघु उद्योग हैं। मशीनरी उद्योग के क्षेत्र में कृषि मशीन, आरे, दरारियाँ, मशीनों के पुर्जे, बिजली एवं संचार के सामान आदि के लघु उद्योग हैं। धातु उद्योग में दलाई के काम, जालियाँ, तार, स्टेन-लैस-स्टील के सामान आदि के लघु उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त काँच, इनामिल छत ढकने की चद्दरें, दियासलाई, हल्की धातु के सामान, लौह इस्पात के दैनिक जीवन के सामान, चमड़े, लकड़ी, प्लास्टिक एवं स्टेशनरी के सामान, सिलाई मशीनें, सुइयाँ, स्टोप, चाकू, छुरियाँ चम्मच, रबड़ का सामान, लाख का सामान, प्लेट, घरेलू सजावट के सामान, बाँस के बने-सामान आदि के अनेको लघु उद्योग हैं।

जापानी लघु उद्योग बड़े उद्योगों के सहायक और पूरक का काम करते हैं। बहुत से लघु उद्योग बड़े उद्योगों के लिए उनके आर्डर के मुताबिक सामान, पुर्जे आदि तैयार करते हैं। ये लघु उद्योग छोटी जगहों पर घरों में और छोटे-छोटे बर्कशाँपो में चलाए जाते हैं। बड़ी संख्या में लघु उद्योग अपने अस्तित्व के लिए सरकारी आर्डरों पर निर्भर हैं। अनेक लघु उद्योग प्रगति करके बड़े उद्योगों की राह पकड़ लेते हैं।

सन् 1948 से ही जापानी सरकार का लघु उद्योग बोर्ड (Board of Small Scale Industries) लघु उद्योगों के विकास, नियमन और सफल संचालन की दिशा में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। बोर्ड लघु उद्योगों में नई तकनीक के विकास, कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, आदर्श कारखानों की स्थापना, अल्पावधि प्रशिक्षण कोर्स, अनुसंधान व सर्वेक्षण की अवस्था, समस्याओं के निरीक्षण, उपयोगी परामर्श आदि के लिए प्रयत्नशील रहता है। प्रशिक्षण के क्षेत्र में सरकार की ओर से समुचित निःशुल्क प्रबन्ध है।

जापान में लघु एवं बृहद् उद्योगों का सम्बन्ध प्रथम

लघु उद्योगों पर बृहद् उद्योगों का प्रभाव

हम कह चुके हैं कि जापान में लघु और कुटीर उद्योग सदियों पहले से चले आ रहे हैं और जब भारी उद्योगों का विकास हुआ तो लघु उद्योग गौण नहीं हुए बल्कि बृहद् प्रथम बड़े पैमाने के उद्योगों के सहायक के रूप में काम करते रहे।

वास्तव में जापानी अर्थ-व्यवस्था में ये दोनों ही क्षेत्र एक-दूसरे के सहयोगी रहे और अपने देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने में उल्लेखनीय योग देते रहे। जापान के निर्यात व्यापार में द्वितीय महायुद्ध से पूर्व तक लघु और मध्यम वर्ग के उद्योग-वर्गों का महत्त्व बृहद् उद्योग-वर्गों से तुलनात्मक रूप में अधिक ही रहा। लघु उद्योगों ने अपनी उत्पादन प्रणाली में सुधार करके तथा अपना आधुनिकीकरण करके अपने आपको बड़े उद्योगों का सहयोगी बनाए रखने की सफल चेष्टा की।

जापानी औद्योगिक व्यवस्था में लघु और बृहद् दोनों ही प्रकार के उद्योगों के बीच एक निश्चित सम्बन्ध बना रहा जो आज भी कुछ अंश तक बिलम्बित है। लघु उद्योगों ने बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता नहीं बल्कि उनके पूरक का नाम दिया। वे बड़े पैमाने की विप्रेषण-व्यवस्था, अताप्राप्त और वित्त से लाभ उठाते रहे। लघु और कुटीर संस्थान बड़े कारखानों को कच्चे पदार्थ और सेवाएँ देते रहे या उत्पादन प्रक्रिया में किसी विशिष्ट कार्य का सम्पादन करते रहे। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों में परस्पर सहायक सम्बन्ध फलते-फूलते गए।

जापान में लघु और बृहद् उद्योगों में परस्पर सहायक सम्बन्ध का विकास इसलिए भी हुआ कि जापान के बृहद् उद्योग वहाँ के मूल उद्योगों से नहीं उभरे थे, बल्कि पश्चिमी देशों से आयातित थे। इस प्रकार बड़े उद्योगों के महल छोटे उद्योगों की कीमत पर खड़े नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त बड़े उद्योग अधिकांशतः सैनिक और पारिवाहक सामान का उत्पादन करने में लगे थे, अतः वे मूल छोटे उद्योगों के प्रतियोगी नहीं थे जो कि जापान के परम्परागत माल का उत्पादन करते थे।

सारांशतः लघु और बृहद् दोनों उद्योग जापान की आर्थिक गाड़ी के दो पहिए थे जिन्होंने मिलकर देश की औद्योगिक क्रान्ति को आगे बढ़ाया। पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि छोटे उद्योगों के विकास में कोई बाधा ही नहीं आई। वास्तव में इन उद्योगों को अपनी ही अर्थी के उद्योगों की आन्तरिक प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। ये प्रतियोगितात्मक समस्याएँ अधिकांश लघु एवं मध्यम आकार के जापानी उद्योगों के सामने बनी रहीं।

सद्युस्तरीय उद्योगों की समृद्धि के कारण

जापान में लघु एवं कुटीर उद्योग सदा से समृद्ध रहे हैं और आज देश के अत्यधिक औद्योगिकीकरण के युग में भी अपना महत्त्व बनाए हुए हैं। निश्चय ही इन उद्योगों की इस समृद्धि और शक्ति के मूल में अनेक कारण निहित हैं। कुछ कारण तो पहले के हैं जो आज भी अपना फल दिखा रहे हैं और कुछ कारण नवीन हैं जो आधुनिक परिस्थितियों के प्रतिकूल हैं। संक्षेप में ये सभी कारण इस प्रकार हैं—

(1) जापान के लघु और मध्यम आकार के उद्योग मेजी शासन काल में कृषि जनसंख्या के लिए पूरक आय के स्रोत बने रहे। फलस्वरूप रोजगार, मजदूरी आदि उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला।

(2) मेजी युग में विदेशी व्यापार में सतुलन रखना आवश्यक था। इस आवश्यकता ने लघु और मध्यम आकार के उद्योगों के महत्त्व में वृद्धि की। जापान

को औद्योगिक आधारभूत सामान के आयात के कारण विदेशों को काफी भुगतान करना होता था। जापान के मूल लघु उद्योगों द्वारा उत्पन्न कच्चा रेशम, चाय, चट्टाई आदि के निर्यात द्वारा प्राप्त आय से इन भुगतानों में बड़ी सहायता मिल सकती थी। अतः इन उद्योगों को समृद्ध बनाए रखने की चेष्टा की गई।

(3) जब जापान में पश्चिमी देशों के अनुसार औद्योगीकरण होने लगा तो लघु उद्योगों ने भी अपनी उत्पादन प्रणाली में सुधार करके अपनी क्षमता बनाए रखने की सफल चेष्टा की।

(4) लघु उद्योगों ने बड़े पैमाने के कच्चे पदार्थ, कार्यशील पूँजी, बाजार आदि के संगठन से उपलब्ध बड़े पैमाने की मितव्ययिताओं से लाभ उठाकर अपने पर मजबूत किए।

(5) जापान के लघु उद्योग लकीर के फकीर नहीं बन रहे। बड़े व्यवसायों के प्रभाव में आकर उन्होंने भी अपने क्षेत्रों का आधुनिकीकरण किया। साथ ही वे परम्परागत माल के उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि नए-नए उद्योग धर्मों के क्षेत्र में भी प्रवेश करने लगे।

(6) जापान की जनसंख्या में जब तेजी से वृद्धि होने लगी तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को उत्पादन कार्य में लगाने के लिए जापान ने प्रधानतः लघु उद्योगों का सहारा लिया।

(7) लघु उद्योग लोगों की भिन्न-भिन्न रुचियों के अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करते रहे, अतः उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई।

(8) जापान में यातायात व सवादवाहन की सुविधाओं के विस्तार से लघु-उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। इन उद्योगों को कच्चा माल पहुँचाने और निर्मित वस्तुओं को बाजार में ले जाने की पूरी सुविधा हो गई। फलस्वरूप यह सम्भव हो गया कि जापान के सभी क्षेत्रों में लघु पैमाने के उद्योग पनप सकें।

(9) मेजी सरकार ने निर्यात के क्षेत्र में लघु उद्योगों के महत्त्व को समझते हुए अनेक ऐसे कानून पास किए जिनका उद्देश्य इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की किस्म को जर्चाना और सुधार की प्रेरणा देना था। इन कानूनों के फलस्वरूप लघु उद्योग में परस्पर अनावश्यक प्रतियोगिता भी कम हो गई। इन कानूनों ने लघु उद्योगकर्तियों तथा व्यापारियों में पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन दिया।

(10) लघु उद्योगों ने बड़े पैमाने के उद्योगों से कोई प्रतियोगिता नहीं की बल्कि पूरक और सहायक का कार्य किया।

(11) सस्ते श्रम और विद्युत की उपलब्धि के कारण इन्हे काफी सहायता मिली। सस्ते श्रमिकों के रूप में निर्धन किसानों की लडकियाँ सूती वस्त्र और अन्य लघु उद्योगों के उत्पादन को बढ़ाने में बड़ी सहायक हुईं।

(12) महान मन्दी काल के समय सरकार ने लघु उद्योगों को सहायता देने की सक्रिय नीति अपनाई। मन्दी का रेशम उद्योग पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, अतः सरकार ने इस उद्योग की सभी शाखाओं को आर्थिक सहायता दी। मन्दी काल

के दौरान लघु पैमाने के लिए निर्माता गिल्ड और निर्यात गिल्ड संगठित किए गए जिन्हें सरकार द्वारा कम व्याज पर ऋण और अनुदान दिए जाने लगे ताकि वे सहकारिता के आधार पर पथ विकस्य कर सकें।

(13) 1933 में जापानी मुद्रा (येन) के अवमूल्यन के फलस्वरूप जब विश्व में जापानी वस्तुओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई तो लघु और कुटीर उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस समय सरकार ने इन्हें अपने संरक्षण में निर्यात की मात्रा और मूल्य को नियंत्रित करने का अधिकार दिया।

(14) सन् 1948 में जापान सरकार ने एक लघु उद्योग परिषद् की स्थापना की जिसका कार्य इन उद्योगों के विकास का प्रयास करना रखा गया। यह परिषद् आज भी बड़ा उपयोगी कार्य कर रही है। लघु उद्योगों के विकास के लिए यह सभी प्रकार के प्रयत्न करती है।

(15) 1948 में ही सरकार ने ग्रामीण पुनर्निर्माण की एक योजना भी क्रियान्वित की जिससे गांवों में उद्योग और कृषि को बड़ा प्रोत्साहन मिला।

(16) जापानियों की शक्ति, कुशलता और कार्यक्षमता लघु उद्योगों की समृद्धि बनाए रखने में सर्वाधिक सहायक हुई है। जापानियों की इस प्रवृत्ति में भी लघु-उद्योगों को बड़ा भारी सहारा मिला हुआ है कि जिन क्षेत्रों में वस्तु की प्रकृति ऐसी है कि उसका उत्पादन कम पूंजी वाले तरीके से किया जा सकता है, वहाँ उस वस्तु का उत्पादन-कार्य लघु पैमाने के उद्योगों के हाथ में ही छोड़ दिया गया है।

इन सभी कारणों और परिस्थितियों का ही सम्मिलित परिणाम है कि आज के महान् औद्योगिक देश जापान में भी लघु व कुटीर उद्योग अपने सम्मानजनक अस्तित्व बनाए हुए हैं।

लघु उद्योगों का महत्त्व और योगदान

(Importance and Contribution of Small Scale Industries)

जापान की अर्थ-व्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का सदैव से महत्त्व रहा है। यद्यपि वर्तमान प्रवृत्ति पूंजी-प्रधान बड़े उद्योगों पर विशेष आप्रह की है, तथापि लघु उद्योग देश की अर्थ-व्यवस्था में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। जापान की आर्थिक संरचना में इनके महत्त्व और योगदान को हम निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं—

1. अर्थ-व्यवस्था में विशिष्ट स्थान—देश की अर्थ-व्यवस्था में लघु उद्योगों का प्रारम्भ से ही विशिष्ट स्थान रहा है। प्रारम्भ में धान्तरिक और बाह्य आवश्यकताओं की अधिकांश पूर्ति इन्हीं उद्योगों द्वारा होती थी और निर्यात व्यापार में भी इनका महत्त्वपूर्ण स्थान था। प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के बीच तो इन उद्योगों ने इतना तीव्र विकास किया कि गुण, मात्रा और मूल्य—सभी दृष्टियों से इनके द्वारा उत्पादित माल विश्व-बाजारों में छा गया और पश्चिमी, राष्ट्रीय को विवश होकर जापान पर मह प्रारोप लगाना पड़ा कि वह राशिपातन (Dumping) की नीति अपना रहा है। भारत सरकार ने कुछ वर्षों पूर्व अपना जो लघु उद्योग

अध्ययन दल जापान भेजा था उसकी रिपोर्ट के अनुसार जापान जैसा सुविशाल औद्योगिक साम्राज्य अपनी शक्ति इन्हीं लघु एव कुटीर उद्योगों से प्राप्त करता है। लघु एव कुटीर उद्योग क्षेत्र में लगभग 54 प्रतिशत एक-व्यक्ति कमशालाएँ तथा 40 प्रतिशत अन्य छोटे सस्यान हैं जिनमें 5 व्यक्तियों से कम व्यक्ति काम करते हैं।

2 बड़े उद्योगों के पूरक और सहायक—जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, जापान के लघु एव कुटीर उद्योग देश के वृहद पैमाने के उद्योगों के पूरक और सहायक के रूप में काम करते हैं। बड़ी सस्या में लघु उद्योगों द्वारा बड़े उद्योगों के आर्डरों के अनुसार माल उत्पादित और सप्लाई किया जाता है। लघु उद्योगों में काम करने वाले व्यक्ति बड़े अनुभवी और कार्य-कुशल हैं तथा बड़े उद्योगों के लिए सहायक माल तैयार कर उनकी लागत व्यय को नीचा रखते हैं। लघु उद्योगों द्वारा बड़े उद्योगों को कच्चा माल, पदार्थ, सहायक पुर्जों, हिस्सों, सेवाओं आदि की पूर्ति की जाती है। साथ ही बड़े उद्योगों की विनय-व्यवस्था, पूँजी, यातायात आदि से लाभ उठाकर ये लघु-उद्योग अपनी प्रतियोगी क्षमता को भी बनाए रखते हैं।

3 रोजगार तथा उच्च जीवन-स्तर में सहायक—जापानी लघु और कुटीर उद्योग भारी सस्या में देशवासियों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। ये लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक हैं। लघु एव कुटीर उद्योगों की जितनी विभिन्नता जापान में पाई जाती है, उतनी अन्यत्र नहीं। ये उद्योग उपभोक्ताओं की विभिन्न रुचियों का सामान तैयार करते हैं और आय-स्रोतों की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होते हैं।

4 अर्थ-व्यवस्था के सन्तुलन में सहायक—लघु एव कुटीर उद्योग जापानी अर्थ-व्यवस्था को सन्तुलित बनाए रखने में सहायक हैं। जिन क्षेत्रों में वस्तुओं की प्रकृति ऐसी है कि कम पूँजीवादी तरीके अपनाकर उसका निर्माण सम्भव है, वहाँ उत्पादन-कार्य लघु स्तरीय उद्योगों के हाथ में ही है। जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने के औद्योगिक सस्थानों की गुँजाइश नहीं है अथवा कम है वहाँ लघु स्तरीय उद्योग ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं।

5 सरकारी सहयोग और लघु उद्योगों का प्रसार—जापान के लघु और कुटीर उद्योग देश की अर्थ-व्यवस्था में बमालू बेटे की भाँति है, अतः सरकार सर्वद्वेष इन्हें प्रोत्साहित करती रहती है। सरकार का यह प्रयत्न है कि लघु उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हो, उनकी कार्य-क्षमता बड़े, उत्पादित माल की विस्म अर्द्धी हो और उद्योगों में निरन्तरता लाई जाय ताकि नए नए उद्योगों का विकास हो सके। लघु उद्योग बोर्ड (Board of Small Industries) इस दिशा में कितना सक्रिय है, इसका संकेत पिछले पृष्ठों में दिया जा चुका है। सरकारी सहयोग और अनुकूल वातावरण के फलस्वरूप पिछले कुछ वर्षों से जापान में लघु उद्योगों ने बड़ा हुआ उत्पादन दिया है। इन उद्योगों का प्रसार इतनी तेजी से हो रहा है कि बड़े उद्योगों के लिए अब ये समस्या रूप में प्रस्तुत होने लगे हैं।

6 आर्थिक क्रियाओं को अधिक गतिशीलता देना—जापानी लघु और कुटीर उद्योग आर्थिक क्षेत्र में इतने छाए हुए हैं कि न केवल इनसे यातायात और सन्देश-वहन के साधनों को अधिक गति मिली है वरन् बैंकिंग व्यवसाय, व्यापार, कच्चे माल की माँग और तैयार माल की पूर्ति आदि को भी काफी बढ़ावा मिला है।

वास्तव में जापानी लघु और कुटीर उद्योग अर्थ-व्यवस्था में अपनी जड़े भविकान्तिक गहरी जमाते जा रहे हैं। जापान अपनी हस्तकला और अन्य लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए विश्व विख्यात बन चुका है। जापानी जनता का इन उद्योगों के प्रति इतना गहरा प्यार है कि यह आशा करना ही स्वर्ण है कि पूँजी-प्रधान उद्योगों के प्रति आकर्षण की लहर इन्हें निकट या सुदूर भविष्य में समाप्त कर देगी।

लघु उद्योगों के बने रहने के कारण

जापान में लघु एवं कुटीर उद्योगों के बने रहने के मुख्य कारण निम्न-लिखित हैं—

(1) जिन आर्थिक क्षेत्रों में कम पूँजी से काम चलाया जा सकता है उनमें लघु एवं कुटीर उद्योग ही पनपते हैं।

(2) बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ रोजगार के अवसरों की माँग बढ़ती जा रही है और लघु एवं कुटीर उद्योग रोजगार को बढ़ती हुई माँग की पूर्ति में विशेष सहायक हैं। देश में बेरोजगारी की समस्या उपस्थित न होने देने में इनका विशेष योगदान है।

(3) इन उद्योगों द्वारा उपभोक्ताओं की विभिन्न रुचियों और आवश्यकताओं के अनुकूल सस्ती वर सुन्दर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है।

(4) पर्याप्त यातायात की उपस्थिति और कच्चे माल के शीघ्र वहन के साधनों में लघु उद्योगों के विकास को सम्भव बनाया है।

(5) अधिकांश लघु उद्योग बड़े उद्योगों से सम्बन्धित हैं और इनमें आपसी प्रतियोगिता नहीं है।

(6) लघु उद्योग अपनी कार्य-क्षमता को आवश्यकतानुसार बढ़ाते रहते हैं और बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ विकसित तकनीक को लागू करते रहते हैं।

(7) सस्ते स्त्री श्रमिकों की उपलब्धि भी इन उद्योगों के विकास में सहायक है।

(8) सरकार भी इन उद्योगों की क्षमता बढ़ाने में पर्याप्त सहयोगी रही है।

(9) जापानी जनता अपनी प्रकृति से लघु एवं कुटीर उद्योगों तथा इनके द्वारा उत्पादित माल को प्रेमी है।

लघु उद्योगों के प्रति सरकारी नीति

(Govt. or State Policy Towards Small Scale Industries)

जापान में लघु उद्योगों की सृष्टि और कार्य-क्षमता के बने रहने में सरकारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। लघु उद्योगों के प्रति जापानी सरकार की सक्रियता

का प्रारम्भ हम मेज़ी पुनर्स्थापन काल से ही स्पष्ट रूप से देखते हैं। उस समय सरकार ने यद्यपि इस दिशा में उतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी बड़े उद्योगों के विकास में, तथापि वह इस ओर बिलकुल उदासीन भी नहीं रही है। निर्यात-व्यापार में लघु एवं मध्यम आकार के उद्योगों के महत्त्व को सरकार ने भाँप लिया, भ्रत उसका प्रयत्न रहा कि इनकी कार्य-क्षमता बड़े और ये सुबरे हुए तथा उन्नत किस्म का माल उत्पादित करें।

सन् 1884 के बाद सरकार के अनेक कानूनों का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योग-पतियों और व्यावसायियों के बीच सहकारिता को प्रोत्साहन देना रहा ताकि उत्तम श्रेणी की वस्तुओं का उत्पादन सम्भव हो सके। सरकार ने अस्वस्थ प्रतियोगिता को रोकने की सफल चेष्टा की, जिससे घटिया उत्पादन हतोत्साहित हुआ।

सन् 1925 में सरकार ने एक नियम द्वारा गिल्ड जैसी स्वेच्छिक संस्थाओं की व्यवस्था की ताकि लघु उद्योगों की वस्तुओं में गुणों की समय-समय पर अच्छी तरह जाँच हो सके। वास्तव में सन् 1930 तक सरकार की नीति का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि लघु उद्योगों तथा निर्यात के लिए उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं के गुणों में उत्तरोत्तर सुधार हो। सरकार ने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप और नियन्त्रण की नीति पर न चलकर अपरोक्ष रूप में ही अपनी नीति को ही अधिक संचालित किया, परोक्ष रूप में केवल जाँच और सुधार तक ही सरकार ने अपने को सीमित रखा।

मन्दी काल में सरकार ने लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर संरक्षण दिया। कम व्याज पर ऋण और छोटे-छोटे अनुदान देने की व्यवस्था की गई। लघु उद्योगों को निर्माता गिल्डों और निर्यात गिल्डों के रूप में संगठित करने का प्रयत्न किया गया ताकि वे सहकारिता के आधार पर अधिक अच्छी तरह क्रय-विक्रय कर सकें। मुद्रा के अवमूल्यन के समय भी सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों की सहायता की।

महायुद्ध-काल में जापानी लघु और कुटीर उद्योगों को काफी आघात पहुँचा तथा पुनर्निर्माण काल में भी बड़े उद्योगों में अधिकाधिक विनियोग और विकास का प्रयत्न किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से इन उद्योगों द्वारा उत्पादित कई वस्तुओं की माँग घटी। पर शीघ्र ही सरकार द्वारा लघु उद्योग बोर्ड, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना आदि का गठन और क्रियान्वयन किया गया जिससे लघु, कुटीर, मध्यम आकार के उद्योगों को काफी प्रोत्साहन मिला। लघु उद्योग बोर्ड (Board of Small Industries) जो मार्च, 1948 में स्थापित किया गया, लघु उद्योगों के विकास, नियमन और सफल संचालन की दिशा में महत्त्वपूर्ण शस्त्र बना हुआ है। जैसा कि पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका है, इस बोर्ड का काम सूचनाओं की प्राप्ति, विश्लेषण, लघु उद्योगों की समस्याओं का निरीक्षण और सुलभाव, उनमें नई तकनीकों और सुविधाओं का विकास, नये पदार्थों को प्रोत्साहन, समुचित अनुसन्धान और सर्वेक्षण, आदर्श कारखानों की स्थापना, अत्यावधि प्रशिक्षण कार्य क्रम चलाना आदि हैं। प्रशिक्षण क्षेत्र में सरकार की ओर से निःशुल्क प्रबन्ध हैं।

सरकार की नीति लघु उद्योगो को हतोत्साहित करने की नही है, वरन् जिन क्षेत्रो मे ये उद्योग अधिक उपयोगी हैं, उनमे इन्हें प्रोत्साहन ही दिया जाता है।

इस अध्याय के सम्पूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि जापान की वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था मे लघु एव कुटीर उद्योगो का महत्वपूर्ण स्थान है। बड़े उद्योगो का प्रसार हो रहा है तथापि लघु उद्योगो का न केवल प्रभावशाली अस्तित्व बना हुआ है बल्कि दिनो-दिन अपने विकसित रूप मे, ये बड़े उद्योगो के लिए समस्या-रूप लेते जा रहे हैं। जापान मे लघु उद्योगो का भविष्य उज्ज्वल है, तथापि इनके अत्यधिक प्रसार के प्रति सरकार सजग है। सारांश रूप में, जापानी अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रो को लघु, कुटीर एव मध्यम आकार के उद्योगो ने काफी प्रभावित कर रखा है।

जापानी विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of Japanese Trade)

“सन् 1968 के बाद जापान के विदेशी व्यापार में क्रान्तिकारी वृद्धि सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है।”

—प्रो लॉकवुड

विदेशी व्यापार जापान का प्राण है। जापान की आवादी बढ़ती जा रही है, उसके पास प्राकृतिक साधनों का अभाव है। और उसका भूमि क्षेत्र भी सीमित है, ऐसी स्थिति में आर्थिक दृष्टि से जीवित रहने के लिए जापान विदेश व्यापार पर निर्भर रहता है। जापानी अर्थ-व्यवस्था की गति जापान के विदेशी व्यापार पर निर्भर करती है। महायुद्ध के बाद से तो जापान विदेशी व्यापार पर पहले से भी अधिक निर्भर रहने लगा है। युद्ध से पहले देश की आवादी 6 करोड़ से भी कम थी और आज लगभग 10 करोड़ हो गई तथा निरन्तर बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई आवादी की दैनिक जीवन की आर्थिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए जरूरी है कि जापान अपने बहुत सारे खाद्य पदार्थ और अधिकतर कच्चा माल बाहर से मगाए और इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि इनकी कीमत का भुगतान करने के लिए वह कच्चे माल का परिष्कार करके उनसे तैयार और प्रदूषण-रहित चीजें बनाएँ तथा दुनिया की मण्डलों से उन्हें बेचे।

विदेशी व्यापार ने जनता की आर्थिक समृद्धि के चार चाँद लगा दिए हैं और आज यह देश विश्व के चार महान समृद्ध राष्ट्रों में गिना जाता है। जापानी माल ससार के सभी बाजारों में छाया हुआ है। जापान के विदेशी व्यापार की विशेषताओं और उसके लक्षणों को भली प्रकार समझने के लिए उपयुक्त होगा कि हम मेची पुनर्संस्थापन से लेकर अब तक जापान के विदेशी व्यापार के विकास को देखें। इसके हमें समय-समय पर इसमें प्रकट होने वाली प्रवृत्तियों का परिचय मिल सकेगा और हम यह जान सकेंगे कि किन लक्षणों और परिस्थितियों ने जापान के विदेशी व्यापार को समय-समय पर गति दी है।

जापानी विदेशी व्यापार के विकास की गाथा (History of Growth of Japanese Trade)

जापान के विदेशी व्यापार के विकास को मोटे रूप में हम अग्रलिखित कालों में विभाजित कर सकते हैं—

सन्तुलन के अन्तर को पाटा नहीं जा सका। 1894 से 1913 की अवधि में जापान के आयात निर्यात की निम्नलिखित स्थिति रही—

वर्ष	आयात	निर्यात (मिलियन येन में)	व्यापार सन्तुलन
1894-98	223 0	139 2	-83 6
1909-13	544 1	495 6	-48 5

इन आंकड़ों से प्रकट है कि इस अवधि में आयात और निर्यात दोनों ही क्षेत्रों में जापान आगे रहा। निर्यात और आयात में यह वृद्धि इस बात का चोत्कथी कि जापान निर्मित माल का एक प्रमुख निर्यातक देश बनने जा रहा है।

1914 से 1936 तक का काल

प्रथम महायुद्ध काल में विदेशी व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन मिला। 1914 से 1919 तक, विदेशी प्रतियोगिता का कोई भय न होने से जापान के निर्यात में बहुत ही अधिक वृद्धि हुई। इन पांच वर्षों के दौरान उसने मित्र राष्ट्रों के अधिकांश पूर्वी बाजारों को हथिया लिया। मित्र राष्ट्र युद्ध में व्यस्त होने के कारण प्रतियोगिता न कर सके। इस समय तक जापान ने अपने व्यापारिक जहाजों का अच्छा विकास कर लिया था अतः वह अपना माल दूर-दूर के देशों तक भेज सका। इस अवधि में जापान का विदेशी व्यापार अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। इस अवधि में उसके आयात निर्यात की स्थिति यह रही—

वर्ष	आयात	निर्यात (मिलियन येन में)	व्यापार सन्तुलन
1914-16	628 2	808 8	+180 76
1916-19	1625 9	1885 9	+260 0

महायुद्ध की समाप्ति पर 1920 से 1930 के दौरान जापान को पुनः विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। आघातग्रस्त रूप से जापान अभी इतना समथ नहीं हुआ था कि वह पश्चिम के उन्नत देशों का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूरा मुकाबला कर पाता। फलस्वरूप जापानी व्यापार और उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 1923 के भूकम्प ने भी जापान के विदेशी व्यापार पर बुरा असर डाला। स्थिति में सुधार लाने के लिए जापानी मुद्रा का अवमूल्यन किया गया, लेकिन कोई स्याई सुधार नहीं हो सका। फिर भी 1923 के बाद निर्यात बढ़ा। पर दूसरी ओर आयात भी अधिक हुआ क्योंकि अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए भारी मात्रा में विदेशी सामग्री और मशीनरी मगानी पड़ी। कुल मिलाकर 1920 से 1927 के बीच निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक हुआ।

विदेशी व्यापार को उन्नत करने और विदेशी बाजारों में पैर जमाने के लिए सरकार ने अपने उद्योगों का पुनर्गठन किया लेकिन तभी 1927 में वित्तीय संकट का और बाद में 1929 की विश्वव्यापी मन्दी का सामना करना पड़ा। इन दो संकटों ने जापानी उद्योगों की उन्नति को अस्त व्यस्त कर दिया और जापानी माल

की विदेशी माँग घट गई। 1921-24 के दौरान जापान के विपक्ष में व्यापार सन्तुलन (-) 448 8 मिलियन येन था जो 1928-30 की अवधि में (-) 3136 मिलियन येन हो गया।

मन्दीकाल के कुप्रभाव और विदेशी व्यापार की प्रतिफल स्थिति को दूर करने की दृष्टि से व अन्य भाषिक कारणों से जापान ने अपनी मुद्रा येन का पुनः अवमूल्यन किया। इसके प्रतिरिक्त सरकार शस्त्रास्त्रों के उत्पादन पर अधिक व्यय करने लगी। फलस्वरूप जापान की अर्थ-व्यवस्था न केवल सम्भल गई बल्कि बड़ी तेजी से सगृद्धि की ओर चल पड़ी। युद्ध-सामग्रियों के निर्माण पर विपुल व्यय करने से औद्योगिक क्रियाशीलता में भारी वृद्धि हुई जिसका विदेशी व्यापार पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ा। जहाँ जापान मन्दी काल के झटके को आसानी से पार कर गया, वहाँ विश्व के अन्य प्रमुख देशों की बड़ी बठिकाण्डियों का सामना करना पड़ा।

सन् 1931 से 1939 के बीच जापान का विदेशी व्यापार पहले की सभी सीमाओं को लाघ गया। उसके निर्यात व्यापार का आकार लगभग 83 से 85 प्रतिशत अधिक बढ़ गया जबकि आयात के आकार में वृद्धि लगभग 30 प्रतिशत ही हुई। मुख्य बात यह थी कि जापान का विदेशी व्यापार उस स्थिति में बढ़ा जब कि कुल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति सतोपजनक नहीं थी। जापान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में प्रमुखता अपने तीव्र औद्योगीकरण के फलस्वरूप प्राप्त कर सका। निर्मित माल के निर्यात के अनुपात में कमी हो गई। वृणरी और कच्चे और अर्द्ध-निर्मित माल का आयात गिरा।

इस अवधि में जापान पृथिवी विश्व के सभी बाजारों में छा गया, लेकिन सुदूरपूर्व और समुक्तराज्य अमेरिका जापानी विदेशी व्यापार के सबसे प्रमुख क्षेत्र थे। सुदूरपूर्व को जापान सूती माल और मशीनरी का निर्यात करता था तथा समुक्तराज्य अमेरिका को कच्चे रेशम, चाय, मछली आदि का। आयात के क्षेत्र में सुदूरपूर्व से जापान कच्चा माल खरीदता था और अमेरिका से कपास, खनिज तेल, बेहूँ और इजोनियरिंग सामग्री।

(Trade Corporation) स्थापित किया जिसे युद्ध काल में देश की व्यावसायिक नीति के सम्बन्ध में पूर्ण एकाधिकार था। युद्ध काल में जीते गए उपनिवेशों में भी कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था की गई।

महायुद्ध में प्रारम्भिक तूफानी विजयों के बाद धीरे-धीरे पलड़ा धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध होने लगा। बाद में घटना-चक्र इस तेजी से घूमा कि जापान, जर्मनी, इटली आदि धुरी राष्ट्र एक-एक करके विजित प्रदेशों को खोते गए। मित्र राष्ट्रों की भीषण बम वर्षा ने जापानी उद्योगों में अधिकांश को तहस-नहस कर दिया। युद्ध की समाप्ति पर जब जापान ने आत्म समर्पण किया तो उसकी अर्थ-व्यवस्था एक प्रकार से तबाह हो चुकी थी और उसका विदेशी व्यापार ठप्प हो गया था।

द्वितीय महायुद्धोत्तर एवं वर्तमान काल में जापानी विदेशी व्यापार

महायुद्ध की समाप्ति पर जो मित्र राष्ट्रीय सैनिक शासन घोषा गया, उसने 1946 में विदेश व्यापार निगम को भंग करके उसके स्थान पर विदेश व्यापार बोर्ड (Foreign Trade Board) की स्थापना की। सैनिक शासन के प्रारम्भिक दो वर्षों में व्यापार-संचालन सरकार के हाथ में रहा, लेकिन 1947 में निजी व्यापार को भी मुक्त कर दिया गया। इस समय जापान का निर्यात तो लगभग बन्द था, किन्तु आयात में वृद्धि होती जा रही थी। इस प्रकार जापान सम्भलना चाहकर भी सम्भल नहीं पा रहा था। लेकिन यह स्थिति अधिक समय तक चलने वाली नहीं थी। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और साम्यवाद के भय से मित्र राष्ट्र बाध्य हो चुके थे कि वे जापान के पुनरुद्धार के द्वार खोल दें।

सैनिक प्रशासन की नीति में परिवर्तन के फलस्वरूप जापान के व्यापारिक असन्तुलन को अमेरिकन आर्थिक सहायता द्वारा अधिकाधिक दूर किया जाने लगा। जापान के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए एक नौ सूत्री कार्यक्रम बनाया गया। 1947 के बाद जापान के उद्योग पुनः पनपने लगे, लेकिन विदेशी व्यापार की स्थिति में अविलम्ब कोई सुधार नहीं हो सका। 1949 के प्रारम्भ तक जापानी विदेशी व्यापार मुख्यतः सरकारी व्यापार संस्थानों और सैन्य प्रशासन के कठोर नियन्त्रण में संचालित होता रहा। सन् 1948 में जो निर्यात हुआ उसकी मात्रा 1934-36 के वार्षिक औसत के 8 प्रतिशत से अधिक नहीं थी, पर कुछ समय बाद 1950 के मध्य जो कोरिया युद्ध छिड़ा उसने जापानी अर्थ-व्यवस्था में प्राण फूँक दिये। जापान ने संयुक्तराष्ट्र सघीय सेना को अपना माल बेचकर विशाल धन राशि उपार्जित की, इसके प्रतिशत सन् 1951 में 1,949 की अपेक्षा निर्यात का मूल्य भी लगभग 165 प्रतिशत अधिक रहा। फलस्वरूप जापानी अर्थ-व्यवस्था तेजी से पनपी जिसका विदेशी व्यापार पर काफी अनुकूल प्रभाव पड़ा।

सन् 1952 में पराधीनता से मुक्त हो जाने पर जापान के आर्थिक पक्ष तेजी से फटफटाने लगे और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में वह तेजी से घुसता चला गया। सन् 1953 में सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन के अनेक उपाय किये गये। सन् 1954 के बाद निर्यात की तुलना में आयात गौण हो गया। फिर भी

1955 तक उसका निर्यात युद्ध पूर्व के स्तर को नहीं छू सका, हालांकि औद्योगिक उत्पादन उस समय दुगुने से भी अधिक हो गया।

जापान ने अपने निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए नये-नये बाजार ढूँढना और आयात के लिए नये-नये साधन खोजना शुरू कर दिया। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका की दिलचस्पी जापान के विदेशी व्यापार की समृद्धि में अधिकाधिक बढ़ती गई क्योंकि उसने समझ लिया कि एक समृद्ध जापान ही अमेरिकन हितों के लिए अधिक सुरक्षित हो सकता है। इन सभी कारणों से जापान का विदेशी व्यापार शीघ्र ही युद्ध पूर्व के स्तर को छूने लगा। निर्यात व्यापार की संरचना में परिवर्तन से भी इसे प्रोत्साहन मिला जहाँ सन् 1956 में निर्यात 250.1 करोड़ डॉलर का हुआ था वहाँ 1962 में यह 491.6 करोड़ डॉलर का हुआ। उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक सामान बाहर से मँगाने के फलस्वरूप आयात में भी वृद्धि हुई। 1956 में 322.9 करोड़ डॉलर का आयात हुआ था जबकि 1962 में 563.7 करोड़ का। विगत कुछ वर्षों में जापान के बढ़ते हुए आयात-निर्यात का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है —

(मूल्य करोड़ डॉलर)

वर्ष	आयात	निर्यात	कुल व्यापार	व्यापार शेष
1947	52.6	17.4	70.0	-35.2
1965	816.9	845.2	1,662.1	+28.3
1970	1,888.1	1,931.8	3,819.9	+43.7
1974	6,200.0	5,600.0	11,800.0	-600.0
1977	7,076.0	8,051.0	15,127.0	+975.0

तुलना से स्पष्ट है कि महायुद्ध काल में जापान के विदेशी व्यापार को इतना पवरदस्त आघात पहुँचा कि अनेक वर्षों तक व्यापार शेष उसके प्रतिकूल रहा। 1947 में 52.6 करोड़ डॉलर के आयात की तुलना में निर्यात केवल 17.4 करोड़ डॉलर का हुआ और कुल व्यापार 70 करोड़ डॉलर का हुआ। 1947 से, मुख्यतः कोरिया युद्ध के कारण विदेशी व्यापार में लगभग चौगुने से भी अधिक वृद्धि हुई और आयात एवं निर्यात को मिलाकर कुल व्यापार 335.5 करोड़ डॉलर का हुआ। फिर भी आयात अधिक मूल्य का रहा, अतः व्यापार शेष का घाटा 64 करोड़ डॉलर का हुआ। 1965 में लगभग 28 करोड़ डॉलर से व्यापार शेष अनुकूल रहा। कुल व्यापार लगभग 1,662 करोड़ डॉलर का हुआ जो 1947 की तुलना में लगभग 24 गुना अधिक था। 1970 में व्यापार शेष 43.7 डॉलर से पक्ष में रहा और कुल व्यापार लगभग 3,820 डॉलर का हुआ जो 1947 की तुलना में 54 गुना से भी अधिक था। 1974 में कुल व्यापार 11,800 डॉलर का हुआ किन्तु आयात 6,200 करोड़ डॉलर का था जबकि निर्यात 5,600 के थे, अतः व्यापार शेष 600 करोड़ डॉलर से प्रतिकूल रहा। बाद के वर्षों में स्थिति में तेजी से सुधार हुआ और

1977 में व्यापार दोष 975 करोड़ डॉलर से पक्ष में रहा। इस वर्ष कुल व्यापार लगभग 15,127 करोड़ डॉलर का हुआ जो 1947 की तुलना में 216 गुना अधिक था।

आज जापान का विदेशी व्यापार इतना अधिक समृद्ध है जितना पहले कभी नहीं था। जापान द्वारा आयात की जाने वाली चीजों में मुख्य ये हैं—(क) खाद्य-पदार्थ—चावल, गेहूँ, नमक, चीनी (ख) औद्योगिक सामग्री—कपास, कच्ची ऊन, लोहा अयस्क, वाक्साइड, ताँबा अयस्क, कोककारी कोयला, कच्चा रबड़, कच्चा तेल आयात की सर्व प्रमुख चीजें कच्चा माल, ईंधन और खाद्य पदार्थ हैं। जापान प्रायः अपने सारे के सारे कच्चे तेल के लिए, कपास और रबड़ के लिए, तथा 90 प्रतिशत से अधिक लोहा अयस्क और चाँदी के लिए विदेशी स्रोतों पर निर्भर करता है। निर्यात की दृष्टि से प्रमुख चीजें ये हैं—समुद्री चीजें, कपड़ा और कपड़े की चीजें, कच्चा रेशम, सूती घागा, रेयोनी घागा, नकली कपड़े की चीजें, सूती चीजें, रेशमी चीजें, ऊनी चीजें, रेयोन की चीजें, बुने हुये रेयोन की चीजें, कपड़े, औपचारिक आदि तथा रासायनिक चीजें, रासायनिक उर्वरक, चीनी-मिट्टी के बर्तन, धातु और धातु की चीजें, लोहा और इस्पात, मशीनें, कपड़े की मशीनें, तिलाई मशीनें, रेडियो सैट, मोटर गाड़ियाँ आदि, जहाज, प्लाईवुड, प्रकाशीय उपकरण, खिलौने आदि। धातु की चीजों, मशीनों और रासायनिक पदार्थों का निर्यात विशेष रूप से बढ़ा है।

जापान के बदलते हुए औद्योगिक ढाँचे और विदेशों में उसके नये व्यापार तथा धन्य कारणों से देश के विदेश व्यापार के स्वरूप में और उसके प्रसार-क्षेत्रों में स्पष्ट परिवर्तन आया है। जहाँ तक प्रसार-क्षेत्र का प्रश्न है युद्ध के बाद से एशिया के बजाय उत्तरी अमेरिका पर जोर बढ़ गया है। युद्ध से पहले, जापानी माल की सबसे अधिक निकासी एशियाई मंडियों में हुआ करती थी। महाद्वीपीय चीन, भारत और इंडोनेशिया में ही जापान के कुल निर्यात का 40 प्रतिशत हिस्सा खप जाता था। आज जापान का एक सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है।

विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्रिय है। सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

जापान के विदेशी व्यापार के तीव्र प्रसार के कारण

जापानी विदेशी व्यापार का जो चित्र खींचा गया है उससे न केवल इसकी विशेषताएँ और महत्ता स्पष्ट होती है, बल्कि इसके विकास के कारणों का भी आभास मिल जाता है। फिर भी स्पष्टता की दृष्टि से इसकी वृद्धि के कारणों को निम्नानुसार प्रकट करना उचित होगा—

(1) तोकुगावा शासन काल में जापानी अर्थ-व्यवस्था पूरी तरह कृषि प्रधान और पिछड़ी हुई थी। पृथक्करण की नीति के फलस्वरूप विदेशी-व्यापार नगण्य था, लेकिन मेजी सरकार ने पृथक्करण की नीति का परित्याग करके विदेशी व्यापार के द्वार खोल दिए।

() मेजी शासन-काल में जापान के औद्योगीकरण की नींव डाली गई। पाश्चात्य औद्योगिक प्रणालियों को अपनाया गया। उद्योगों का विकास होने से निर्यात माल का निर्यात बढ़ा।

(3) कुछ वस्तुओं के उत्पादन में जापान को अन्य देशों के मुकाबले सदा प्रतियोगात्मक लाभ रहा। उदाहरणार्थ, रेशम के उत्पादन में जापान की श्रेष्ठता ने उसे बड़ी सहायता पहुँचाई। इसके निर्यात के बल पर वह अपने औद्योगीकरण के लिए आवश्यक सामग्री का भ्राम्यता कर सका। सूती वस्त्र उद्योग में भी जापान ने इतनी प्रगति कर ली कि आगे चलकर वह इस क्षेत्र के 'राजा' ब्रिटेन से भी आगे निकल गया।

(4) प्रथम महायुद्ध काल में विदेशी प्रतियोगिता के न रहने से जापान के विदेशी व्यापार को भारी प्रोत्साहन मिला। पश्चिमी देश युद्ध में फँसे रहे और जापान ने उनके पूर्वी बाजारों को हथिया लिया।

(5) सत्तार की व्यापारिक गतिविधियाँ भी जापान के विदेशी व्यापार के अनुकूल रही। उदाहरणार्थ, अमेरिका जापान के रेशम का निरन्तर भारी ग्राहक बना रहा और व्यापार की शर्तें भी जापान के अनुकूल रही।

(6) जापानियों की सीखने और सुधरने की प्रवृत्ति ने उनके विदेशी व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया। सरकार ने विदेशी वस्तुओं के नमूने मगान-मगा कर जापानी उद्योगपतियों और निर्माताओं को दिए ताकि वे भी वैसे प्रयत्न उनसे अच्छी वस्तुओं का निर्माण करके विदेशी बाजारों को प्रोत्साहन न दें।

(7) जापान में श्रम के सस्ते होने से माल की उत्पादन लागत कम रही। फलस्वरूप वह पश्चिमी देशों की शक्तिशाली प्रतियोगिता का मुकाबला कर सका।

(8) जापान की विकसित व्यवस्था भी बहुत अच्छी रही। जापानी एजेंटों ने विदेशी बाजारों की माँग का अच्छी तरह अध्ययन किया और तदनुसार पूर्ति को बढ़ाया। जापानियों ने सदैव विविध प्रकार की ऐसी वस्तुओं को बनाने की चेष्टा की जो सस्ती भी हो और आकर्षक तथा अच्छी भी। जापानी उत्पादन उपभोक्ताओं की रुचियों के अनुसार बदलता रहा, अतः उसकी लोकप्रियता में स्थायी कमी कभी नहीं आ पाई।

(9) जंबलु संगठन ने विदेशी व्यापार का विस्तार करने में भारी भूमिका प्रदा की। जबसु परिवारों के पास बड़े-बड़े उद्योग, बैंक, बीमा और जहाजी निगम रहे। फलस्वरूप वे सभी (बीमा, जहाजी और बैंकिंग संगठन) समुक्त रूप में प्रभावशाली ढंग से काम कर सके और अपने देश के विदेशी व्यापार को गति दे सके।

(10) विदेशी व्यापार को बढ़ाने में सरकार ने सदैव सक्रिय रुचि ली और समय-समय पर उपयोगी कदम उठाए। विदेशों में वाणिज्य मिशन भेजे गए। ऐसे नियम बनाए गए जिनसे वस्तुओं की किस्म सुधरी हुई निकले। छोटी औद्योगिक इकाइयों के गिहड़ बनाए गए जिनका निर्यात व्यापार में बड़ा सहयोग रहा। सरकार ने निर्यात की दृष्टि से उपयोगी वस्तुओं को बढ़ाने वाले लघु और कुटीर उद्योगों को

आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया। समय-समय पर मौद्रिक व्यवस्था में सुधार करके या परिवर्तन करके विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। निर्यात किए जाने वाले माल के समुचित निरीक्षण की व्यवस्था की गई। जहाजरानी का तेजी से विकास किया गया ताकि जापानी माल विश्व के बाजारों में आसानी से भेजा जा सके। निर्यात व्यापार के क्षेत्र में तोचशीलता रखी गई। जापान उदार व्यापारिक व्यवस्था का समर्थक रहा और इससे भी उसके विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सरकार ने अधिकांशतः उन्हीं सामग्रियों का आयात किया जिनसे देश का औद्योगीकरण हो ताकि उन उद्योगों में माल बनाया जाकर बाहर भेजा जा सके।

(11) विगत कुछ वर्षों से जापान सरकार ने आयात-नियन्त्रण को भी अधिकाधिक ढीला करने की नीति अपनाई है। इसके अतिरिक्त, अधिकाधिक प्रतियोगिता की सम्भावनाओं का सामना करने के लिए जापान के निजी उद्योगों ने अपने सदस्यों और सौज सामान को आधुनिक बनाने की दृष्टि से औद्योगिक पूँजी-निवेश का एक विस्तृत कार्यक्रम लागू किया है।

इन्हीं सब कारणों से जापान की अर्थ-व्यवस्था और विदेशी व्यापार की स्थिति अत्यधिक समृद्ध बन सकी है।

जापान के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ (Salient Features of Japanese Foreign Trade)

जापान के विदेशी व्यापार के विकास की कहानी पढ़ने के उपरान्त उसकी निम्नलिखित विशेषताएँ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं—

1. विदेशी व्यापार की प्रधानता—विदेशी व्यापार जापानी अर्थ-व्यवस्था की समृद्धि और गति का मुख्य आधार है। निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों की कमी और सीमित भू-क्षेत्र की परिस्थितियों में आर्थिक दृष्टि से जीवित रहने के लिए जापान विदेशी व्यापार पर अत्यधिक निर्भर है। 1870 में जापान का विदेशी व्यापार 70 लाख डॉलर था पर अब यह लगभग 2,000 करोड़ डॉलर से भी अधिक हो गया है।

2. विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि—जापान का विदेशी व्यापार निरन्तर वृद्धिशील है। यह वृद्धि आयात और निर्यात दोनों ही क्षेत्रों में हो रही है। उदाहरणार्थ 1967 में आयात-मूल्य 1167 करोड़ डॉलर था जो 1970 में बढ़कर लगभग 1888 करोड़ डॉलर हो गया और इसी प्रकार निर्यात-मूल्य 1967 में 1045 करोड़ डॉलर था जो बढ़कर 1970 में लगभग 1931 करोड़ डॉलर हो गया।

3. विदेशी व्यापार संरचना में परिवर्तन—जापान के बदलते हुए औद्योगिक ढाँचे और विदेशों में इसके नये व्यापार आदि के फलस्वरूप उसके विदेशी व्यापार के स्वरूप में और उसके प्रसार क्षेत्रों में स्पष्ट परिवर्तन आया है। मुद्र से पहले कपड़ा उद्योग के कच्चे माल का आयात कुल आयात का 32 प्रतिशत हुआ करता था और कपड़े का निर्यात कुल निर्यात के आधे के बराबर था। लेकिन 1965 तक आते-आते कपड़ा उद्योग के कच्चे माल का आयात कुल आयात के 10.4 प्रतिशत के बराबर

रह गया और कपड़े का निर्यात कुल निर्यात के 18.67 के बराबर। अब तो इस स्थिति में कुछ और भी परिवर्तन आया है। इसी प्रकार जापान के आयात-मूल्य का अधिकांश कच्चे माल और ईंधन पर लगता है। लेकिन उसमें कमी आती जा रही है। उदाहरणार्थ युद्ध से पहले वह कुल आयात का 80 प्रतिशत होता था। 1965 में 58.6 प्रतिशत हो गया और अब और भी कम। दूसरी ओर निमित्त माल के आयात में पूर्वाधिका वृद्धि हुई है। प्रसार क्षेत्र की दृष्टि से युद्धोत्तर काल में एशिया के बजाय उत्तरी अमेरिका पर जोर बड़ गया है। निर्यात-क्षेत्र में धातु की वस्तुओं मशीनों और रासायनिक पदार्थों का निर्यात बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में तैयार माल के निर्यात में विशेष प्रगति हुई है।

4 आयात नियन्त्रण ढीला करने की नीति—जैसा कि कहा जा चुका है, पिछले कुछ वर्षों से जापान सरकार ने क्रमशः आयात-नियन्त्रण ढीले करते जाने की नीति अपनाई है। 1965 तक आयात व्यापार के 93 प्रतिशत पर से प्रतिबन्ध हटा लिए गए थे और अब तो दोष व्यापार प्रतिबन्ध भी शिथिल कर दिए गए हैं।

5 औद्योगिक पूँजी-निवेश में निरन्तर वृद्धि—अधिकाधिक प्रतिपोगिता की सम्भावनाओं के सफल मुकाबले के लिए जापान के निजी उद्योगों ने अपने सयनों और साज-सामान को आधुनिक बनाने की दृष्टि से औद्योगिक पूँजी निवेश का विस्तृत कार्यक्रम अपनाया है जिससे कच्चे माल और मशीनों के आयात में वृद्धि हुई है।

6 लोचशील व्यवस्था—समूर्ण जापानी अर्थ-व्यवस्था लोचशील है, अतः सम्पानुसूल परिवर्तनों के माध्यम से जापान विदेशी व्यापार में सफ़टों को टालने अथवा उनका सफल मुकाबला करने की क्षमता रखता है। प्रो० एलन ने ठीक ही लिखा है कि “जापानी अर्थ-व्यवस्था की लोचशीलता ने उसे नये बाजार ढूँढने और नई प्रतिस्थापना वस्तुओं से उन बाजारों तथा वस्तुओं के होने वाले नुकसान से बचाया है जो बाजार और वस्तुओं के व्यापार में होने वाले परिवर्तनों से हुआ।” युद्धोत्तर काल में विदेशी व्यापार की संरचना और दिशा में जो परिवर्तन होते रहे हैं, वे इसकी लोचशीलता के परिणामक हैं।

7 निर्यात वृद्धि के प्रति जागरूकता—जापानी उद्योगपति निर्यात-वृद्धि के प्रति अत्यधिक जागरूक हैं। वे उत्पादन लागत को कम करने के लिए आधुनिकीकरण और स्वचालितता की पद्धतियाँ तो अपना ही रहे हैं, पर साथ ही विश्व बाजार को अपने उत्पादनों से परिचित कराने के लिए प्रदर्शनियों, शिष्टमण्डलों, नमूनों की भेंट आदि उपायों का भी भरसक आश्रय लेते हैं।

8 सरकार की प्रोत्साहन नीति—जापान सरकार ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देने की प्रभावशाली नीति अपना रखी है। निर्यात सब्सिडी की प्रगतिशील नीतियाँ अपनाई गई हैं और निर्यात उद्योगों को विभिन्न रियायतें दी जाती हैं। आयातों को हमेशा उत्पादन तथा निर्यात-मुख्य (Production-cum Export Oriented) बनाने की नीति पर बल दिया गया है।

9. अमेरिकी प्रोत्साहन—जापानी विदेश व्यापार को प्रोत्साहित करने में संयुक्त राज्य अमेरिका का विशेष योगदान रहा है। जैसाकि हम कह चुके हैं, आज जापान का एक सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। अमेरिका जापान के निर्यातों का सबसे बड़ा ग्राहक और जापान के आयातों का सबसे बड़ा विक्रेता रहा है।

10 अन्य—और भी अनेक बातें जापानी विदेशी व्यापार को समृद्धि को बढ़ाने वाली हैं। उदाहरणार्थ जापानी लोग पक्के “बनिया” हैं जो अपने आर्थिक लाभ के लिए अपनी विदेश नीति में समयानुसार हेर-फेर करने से नहीं झुकते। हाल ही के वर्षों में जापान साम्यवादी देशों के साथ भी अपना व्यापार-सम्बन्ध बढ़ा रहा है। भारत के साथ जापान के विदेशी व्यापार में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जापान का विदेशी व्यापार पूर्वपेक्षा आज अधिक विविधता-पूर्ण है और अधिकांश व्यापार सामुद्रिक मार्ग से होता है।

निष्कर्ष रूप में, जापान का विदेशी व्यापार उसके आर्थिक समृद्धि की रीढ़ की हड्डी है।

अ) एक विकास में राज्य का योगदान

(Role of State in Economic Development of Japan)

“मेजी सम्राट के शासन-काल में जापान ने कुछ ही दशकों में वह सब पाने का प्रयत्न किया जिसे पाने में पश्चिम को सवियाँ लगी थीं। एक आधुनिक राष्ट्र अस्तित्व में आया ...।”

—विदेश-मन्त्रालय, जापान

लगभग एक शताब्दी पूर्व जापान पूरी तरह एक कृषि प्रधान देश था। सुदूरपूर्वी कृषि अर्थ-व्यवस्था के सभी लक्षण उसमें विद्यमान थे। दरिद्रता का बोल-बाला था, भूमि पर जनसत्ता का अनुचित भार था और कृषि उत्पादन क्षमता बहुत ही गिरी हुई थी। परम्परागत और पिछड़ा हुआ प्राविधिक ज्ञान था, राजनीतिक दृष्टि से देश सामन्तवादी प्रथा में जकड़ा हुआ था और विदेशों से उसका सम्बन्ध नगण्य होने से विदेशी व्यापार नहीं के बराबर था। तोकुगावा शासन समाप्ति के के समय तक जापान की यही स्थिति थी।

लेकिन 1868 में मेजी पुनर्स्थापन के बाद जापान की अर्थ-व्यवस्था तेजी से अगड़ाई लेकर उठ खड़ी हुई। विदेश मन्त्रालय, जापान के एक प्रकाशन के अनुसार “मेजी काल (1868-1912) विश्व इतिहास के सबसे उल्लेखनीय युगों में से है। सम्राट मेजी के शासन काल में देश ने कुछ ही दशकों में वह सब कुछ पाने का प्रयत्न किया जिसे पाने में पश्चिम को सवियाँ लगी थीं। एक आधुनिक राष्ट्र अस्तित्व में आया...” उसमें आधुनिक उद्योग थे, आधुनिक राजनीतिक संस्थाएँ थी और समाज का आधुनिक ढाँचा था।” मेजी पुनर्स्थापन के समय से ही जापान की आर्थिक प्रगति के द्वार खुल गए और राज्य की सक्रिय भूमिका के फलस्वरूप लगभग 75 वर्षों के अल्पकाल में ही जापान विश्व का एक अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बन गया। आज जापान को हम विश्व के चार महान समृद्ध औद्योगिक देशों में गिनते हैं और इसका मुख्य श्रेय इसी बात को है कि सरकार ने देश के आर्थिक विकास में निर्णायक भूमिका अदा की है। जापान के आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका को पृथक्-पृथक् शोधकों में देखना उपयुक्त होया।

कृषि क्षेत्र में राज्य की भूमिका

(Role of State in Agricultural Development of Japan)

यद्यपि कृषि क्षेत्र में कुछ रुचि तोकुगावा शासन ने भी ली, लेकिन राज्य की वास्तविक रूप से सक्रिय भूमिका का आरम्भ मेजी युग में हुआ जो बढ़ता ही गया। सरकार ने फार्म-व्यवस्थापन किया, कृषि वित्त की व्यवस्था की, कीमत-स्थायित्व लागू किया और कृषि के विकास की दृष्टि से विभिन्न कार्य किए। सरकार का योगदान मुख्यतः इस रूप में रहा—

1 कृषि वित्त की व्यवस्था के लिए 1896 में एक कानून पास करके दस मिलियन येन की पूंजी से एक बैंक की स्थापना की गई जो किसानों को अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति पर ऋण दे सके। इसके अलावा 46 कृषि एवं औद्योगिक बैंक स्थापित किए गए। सरकारी वित्तीय सहायता सरकारी कार्य-गृहों और खाद-फैक्ट्रियों को प्रोत्साहन देने के लिए भी प्रदान की गई। 1922 में किसानों को डाक-घर के सुरक्षित कोष और जीवन बीमा पालिसी से ऋण दिया जाने लगा। 1925 तक इस प्रकार के सैंकड़ों वेयर हाउस स्थापित कर दिए गए जो किसानों के माल पर साख प्रदान करने की अनुमति दें। सन् 1920 में एक केन्द्रीय सहकारी बैंक भी स्थापित किया गया जिसने 1924 के बाद काम करना शुरू कर दिया। सहकारी समितियों को प्रोत्साहन दिया गया जिनकी संख्या 1937 तक लगभग 16 हजार हो गई। 1932 में विशेष ऋण और हानि मुआवजा कानून पास किए गए ताकि केन्द्रीय सहकारी बैंक व बन्धक बैंक किसानों को दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण दे सकें। सरकार ने किसानों की नकद आय बढ़ाने के लिए राहत कार्य भी शुरू किए मन्दी के समय रेशम की कीमत बनाये रखने के लिए वित्तीय सहायता दी गयी। राहत-सहायताओं का मुख्य भाग कृषि भूमि के लिए सुधार, देहाती नालियों और जल-व्यवस्था में सुधार आदि के काम में लिया गया।

2 राज्य ने कृषि क्षेत्र में कीमत-स्थायित्व का प्रयास किया। 1921 में चावल-नियन्त्रण अधिनियम पास किया गया जिसके अनुसार सरकार को चावल की पूर्ति नियमित करने के लिए चावल खरीदने, बेचने और एकत्र करने की शक्ति मिली। 1925 में एक अन्य कानून कीमतों पर नियन्त्रण लगाने के बारे में पारित हुआ। इन प्रयत्नों से कृषि उत्पादन की कीमतों में गिरावट रूक गई। पर मन्दी-काल में, विशेषकर महामन्दी के समय कीमतें तेजी से गिरी। सरकार ने 1930 में दूसरा चावल कानून पास करके यह व्यवस्था की कि नियन्त्रण स्तर से कीमतें गिरने पर राज्य चावल की खरीददारी कर लेगा और अधिकतम स्तर से कीमतों के ऊपर उठने पर राज्य बिक्री कर देगा। 1933 में सरकार ने न्यूनतम और अधिकतम कीमतें निश्चित करने तथा चावल-नियमन और चावलों के आयात पर लाइसेंस लगाने के लिए एक चावल मण्डल की स्थापना की अनुमति दी।

3 सरकार ने 1930 में रेशम कीमतें स्थाई बनाने के लिए अधिनियम पारित किया। इसी कानून के अनुसार रेशम उत्पादकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था

की गई। गेहूँ के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। गेहूँ और घाट पर कर्तों की मात्रा बढ़ाई गई तथा गेहूँ के उत्पादन के लिए सुधरे हुए साधनों व प्रणालियों को काम में लाया जाने लगा। योजनाओं द्वारा गेहूँ के उत्पादन को 1937 तक लगभग 50 मिलियन बुशल तक बढ़ाने की योजना बनाई गई और विनालो की आय को 30 प्रतिशत बढ़ाने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया।

4 बेजी सरकार ने किसानों को सामन्तवादी प्रतिबन्धों से मुक्त करके उन्हें खेती में सुधरे हुए तरीकों का प्रयोग करने को प्रोत्साहित किया। कृषि के अन्तर्गत भूमि क्षेत्र में वृद्धि की गई तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। कीड़ो-मकोड़ों और विभिन्न प्रकार की कृषि बीमारियों पर नियंत्रण, प्रादि से कृषि का उत्पादन बढ़ाया गया। आगे चलकर राज्य ने गहन कृषि को अधिकधिक प्रोत्साहित किया। राजकीय प्रयत्नों से कृषि का आधुनिकीकरण हुआ तथा कृषि यन्त्रों का प्रयोग किया जाने लगा।

5 राज्य ने भूमि-क्रय नीति और भूमि सुधार नीति द्वारा कृषि को प्रोत्साहित किया। प्रारम्भ में एक 25 वर्षीय कार्यक्रम निश्चित करके किसानों को वह भूमि खरीदने की सुविधा दी गई जिसे वह खुद जोतता था। किसानों को अधिक से अधिक भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और अच्छे बीजों व अच्छी खाद को शोकप्रिय बनाया गया। महायुद्ध के बाद सैनिक शासन ने यह अनुभव किया कि कृषि सुधारों के लिए व्यापक भूमि-सुधार आवश्यक है। पत्तस्वरूप बड़-बड़े किसानों को समाप्त कर दिया गया और सभी जमींदारों से एक निश्चित मात्रा से अधिक भूमि लेकर उसे जनता के हाथ में देच दिया गया। जमींदारों को उनकी भूमि के बदले मुफ्तवाजा दे दिया गया। इन सुधारों से युद्ध के बाद जापान कृषक-स्वामियों का देश बन गया। 1952 में सैनिक शासन की समाप्ति के बाद भी प्रत्यक्ष-भरोसा रूप से सरकार का यह प्रयत्न निरन्तर जारी है कि कम से कम भू-क्षेत्र में अधिक से अधिक कृषि उत्पादन किया जाए। सरकारी प्रयत्नों और निजी परिश्रम का ही यह सम्मिलित परिणाम है कि जापान में प्रति एकड़ उपज विश्व में सबसे अधिक होती है।

कृषि क्षेत्र में जापान के अनुभवों से लाभ उठाते हुए भारत-सरकार की कीमत-न्यायित्व, देहाती वित्त, फार्म-अपबस्थापन, गहन-कृषि प्रादि के उपायों को प्रभावशाली ढंग से अपनाकर और जापानी खेती को प्रोत्साहन देकर अपनी कृषि समस्याओं का बहुत कुछ निराकरण कर सकती हैं।

औद्योगिक विकास में सरकार की भूमिका

(Role of Govt. in Industrial Development)

जापान के आधुनिक औद्योगिक रूप का श्रेय बहुत कुछ सरकार के सक्रिय सहयोग को है। बेजी युग में सरकार ने आवागमन, व्यापार और उद्योग की स्वतन्त्रता पर लगाए गए अधिकार प्रतिबन्धों को समाप्त करके उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहित किया। सरकार ने जापानी व्यापार व उद्योग का पश्चिमीकरण करने की

नीति अपनाई। फलस्वरूप आवश्यक विदेशी उपकरणों का आयात किया गया और आधारभूत उद्योग स्थापित किए गए। प्रारम्भ में राज्य ने पहले के बहुत से कारखानों की व्यवस्था स्वयं अपने हाथ में लेकर उनका गठन किया। इसके अतिरिक्त अनेक वस्तुओं के निर्माण के लिए राज्य ने खुद आधुनिक ढंग के नए-नए कारखानों की स्थापना की। गैर-सरकारी उद्यम को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य द्वारा विदेशी मशीनों का आयात किया गया और उन्हें आसान किस्तों पर निजी उद्यम कर्ताओं को बेच दिया गया। राज्य द्वारा बस्त्र-निर्माण, युद्धपोत निर्माण, सीमेंट उत्पादन आदि के उद्देश्य से विभिन्न कारखाने स्थापित किए गए। व्यापारिक जहाजों के विकास पर भी सरकार ने बहुत अधिक ध्यान दिया। न केवल देश में ही जहाजों का निर्माण आरम्भ किया गया बल्कि विदेशों से जहाज खरीदकर बाद में जापानी फर्मों को सौंप दिए गए।

आगे चलकर 1882 के बाद मेजी सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में स्वयं कार्य करने की नीति को छोड़कर सरकारी औद्योगिक संस्थानों को निजी उद्योगपतियों के हाथ बड़े रियायती और सुविधाजनक दरों पर बेच दिए। इस नीति के फलस्वरूप निजी क्षेत्र को भारी प्रोत्साहन मिला। राज्य ने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप बन्द नहीं किया, बरन् समुचित आर्थिक विकास की दृष्टि से देश के औद्योगिक विकास-संचालन में अपना महत्वपूर्ण हाथ बनाए रखा। सरकार द्वारा निर्यात व्यापार को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से जापान के उद्योग-धन्धों को भारी प्रेरणा मिली।

जापानी सरकार विकासशील उद्योगों को आवश्यकतानुसार संरक्षण व आर्थिक सहायता देती रही। भूकम्प और मन्दी काल के समय सरकार द्वारा उद्योगों की संरचना तथा युक्तिकरण की नई नीति अपनाई गई जिससे देश के औद्योगिक उत्पादन में काफी प्रगति हुई। महान मन्दी के परिणामस्वरूप सूती वस्त्र व रेशम के निर्यात में बहुत अधिक कमी आ जाने तथा अन्य आर्थिक अस्त-व्यस्तताएँ उत्पन्न हो जाने से सरकार बहुत चिंतित हुई। उसने परिस्थिति में सुधार के लिए पहले तो कुछ अन्य उपाय किए, किन्तु बाद में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। यद्यपि तात्कालिक परिणाम अच्छे नहीं निकले, लेकिन आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ अन्य ठोस उपाय करने पर शुभ परिणाम निकलने लगे। सरकार ने सम्पूर्ण औद्योगिक व्यवस्था को संरचना के उद्देश्य से एक 'इंडस्ट्रियल रेशनलाइजेशन ब्यूरो' (Industrial Rationalisation Bureau) की स्थापना की। इसके अतिरिक्त अनुचित आन्तरिक प्रतियोगिता को समाप्त करने के लिए और कम्पनियों में आपसी समझौतों के आधार पर कार्टेल्स (Cartels) की स्थापना के लिए 1931 में 'स्टेबल इंडस्ट्रीज कंट्रोल एक्ट' (Stable Industries Control Act) पारित किया। इन उपायों को अपनाने से पूर्व इंग्लैंड व अन्य देशों द्वारा स्वयंमान त्याग देने पर जापान ने भी इनका अनुकरण करते हुए येन का पुनः अवमूल्यन किया जिससे जापानी अव्यवस्था पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ा।

महामन्दी से द्वितीय महायुद्ध के बीच की अवधि में जापानी सरकार ने

सन्धानों के निर्माण को आर्थिकाधिक प्रोत्साहन दिया जिसने सारे औद्योगिक क्षेत्र में सक्रियता आ गई। ज्यों-ज्यों जापान में सैनिक नियन्त्रण बढ़ता गया, त्यों-त्यों उद्योगों पर सरकारी नियन्त्रण अधिकाधिक होता गया। युद्ध की तैयारियों के लिए सरकार ने बड़े पैमाने के उद्योगों को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। सन् 1934 में पारित एक नियम के अधीन सरकार ने लोहा व इस्पात निर्माण करने वाली सभी निजी कम्पनियों के नियन्त्रण को अपने हाथ में ले लिया। 1935 में 'पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज ला' (Petroleum Industries Law) द्वारा पेट्रोल उद्योग पर सरकार का नियन्त्रण स्थापित हो गया। इसी तरह 1936 के 'शिपिंग रूट कंट्रोल ला' (Shipping Route Control Law) के अनुसार सम्पूर्ण जहाजरानी को पूर्ण सरकारी नियन्त्रण के अन्तर्गत ले लिया गया। संक्षेप में द्वितीय महायुद्ध से पूर्व सरकार ने सभी महत्वपूर्ण उद्योगों को अपने नियन्त्रण में लेकर युद्ध की पूरी तैयारियाँ कर लीं। अन्य उद्योगों में भी, युद्ध के उद्देश्या से, सरकार ने विभिन्न प्रकार से प्रोत्साहन देना शुरू किया। सरकार का यह प्रयास रहा कि निर्यात की वस्तुओं के गुणों में सुधार हो।

महायुद्ध काल में प्रारम्भिक सफलताओं के बाद अन्त में जापान की भीषण पराजय हुई और पहले इस देश ने जो कुछ प्राप्त किया था, युद्ध के अन्त तक उनका अधिकांश विनष्ट हो गया। जापान की सम्पूर्ण अर्थ-अवस्था तहस-नहस हो गई। युद्ध के बाद सरकार देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में जुट गई। जब सैनिक प्रभुत्व ने जापान के औद्योगिक पुनरुद्धार के मार्ग खोल दिए तो सरकारी प्रयासों की सक्रियता से जापान पुनः आर्थिक प्रगति की ओर दृष्टांत भरने लगा। सरकारी निवेश में बहुत प्रगति हुई। 1958 तक सरकारी स्याई निवेश कुल राष्ट्रीय उपज का लगभग 8 प्रतिशत हो गया। सरकार ने 1961 से 1970 तक के लिए एक दस वर्षीय योजना बनाई जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय आय को दुगुना करना रखा गया। पिछले वर्षों की प्रगति यही बताती है कि जापान योजना के लक्ष्यों को गंभीर प्रकार पूरा कर सका है।

आर्थिक क्षेत्र में प्रारम्भ से अब तक के राजकीय योगदान से प्रकट है कि जापान का वर्तमान तीव्र औद्योगिकरण राज्य की सक्रियता का ही परिणाम है।

सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में राज्य की भूमिका (Role of Govt. in the Field of Small & Cottage Industries)

सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में जापान सदा से विश्व-विख्यात रहा है। आज के औद्योगिक जापान में भी सूक्ष्म और कुटीर इकाइयाँ का अपना महत्व है। इन उद्योगों की समृद्धि और कार्यक्षमता बनाए रखने में मेज़ी पुनर्स्थापन के समय से ही सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

मेज़ी युग में सरकार ने निर्यात व्यापार में सूक्ष्म व मध्यम आकार के उद्योगों के महत्व का समझते हुए इस प्रकार के नियम बनाए जिनसे सूक्ष्म उद्योग मुफ्त हुए तथा उन्नत जिल्स का मान उत्पादित करें। सन् 1914- से 1930 तक सरकार ने

विभिन्न प्रकार के कानून पारित किए। इन कानूनों का प्रमुख उद्देश्य ये रहे— (i) छोटे छोटे उद्योगपतियों और व्यावसायियों के बीच सहकारिता का विकास हो ताकि वे उत्तम बोटि की वस्तुओं का उत्पादन कर सकें, (ii) अनावश्यक और नुकसानदेह प्रनियोगिता हतोत्साहित हो, (iii) गिल्ड जैसी स्वेच्छिक सत्याम्रा का विकास हो ताकि लघु उद्योगों द्वारा उत्पन्न माल की समय समय पर अच्छी तरह जाँच की जा सक एव (iv) निरीक्षण और जाँच की ऐसी व्यवस्था बन जाए जिससे लघु उद्योगों द्वारा निर्यात के लिए उत्पन्न की जाने वाली वस्तुओं में उतंगेतर गुणार की प्रोत्साहन मिले।

मेजी सरकार की इस नीति के कारण लघु व कुटीर उद्योगों की वारंशमता और वस्तु उत्पादन की श्रेष्ठता का विकास हुआ। महायुद्ध के बाद जब मन्दी का दौर शुरू हुआ तो सरकार ने लघु व कुटीर उद्योगों को आर्थिक सहायता देकर उनका पोषण किया। कम व्याज पर ऋण और छोटे-छोटे अनुदान देने की व्यवस्था की गई। लघु उद्योगों की निर्माता-गिल्डों के रूप में संगठित किया गया ताकि वे सहकारिता के आधार पर अच्छी तरह क्रय विनय कर सकें। मुद्रा अवमूल्यन के दौरान भी सरकार ने लघु व मध्यम आकार के उद्योगों की सहायता की।

द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में सरकार द्वारा लघु उद्योग बोर्ड, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना आदि का गठन व क्रियान्वयन किया गया। इनका विस्तार से वर्णन लघु उद्योग सम्बन्धी पूर्ववर्ती अध्याय में किया जा चुका है। यद्यपि सरकारी और निजी क्षेत्र की वर्तमान प्रवृत्ति जापान में अधिकाधिक बृहद स्तरीय औद्योगिक संस्थानों का विकास करने की है, तथापि लघु व कुटीर उद्योगों के आवश्यक महत्त्व को उपेक्षित नहीं किया गया। जिन क्षेत्रों में ये उद्योग अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, उनमें यथासम्भव हस्तक्षेप नहीं किया जाता।

विदेशी व्यापार के क्षेत्र में सरकार की भूमिका

(Role of State in Foreign Trade)

तोकुगावा शासन काल में सरकार की पृथक्करण की नीति के फलस्वरूप विदेशी व्यापार के रास्ते बन्द रहे, लेकिन मेजी सरकार ने विदेशों से आर्थिक सम्बन्धों के द्वार खोलकर विदेशी व्यापार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मेजी शासन काल में जापान के विदेशी व्यापार ने बड़ी उन्नति की। विदेशों से तकनीकी विशेषज्ञ बुलाए गए और आवश्यक सामग्री का आयात करके देश में बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण की नींव डाली गई। इन उद्योगों द्वारा निर्यात माल के निर्यात को हर प्रकार से प्रोत्साहन दिया गया। सरकार ने लघु व मध्यम आकार के उद्योगों का भी इस ढंग से नियंत्रण दिया कि वे मुझरे हुए व उन्नत माल का उत्पादन करें जिससे उनके निर्यात में वृद्धि हो सके। वास्तव में मेजी सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्धों के लिए आवश्यक उपरेखा प्रस्तुत करने में सुदृढ भूमिका अदा की। जिन विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन परम्परागत तरीके से होता था, उनका निर्माण के लिए आधुनिक तरीके के नए-नए कारखानों की स्थापना की गई। मौद्रिक व्यवस्था में विभिन्न

व्यापार पहले से भी अधिक उन्नत हो गया। अब जापानी सरकार कुछ वर्षों से आयात नीति को भी अधिकाधिक उदार बना रही है।

यातायात के क्षेत्र में सरकार की भूमिका

(Role of State in the Field of Transport and Communication)

तोकुगावा शासन के समय जापान में यातायात की समुचित व्यवस्था का सर्वथा अभाव था, किन्तु मेजी शासन काल में नई सरकार ने आर्थिक विकास की दृष्टि से यातायात के साधनों का महत्त्व समझा और इस दिशा में प्रभावशाली कदम उठाए। रेलवे के निर्माण पर सबसे अधिक जोर दिया गया। विदेशों से पूंजी और तकनीक द्वारा रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया। आवश्यक पूंजी के लिए सरकार ने आन्तरिक और बाह्य दोनों साधनों से कर्ज लेने की व्यवस्था की। निजी कम्पनियों को भी रेलवे निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। रेलवे कम्पनियों को सरकार ने कम व्याज पर ऋण दिया और भूमि की सुविधायें प्रदान कीं। यद्यपि रेलवे का द्रुत गति से विकास हुआ, तथापि सुनियोजित योजना का अभाव में इसमें कई दोष आ गए तथा अनेक अर्थार्थिक लाइनों का निर्माण हो गया। अन्त में रेलवे को पूर्णतः अपने अधीन न करने के लिए सरकार ने 1906 के बाद रेलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। 17 निजी लाइनें सावजनिक नियन्त्रण क्षेत्र में आ गईं। राष्ट्रीयकरण के बाद इस क्षेत्र में कई सुधार किए गए और नई लाइनों का निर्माण किया गया। सरकार ने मुख्य रेलवे लाइनों को अपने हाथ में लेकर एक प्रकार से सम्पूर्ण रेलवे पर अपना प्रभाव क्षेत्र विस्तृत कर लिया। सहायक लाइनों के निर्माण को यद्यपि निजी कम्पनियों के हाथ में ही छोड़ दिया गया, पर वे स्वभावतः सरकारी नियन्त्रण से अछूत न रही। सन् 1908 में जापान की सम्पूर्ण रेलों को एक रेलवे परिषद के अन्तर्गत रख दिया गया। सन् 1948 में सभा राष्ट्रीयकृत रेलों का नियन्त्रण यातायात मन्त्रालय को सौंप दिया गया।

वर्तमान समय में सम्पूर्ण जापान में रेलों का जाल बिछा है जिनमें राजकीय और निजी दोनों रेलें हैं। राजकीय रेलवे 1963-64 में लगभग 21,180 किलोमीटर थी जबकि निजी रेलवे लगभग 7,400 किलोमीटर। जापान नेशनल रेलवेज जो कि जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक संस्थान है, एक सार्वजनिक निगम है।

रेलवे यातायात के समान ही सामुद्रिक यातायात के क्षेत्र में भी मेजी पुनर्संस्थापन काल से ही राज्य का योग रहा है। मेजी युग में सरकार ने व्यापारिक और सैनिक दृष्टिकोण से जहाजरानों के विकास पर काफी ध्यान दिया। सामुद्रिक यातायात कम्पनियों की स्थापना की गई जिनमें सरकारी और निजी दोनों व्यवस्थाएँ रही। जापान सरकार ने जहाजरानी के विकास के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए। एक मुख्य अधिनियम (Navigation Subsidy Act) 1896 में पास किया गया जिसके अन्तर्गत बड़े-बड़े जहाजों के निर्माताओं को अनुदान दिया जाने लगा। चूंकि सरकार पर आर्थिक सहायता का बोझ बहुत बढ़ गया, अतः 1909 में एक नया अधिनियम बनाया गया जिसके अन्तर्गत सरकार कुछ खास प्रकार के जहाजों

को ही आर्थिक सहायता देने लगी। सरकार ने यह कदम जापान की जहाजरानी में गुणात्मक सुधार के उद्देश्य से उठाया।

प्रथम महायुद्ध काल में जापानी सरकार ने जहाजरानी के विकास को तेजी से आगे बढ़ाया और सुदूर पूर्व के देशों में जहाजरानी को जाने का धक्का देना ताकि वहाँ के बाजारों में जापानी माल छा सके। महायुद्ध के बाद जब मन्दी का दौर चला तो जापानी जहाज उद्योग को बड़ा धक्का लगा। समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने 1932 में 'मिटानो और बनाओ योजना' (Scrap and Build Plan, 1932) क्रियान्वित की जिसका उद्देश्य यह था कि पुराने जहाजों को समाप्त करके नए जहाजों का निर्माण किया जाए। सरकार का यह कदम जहाजरानी की क्षमता और कुशलता बढ़ाने में काफी उपयोगी सिद्ध हुआ। सरकार ने जहाज निर्माण के क्षेत्र में समुचित आर्थिक सहायता दी। सरकार की जागरूकता और सहायता तथा निजी उद्यम-व्यवसायों के परिश्रम आदि के फलस्वरूप द्वितीय महायुद्ध के आते-आते जापानी जहाजरानी के अन्तर्गत बहुत बड़ी मात्रा में नए और आधुनिकतम जहाज हो गए।

द्वितीय महायुद्ध काल के प्रारम्भ में जहाजरानी की क्षमता में बहुत अधिक वृद्धि हुई, किन्तु महायुद्ध की समाप्ति पर जापान की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के विनाश के साथ ही जहाजी उद्योग भी प्रायः नष्ट हो गया। जहाँ द्वितीय महायुद्ध से पूर्व जापान के पास 5 हजार के आसपास सामुद्रिक जहाज थे वहाँ 1946 में इनकी संख्या केवल 17 रह गई। सैनिक प्रशासन ने 1948 तक जापान को केवल तटीय जहाजों के निर्माण की अनुमति दी, परन्तु बाद में स्थिति में सुधार हो गया। सैनिक शासन की समाप्ति के बाद स्वतन्त्र जापानी सरकार द्वारा नीचे व्याज पर ऋण देने के फलस्वरूप जहाजरानी का तेजी से विकास शुरू हो गया। कोरियाई युद्ध से जहाज निर्माण उद्योग को भारी गति मिली। सरकार जहाज निर्माण उद्योग की प्रगति के लिए आवश्यक कानूनों और आर्थिक सहायता के प्रति जागरूक रही जिससे 1956 तक जापान विश्व का सबसे बड़ा सामुद्रिक जहाज निर्माता देश हो गया। सरकार ने 1961 से 1965 के बीच विभिन्न प्रकार के लगभग 40 लाख टन सामुद्रिक जहाज बनाने के लिए संशोधित पञ्चवर्षीय योजना तैयार की जिसमें पूरी सफलता मिली। सरकारी प्रयासों ने जहाजरानी के सुनियोजित विकास का क्रम जारी है। वायु और सड़क यातायात के क्षेत्र में भी सरकार का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

इस सम्पूर्ण विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आज हम जापान की शक्ति और समृद्धि के विश्व पर देखते हैं, इसके लिए राज्य की प्रधान श्रेय है। बिना सरकारी प्रयासों के जापान की इतनी अधिक उन्नति होना असम्भव था। द्वितीय महायुद्ध के दौरान तहस-नहस हो गए जापान का यह आश्चर्यजनक विकास अधिकतर सुनियोजित व जागरूक सरकारी प्रयासों का परिणाम है। सरकार द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए योजनाओं और नए-नए आर्थिक कार्यक्रमों का सहारा लिया गया है। सरकार का सत्य जापान की कुस राष्ट्रीय उत्थिति को 10 वर्ष पूरे की स्थिति से लगभग दुगुना कर देना है।

7

द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में आर्थिक विस्तार के कारक

(Factors Causing Post-World War II
Economic Expansion)

जापान के आर्थिक विकास के पिछले अध्यायो में किए गए विश्लेषण से यह भली-भाँति स्पष्ट हो चुका है कि मेजी पुनर्संस्थापन-काल से जापान की आर्थिक प्रगति शुरू हुई और द्वितीय महायुद्ध काल से पूर्व तक जापान सप्तर के महान औद्योगिक राष्ट्रों में गिना जाने लगा। लगभग 75 वर्षों के अल्पकाल में ही छोटे-छोटे टापुओं पर वैसे हम देश ने आश्चर्यजनक प्रगति कर दिखाई। उद्योग, कृषि, विदेशी व्यापार, जहाजरानी, सैनिक शक्ति, शस्त्र-निर्माण आदि सभी क्षेत्रों में इस देश ने अपनी विलक्षण प्रगति में सप्तर के उन्नत राष्ट्रों को आश्चर्य में डाल दिया।

द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर विनिष्ट जापान का चित्र

द्वितीय महायुद्ध का विस्फोट होने पर जापान ने जर्मनी और इटली का पक्ष लिया। मिन राष्ट्रों के विरुद्ध प्रारम्भिक आश्चर्यजनक सैनिक सफलताओं के बाद अन्त में उसकी घोर पराजय हुई। मेजी पुनर्संस्थापन (1868) के समय से द्वितीय महायुद्ध का श्रीगणेश होने तक जापान ने आर्थिक और सैनिक क्षेत्र में जो कुछ भी उपलब्ध किया था, वह सब विनिष्ट हो गया। 1945 में आत्मसमर्पण करते समय जापान के पाम विनिष्ट घर के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। मिन राष्ट्रों की भयानक दम-शर्पा के फलस्वरूप उमकी 30 से 40 प्रतिशत नगरीय जनता गृहहीन हो गई थी। उसके हिरोशिमा और नागासाकी जैसे विशालतम औद्योगिक नगर राख के ढेर बन चुके थे। महायुद्ध से पूर्व उसके सामुद्रिक जहाजों की संख्या 5 हजार के आसपास थी जो अब केवल 17 रह गई है। उसके 50 हजार से भी ऊपर हवाई जहाज बर्बाद हो गए थे। युद्धपोत, पोत-रक्षक, जगी जहाज, विध्वंसक पनडुब्बी जहाज-निर्माण-केन्द्र सभी कुछ पूरी तरह विनिष्ट हो गए थे। मिन राष्ट्रों के विमानों ने जापान के 44 नगरों को धूल में मिला दिया था। लाखों जापानी सैनिक काल की गोद में समा गए थे। केवल हताहत नागरिकों की संख्या ही 8 लाख से ऊपर थी। जापान की अधिकांश मशीनरी, उसके रेल मार्ग और कारखाने मिट्टी में मिला दिए गए थे।

महायुद्ध के बाद जापान का सम्पूर्ण औपनिवेशिक साम्राज्य अतीत की कहानी बन गया। उसका प्रादेशिक प्रभुत्व केवल चार मौलिक द्वीपों—होनशू, शिकोकू, क्युशू और होकाइडो तक सीमित रह गया। युद्ध के दौरान जापान की लगभग आधी औद्योगिक क्षमता नष्ट कर दी गई और शेष क्षमता भी अधिकांश वित्तीय संकटों व प्रतिबन्धों के कारण पगु बन गई।

आत्मसमर्पण के बाद जापान का वास्तविक नियन्त्रण संयुक्तराज्य अमेरिका की सैनिक कमान के नियन्त्रण में आ गया। जापान में अमेरिकन सेनापति जनरल मैकार्थर को मिन राइटो के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष का पद प्रदान किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण नाम-मात्र का रहा और व्यावहारिक शक्ति का उपयोग मैकार्थर ने किया। 1945 से 1947 के बीच मैकार्थर ने जापानी सरकार को लगभग एक हजार निर्देश दिए। जापान के युद्ध और न-सेना मन्त्रालय खत्म कर दिए गए, सैनिक सेवाओं से सभी जापानियों को हटा दिया गया, जापान की सुरक्षा संस्थाओं को उपयोगिताहीन बना दिया गया, शस्त्रास्त्रों व गोला-बारूद के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, विस्फोटक पदार्थों को समुद्र में डुबो दिया गया और लगभग 65 लाख जापानी सैनिकों व सामान्य नागरिकों को एशिया तथा प्रशान्त महासागर के द्वीपों में इधर-उधर भेज दिया गया।

सैनिक प्रशासन की प्रारम्भिक नीति जापान को हर प्रकार से कुचल देने की रही ताकि वह पुनः शक्ति और समृद्धि का सचय न कर सके। विदेशों में जापानी नागरिकों की सम्पत्ति उन देशों की क्षति-पूर्ति के रूप में प्रदान कर दी गई। जापान की विदेशी सम्पत्ति, जो लगभग 3 अरब डॉलर के मूल्य की थी हस्तगत कर ली गई। सन् 1946 में राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा भेजे गए 'फाले मिशन' ने जापान की भावी क्षति का सर्वेक्षण करके यह सिफारिश की कि, "जापान की युद्ध-क्षमता शक्ति से कुचल दी जानी चाहिए ताकि उसका जीवन-स्तर न्यूनतम हो जाय।" इस मिशन के सुझाव पर जापान के विभिन्न महत्त्वपूर्ण उद्योगों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और अनेक कारखानों की संस्था अत्यधिक कम कर दी गई। चूंकि अमेरिका को जापान की जनता के लिए भोजन-सामग्री जुटाने पर प्रतिदिन लगभग 10 लाख डॉलर व्यय करने पड़ रहे थे, अतः अमेरिका की नीति यही रही कि जापान से इतने वज्जे का व्यय और क्षति-पूर्ति एकत्रित की जानी चाहिए। सारांशतः मिन राइटो के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष (SCAP) की नीति जापानी साम्राज्यवाद के नीतिक आधार को पूर्णतः नष्ट कर देने की रही और क्षति-पूर्ति इस तरह लादी गई जिससे जापान की औद्योगिक युद्ध-क्षमता का पुनर्निर्माण न हो सके।

पर यह स्थिति अधिक समय तक नहीं बनी रही। शीघ्र ही जापान के नियन्त्रक सैनिक प्रशासन को अपनी नीति बदलनी पड़ी और बाद में 1952 में शान्ति सन्धि पर हस्ताक्षर होने के उपरान्त जापान पुनः एक स्वाधीन राष्ट्र हो गया। जापानियों ने आश्चर्यजनक नीति से अपना पुनरुद्धार किया। अद्भुत साहस, प्रवीणता, कार्यक्षमता और परिश्रम का परिचय देते हुए 1955 के आते आते जापानियों ने अपने

युद्ध के घाव भर लिए और आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया सम्पन्न कर ली। इसके बाद अपूर्व तेजी से जापान ने औद्योगिक प्रगति की। उन्होंने अपने नष्ट-भ्रष्ट देश को समृद्धि के उस शिखर पर पहुँचा दिया कि आज जापान का स्थान सत्सार के चार महान समृद्ध राष्ट्रों में गिना जाता है तथा वह समय दूर नहीं है जब उसे सत्सार का राष्ट्र नम्बर तीन गिना जाने लगेगा।

इस पृष्ठभूमि के उपरान्त अब हमें देखना चाहिए कि द्वितीय महायुद्धोत्तर काल में जापान के इस आश्चर्यजनक आर्थिक विस्तार में किन कारणों और परिस्थितियों ने सहयोग दिया।

महायुद्धोत्तरकाल में आर्थिक विस्तार के कारक

जापान के आर्थिक पुनरुद्धार और विस्तार को मुख्यतः दो कालों में बाँटना उपयुक्त है—(क) 1946 से 1955 तक का काल, जिसमें आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया (The Process of Economy) लगभग पूर्ण हो गई एवं (ख) 1956 से वर्तमान काल तक, जिसमें आर्थिक विस्तार की गति आश्चर्यजनक रही।

(क) 1946 से 1955 तक का काल

इस अवधि में आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया में मुख्यतः निम्नलिखित कारणों व परिस्थितियों ने सहयोग दिया—

1. सैनिक प्रशासन की परिवर्तित नीति—जापान के सैनिक, आर्थिक और औद्योगिक पतन से विकट समस्याएँ पैदा हो गईं। एक तरफ तो अमेरिका को जापानी श्राव्य सामग्री का अभाव दूर करने और आवास, चिकित्सा आदि समस्याओं का हल खोजने में विपुल धनराशि व्यय करनी पड़ रही थी और दूसरी ओर जापान पूर्ण पतन से यह चिन्ता पैदा हो गई थी कि पूर्वी एशियाई बाजारों पर कहीं रुस। उसके गूट का कोई अन्य राज्य प्रभुत्व न जमा ले। महायुद्ध के बाद मास्को एशिया के निर्धन राज्यों में साम्यवाद के प्रचार को हर प्रकार से उत्साहित कर रहा था। वह जापान के छात्रों व श्रमिकों में साम्यवाद फैलाने में सफल होने लगा था। इसके अतिरिक्त 'पूर्व और पश्चिम' के बीच शीत युद्ध ने जन्म ले लिया था। अब इस बात की तीव्र आवश्यकता उत्पन्न हो गई थी कि स्वतन्त्र विश्व अपनी पूरी शक्ति के साथ अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से सघर्ष करे। चीन में तेजी से पनपता हुआ साम्यवाद भी एशियाई राज्यों के लिए गम्भीर खतरा पैदा कर रहा था।

उपरोक्त परिस्थितियों में अमेरिका के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह जापान को पुनः आदर और सम्मानपूर्ण स्तर प्रदान करे तथा उसके पुनरुद्धार की दिशा में आगे बढ़े। बढ़ते हुए साम्यवाद के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए और प्रशान्तसागरीय क्षेत्र में अपने हितों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने जापान के पुनर्जागरण को अनिवार्य मान लिया।

इस अनुभूति के बाद अमेरिका ने सर्वप्रथम एक 'नौ सूत्री आर्थिक स्थिरता कार्यक्रम' बनाया। इसका उद्देश्य बजट को सन्तुलित करना, कर एकत्रित करने व कार्य को सुगम बनाना, वेतन-क्रम स्थिर बनाना, मूल्य नियंत्रण को सुदृढ़ करना,

विदेशी व्यापार और विदेशी मुद्रा-निदानों में सुधार करना, राशनिंग व्यवस्था को सुधारना, कच्चे तेल और तैयार शुद्ध तेल के उत्पादन में वृद्धि करना, खाद्य सामग्री एकत्र करने के कार्यक्रम को सुधारना आदि था। सैनिक प्रशासन ने जापान के पुनरुद्धार की दृष्टि से इस कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित किया। जापानी सरकार को आवश्यक निर्देश दिए गए और उसकी श्रमशास्त्रियों को बहुत कुछ स्वीकार किया गया। सन् 1948 में कुछ विख्यात अमेरिकन व्यवसायियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने जापान की यात्रा की। इन मण्डल ने अपनी सरकार को यह सुझाव दिया कि जापान को यथा-सोपान अमेरिकन निर्भरता से मुक्त कर दिया जाय।

शुद्ध अमेरिकन प्रशासन ने जापान को एक स्वतन्त्र राष्ट्र का स्तर देने की नीति पर विशेष सक्रिय रूप से चलना शुरू कर दिया। जापान की आर्थिक दशा सुधारने के लिए क्षतिपूर्ति को स्थगित कर दिया गया और हड़ताला पर विभिन्न प्रतिबन्ध लगा दिए गए ताकि उत्पादन बाध न हो सके। दिसम्बर, 1948 में जापानियों को निर्दान के लिए उत्पादन में अधिकारिता वृद्धि करने का अधिकार दे दिया गया। जापान को सतार की गतिविधियों में पुनः भाग लेने का अधिकार भी दिया गया। जापान के औद्योगिक उत्पादन के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री उपलब्ध कराई गई। यह सामग्री विशेषतः अमेरिका में मिली।

सैनिक प्रशासन की इस परिवर्तित नीति से जापान के आर्थिक पुनरुत्थान को आभारशिला तैयार हो गई।

2 जापानी अधिकारियों को विशेष उत्पादन नीति—सैनिक प्रशासन की नीति से प्रोत्साहित होकर जापानी अधिकारियों ने एक विशेष उत्पादन नीति अपनाई। इस नीति के अन्तर्गत कोयला, लोहा और इस्पात को प्राथमिकता दी गई क्योंकि इन्हें उत्पादन के क्षेत्र से विप्ले चक्र को तोड़ने के लिए आभारभूत सामग्री समझा गया। इस नीति के फलस्वरूप 1948 में कोयले का उत्पादन लगभग 35 मिलियन टन तक जा पहुँचा अर्थात् 1934-36 की अवधि का 90 प्रतिशत कोयला उत्पादित किया गया। लोहे और इस्पात के उत्पादन में भी तीव्र वृद्धि हुई। सन् 1948 में और 1949 में कच्चे लोहे का उत्पादन युद्ध पूर्व काल का क्रमशः 43 प्रतिशत और 82 प्रतिशत हुआ। इसी तरह इस्पात पिन्ड और टना हुआ इस्पात 1948 व 1949 में युद्ध पूर्व स्तर का क्रमशः 34 व 60 प्रतिशत हुआ। कृषिगत ज्वरकों और सूती धातों के उत्पादन को भी पर्याप्त महत्त्व दिया गया जो कि जापान की आय-निर्भर व्यवस्था के लिए आवश्यक था।

3 उत्पादकों को वित्तीय सहायता—जापानी सरकार और केन्द्रीय वित्तीय अधिकारियों ने आभारभूत सामग्री के उत्पादकों को हुसकर वित्तीय सहायता दी। 1946 के अन्त तक बैंक ऑफ जापान ने अन्त बैंकों को औद्योगिक पुनर्निर्माण में वित्तीय सहायता देने के लिए उदारतापूर्वक साक्ष प्रदान की। फरवरी, 1947 में स्थापित पुनर्निर्माण वित्तीय बैंक (Reconstruction of Finance Bank) ने इस दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया। इस बैंक ने प्रतिवार्य उद्योगों को पुनर्जीवन प्रदान

करने के लिए श्रृंखला दिए और इस प्रकार जापान के औद्योगिक पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

4 अम-शक्ति का उपयोग—औद्योगिक विनाश और सगठन के विपटन आदि के कारण जापान में विशाल अम-शक्ति देकार हो गई। आर्थिक-पुनरुद्धार के समय उस अम-शक्ति को यथा-साध्य उपयोग में लाना गया। तत्पश्चात् किन्तु कार्य-नुसल अम शक्ति के कारण उत्पादन की लागत कम रही और निर्यात के विस्तार को प्रोत्साहन मिला। युद्धोत्तरकाल में वृष्टि पर आधिन जनसंख्या घटती गई और अधिकाधिक लोग औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होते गए। फलस्वरूप जापान के औद्योगिक विस्तार में बहुत अधिक सुविधा हुई।

5. कोरिया युद्ध—जून, 1950 के कोरिया युद्ध में विन्फोर्ट ने जापानी अर्थ-व्यवस्था को अवरुद्ध सहायता पहुँचाई। जापान ने समुद्रसंपत्त संधीय सेना को निमित्त सानान बेचकर विपुल धनराशि अर्जित की। इस युद्ध से जापान के निर्यात व्यापार को भारी प्रोत्साहन मिला और वह विशाल डॉलर सुरक्षित कोष निर्मित कर सका। कोरिया युद्ध के दौरान जापान का औद्योगिक उत्पादन युद्ध पूर्व के स्तर को छू गया। अर्जित धन को जापान न उद्योगों का प्राधुनिकीकरण करने और नई तकनीकों का प्रयोग करने में लगाया। वास्तव में कोरिया युद्ध ने जापान के अर्थ आर्थिक शरीर में रक्त का संचार कर दिया जिससे उसकी भावी समृद्धि निश्चित हो गई।

6 आषारभूत उद्योगों में पूँजी-निवेश—इन प्रारम्भिक वर्षों में पूँजी-निवेश आषारभूत उद्योगों में करने की नीति अंगनाई गई। विद्युत-शक्ति उत्पादन, जहाज निर्माण उद्योग, विद्युत मशीन का निर्माण, इंजीनियरिंग उद्योग आदि के विकास पर अधिकाधिक ध्यान दिया गया। टिकाऊ उपभोक्ता सामानों के उद्योगों का भी विकास किया गया। जापान के शस्त्रास्त्र निर्माण उद्योग भी, सीमाश्रमों में रहते हुए पनपने लगे। प्राथमिकता के उद्योगों को सरकारी सहायता दी गई। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप जापान की आर्थिक व औद्योगिक क्षमता में तेजी से सुधार हुआ।

7 अम सच, भूमि सुधार और मुद्रा-स्फीति का प्रभाव—युद्धोत्तर काल में वृष्टि क्षेत्र में भूमि-सुधार के लिए एक क्रान्तिकारी कार्यक्रम अपनाया गया और अमिक सधों को नए सिरे से संगठित किया गया। लगभग 50 लाख एकड़ भूमि अतुल्यत जमींदारों व जागीरदारों से लेकर किसानों को वितरित कर दी गई। जमींदारों की कुल भूमि का लगभग तीन चौथाई भाग रेंट को दे दिया गया। फलस्वरूप किसानों की आय काफी बढ़ गई और वृष्टि-अवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ। सैनिक शासन ने युद्धकालीन अम-नियमों को समाप्त करके अमिकों के वैधानिक सगठनों को प्रोत्साहित किया।

अमिकों और किसानों की आर्थिक हालत सुधरने से आन्तरिक बाजार का विस्तार हुआ जिससे औद्योगिक पुनर्निर्माण को काफी बल मिला। औद्योगिक उत्पादन माँग की तुलना में कम होने से मुद्रा-स्फीति की दशाएँ उत्पन्न हो गईं। इस मुद्रा-स्फीति से आर्थिक विकास को परोक्ष रूप से बड़ा प्रोत्साहन मिला। पूँजी-निर्माण

तेजो से हुआ। यद्यपि सैनिक शासन ने गुद्रा स्फीति विरोधी नीति पर अमल किया, लेकिन कोरिया युद्ध तक गुद्रा स्फीति स्थिति बनी ही रही।

8 सैनिक व्यय में कमी—महायुद्धोत्तर काल में जापान के सैनिक व्यय में भारी कमी हो गई। शस्त्रास्त्र निर्माण सम्बन्धी और सैन्य उपकरण सम्बन्धी प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जापानी सरकार के लिए यह सम्भव न था कि वह अपनी सैनिक शक्ति का संचय करती। जहाँ सन् 1940 में कुल व्यय का लगभग 63.8 प्रतिशत भाग सेना पर व्यय किया गया था वहाँ 1960 में कुल सरकारी व्यय का केवल 5.9 प्रतिशत भाग ही सेना पर व्यय पर हुआ। सैनिक खर्च में इस भारी कमी से औद्योगिक क्षेत्र में अधिकाधिक विनियोग सम्भव हुआ जिससे जापान के आर्थिक विकास में द्रुतगति से वृद्धि हुई।

9 तकनीकी प्रगति—युद्धोत्तर काल के प्रारम्भ में जापान तकनीकी क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं कर सका। 1948 के बाद जब जापान को सभार की गति-विधियों में गुन भाग लेने का अधिकार दिया गया तो जापानी विद्वानों और नेताओं ने एशिया व यूरोप की विस्तृत यात्राएँ की। प्राविधिक योग्यता प्राप्त विभिन्न जापानियों ने विदेशों का भ्रमण किया। जापान ने वारिण्य और व्यापार के लिए विदेशों में अपनी एजेंसियाँ स्थापित की और स्वदेश में उन्नत तकनीकी का प्रसार करने की भरपूर चेष्टा की। 1955 से 1959 के दौरान तकनीकी के क्षेत्र में तीव्र प्रगति हुई। औद्योगिक क्षेत्र में नए-नए तरीके अपनाए गए जिससे उत्पादन बहुत ही अधिक बढ़ गया। जैवतु के विघटन और एकाधिकार विरोधी नियमों से भी तकनीकी प्रगति को विदोष बल मिला।

विभिन्न रूपों में सरकारी सहायता—सरकार ने देश के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए औद्योगिक संस्थानों को केवल वित्तीय सहायता ही नहीं दी बल्कि अन्य उपायों से भी उन्हें प्रोत्साहन दिया। सरकार ने ऐसे विभिन्न कदम उठाए जिनसे देश के आर्थिक विकास की गति मिली। 1950-51 और 1953 में साधनों के पुनर्मूल्यान (Revaluation of Assets) की व्यवस्था की गई। पर चूँकि पुनर्मूल्यान स्वैच्छिक था, अतः खासकर बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ हुआ। सरकार ने औद्योगिक संस्थानों के आधुनिकीकरण और विनियोग की वृद्धि के लिए व्यावसायियों के स्थाई साधनों के अग्रिम चिसावट की व्यवस्था की। उदाहरणार्थ यन्त्रों व सामुद्रिक जहाजों के लिए तीन वर्षों में 50 प्रतिशत से अधिक चिसावट का प्रावधान रखा गया। विशेष चिसावट की व्यवस्था से यद्यपि सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था के तीव्र विकास की आशा की गई, लेकिन लाभ मुख्यतः बड़े उद्योगपतियों और व्यावसायियों को ही हुआ। सरकार ने अपनी कर-नीति में सुधार द्वारा भी आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया। विभिन्न प्रकार के सुरक्षित कोषों की व्यवस्था की गई जिनमें व्यावसायिक संस्थानों के पूँजीगत साधनों में काफी वृद्धि हुई। सरकार ने कुछ इस प्रकार के सुरक्षित कोष खोले जिनमें रखी जाने वाली रकम को कर-निर्धारण के लिए घाटे के अन्तर्गत लिया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था से पूँजी निर्माण में

नई गुना वृद्धि सम्भव हुई। उदाहरणार्थ कम्पनियों द्वारा प्रयोग में लाई गई पूँजी में 1952 से 1959 के बीच लगभग 3.17 गुना और करो से छूट प्राप्त कोपो की मात्रा से लगभग 10.2 गुना वृद्धि हुई। सरकार ने वक्त व पूँजी-निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक करो में छूट की व्यवस्था की।

इन सभी कारणों पर परिस्थितियों का सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि 1955 तक जापान ने अपने महायुद्धकालीन घाव भर लिया और आर्थिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया लगभग सम्पन्न कर ली।

(ख) 1956 से वर्तमान तक का काल

1955 के बाद जापान ने आर्थिक व औद्योगिक क्षेत्र में इतनी आश्चर्यजनक गति से प्रगति की जिसका उदाहरण विश्व के किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता। Prof Sakae Tsunoyama ने जापान के अपने आर्थिक इतिहास में संयुक्त-राष्ट्र सभ द्वारा प्रकाशित आँकड़ों को दिया है जिनसे पता चलता है कि 1955 से 1961 के बीच जापान के औद्योगिक उत्पादन का विकास विश्व के अन्य किसी भी राष्ट्र की अपेक्षा अधिक हुआ। ये आँकड़े इस प्रकार हैं —

प्रमुख देशों में औद्योगिक उत्पादन के गुरानांक (Indices) (1955=100)

सन्	जापान	यू एस ए	इंग्लैण्ड	फ्रांस	पश्चिमी जर्मनी	इटली	रूस
1955	100	100	100	100	100	100	100
1956	125	104	100	110	108	107	108
1957	143	104	102	120	114	114	123
1958	145	97	101	125	118	119	135
1959	180	110	106	130	126	132	150
1960	226	113	113	145	140	152	164
1961	270	114	115	153	148	169	178

1961 के उपरान्त वर्तमान समय तक जापान की औद्योगिक क्षमता और भी अधिक बढ़ गई है। संयुक्त-राष्ट्र सभ की एक विज्ञप्ति के अनुसार सन् 1958 से 1967 के बाद जहाँ औद्योगिक विकास में रूस में 121, इटली में 113, अमेरिका में 71 और ब्रिटेन में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं जापान में 245 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जो विश्व में सर्वाधिक थी।

युद्धोत्तर काल में जापान ने राष्ट्रीय और प्रतिव्यक्ति आय में काफी वृद्धि की है। स्थिर मूल्यों के आधार पर जापान की राष्ट्रीय आय में 1955-60 के अवधि में विकास की औसत वार्षिक दर लगभग 9 प्रतिशत रही थी 1960-64 की अवधि में यह लगभग 10-8 प्रतिशत वार्षिक रही और 1967 में विकास दर 14 प्रतिशत से कुछ ही कम रही। यह विकास दर आश्चर्यजनक ही मानी जायेगी क्योंकि पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में राष्ट्रीय

उत्पादन में औसत वार्षिक दर प्रायः 3 प्रतिशत से 8 प्रतिशत तक रही है। जापान में 1976-77 में राष्ट्रीय आय में लगभग 13 प्रतिशत वृद्धि जबकि वास्तविक आय में लगभग 7 प्रतिशत। 1960-70 की अवधि में जापान में राष्ट्रीय आय में औसत वार्षिक वृद्धि की दर लगभग साठे ग्यारह प्रतिशत रही जो विश्व का कोई भी राष्ट्र प्राप्त नहीं कर सका। जहाँ 1950 में जापान में प्रति व्यक्ति आय लगभग 123 अमेरिकी डॉलर थी वहाँ 1970 में यह लगभग 1122 अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई और 1976-77 में 4930 अमेरिकी डॉलर तक। औद्योगिक उत्पादन में जापान ने जो आशातीत वृद्धि की है उसका उल्लेख पिछले एक अध्याय में किया जा चुका है। 1970 को आधार वर्ष लें तो औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 1977 में लगभग 125 हो गया था। विदेशी व्यापार में भी जापान ने अप्रत्याशित वृद्धि की है। पिछले लगभग 2 दशकों में जापान ने 1950 के मुकाबले 26 गुना से भी अधिक निर्यात व्यापार और बीसगुना से भी अधिक आयात व्यापार किया है। जापान का विदेशी व्यापार जो महायुद्ध के बाद अनेक वर्षों तक घाटे में चल रहा था अब भारी बचत में बदल गया है। 1977 में जापान का व्यापार शेष लगभग 975 करोड़ डॉलर पक्ष में था। अनेक 1977 में ही जापान के निर्यातों में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि आयात कुल 9 प्रतिशत ही बढ़ा 1977 में जापान का विदेशी विनिमय कोष लगभग 18000 करोड़ डॉलर था। जापान अन्त-उत्पादकता में भी धीरे-धीरे उत्पादकता में वृद्धि की दर वेतनों की अपेक्षा अधिक रही है। 1970-77 की अवधि में वास्तविक वेतन वृद्धि की दर 8 प्रतिशत से कुछ ही अधिक रही जबकि उत्पादकता दर लगभग 13 प्रतिशत थी। कृषि उत्पादन में 1952 के आधार वर्ष के अनुसार लगभग 3 गुना वृद्धि देखने को मिलती है। 1950 में कुल कृषि उत्पादन सूचकांक 95 था जो 1977 में बढ़कर लगभग 195 हो गया। जापान ने आज इतना आर्थिक विकास कर लिया है कि समुत्तराज्य अमेरिका, सोवियत रूस और पश्चिमी जर्मनी के बाद विश्व में जापान का ही स्थान आता है तथा यह आशा की जाती है कि एक-दो वर्षों में ही पश्चिमी जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए जापान का स्थान विश्व में तीसरे नम्बर पर पहुँच जाएगा। आज सामुद्रिक जहाज के निर्माण में जापान सबसे आगे है। विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत यह अकेला उत्पादन करता है। लोहा और इस्पात के उत्पादन में अमेरिका व रूस के बाद जापान का ही नम्बर आता है। मोटरो के उत्पादन में सप्ताह में अमेरिका के बाद जापान ही की गिनती होती है। रसायन उद्योग के क्षेत्र में भी अमेरिका और जर्मनी के बाद जापान का ही स्थान है।

जापान के इस अद्भूत आर्थिक विकास के लिए मूल रूप से वे आर्थिक कारण ही उत्तरदाई हैं जिनका उल्लेख हम कर चुके हैं। लेकिन कितनी भी देश के आर्थिक विकास के लिए कुछ दीर्घकालीन तत्व स्थाई रूप से उत्तरदाई होते हैं। अभिन्न पक्षियों में हम महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन तत्वों प्रथम कारणों का उल्लेख करेंगे।

1 वित्तीय ढांचा तथा जापानियों की विनियोग-प्रवृत्ति—महायुद्ध काल के तुरन्त बाद जापान अपना आर्थिक पुनरुद्धार इसीलिए कर सका क्योंकि देशवासियों ने व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में विनियोग करने की प्रवृत्ति दिखाई जो 1952 में पराधीनता काल से मुक्त होने के बाद बहुत ही तीव्र हो गई। फलस्वरूप जापान ने आर्थिक क्षेत्र के प्रत्येक पहलू में अद्भुत तेजी से विकास किया। व्यावसायी बैंको, बैंक ऑफ जापान आदि की तरफ से जापानी उद्योगपतियों को सदैव प्रोत्साहन मिलता रहा। जापान का सम्पूर्ण बैंकिंग और वित्तीय ढांचा इन रूप में गठित किया गया जो देश के आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करे।

2 आर्थिक व्यवस्था की दोहरी प्रवृत्ति—जापान के आर्थिक विकास का बहुत कुछ श्रेय वहाँ की दोहरी अर्थ व्यवस्था की दोहरी प्रवृत्ति को है, अर्थात् जापान में जहाँ बड़े पैमाने के उद्योगों का बोलबाला है वहाँ लघु एव कुटीर उद्योगों का महत्त्व भी कम नहीं है। द्वितीय महायुद्ध काल से पूर्व तो लघु और मध्यम आकार के उद्योगों ने जापान के आर्थिक विकास में सहयोग दिया ही था लेकिन द्वितीय महायुद्ध के बाद भी इनकी भूमिका कम नहीं रही है। यद्यपि जापानी प्रवृत्ति आज विशाल पैमाने के उद्योगों की ओर है तथा बृहद् औद्योगिक संस्थानों के कारण ही जापान का इतना अधिक आर्थिक प्रसार हो सका है, तथापि कुछ क्षेत्रों में लघु उद्योग बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। जिन वस्तुओं के उत्पादन में कम पूँजी ही अधिक सहायक हो सकती है, उन वस्तुओं का उत्पादन लघु उद्योगों के हाथ में ही छोड़ दिया गया है। इससे जापानी अर्थ-व्यवस्था को भारी बल मिलता है और बीच के रिक्त स्थान स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। रोजगार की दृष्टि से लघु उद्योग काफी उपयोगी सिद्ध हुए हैं जिससे जापानी आर्थिक प्रसार को भारी सहारा मिलता है।

3 विदेशी व्यापार पर अधिकाधिक बल—विदेशी व्यापार सदा से जापान की समृद्धि का मुख्य आधार रहा है। महायुद्ध की समाप्ति पर जापान का विदेशी व्यापार ठप्प हो चुका था। अमेरिकन सैनिक प्रशासन ने अपने उत्तरवालीन वर्षों में जापान के विदेशी व्यापार पर से प्रतिबन्ध उठा लिया। जापानी सरकार की सक्रियता और विवेकपूर्ण नीति के कारण ज्यों ज्यों जापान की औद्योगिक क्षमता बढ़ती गई त्यों-त्यों उसका विदेशी व्यापार भी चमकता गया। कोरिया युद्ध के दौरान इसे विशेष प्रोत्साहन मिला। पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त होने के उपरान्त जापानी सरकार ने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए विश्व में नए-नए बाजारों की खोज को, निर्यात-व्यापार की संरचना में परिवर्तन किया, नई-नई वैज्ञानिक तकनीकों का औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किया और मौद्रिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार तथा परिवर्तन किए। सार्वजनिक और निजी प्रयासों के फलस्वरूप जापान का विदेशी व्यापार युद्ध पूर्व के स्तर से भी बहुत अधिक उन्नत हो गया जिसका सम्पूर्ण व्यवस्था पर बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा।

4. उच्च बचत अनुपात—महायुद्धोत्तर काल में जापान ने तीव्र आर्थिक प्रसार को जापानियों की उच्च बचत की प्रवृत्ति ने महत्त्वपूर्ण सहयोग दिया।

सन् 1959 में कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति में से जापान में लगभग 54.5 प्रतिशत वैयक्तिक उपभोग व्यय था जबकि अमेरिका में यह वैयक्तिक उपभोग-व्यय कुल राष्ट्रीय उत्पत्ति में 82.1 प्रतिशत और जर्मनी में 72.3 प्रतिशत था। व्यय की जाने योग्य वैयक्तिक आय में से जहाँ जापान में व्यक्तिगत बचत लगभग 18.5 प्रतिशत थी वहाँ अमेरिका में यह बचत 7.6 तथा ब्रिटेन में 5.0 प्रतिशत थी। स्पष्ट है कि जापान बचत अनुपात की दृष्टि से विश्व के उन्नत देशों में बहुत आगे था। उच्च बचत अनुपात के कारण ही जापान में विनियोग की दर भी बहुत उच्च रही जिससे देश का द्रुत गति से आर्थिक विकास सम्भव हो सका। जापानियों का बचत अनुपात उनकी आय का लगभग 25 प्रतिशत है जो विश्व के किसी राष्ट्र की तुलना में बहुत अधिक है इसीलिए वार्षिक विनियोग राष्ट्रीय आय का लगभग 30% है।

5 नियोजन का आश्रय—देश की आर्थिक प्रगति की रफ्तार उच्च करने के लिए जापानी सरकार न प्रभावशाली नियोजन का आश्रय लिया। वर्तमान जापान की आर्थिक नीति का सार 'स्थायित्व के साथ-साथ विकास' (Growth with stability) है। इस व्यापक आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सन् 1961 में जापान ने एक दशवर्षीय योजना (1961-70) बनाई जिसका लक्ष्य 1970 तक कुल राष्ट्रीय उत्पादन को दुगुना करने का रखा गया था। इसके बाद 1970-80 की द्वितीय योजना समाप्ति पर है।

इस सम्पूर्ण विवरण से प्रकट है कि महायुद्धोत्तर काल में जापान के तीव्र आर्थिक विस्तार के मूल में अनेक तत्त्व निहित रहे हैं। इस क्षेत्र में राज्य का योगदान बहुत ही मूल्यवान रहा है। जापानियों की कार्य क्षमता, लग्न, विनियोग क्षमता, उच्च तकनीक और अथवा परिश्रम का योग निर्यातिक सिद्ध हुआ है। छोटे-छोटे टापुओं पर बसा यह देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसका उदाहरण विश्व इतिहास में देखने को नहीं मिलता। यद्यपि पश्चिमी जर्मनी और रूस की आर्थिक विकास की गति भी कम नहीं रही है तथापि जापान का पलड़ा इस दृष्टि से अधिक भारी रहा है। श्री सरमन काहन की यह भविष्यवाणी सिद्ध होने में कोई असम्भव बात न उठ रही आती कि "आगामी सदी (21वीं सदी) में जापान समग्र विश्व पर छा जायगा।"

प्रश्नावली (University Questions)

अध्याय 1

- 1 मेजी पुनर्संस्थापन के दौरान जापान की अर्थ-व्यवस्था के विकास का वर्णन कीजिए । (1977)

Describe the development of Japanese economy during Meiji Restoration

- 2 मेजी पुनर्संस्थापन की अवधि में जापानी कृषि विकास का समीक्षात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए । (1978)

- 3 मेजी शासन काल में जापान की कृषि की स्थिति की समीक्षा कीजिए । इस अवधि में कृषि के क्षेत्र में क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए ? (1978)

Discuss the Conditions of Japanese agriculture in the Meiji period. What important changes were made in the field of agriculture during this period ?

- 4 मेजी युग के समय जापानी कृषि सुधारों का वर्णन कीजिए । इनका क्या प्रभाव हुआ ? (1977)

Give an account of Japanese Agricultural Reforms during the Meiji Period What was their effect ?

- 5 जापान में टोकुगावा शासन के पतन के कारणों का विवेचन कीजिए तथा मेजी पुनर्संस्थापन काल में जापानी अर्थ-व्यवस्था के विकास का विवरण दीजिए । (1977)

Discuss the causes of the downfall of Tokugawa Regime in Japan and explain the development of Japanese Economy during Meiji Restoration

- 6 मेजी पुनर्संस्थापन के द्वारा लाये गए परिवर्तनों के तात्कालिक परिणाम क्या थे ? (1978)

What were the immediate effects of changes brought about by the Meiji Restoration ?

- 7 मेजी पुनर्संस्थापना के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए । (1978)

Critically examine the social, economic and political changes brought about by the Meiji Restoration

अध्याय 2

- 8 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में अपनाए गए भूमि सुधारों की व्याख्या कीजिए । (1978)

Give a brief idea of the land reform measures adopted in Japan since the second world war

- ✓ 9. जापान में युद्धोत्तरकाल में कृषि विकास का मूल्यांकन करते हुए बताएं कि भारत तथा अन्य विवातशील देश उससे क्या मार्ग दर्शन ले सकते हैं? (1977)
Evaluate the development of agriculture in post war period in Japan and show how it can guide the developing countries and India
10. जापान में कृषि विकास का संक्षिप्त विवेचन कीजिए और उसकी वर्तमान प्रवृत्तियों तथा स्थिति की समीक्षा कीजिए। (1977)
Discuss briefly the development of agriculture in Japan and also examine critically the present trends and position of agriculture
11. द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् से जापानी कृषि विकास की प्रमुखताओं का उल्लेख कीजिए और कृषि की आधुनिक प्रवृत्तियों व समस्याओं का विवेचन कीजिए। (1978)

अध्याय 3

12. जापान के मुख्य उद्योगों की गणना कीजिए। जापान के औद्योगिक विकास की क्या मुख्य विशेषताएँ हैं?
Enumerate the main industries of Japan. What are the chief characteristics of Japan's industrial development?
13. जापान के आधुनिक उद्योगों की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। (1978)
Describe briefly some salient features of the modern industries of Japan
14. जापान की आर्थिक समृद्धि का प्रमुख कारण वहाँ के बड़े उद्योग हैं। इस संदर्भ में जापान के किसी एक बड़े उद्योग की स्थापना, विकास, समस्याओं व भावी सम्भावनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। (1978)
15. जापान सरकार की औद्योगिक नीति की समीक्षा कीजिए। अपने देश के लिए इससे हम क्या सीख सकते हैं? (1978)
Survey the industrial policy of the Govt. of Japan. What lesson can we draw from it for our country?
16. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—
(i) जापान का सूती वस्त्र उद्योग,
(ii) जापान का लोहा तथा इस्पात उद्योग, एवं
(iii) जापान का कोयला उद्योग। (1977)
Write short notes on any two of the following—
(i) Cotton Textile Industry of Japan,
(ii) Iron and Steel Industry of Japan, and
(iii) Coal Industry of Japan

अध्याय 4

- 17 "जापान में लघु उद्योग बृहत् उद्योगों के सहायक तथा पूरक हैं- प्रतिद्वन्द्वी नहीं।" इस कथन की पुष्टि कीजिए। (1978)
 "In Japan small scale industries are not competitive but complementary to large scale industries" Comment on the truth of this statement
- 18 जापान की अर्थ-व्यवस्था के विकास में कुटीर और लघु उद्योगों की क्या भूमिका रही है? (1977)
 What has been the role of cottage and small scale industries in Japanese economic development?
- 19 जापान की अर्थ-व्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योगों के महत्त्व का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। (1978)
 Discuss in brief the importance of cottage and small scale industries in the economy of Japan
- 20 जापान में लघु उद्योगों की समृद्धि के कारण एवं महत्त्व का विवेचन करते हुए बताइए कि अल्पविकसित (विकासशील) देशों के लिए जापान के लघु उद्योग किस प्रकार प्रेरणा एवं मार्गदर्शन दे सकते हैं। (1977)
 Discuss the causes and importance of the prosperity of small scale industries in Japan Explain how small scale industries of Japan can inspire and guide the developing countries?

अध्याय 5

- 21 जापान में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् से जापान के विदेशी व्यापार की रचना, विकास और बदलती प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। (1978)
- 22 जापान की अर्थ व्यवस्था में विदेशी व्यापार के महत्त्व की व्याख्या कीजिए। (1978)
 Describe the importance of foreign trade in the economy of Japan
- 23 जापान की अर्थ व्यवस्था में विदेशी व्यापार का क्या महत्त्व है? पिछले दशक में इसमें वृद्धि के क्या कारण रहे? (1977)
 What is the importance of foreign trade in the Japanese Economy? Discuss the factors responsible for its growth during the last decade
- 24 जापान के प्रमुख आयात-निर्यात का विवरण देते हुए जापान के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। (1977)
 Giving main items of export and import of Japan Discuss the features and characteristics of foreign trade of Japan

अध्याय 6

- 25 जापान के आर्थिक विकास में राज्य के योगदान को स्पष्ट कीजिए । (1978)
 Explain the role of state in the economic development of Japan
- 26 जापान के आर्थिक विकास में आधुनिक उद्योगों की भूमिका निर्धारित कीजिए और औद्योगिक विकास में राज्य सरकार का योगदान बतलाइए । (1978)
- 27 जापान के आर्थिक विकास से विकासशील देश क्या शिक्षाएँ ग्रहण कर सकते हैं ? (1978)
 What lessons can be developing countries draw from the economic development of Japan ?

अध्याय 7

- 28 दूसरे विश्वयुद्ध के पश्चात् जापान के आर्थिक विस्तार के कारणों का विश्लेषण कीजिए । (1978)
 Analyse the causes of Japan's economic expansion after the second world war
- 29 युद्धोत्तर काल में जापान के उद्योगों के पुनर्निर्माण की व्याख्या कीजिए । द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के द्रुतगति से औद्योगीकरण के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए । (1978)
 Discuss the reconstruction of Japanese industries in the post-war period. What are the factors behind the rapid industrialization of Japan after the Second world war ?
- 30 युद्धोत्तरकाल में जापान के तीव्रगति से औद्योगीकरण के कारणों का विवरण दीजिए तथा उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं समस्याओं का विवेचन कीजिए । (1977)
 Explain the causes of rapid industrial development of Japan during post war period and discuss its present position and problems
- 31 दूसरे विश्वयुद्धोत्तर काल में जापान के द्रुतगति से आर्थिक पुनरुत्थान के तत्वों की व्याख्या कीजिए । (1978)
 Discuss the factors responsible for the rapid economic recovery of Japan in the post war years
- 32 निम्नलिखित पर नोट लिखिए—
 (अ) जापान में उच्च आर्थिक विकास की दर का भविष्य ।
 (ब) जापान की दस वर्षीय (1961-70) योजना । (1978)
 Write short notes on—
 (a) Future of high rate of growth in Japan.
 (b) Ten year Economic Plan (1961-70) of Japan

SUGGESTED READINGS

1. *W. G. Beasley* : The Modern History of Japan.
2. *William W. Lockwood*. The Economic Development of Japan : Growth and Structural Change.
3. *G. C. Allen* : A Short Economic History of Modern Japan 1867-1960.
4. *E. S. Crawcour* : "The Japanese Economy of the Eve of Modernization". The Journal of the Oriental Society of Australia, Vol. 2, No. 1. 1963.
5. *Yasuzo Horie* : "The Problem of the Modernization of Japan".
6. *Thomas C Smith* : Political Change and Industrial Development in Japan.
7. *S. Tsuru* : Essay on the Japanese Economy, Tokyo.
8. *Economic Planning* : New long Range Economic Plan Agency of Japan, 1961-70.
9. *H. Aoyama and T. Nishikawa* : "Japanese Economy in the Inter-war Period"
10. *Mitsubishi Economic Research Bureau* : Japanese Trade and Industry - Present and Future.
11. *E. B. Schumptere* : The Industrialisation of Japan and Manchuko, 1930-1940.
12. *T. Ujeda and associates* : The Small Industries of Japan
13. *H Nishi* : "Japan's Economic Devept 1951-61"
14. *Cohen, J B* : Economic Progress of Free Japan
15. *Lockwood, W W* : The Economic Development of Japan (1954), Princeton, New Jersey.
16. *Allen G. C.* : A Short Economic History of Modern Japan.
17. *Allen G C.* : Japan's Economic Recovery (1960), Oxford University Press.
18. *Allen G. C.* : Japan's Economic Expansion
19. *Cohen J B.* : Japan's Economy in War and Reconstruction.
20. *Story Richard* : A History of Modern Japan
21. *Rostow, W. W.* : The Stages of Economic Growth
22. *Norman, E. H.* : Japan's Emergence as a Modern State.
23. *Cowan C D.* : The Economic Development of China and Japan.
24. *Shinohara, M.* : Growth and Cycles in the Japanese Economy.
25. *Economist Correspondents* : Consider Japan (1963), Gerald Duckworth & Co, Ltd., London.
26. *United Nations* : Economic Survey of Asia and the Far East, 1961. Govt of Japan : The Japan of to-day.
27. *Sakae Tsunoyanea* : A Concise Economic History of Modern Japan.
28. *Japan To-day*
29. *Statistical Handbook of Japan.*

सोवियत रूस

के

आर्थिक विकास में सीमा-चिन्ह

(Landmarks in the Economic
Development of U.S.S.R.)

- 1 नई आर्थिक नीति
(New Economic Policy)
- 2 प्रथम पंचवर्षीय योजना के ठीक पूर्व आर्थिक दशा
(Economic Condition on the Eve of the First Five
Year Plan)
- 3 सामूहीकरण
(Collectivisation)
- 4 1954 से सोवियत कृषि-विकास
(Soviet Agricultural Development since 1954)
- 5 तीव्र औद्योगीकरण की समस्याएँ
(Problems of Rapid Industrialisation)
- 6 नियोजन और आर्थिक विकास में नवीन प्रवृत्तियाँ
(Recent Trends in Planning and Economic Development)

“सामाजिक उत्पादन-व्यवस्था में लगे हुए लोग कुछ ऐसे स्थिर और निश्चित सम्बन्ध स्थापित कर बैठते हैं जो उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं होते। ये उत्पादन-सम्बन्ध भौतिक शक्तियों की एक विशेष अवस्था से मिलते-जुलते हैं। इन्हीं सम्बन्धों के योग से समाज के आर्थिक ढाँचे और प्रणाली का निर्माण होता है। समाज का यही आधार है जिस पर कानून और राजनीति का भवन बनता है।”

—कार्ल मार्क्स

1

नवीन आर्थिक नीति

(New Economic Policy)

“नवीन आर्थिक नीति रूस को नाबी बिनाश और उसके आर्थिक जीवन को प्रथमवस्था से बचाने तथा औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों की उत्पादन मात्रा को युद्धपूर्व के स्तर तक लाने में सफल हुई।”

दुर्गरिन

अक्टूबर, 1917 की क्रान्ति के फलस्वरूप रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई और तभी से इस देश ने अपने सर्वांगीण विकास पे सम्पूर्ण विश्व को आश्चर्यं चकित कर दिया है। आज के रूस का सभी दृष्टियों से विश्व में दूसरा स्थान है। लगभग 2 24 00,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखे हुए यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या 23 करोड़ से भी अधिक है। वन सम्पदाओं, नदियों और भूमि की दृष्टि से यह अग्रणी राष्ट्र है। यहाँ प्रायः सभी खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं। 16 महत्त्वपूर्ण खनिज पदार्थों में 13 में रूस का प्रथम स्थान है। रूस ही वह प्रथम देश है जिसने आर्थिक विकास के क्षेत्र में केन्द्रीकृत नियोजन का मार्ग बड़े भारी पैमाने पर अपनाया है। सफल आर्थिक नियोजन का ही यह परिणाम है कि रूस एक अत्यन्त पिछड़ा राष्ट्र से आज का एक अत्यन्त आधुनिक, विकसित और उद्योग प्रधान राष्ट्र बन गया है। इसी अर्थव्यवस्था एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का स्वामित्व और नियन्त्रण है।

रूसी अर्थव्यवस्था को हम मुख्यतः चार चरणों में बाँट सकते हैं—नियन्त्रित अथवा राजकीय पूँजीवाद (नवम्बर 1917—जून 1918), यौद्धिक समाजवाद (जून 1918—मार्च 1921) नवीन आर्थिक नीति (अप्रैल 1921—1927), एवं योजनाओं का काल (1928 से अद्य तक)। यहाँ हम रूसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन नवीन आर्थिक नीति की अवधि से करेंगे।

नवीन आर्थिक नीति कारण एवं उद्देश्य

(New Economic Policy : Causes and Objectives)

रूसी अर्थव्यवस्था के तृतीय चरण नवीन आर्थिक नीति अप्रैल, 1921 से

4 सोवियत रूस का आर्थिक विकास

1927 तक प्रभावी रही। यह नीति समाजवाद का आधार प्रस्तुत करने के लिए निर्मित की गई। इस अवधि में आर्थिक नीतियों में अनेक परिवर्तन किए गए। यह अनुभव किया गया कि रूस का भविष्य औद्योगीकरण में तिहित है और आर्थिक गति को तीव्रता देने के लिए भविष्य में नियोजन का मार्ग अपनाया जाना चाहिए। नवीन आर्थिक नीति अपनाने के कारण

(1) आर्थिक आधार में परिवर्तन—युद्ध समाप्ति के उपरान्त श्रमिकों और किसानों में मतभेद उठ खड़े हुए किसान अपनी वस्तुओं की स्वतन्त्र विक्री का अधिकार चाहते थे जबकि श्रमिकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार के पास खाद्यान्नों का होना जरूरी था। इन दोनों ही बातों का समन्वय करने के लिए नवीन आर्थिक योजना की आवश्यकता थी।

(2) मुद्रा के प्रयोग की अनिवार्यता—किसान अपने उत्पादन की स्वतन्त्र विक्री चाहते थे। यह माँग तभी पूरी हो सकती थी जब बाजार-व्यवस्था को पुनः प्रारम्भ किया जाता। इसे पुनः चालू करने के लिए नवीन आर्थिक नीति लागू करना आवश्यक हो गया। इस नीति के अन्तर्गत ही मौद्रिक प्रयोग और पारस्परिक लेन-देन करने वाले बैंकों की पुनः शुरुआत हुई।

(3) व्यापारिक असतोष का निवारण—देश में व्यापारिक असतोष व्याप्त था। इस असतोष को मिटाने और आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नई और प्रभावशाली नीति जरूरी थी।

(4) व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की माँग—रूस में उस समय व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की माँग जोरों से उठ खड़ी हुई। लोग विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता चाहने लगे। किसान अपनी भूमि और पशु-धन पर स्वतन्त्र अधिकार की इच्छा करने लगे। जनता में फैल रही इस प्रक्रिया को शान्त करने के लिए यह आवश्यक हो गया कि एक नवीन और रचनात्मक आर्थिक नीति अपनाई जाए।

नवीन आर्थिक नीति के उद्देश्य

मार्च, 1921 में स्वीकृत इस नवीन आर्थिक नीति के निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए —

(1) उत्पादन में वृद्धि—ऐसे कार्यक्रमों पर विशेष महत्त्व देने का उद्देश्य रखा गया जिनकी सहायता में (क) उत्पादन वृद्धि हो, (ख) आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, (ग) निर्यात व्यापार पुनः प्रारम्भ हो सके, (घ) कच्चे माल के उत्पादन में वृद्धि हो और औद्योगिक उत्पादन-व्यवस्था पुनर्सं गठित हो, (ङ) कृषि क्षेत्र में चहुँमुखी प्रगति की जा सके।

(2) खेतीहर वर्ग के असतोष का निवारण—दूसरा मुख्य उद्देश्य कृषक वर्ग में व्याप्त असतोष को दूर करना रखा गया। लेनिन ने कहा, “खेतीहर वर्ग की सहमति से ही रूस में समाजवादी क्रान्ति को बढ़ाया जा सकता है। कृषक वर्ग और सर्वहारा वर्ग (श्रमिक वर्ग) में सहयोग आवश्यक है।”

(3) मिश्रित अर्थ-व्यवस्था—इस नीति का तीसरा उद्देश्य मिश्रित अर्थ-व्यवस्था

को बनाना रखा गया। इस नीति के अन्तर्गत सीमित और प्रांशिक राष्ट्रीयकरण को ही स्थान दिया गया। समाजवादी तत्त्वों के विनाश द्वारा पूँजीवादी तत्त्वों के विनाश पर बल दिया गया। इस तरह मिश्रित षर्ष-व्यवस्था निमित्त की गई। इसके मूल में यह भावना निहित थी कि पूँजीवाद और साम्यवाद के आपसी संघर्ष को जब तक आर्थिक क्षेत्र में नहीं लाया जायेगा तब तक साम्यवादी तत्त्वों की विनाश नहीं हो सकेगी।

(4) जनकल्याण—नवीन आर्थिक नीति में जन कल्याण का उद्देश्य सर्वोपरि था। जनता का असन्तोष दूर हो, देश में सुख-समृद्धि बढ़े, क्रांति की दिग्गम हो, यह इस नीति का लक्ष्य था।

नवीन आर्थिक नीति तत्कालीन सरकार को अल्पकालिक विश्राम देन वाली नीति थी। उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि पूँजीवादी तत्त्वों को कुछ सहारा दिए बिना राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार नहीं किया जा सकता था। टूर्निंग (Turn) के शब्दों में, नवीन आर्थिक नीति रुस को भावी विनाश और उसके आर्थिक जीवन को अव्यवस्था से बचाने तथा औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रों की उत्पादन मात्रा को युद्धपूर्व के स्तर तक लाने में सफल हुई।

नवीन आर्थिक नीति के कार्यक्रम और उपलब्धियाँ
 (Aspects, Programme and Achievements of New Economic Policy)

अब हमें देखना चाहिए कि नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत कृषि, उद्योग आदि विभिन्न क्षेत्रों में क्या कार्यक्रम अपनाए गए।

कृषि (Agriculture)

इस नीति ने कृषि को विशेष रूप से प्रभावित किया। कृषि-क्षेत्र में दो मुख्य उद्देश्य रखे गए—किसानों का असन्तोष दूर करना और कृषि-उत्पादन में अधिकतम सम्भव वृद्धि करना। इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कृषि सम्बन्धी आसक्ति निकासी गई और अनेक त्रियात्मक कदम उठाए गए। कुल मिला कर कृषि-क्षेत्र में निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए गए।

- (1) अन्ननिर्धारण वसूली का अन्त—किसानों से अन्ननिर्धारण वसूली समाप्त कर दी गई ताकि सरकार को उनका राजनीतिक और आर्थिक समर्थन मिल सके। इस स्थान पर एक कृषि-कर लगाया गया जिसके अन्तर्गत किसानों को एक निश्चित परिणाम में अन्न सरकार को देना आवश्यक ठहराया गया। इस कर की वसूली आरम्भ म तो वस्तु के रूप में की गई, लेकिन मुद्रा-स्थिरता आने पर रूबल में होने लगी। कृषि-कर नीति का यह लाभ हुआ कि कर देने के उपरान्त शेष बचे हुए अतिरिक्त अन्न को किसान इच्छानुसार खुले बाजार में बेच सकता था और उत्तम प्राप्त पान का किसी भी रूप में ब्यय कर सकता था। कर-व्यवस्था ऐसी थी कि सरकार को अन्ननिर्धारण वसूली से प्राप्त अन्न की मात्रा का लगभग 50 प्रतिशत प्राप्त हो जाता था। इस अन्न से वह सैनिकों और महत्त्वपूर्ण उद्योगों से श्रमिकों की माँग की बहुत-कुछ पूर्ति कर सकती थी।

(2) कृषि-उत्पादन में वृद्धि के उपाय—नवीन कृषि-नीति के अन्तर्गत कृषि-उत्पादन बढ़ाने के विभिन्न उपाय किए गए। किसानों में निजी प्रेरणा को प्रोत्साहन दिया गया। भूमि पर तत्कालीन व्यक्तिगत अधिकार को मान्यता देते हुए किसानों को सामुदायिक और व्यक्तिगत रूप से कृषि करने की छूट दी गई। फसलें नष्ट होने की खतरा में उन्हें ऋण की सुविधाएँ प्रदान की गईं। विभिन्न रियायतें देकर किसानों को सहकारी और समाजवादी ढंग से खेती करने को प्रोत्साहित किया गया। घनी किसानों पर वृद्धिमान दर से कर लगाया गया और उनकी आर्थिक समृद्धि को उचित रूप से सीमित कर दिया गया जबकि गरीब किसानों को प्रत्येक सम्भव सहायता दी जाने लगी।

(3) खाद्यान्नों के व्यापार की स्वतन्त्रता—कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को यह छूट दी गई कि वे कृषि कर चुकाने के बाद बची अपनी अतिरिक्त उपज को कहीं भी और किसी प्रकार भी बेचें। प्रारम्भ में उन्हें केवल स्थानीय बाजार में ही स्वतन्त्र व्यापार का अधिकार दिया गया, लेकिन बाद में यह प्रतिबन्ध भी हटा दिया गया। बाजारों के विस्तृत होने और खाद्यान्नों के विक्रय में आजादी मिलने से किसानों का कृषि-कार्य में आकर्षण बढ़ा और साथ ही उनका अधिक आर्थिक कल्याण भी सम्भव हो सका।

(4) वेतनभोगी मजदूर रखने की सुविधा—किसानों को यह भी अधिकार दिया गया कि वे किराये के अथवा वेतनभोगी मजदूर (Hired labour) रख सकें। इससे किसानों के मताधिकार पर कोई आंच आने की आशंका भी समाप्त कर दी गई।

(5) कृषि सहकारिता को प्रोत्साहन—कृषि-क्षेत्र में सहकारिता के विकास पर बल दिया गया और सहकारी समितियों को पुनर्जीवित तथा विकसित किया गया। अक्टूबर, 1921 में एक आज्ञापित निकाल कर सहकारी समितियों को स्वतन्त्र अस्तित्व प्रदान किया गया। किसानों को यह सुविधा दी गई कि वे ऐच्छिक आधार पर व्यापारिक सुविधा के लिए अपनी सहकारी समितियाँ गठित करें।

नवीन कृषि-नीति की उपलब्धियाँ और असफलताएँ—नवीन कृषि-नीति के फलस्वरूप एक ओर तो किसानों का असन्तोष दूर हुआ तथा दूसरी ओर श्रमिक वर्ग के लिए सरकार किसानों की पूर्ति भी कर सकी। इस नीति से किसानों और मजदूरों के बीच कटुता कम होकर मैत्री के एक नए आधार का स्तम्भित हुआ।

नवीन नीति से कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। अनाज का उत्पादन 1921-22 में 423 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 1926-27 में 783 लाख मीट्रिक टन हो गया। कृषि-क्षेत्रफल 1922-23 में 662 लाख हेक्टर से बढ़कर 1926-27 में 937 लाख हेक्टर हो गया। प्रतिशत की दृष्टि से कृषि-उत्पादन की मात्रा में 1925-26 में युद्धपूर्व के उत्पादन की मात्रा के 92 प्रतिशत के बराबर वृद्धि हुई। 1913 में जो क्षेत्रफल था उसके 92.7 प्रतिशत भाग पर 1925-26 में पुनः कृषि-कार्य होने लगा। अगले वर्ष अर्थात् 1926-27 में कृषि-क्षेत्रफल युद्धपूर्व के क्षेत्रफल के बराबर पहुँच गया। कपास, फलैक्स, तम्बाकू, चुकन्दर आदि का उत्पादन निरन्तर

बढ़ता गया। कृषि में विकास के फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन और समृद्धि की पृष्ठभूमि स्वतः बनने लगी। कृषि अर्थ-व्यवस्था में सुधार होने से कृषि सम्बन्धी पशुधन में भी वृद्धि हुई।

कृषि-क्षेत्र में चहुँमुखी विकास होने पर भी गेहूँ, जौ आदि का उत्पादन 1913 के उत्पादन के बराबर नहीं पहुँच सका। 1922 में फसल बहुत अच्छी हुई और रूसी जनता क्रान्ति के बाद पहली बार अन्न सफ़ट से बहुत-कुछ मुक्ति पा सकी। इसी वर्ष रूस ने पहली बार अन्न का निर्यात शुरू किया। कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने यह नीति भी अपनाई कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो किसान बसना चाहे उन्हें नि:शुल्क भूमि दी जाए।

नवीन कृषि नीति से ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति में सुधार तो अवश्य हुआ, लेकिन वास्तविक लाभ मध्यवर्गीय किसानों तथा धनिक बुलक वर्ग को ही हुआ। छोटे-छोटे कृषि फार्मों की सख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने से खेती के लिए पर्याप्त कृषि योजनारक्षक की आवश्यकता से उत्पन्न हुई और कृषि के लिए श्रेष्ठ प्रशिक्षण नहीं की जा सकी। परिणाम यह हुआ कि प्रति व्यक्ति उत्पादन-क्षमता घट गई। कृषि-नीति के कारण पूँजीवादी तत्त्व पुनः सिर उठाने लगे। मध्यवर्गीय और गरीब किसान देश की कुल उपज का लगभग 85.3 प्रतिशत भाग पैदा करते थे, लेकिन फसल का केवल 13 प्रतिशत भाग ही बाजार में बेच पाते थे। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि जहाँ 1903 में लगभग 21 मि. टन अनाज विन्नी के लिए बाजार में आता था वहाँ 1926-28 में केवल 8 मि. टन सांचा ही विन्नी के लिए बाजार में लाया गया। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि किसानों ने राजकीय सस्याओं को निर्धारित मूल्य पर अनाज बेचने से इन्कार कर दिया। सरकार को अनाज बेचने की अपेक्षा उन्होंने अपने जानवरों को अनाज खिला देना अधिक उपयुक्त समझा, क्योंकि अनाज के वनिस्वत जानवरों का मांस बाजार में बेचना अधिक सुगम था। यही नहीं, किसानों ने अनाज के स्थान पर व्यापारिक फसलों का बोना शुरू कर दिया। परिस्थिति बहुत विकट हो गई क्योंकि अनाज का मूल्य बढ़ाते ही औद्योगिक उत्पादन का मूल्य बढ़ जाता था जिससे जनता में असन्तोष अधिक उत्पन्न हो रहा था। जनता का सन्तोष सरकार के लिए जबरदस्त चुनौती थी। इन परिस्थितियों ने सरकार के सामने इसके सिवाय कोई उपाय नहीं रहा कि अनाज वसूल करने के लिए कठोर उपायों का आश्रम लिया जाय और बल प्रयोग तक किया जाय।

इस प्रकार नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत अन्न में किसानों की दशा लगभग वैसी ही हो गई जैसी क्रान्ति से पहले थी। इतना ही नहीं, कृषि की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि देश में भयानक अकाल की आशंका प्रबल हो गई। सरकार ने जो भी कदम उठाए वे कृषि संगठन को कमजोर करने वाले सिद्ध हुए। कृषि का पुनरुद्धार तभी सम्भव हुआ जब नवीन आर्थिक नीति को तिलांजलि देकर 1928 से नियोजन का मार्ग अपनाया गया।

उद्योग (Industry)

नवीन आर्थिक नीति से पहले सोवियत सरकार ने उद्योगों में अत्यधिक केन्द्रीयकरण की नीति अपनाई थी। लगभग सभी औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इनका प्रबन्ध संचालन और नियन्त्रण सर्वोच्च आर्थिक परिषद् वेसेन्खा (Vasenkha) तथा उसके सहायक विभागो ग्लवकी (Glavki) के हाथों में केन्द्रित था। नवीन आर्थिक नीति के प्रारम्भिक काल में इस प्रचलित औद्योगिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किए गए लेकिन आगे चलकर विकेन्द्रित औद्योगिक प्रणाली स्थापित की गई जिसके अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में प्रबन्ध एवं नियन्त्रण में विकेन्द्रीकरण तथा छोटे छोटे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम अपनाए गए। इस नवीन औद्योगिक नीति के अनुपालन में जो व्यवस्थाएँ की गई वे मुख्यतः इस प्रकार थी—

(1) मिश्रित अर्थ-व्यवस्था—सरकार ने ऐसी नीति अपनाई जिससे व्यक्तिगत प्रेरणा को प्रोत्साहन मिले। इन दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र को दो भागों में बाँटा गया निजी क्षेत्र और समाजवादी क्षेत्र। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था पर बल दिया गया। तदनुसार बँकिंग व्यवसाय, बिजली परिवहन, धातु तथा इन्जीनियरिंग आदि राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ उद्योग सरकार के पूर्ण अधिकार और नियन्त्रण में रखे गए तथा कुछ उद्योगों के प्रबन्ध और नियन्त्रण को विकेन्द्रीकृत कर दिया गया।

(2) अराष्ट्रीयकरण—नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अराष्ट्रीयकरण की नीति का मार्ग अपनाया गया। 1920 के आगम राष्ट्रीयकरण द्वारा जिन छोटे छोटे प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, उन्हें या तो सहकारी समितियों और निजी उत्पादकों को सौंप दिया गया या वापिस लौटा दिया गया। 1922 तक लगभग 4 हजार ऐसे ग्रामीण तथा सपु औद्योगिक प्रतिष्ठानों का अराष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनमें 10 या 20 से अधिक श्रमिक कार्य नहीं करते थे। अब ये उद्योग वेसेन्खा तथा उसकी सहयोगी शाखाओं के नियन्त्रण से पूरी तरह मुक्त हो गई। सन् 1923 के आँकड़ों के अनुसार 1,65,781 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से 1,47,471 अर्थात् लगभग 88.5 प्रतिशत प्रतिष्ठान व्यक्तिगत नियन्त्रण में रहे जबकि 4,613 अर्थात् लगभग 3.1 प्रतिशत प्रतिष्ठान सहकारी क्षेत्र के नियन्त्रण में आए। महत्त्वपूर्ण राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठान केवल 13,597 अर्थात् लगभग 8.4 प्रतिशत ही थे, लेकिन उनमें काम करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत 84.1 था।

(3) औद्योगिक प्रबन्ध व्यवस्था में परिवर्तन—धार्मिक साम्यवाद के अन्तर्गत उद्योगों के नियन्त्रण और संचालन के लिए केन्द्रीयकरण की नीति अपनाई गई थी लेकिन नवीन आर्थिक नीति के दौरान औद्योगिक प्रबन्ध व्यवस्था को ज़िखिल करते हुए विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाई जाने लगी। ऐसी व्यवस्था की गई कि प्रान्तीय आर्थिक परिषदें वेसेन्खा (Vasenkha) के नियन्त्रण से हटकर प्रान्तीय सोवियत राज्य सभा के मातहत हो गईं। वेसेन्खा सगठन और उसकी कार्य-प्रणाली में भी आवश्यक परिवर्तन तथा सुधार किए गए, उप-विभागों (Glavki) की सहाय 53

से घटा कर 16 कर दी गई। यद्यपि आर्थिक एव औद्योगिक गतिविधि का सामान्य नियन्त्रण केन्द्रीय सत्ता के अधीन ही रहा, लेकिन दिन प्रतिदिन की कार्य-व्यवस्था का विकेन्द्रीयकरण कर दिया गया।

नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्वायत्त प्रबन्धीय व्यवस्था को पुनर्संगठित किया गया। एक ही प्रकार की उत्पादन व्यवस्था के औद्योगिक प्रतिष्ठानों को मिला कर उनके सघ (Unions) बना लिए गए जिन्हें बाद में "ट्रस्ट" (Trusts) कहा जाने लगा। 1921 के उत्तरार्द्ध और 1922 में ट्रस्टों का निर्माण बड़ी तजी से हुआ। इन ट्रस्टों तथा बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वेसेन्ला तथा उसकी सहायक संस्थाओं के प्रबन्ध नियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया। जो ट्रस्ट बने उनमें औसतन 12 औद्योगिक प्रतिष्ठान सम्मिलित किए गए। 478 ट्रस्टों में लगभग 10 लाख श्रमिक कार्य करते थे।

सोवियत सरकार ने ट्रस्टों को तीन भागों में विभाजित किया—सघीय ट्रस्ट, प्रादेशिक ट्रस्ट तथा स्थानीय ट्रस्ट। इन्हें क्रमशः वेसेन्ला ग्लावकी (प्रादेशिक अर्थ-परिषद्) और संन्तसं (स्थानीय अर्थ-परिषद्) के नियन्त्रण में रखा गया। 1922 में एव प्रादेश जारी करके ट्रस्टों के पुनर्संगठन को नियमित किया गया। अप्रैल, 1923 में इन ट्रस्टों को स्वतन्त्र रूप से समझौते आदि करने की छूट दे दी गई। ट्रस्टों को बॉण्ड या ऋण-पत्र जारी करने का अधिकार भी मिला, किन्तु इस बारे में राज्य ने अपने पर कोई भी उत्तरदायित्व नहीं रखा और न ही ट्रस्ट की हानि को पूरा करने की जिम्मेदारी सभाली। ट्रस्टों पर वह प्रतिबन्ध रहा कि वे वेसेन्ला अर्थात् सर्वोच्च आर्थिक परिषद की अनुमति के बिना स्थाई सम्पत्ति का विक्रय भगवा हस्तांतरण नहीं कर सकते थे। चल सम्पत्ति के बारे में अनुबन्ध करने की ही उन्हें पूरी स्वतन्त्रता थी। ट्रस्टों का मुख्य कार्य कारखानों के उत्पादन-कार्यक्रमों का निर्धारण और सुचारु संचालन था। वेसेन्ला को अधिकार था कि वह इन ट्रस्टों का विघटन करदे तथा अपनी इच्छानुसार उनके लाभों का बटवारा करे। ट्रस्ट के प्रकेशन के लिए तीन प्रकेशका की एक समिति होती थी जिसमें एक श्रम-सघ का सदस्य अवश्य होता था। प्रकेशक ट्रस्ट के वागजात देख सकते थे, लेकिन ट्रस्ट के संचालन के बारे में उन्हें कोई अधिकार नहीं था। ट्रस्टियों की नियुक्ति वेसेन्ला द्वारा श्रम-सघों के सदस्यों की सलाह से की जाती थी। ये ट्रस्ट आन्तरिक रूप से वाणिज्य के सामान्य सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करने थे। सरकारी प्रधानत मूल्य-नियन्त्रण के सम्बन्ध में था।

नवीन औद्योगिक नीति के अन्तर्गत बाजार-व्यवस्था पुनः स्थापित की गई तथा सहकारी संस्थाओं को भी समझौते आदि करने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई।

नवीन औद्योगिक नीति का मूल्यांकन—नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत लगभग सभी उद्योगों ने प्रगति की। केवल लौह उद्योग को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों का उत्पादन 1926-27 में उस स्तर तक पहुँच गया जो 1913 में था।

10 सोवियत रूस का आर्थिक विकास

कुछ उद्योगों में तो उत्पादन की गति और भी तेज रही। नवीन नीति के अन्तर्गत औद्योगिक उत्पादन की जो प्रगति हुई वह अप्रतिक्षित सारणी से स्पष्ट है—

युद्ध पूर्व के मूल्य मिलियन रुबल में

	1922-24	1924-25	1925-26
(क) राजकीय उद्योग			
(1) बड़े पैमाने के	2383	3740	5309
(II) लघु एव कुटीर	17	21	24
(ख) सहकारी उद्योग			
(1) बड़े पैमाने के	108	154	247
(II) लघु एव कुटीर	64	79	91
(ग) निजी उद्योग			
(1) बड़े पैमाने के	136	167	241
(II) छोटे पैमाने के	706	879	1011
योग	3 414	5 040	6 923

विभिन्न उद्योगों में जो उत्पादन वृद्धि हुई उसका अनुमान इस तालिका से स्पष्ट है—

उद्योग	इवार्ड 1913	1924-25	1925-26	1926-27	1927-28
कोयला मि०					
टन में	29 1	16 1	25 4	32 1	35 4
लोहा मि०					
टन में	4 2	1 3	2 2	3 0	3 3
इस्पात मि०					
टन में	4 2	1 9	—	—	4 3
तेल मि०					
टन में	9 2	7 0	8 5	10 3	11 8
विद्युत् विलियन					
शक्ति किलोवाट	1 9	2 3	3 3	4 1	5 1

वास्तव में नवीन आर्थिक नीति औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने में पूर्ण रूप से सफल हुई। कोयला, इस्पात, तेल, विद्युत्-शक्ति, सूती वस्त्र एव कृषि यन्त्रों का उत्पादन 1913 की तुलना में अधिक हुआ जबकि लोहे, चीनी, ऊनी वस्त्र आदि का उत्पादन कुछ कम रहा। फिर भी उत्पादन की किस्म में कुछ अवनति ही हुई।

देशी या आन्तरिक व्यापार (Internal Trade)

राष्ट्रीयकरण से उत्पन्न दोष दूर करने के लिए सरकार ने नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत मुक्त व्यापार-नीति को प्रोत्साहित किया। इस प्रकार छोटे पैमाने पर उत्पादन द्वारा आर्थिक दशाओं की पूर्ति की दिशा में एक प्रभावशाली कदम

उठाया गया। व्यापारियों को देशी व्यापार-क्षेत्र में लाभ कमाने की छूट दी गई। किसानों को स्वतन्त्रता दी गई कि वे कर चुकाने के उपरान्त घेप बचे लाद्यानो, कच्चे माल और चारे को इच्छानुसार बाजार में बेच कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधरें। आगे चल कर श्रमिकों को भी इस प्रकार की सुविधा देना आवश्यक हो गया क्योंकि वस्तु विनिमय के अन्तर्गत श्रमिकों को इस तरह की व्यवस्था न होने पर आवश्यक वस्तुएँ मिलने में भारी कठिनाई आती थी। इस प्रकार के वस्तु विनिमय को सुगम बनाने के लिए श्रमिकों को अपने उत्पादन का एक भाग कृषि पदार्थों से विनिमय करने के लिए अलग रखने का अधिकार दिया गया। उन्हें यह भी अधिकार दिया गया कि वे एक निश्चित आधार पर उत्पादन का कुछ भाग अपने पास रख सकें।

आन्तरिक विनिमय की उपयुक्त व्यवस्था को प्रोत्साहित करने के साथ साथ राज्य में उसे नियन्त्रित करने के भी प्रयत्न किए लेकिन इसमें सरकार को सफलता नहीं मिली। मई, 1921 में एक नया आदेश निकाल कर स्थानीय व्यापार के क्षेत्र को पूर्वापेक्षा काफी विस्तृत कर दिया गया। सरकारी नीति के फलस्वरूप "नेपमेन" (Napaman) के रूप में छोटे-बड़े व्यापारियों के पुनर्दशन हुए। ये व्यापारी भारतीय महाजनो के समान थे। ये लोग किसानों से अनाज खरीद कर उसे निकट की मण्डियों और नगरों में ले जाकर बेचने लगे। इसी तरह किसानों की मुर्गियाँ, साग-सब्जी, फल, घण्डे, आदि को भी खरीद कर ये उन्हें नगरों में अपनी दूकानों पर बेचने लगे। यह व्यापारी वर्ग ट्रस्टों से थोक सामान खरीदने और उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराने में सहयोग देने लगा। नवीन आर्थिक नीति के प्रथम दो वर्षों में ही इन नेपमेन व्यापारियों ने थोक और खुदरा व्यापार पर अपना इतना प्रभाव जमा लिया कि औद्योगिक और सहकारी ट्रस्टों का लगभग 50 प्रतिशत व्यापार उन्हीं के द्वारा सम्पन्न होने लगा। ये व्यापारी इतनी प्रगति इसलिए कर सके क्योंकि विदेशीकरण की नीति के फलस्वरूप सरकार आरम्भ में सरकारी व्यापार सगठन और सहकारी दूकानों अधिक सरवा में नहीं खोल सकी। लेकिन धीरे-धीरे सहकारी और सरकारी विक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ने लगी तथा विभिन्न उद्योगों ने अपनी अपनी खुदरा दूकानें खोल कर व्यक्तिगत व्यापार की प्रभुत्वकारी स्थिति समाप्त कर दी। 1922-23 में कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य में भारी असन्तुलन आ जाने से आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। इससे भी व्यक्तिगत व्यापार को ठेस पहुँची इन संकट के कारण यह निश्चय किया गया कि व्यक्तिगत व्यापार को सीमित करके राज्य एवं सहकारी व्यापारिक माध्यम बनाया जाए।

सन् 1922 के उपरान्त राजकीय एवं सहकारी संस्थाओं की संख्या में तेजी से विस्तार हुआ। औद्योगिक प्रस्थासो (Industrial Syndicates) ने थोक व्यापार के लिए अपने सगठन बना लिए और प्रान्तीय सरकारों द्वारा भी थोक तथा खुदरा व्यापार के लिए संस्थाएँ बनाई गईं। सर्वोच्च आर्थिक परिषद "वेसेन्सा" ने केन्द्रीय स्तर पर व्यापारिक कम्पनियाँ स्थापित कीं। जहाँ सन् 1922 में कुल व्यापार की

गतिविधि इस प्रकार थी—व्यक्तिगत व्यापार 75.3 प्रतिशत, राज्य द्वारा व्यापार 14.4 प्रतिशत, एव सहकारी समितियों द्वारा व्यापार 10.3 प्रतिशत, वहाँ इन विभिन्न आर्थिक परिवर्तनों के फलस्वरूप सन् 1928-29 में निजी व्यापारियों के हाथ में कुल योक व्यापार का केवल 5 प्रतिशत भाग ही बच रहा और फुटकर व्यापार-क्षेत्र में लगभग 20 प्रतिशत भाग। इस प्रकार कुल आन्तरिक व्यापार का लगभग 80 प्रतिशत राजकीय और सहकारी संस्थाओं के हाथ में आ गया।

इस प्रकार नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत सरकार ने ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसमें मजदुरि पूर्णजीवाद को कुछ स्थान प्राप्त रहा तथापि राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अन्य महत्त्वपूर्ण अंगों की भाँति देशी व्यापार पर सरकारी प्रभुत्व ज्यों का त्यों बना रहा।

विदेशी व्यापार (Foreign Trade)

यौद्धिक साम्यवाद के काल से विदेशी व्यापार पर रूसी सरकार का एकाधिकार था और नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत भी विदेशी व्यापार के क्षेत्र में मे राज्य का एकाधिकार ही सर्वोपरि रहा। अन्य क्षेत्रों की भाँति विदेशी व्यापार के क्षेत्र में छूट नहीं दी गई। सरकार का विचार था कि जब तक विदेशी व्यापार पर पूर्ण राजकीय नियन्त्रण नहीं होगा तब तक देश की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। सरकार की यह नीति ठीक ही सिद्ध हुई क्योंकि विदेशी व्यापार पर सरकारी एकाधिकार के कारण ही—(1) रूस सत्तार की पूर्णजीवादी मन्दी और तेजी से दुष्प्रभावों से अपनी अर्थ-व्यवस्था को बचा सका, (2) विदेशी प्रतिस्पर्धा से अपने औद्योगिक विकास की रक्षा कर सका, (3) आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सफल हुआ, एव (4) आगे चल कर पञ्चवर्षीय योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधन आसानी से जुटा सका।

अपनी औद्योगिक ज्ञानि को आगे बढ़ाने के लिए सोवियत सरकार को यन्त्रों और मशीनों की बड़ी आवश्यकता थी। प्रारम्भ में रूस ने अपने स्वर्णकोप की सहायता से उनका आयात किया, लेकिन जब स्वर्णकोष सीमित हो गया तो हानि उठा कर भी अपना माल बेच कर इनका आयात किया जाने लगा। सोवियत सरकार ने विदेशी व्यापार का प्रयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया। हानि पर माल खरीदने का लालच देकर राजनीतिक मामला प्राप्त करने के प्रयत्न किए गए।

सोवियत सरकार की नवीन औद्योगिक एव व्यापारिक नीति के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होने लगी। अतः सरकार ने अब निर्मात की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करना शुरू किया। निजी व्यापारियों तथा सहकारी समितियों को भी विदेशी व्यापार में भाग लेने के अधिकार प्रदान किए गए। केन्द्रीय स्तर पर एक विदेशी व्यापार विभाग (Commissariat of Foreign Trade) संगठित किया गया। सन् 1923 में देशी और विदेशी व्यापार नीतियों में समन्वय लाने की दृष्टि से एक और व्यापार विभाग अथवा नारकॉमटोर्ग (Narcomtorg) संगठित किया गया।

विदेशी दूतावासी ने व्यापार-प्रतिनिधि नियुक्त किए गए। जिन देशों में रूसी दूतावासी नहीं थे, वहाँ विदेशी व्यापार के विकास के लिए एक कम्पनी संगठित की गई। निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से करो में भी छूट दी गई। नवीन आर्थिक नीति की श्रमण में रूस ने ब्रिटेन, इटली आस्ट्रिया, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, मैक्सिको, जर्मनी, चीन तथा अन्य कई देशों से सफलतापूर्वक राजनयिक और व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए। रूस ने अपने अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक अन्वेषण को दूर करने के सफल प्रयास किए। विश्व-व्यापी आर्थिक मन्दी के वातावरण में भी विदेशी राष्ट्रों को इस बात पर विवश किया कि वे रूस में अपना माल निर्यात करने की सम्भावनाओं पर विचार करें।

आर्थिक क्षेत्र में जो विभिन्न प्रभावशाली कदम उठाए गए उनके फलस्वरूप विदेशी व्यापार में काफी वृद्धि हुई। सन् 1920 में रूसी निर्यात जहाँ केवल 6.1 मिलियन रूबल का हुआ था वहाँ 1923 में 954.8 मिलियन रूबल का हुआ। सन् 1921 की तुलना में 1928 में विदेशी व्यापार सात गुने से भी कुछ अधिक हो गया। 1921 में कुल विदेशी व्यापार 18.2 करोड़ रूबल का था जो 1928 में 138 करोड़ रूबल तक पहुँच गया। 1924 में ही रूस का व्यापार-अधिक्य (Balance of Trade) उसके प्रतिभूल होने के स्थान पर अनुभूल हो गया।

मौद्रिक तथा बैंकिंग व्यवस्था

नवीन आर्थिक नीति के दौरान मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था पर सरकार का पूर्ण नियन्त्रण रहा। मौद्रिक साम्यवाद के अन्तर्गत अर्थात् 1917 से 1921 के मध्य जो मुद्रा-विहीन अर्थ-व्यवस्था स्थापित की गई थी, वह 1921 के बाद भी जारी रखी गई। विनिमय के माध्यम की क्रिया को सीमित कर दिया गया और मुद्रा केवल लाभ की इकाई तथा मूल्य-मापन का साधन रह गई। मुद्रा विहीन समाज की स्थापना की दिशा में अनेक सुधारक कदम उठाए गए। मुद्रा की श्रमण शक्ति छीनली गई तथा राशनकार्ड और सहकारी समिति की सदस्यता के प्रमाण-पत्र ही उनका रूप ले सके। पूँजी निर्माण में भी मुद्रा का स्थान बैंक-साख ने ले लिया। इन सब परिवर्तनों के फलस्वरूप रूबल की श्रमण शक्ति इतनी घट गई कि मुद्रा का जनता के लिए कोई प्राकर्षण नहीं रहा। मुद्रा-स्फीति की दशा शोचनीय हो गई। मूल्य स्तर अधिकाधिक बढ़ता गया। फलस्वरूप 1919 और 1922 में दो बार मुद्रा का प्रमूल्यन किया गया। इस प्रमूल्यन द्वारा एक नया रूबल पहले के 10 लाख रूबल के बराबर बनाया गया। पुराने कागजी रूबलों को वापिस लेकर उनके स्थान पर नए रूबल दे दिए गए। विनिमय के माध्यम की क्रिया को कम से कम कर देने के कार्य में इतनी अधिक सफलता मिली कि 1928 तक स्थिति यह हो गई कि मुद्रा के रहते हुए भी उस पर व्यय करना कठिन हो गया।

मुद्रा का नियन्त्रण करने तथा विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को ऋण देने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय बैंक 'गोसप्लान' (Gosplan) की स्थापना की गई। इस राजकीय बैंक का उद्देश्य देश को प्रमूल्यन के प्रभावों से बचाना, मुद्रा प्रचलन को नियमित एवं नियंत्रण करना तथा कृषि, यातायात, उद्योग, व्यापार आदि को

अल्पकाल के लिए साख प्रदान करना था। अवमूल्यन के हानिकारक प्रभावों के निराकरण के लिए बैंक ने ब्याज दर 12 से 18 प्रतिशत प्रतिमाह करदी। स्वयं मूल्यों के आधार पर ऋण और अग्रिम ऋण देना निश्चित किया गया। बैंक की इस नीति के फलस्वरूप देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार हुआ। यह बैंक पहले वित्त मन्त्रालय के अधीन था, किन्तु 1929 में इसे वित्त मन्त्रालय से अलग कर दिया गया। परन्तु राज्य और बैंक की घनिष्ठता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडा। यह बैंक ही राज्य की अर्थ एव साख व्यवस्था का आधार था तथा अन्य बैंक उसके सहायक या प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। यह बैंक नवीन सिद्धान्तों का पोषक बना और कुछ ही अर्से में राष्ट्र की उन्नति का रक्षक, पोषक और सब कुछ बन गया। मुद्रा-प्रणाली में स्थिरता लाकर इस बैंक ने सरकारी वित्तीय कार्यक्रम में सन्तुलन स्थापित कर दिया। सम्पूर्ण औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र में बैंक का प्रभुत्व छा गया। बैंक के परामर्श से व्यय भी मदे कम करके आय के साधन बढ़ाए गए तथा घाटे की अर्थ-व्यवस्था कम करके ऋणों का सहारा लिया गया। बैंक ने देश को अनेक आर्थिक संकटों से बचाकर बजट के आकार और स्वरूप में विभिन्न उपयोगी परिवर्तन करने के लिए सरकार को प्रेरित किया।

बैंकिंग व्यवस्था को उन्नत करने के लिए और भी अनेक प्रयत्न किए गए। सितम्बर, 1922 में 'औद्योगिक बैंक-प्रमो बैंक' (Bank of Industry-Prom Bank) खोलने की अनुमति दी गई। यह बैंक उद्योगों को अल्पकालीन और त्रि-वर्षीय ऋण दे सकता था। फरवरी 1922 में सहकारी समितियों ने मिलकर उपभोक्ता बैंक (Consumers Co-operative Bank) तथा पोको बैंक स्थापित किए। बाद में यह बैंक जनवरी, 1923 में अखिल रूप से सहकारी बैंक-पोको बैंक (All Russian Co-operative Bank-Poko Bank) के रूप में परिवर्तित हो गया। स्थानीय उद्योगों तथा कार्यक्रमों की वित्तीय सहायता के लिए म्यूनिसिपल बैंक और छोटे-छोटे निजी व्यापारियों की सहायताार्थ पारस्परिक साख संघ (Mutual Credit Associations) स्थापित किए गए।

नवीन आर्थिक नीति के दौरान विभिन्न आर्थिक संकट

(Economic Crises During the Period of New Economic Policy)

आर्थिक क्षेत्र में अनेक महत्त्वपूर्ण सफलताओं के बावजूद नवीन आर्थिक नीति के दौरान देश को अनेक आर्थिक संकटों का सामना करना पडा, जिनमें से प्रमुख तीन थे—

- (क) ईंधन संकट (Fuel Crisis),
- (ख) बिक्री संकट (Sales Crisis), एव
- (ग) कैंची संकट (Scissors Crisis).

(क) ईंधन संकट

नवीन आर्थिक नीति प्रारम्भ करते समय देश के सामने ईंधन की कमी की विकट समस्या थी जिसके फलस्वरूप यात्रायात के क्षेत्र में भीषण संकट उत्पन्न हो

गया और उद्योगों की स्थिति भी बड़ी दयनीय बनती गई। 1921 में ही इस सकट ने इतना गम्भीर रूप धारण कर लिया कि सूती वस्त्र कारखानों को उनकी कुल प्रावश्यकता केवल 7 प्रतिशत ईंधन ही प्राप्त हुआ और अगस्त, 1921 के आते-आते 67 सूती वस्त्र कारखानों में से 51 कारखाने बन्द हो गए। ईंधन के अभाव के कारण ही सीमेंट का उत्पादन युद्ध पूर्व के उत्पादन की तुलना में केवल 91 प्रतिशत रह गया।

इस ईंधन सकट के कतिपय महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे—

1. गृह-युद्ध के कारण डोनबाज (Donbas) क्षेत्र में अनिश्चितता की भावना व्याप्त हो जाने से कोयले का उत्पादन बहुत घट गया था।

2. कोयला-खानों के क्षेत्र में खाद्यान्न का अभाव हो जाने से बड़ी सख्या में अधिक वहाँ से गाँवों की ओर भागने लगे थे जिससे कोयले के उत्पादन में और भी गम्भीर कमी आ गई थी।

3. गृह-युद्ध के कारण कुशल श्रमिकों का अभाव हो जाने से भी ईंधन का उत्पादन काफी घट गया था।

ईंधन सकट ने देश की सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में घोर निराशा की स्थिति पैदा कर दी। सरकार ने सकट को दूर करने के लिए विभिन्न प्रभावशाली कदम उठाए जिनके फलस्वरूप यह सकट धीरे-धीरे दूर होने लगा। सरकारी प्रयास मुख्यतः ये थे—

1. खाद्यान्न की पूर्ति का कार्य राज्य द्वारा निर्धारित कुछ पैर-सरकारी अभिकरणों को सौंप दिया गया। इसके फलस्वरूप खाद्यान्नो के उचित वितरण में सहायता मिली।

2. पूराल से खाद्यान्न, दिनेज (Denetz) से कोयला तथा तुर्किस्तान से व्यास लाने की समस्या पर विशेष ध्यान दिया गया। शहरी क्षेत्रों की ईंधन की माँग की पूर्ति में कमी की गई और कुछ समय के लिए सूती वस्त्र-कारखानों को बन्द कर दिया गया।

3. केन्द्रीय ईंधन सगठन का पुनर्गठन किया गया तथा डोनबाज (Donbas) क्षेत्र में कोयला खानों की समस्याओं को जाँच के लिए एक विशेष आयोग बँठाया गया।

4. अकुशल खानें बन्द करदी गई। उत्पादन-व्यय केवल अधिक कुशल खानों तक ही सीमित रखा गया।

5. कोयला-खानों के श्रमिकों को सन्तुष्ट करने के लिए मजदूरी-भुगतान-पद्धति में विशेष परिवर्तन किए गए।

उपर्युक्त सभी प्रयासों के फलस्वरूप 1921 में कोयले के उत्पादन में वृद्धि शुरू हो गई। वर्ष के अन्त में कोयले का उत्पादन 183 करोड़ पुंड हो गया जबकि वर्ष के आरम्भ में यह केवल 13 करोड़ पुंड ही था। सन् 1922 के अन्त तक ईंधन

16 सोवियत रूस का आर्थिक विकास

सकट पूरी तरह दूर हो गया और सूती वस्त्र मिलों में अगले कुछ महीनों तक के लिए ईंधन का भण्डार जमा हो गया।

(ख) बिक्री सकट

सन् 1923 में सोवियत सरकार को जिस भीषण कैंची सकट का सामना करना पड़ा, उसका एक प्रमुख कारण 1922 का बिक्री सकट था। 1922 के प्रारम्भ में एक ओर तो औद्योगिक प्रत्यासों के पास कार्यशील पूँजी का अभाव हो गया और दूसरी ओर बिना बिक्री निमित्त वस्तुओं का भण्डार जमा होने की समस्या उत्पन्न हो गई। अपने उत्पादन के विषय और कच्चे पदार्थों के क्रय के लिए औद्योगिक प्रत्यास सभी उपलब्ध साधनों को काम में लेते हुए परस्पर भीषण प्रतियोगिता करने लगे। खाद्य-पदार्थों और कच्चे माल की माँग अधिक होने से उनके मूल्य तेजी से बढ़ते गए जबकि औद्योगिक वस्तुओं की माँग कम होने से उनके मूल्य गिरते चले गए। 1922 के शीघ्र तक कृषि-पदार्थों के मूल्य आकाश छूने लगे। औद्योगिक उत्पादन तथा कृषि-पदार्थों के उचित विनिमय दर में औद्योगिक उत्पादन के प्रतिकूल जो परिवर्तन हुए, वे निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हैं—

वर्ष	कृषि पदार्थों का मूल्य	औद्योगिक पदार्थों के मूल्य
1913	100	100
जनवरी, 1922	104	92
फरवरी, 1922	105	90
अप्रैल, 1922	111	79
मई, 1922	113	74

जब औद्योगिक वस्तुओं की माँग एकदम घट गई और उनका मूल्य स्तर शोचनीय रूप में गिर गया तो व्यापारियों ने जिस मूल्य पर भी वस्तुएँ बिक सकी थी, बेचना शुरू कर दिया। सम्पूर्ण औद्योगिक उत्पादन पर बड़े ही प्रतिकूल रूप में सामूहिक प्रभाव पड़ा। कच्चे माल का मूल्य बहुत अधिक होने तथा ऋण की पर्याप्त सुविधा न मिलने के फलस्वरूप औद्योगिक प्रतिष्ठान विवश हो गए कि वे अपना माल कम से कम मूल्य पर ही बेच दें। यह बिक्री सकट जिन कारणों से पैदा हुआ, उनमें मुख्य इस प्रकार थे—

1. औद्योगिक वस्तुओं के विषय और कच्चे पदार्थों के क्रय के लिए औद्योगिक क्षेत्र के पास उचित बाजार-यन्त्र नहीं था।

2. 1921 में जो अकाल पड़ा उसके फलस्वरूप कृषि-पदार्थों के उत्पादन में भारी कमी आ गई।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण-शक्ति निरन्तर घटती गई तथा औद्योगिक वस्तुओं की माँग कम होती गई।

4. अपना-अपना माल बेचने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठान गला-काट प्रतियोगिता करने से सकट और भी तीव्र हो गया। अपने निमित्त माल को यथाशीघ्र

किसी भी कीमत पर बेचने तथा खाद्यान्नों एवं कच्चे पदार्थों को अधिकाधिक खरीदने के प्रयासों के फलस्वरूप विनिमय का अनुपात औद्योगिक वस्तुओं के प्रतिकूल हो गया।

स्पष्ट है कि बिजली सकट प्रथमतया गाँवों और शहरों के बीच आर्थिक असन्तुलन का परिणाम था। इस सकट को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रभावी कदम उठाए गए—

1. कच्चे मास के उचित वितरण की दृष्टि से वितरण व्यवस्था में सुधार किया गया।

2. कच्चे माल की कमी को दूर करने के लिए अति आवश्यक मिलों को छोड़ कर अन्य मिलों को बन्द कर दिया गया।

3. व्यापार की अव्यवस्था और गला-काट प्रतिযোগिता को समाप्त करने के लिए औद्योगिक ट्रस्टों ने व्यावसायिक सिन्डीकेटों का निर्माण किया।

इन उपायों के फलस्वरूप 1922 के मई माह के बाद से ही स्थिति में सुधार आ गया। औद्योगिक एवं कृषि-पदार्थों के मूल्य का सम्बन्ध प्रतिकूल दिशा में जाने लगा जिसके फलस्वरूप अन्त में भीषण कैंची सकट उत्पन्न हो गया। वास्तव में बिजली सकट ही कैंची सकट का आधार था। यही धीरे-धीरे कैंची सकट के रूप में प्रतिकल्पित हुआ।

(ग) कैंची सकट

कैंची सकट औद्योगिक एवं कृषि पदार्थों के मूल्य की विपरीत स्थिति से उत्पन्न हुआ। दोनों उत्पादनों के मूल्य में सामञ्जस्य रहने पर ही स्वस्थ और सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था बन सकती थी, लेकिन 1922-23 में स्थिति एकदम विपरीत हो गई। मई, 1922 के बाद औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य, कृषि-पदार्थों के मुकाबले तेजी से गिरते गए जिसके फलस्वरूप विख्यात कैंची सकट उत्पन्न हुआ। चूँकि औद्योगिक और कृषि उत्पादन के मूल्य कैंची की दो पतियों की तरह चाल चल रहे थे और यह चाल अर्थ-व्यवस्था को काटने वाली अर्थात् इसके लिए घातक थी—अतः इस स्थिति को कैंची सकट के नाम से पुकारा गया। यह आर्थिक सकट कितना गम्भीर था, इसका अनुमान कृषि एवं औद्योगिक पदार्थों के मूल्यों के विन्मांकित सूचकांक से लगाया जा सकता है—

वर्ष	कृषि पदार्थों का मूल्य	औद्योगिक उत्पादन का मूल्य
1913	100	100
जनवरी, 1922	104	92
मई, 1922	113	74
अगस्त, 1922	100.5	99
सितम्बर, 1922	94	112
जनवरी-फरवरी, 1923	88	275

स्पष्ट है कि 1922 के मध्य तक विनिमय दर कृषि पदार्थों के पक्ष में थी जिससे किसानों को जोस्ताहन मिला कि वे कृषि क्षेत्र का विस्तार करें तथा बाजार में विक्रय के लिए अधिकाधिक उपज लाएं। इसका यह स्वाभाविक परिणाम निकला कि किसानों की क्रय शक्ति से बढ़ी और वे औद्योगिक वस्तुओं की अधिकाधिक मांग करने लगे। इस स्थिति में 1922 के उत्तरार्द्ध से ही विनिमय दर औद्योगिक पदार्थों के पक्ष में झुकने लगी और जनवरी, फरवरी, 1923 में औद्योगिक वस्तुओं तथा कृषि-पदार्थों के मूल्यों में 3:1 का अनुपात हो गया। यदि कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में इस परिवर्तन को हम ग्राफ द्वारा इंगित करें तो ये कैची के दो फलों की तरह दिखाई देंगे।

कारण—कैची सकट केवल औद्योगिक और कृषि पदार्थों के मूल्यों में भारी असंतुलन का ही परिणाम नहीं था, इसके एक से अधिक कारण थे जिन पर अर्थशास्त्री एकमत नहीं हैं।

औद्योगिक मूल्य वृद्धि के कारण ये थे—1 उपलब्ध उत्पादन शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं होने से उत्पादन की प्रति इकाई पर व्यय अधिक पड़ने लगा था, 2 जटिल और अकुशल अर्थ-व्यवस्था के फलस्वरूप लागत मूल्य में वृद्धि हो रही थी, 3 एकाधिकार प्राप्त राजकीय उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं के मूल्य बहुत ऊँचे रखे गए 4 उद्योग एवं तस्मान्बन्धी व्यापार को ऋण देने के बारे में उदार नीति अपनाए जाने से औद्योगिक क्षेत्र को अपनी निर्मित वस्तुओं का अधिक समय तक सग्रह करने की क्षमता प्राप्त हुई और वे अभाव की स्थिति पैदा करके मूल्य बढ़ाने में सफल हुए, 5 युद्धकालीन हानि की पूर्ति का प्रयत्न किया गया जिससे औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई, 6 फुटकर व्यापारियों ने भी माल रोक कर अधिक धन कमाने की कोशिश की।

कृषि-क्षेत्र में मूल्यों की गिरावट के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे—1 कृषि-पदार्थों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई जबकि औद्योगिक उत्पादन में कमी आई 2 कृषि प्रणाली में विशेष परिवर्तन नहीं किए जा सके, 3 गृह-युद्ध के दुष्प्रभावों को दूर करके पुनर्निर्माण की दृष्टि से कृषि को उद्योग से अधिक सुविधा मिली जिससे कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ चला, 4 देशी बाजारों में अनाज की पूर्ति की मात्रा बहुत अधिक हो गई, 5 कृषि पदार्थों के विदेशी बाजार की समाप्ति से उनके मूल्य में और कमी आ गई, 6 विशाल संगठित राजकीय संस्थाओं के एकमात्र खरीददार होने से व्यक्तिगत किसान की मोल भाव करने की शक्ति नष्ट हो गई एवं 7 आवश्यकताओं का दबाव इसना बढ गया कि किसान किसी भी मूल्य पर जल्दी से जल्दी फसल बेचने लगे।

उपरोक्त सभी कारणों से कैची सकट उत्पन्न हुआ। इसका तात्कालिक कारण मुद्रा प्रसार था जिसके फलस्वरूप मौद्रिक इकाई के मूल्य में निरन्तर कमी होती गई और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगे।

परिणाम—कैची सकट के फलस्वरूप देश की आर्थिक स्थिति पुनः खराब हो गई। किसानों का सरकार में विश्वास उगमना गया और नवीन आर्थिक नीति की सर्वत्र आलोचना होने लगी। उद्योग धंधों को असामान्य लाभ होने से उनका प्रवृत्त विकास हुआ। ग्रामीण जनता का आर्थिक शोषण हुआ तथा श्रमिकों के कष्ट बढ गए। वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ जाने से उनकी मांग कम हो गई। औद्योगिक माल कारखानों में जमा होता गया और कच्चे पदार्थों की मांग बढ गई। कृषि-पदार्थों की मांग बढ जाने से उनके मूल्य भी चढ गए और स्थिति अधिक बिगड गई। कैची सकट ने केवल आर्थिक विकास की गति को ही धक्का नहीं पहुँचाया बल्कि देश में एक राजनीतिक सकट भी पैदा कर दिया क्योंकि किसानों और मजदूरों की सन्धि अथवा उनके मधुर सम्बन्ध खतरे में पड गए।

सकट निवारण के उपाय—कैची सकट से उत्पन्न राजनीतिक और आर्थिक खतरों का मुकाबला करने के लिए सरकार ने कठोर उपायों का प्रयास किया। लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया कि यदि औद्योगिक उत्पादन और कृषि-पदार्थों के मूल्यों में अधिक कमी या वृद्धि की गई तो एक ओर तो श्रमिकों का असन्तोष बहुत अधिक बढ जावेगा और दूसरी ओर कृषि विपणन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः सरकार ने, स्थिति पर काबू पाने के लिए, दो तरफा प्रयास किए। यह नीति अपनाई गई कि कुछ औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य घटाए जाएँ और कुछ कृषि पदार्थों के मूल्य बढ़ाए जाएँ। इस दृष्टि से सरकार ने औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में मुख्यतः अप्रतिष्ठित कदम उठाए—

(1) राजकीय बैंक के माध्यम से कठोर साख नियन्त्रण की व्यवस्था की गई जिससे विभिन्न व्यवसायों को मुद्रा की कमी महसूस हुई और उन्हें अपना संप्रहीत माल बेचना पडा।

(2) आन्तरिक व्यापार के लिए एक नवीन समिति गठित की गई जिसके द्वारा वस्तुओं का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया।

(3) विदेशों से सस्ती वस्तुओं का आयात किया गया जिससे विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में देशी औद्योगिक वस्तुएँ कम मूल्य पर बेची जा सकी।

(4) व्यक्तिगत व्यापार सीमित करके राज्य एवं सरकारी व्यापार के माध्यम को अपनाया गया।

(5) उधार मूल्य नीति अपनाई गई, साधारण के नियत की प्रोत्साहन दिया गया तथा किसानों के लिए राजकीय बैंक द्वारा उधार-साख व्यवस्था की गई।

(6) मौद्रिक व्यवस्था में सुधार करके मुद्रा के मूल्य में स्थिरता लाने के प्रयास किए गए।

(7) कृषि उत्पादन के व्यापार में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया गया।

इन उपायों के परिणामस्वरूप सन् 1924 तक कैची सकट लगभग समाप्त हो गया। 1924 में औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन के मूल्यों का अन्तर निरन्तर

20 सोवियत रूस का आर्थिक विकास

कम होता गया। 1928 तक सरकारी तौर पर सकट की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। लेकिन वास्तविकता यह थी कि कच्ची सकट कुछ और अवधि तक चला, व्यापारिक सन्तुलन किसानों के विपरीत बना रहा और अन्त में स्टालिन को राशनिंग का सहारा लेना पड़ा।

नवीन आर्थिक नीति का परित्याग (Divorce to New Economic Policy)

यौद्धिक साम्यवाद के बाद जो नवीन आर्थिक नीति अरनाई गई वह समाजवादी ढाँचे में पूँजीवादी उत्पादन के प्रभावशाली तरीकों का एक अनोखा नमूना था। लेनिन जानता था कि रूस को पूँजीवाद की दोनों परिस्थितियों में से गुजरना पड़ेगा—निजी पूँजीवाद और राजकीय पूँजीवाद। निजी पूँजीवाद से राजकीय पूँजीवाद उत्पन्न होगा तथा राजकीय पूँजीवाद से समाजवाद। इस कार्य को नवीन आर्थिक नीति ने भली प्रकार पूरा किया।

नवीन आर्थिक नीति के दौरान आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं में पर्याप्त सन्तोषजनक स्थिति रही और राष्ट्रीय आय चमत्कारी ढंग से बढ़ी। चार वर्ष की अत्यावधि में ही राष्ट्रीय आय में लगभग 150 प्रतिशत की वृद्धि हो गई। आयात-निर्यात के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई तथा 1913 के पूर्व की स्थिति प्राप्त कर ली गई। अर्थ-व्यवस्था में स्थायित्व लाने के प्रभावशाली प्रयास हुए। वास्तव में नवीन आर्थिक नीति ने केवल समाजवाद के भाग को ही प्रशस्त नहीं किया बल्कि दूसरी ओर जनता को समाजवादी अर्थ-व्यवस्था स्थापित करने के लिए प्रशिक्षित भी किया। विभिन्न आर्थिक सकट इस नीति के प्रभावशाली अवलम्बन के कारण ही दूर किए जा सके। इस नीति के दौरान ही बैंकिंग प्रणाली का विस्तार हुआ तथा विदेशी राष्ट्रों से राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने की दिशा में भी प्रगति हुई।

इन सब बातों के बावजूद कतिपय कारणों से नवीन आर्थिक नीति का परित्याग आवश्यक हो गया था। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के अप्राकृतिक मिश्रण से अनेक घातक आर्थिक दुष्परिणाम निकले और जनता में आर्थिक विषमता का प्रसार हुआ। पूँजीवादी तत्त्व पनपने लगे, निजी क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो सका, उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएँ मिलने में कठिनाई होने लगी और उत्पादक उपभोक्ताओं के शोषण में समृद्धिशाली बन्ते गए। मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अपनाए जाने के फलस्वरूप समाजवादी और पूँजीवादी तत्त्वों के बीच एक ऐसा संघर्ष उठ खड़ा हुआ जिसमें पूँजीवादी तत्त्वों की जीत के आसार प्रकट होने लगे। अतः सोवियत सरकार ने इस नीति का परित्याग करते हुए निजी सम्पत्ति के सिद्धान्त को हमेशा के लिए बफना देना ही उचित समझा। इसके अतिरिक्त नवीन आर्थिक नीति को जारी करने वाला लेनिन स्वयं 1924 में चल बसा। लेनिन के उत्तराधिकारी स्टालिन ने कुछ समय तक इस नीति को चलाया और तब 1928 के आते-आते इसका परित्याग करके “निर्घोजन युग” का सूत्रपात किया।

क्या नवीन आर्थिक नीति साम्यवाद के प्रयोगों की विफलता और पूंजीवाद की पुनर्स्थापना का प्रयास था ?

यौद्धिक साम्यवाद के बाद नवीन आर्थिक नीति प्रारम्भ की गई। यह नीति समाजवादी ढांचे में पूंजीवादी उत्पादन के प्रभावशाली तरीकों का एक अनोखा और विचित्र नमूना था। इस नीति के अन्तर्गत लेनिन ने छोटे-छोटे उद्योगों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण किया, कृषि और उद्योग के बीच विनिमय व्यवस्था पुनः कायम की और व्यापक क्षेत्र में, विशेषतः फुटकर व्यापार में, निजी व्यापारियों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की। इससे बहुत से लोगों में और खासकर विदेशों में यह धारणा कायम करने लगी कि नवीन आर्थिक नीति अपना कर लेनिन साम्यवाद की ओर से पीछे हट रहा है। मोरिस डॉग ने लिखा है कि—

“नवीन आर्थिक नीति के प्रारम्भ को तरकालीन विदेशी बुर्जुआ वर्ग द्वारा वापिस मुड़ने, विफलता का परिचायक भूतकाल में प्राप्त की गई स्थिति के परिवर्तन के रूप में बतलाया गया जो अन्ततः पूंजीवाद की पुनर्स्थापना के रूप में फलीभूत होता। देश के अन्दर भी कुछ लोगों में इसे मुड़ना, विरोधी शक्तियों के समझ भुंकना आदि मानने की प्रवृत्ति विकसित होने लगी थी।”

किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था। नवीन आर्थिक नीति को साम्यवाद के प्रयोगों की विफलता और पूंजीवाद की ओर पुनः मुड़ने के रूप में बतलाया जाना भ्रामक था। मोरिस डॉग के ही अनुसार, नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत जो अर्थ-व्यवस्था प्राप्त हुई वह कोई नई अथवा प्राचीन व्यवस्था को समाप्त करने में विफलता का परिणाम नहीं थी। इस नीति के अन्तर्गत वस्तुतः एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था का प्रारम्भ किया गया था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही व्यवस्थाओं की विशेषताएँ विद्यमान थीं। दूसरे शब्दों में नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को अपनाया गया था। यह एक परिवर्तनशील नीति थी जिसने परिवर्तन-कालीन स्थिति में मिश्रित प्रणाली को अपनाकर देश को आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर किया। लेनिन ने “सक्रमणकालीन मिश्रित व्यवस्था” (Transitory Mixed Economy) के रूप में इसकी व्याख्या की और इसे राजकीय पूंजीवाद ही बतलाया। लेनिन ने बलपूर्वक यह कहा कि राजकीय पूंजीवाद अनिवार्य रूप से सक्रमणकालीन होगा। इसके अन्तर्गत बहुत-सी परस्पर विरोधी शक्तियों का समावेश है जिससे यह प्राणना रहती है कि या तो पूंजीवादी तत्त्व या समाजवादी तत्त्व अन्त में विजयी होंगे। लेकिन सोवियत सरकार इस बात के लिए पूर्णतः सचेत है कि समाजवादी शक्तियाँ ही विजयी होंगी। लेनिन की इस व्याख्या से स्पष्ट है कि नवीन आर्थिक नीति का अन्तिम उद्देश्य समाजवाद का सुदृढीकरण ही था। लेनिन इतना तेजी से भागने के पक्ष में नहीं था कि गिरने की नौबत आ जाए। वह जानता था कि साम्यवाद लाने के लिए एक विशेष प्रकार की सच्ची तैयारी की आवश्यकता है और उस तैयारी को किए बिना साम्यवाद को ला देना स्वयं के पैरों पर अपने-आप पुच्छाही मारने जैसा होगा। इतिहास बताता है कि लेनिन ने सही दिशा में सोचा

था और उसका निर्णय सही था। नवीन आर्थिक नीति पूँजीवाद और साम्यवाद के बीच के संधि काल की आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें दोनों प्रकार की अर्थ-व्यवस्थाओं के तत्त्वों और विशेषताओं का रहना अनिवार्य था।

नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत अपनाई गई अर्थ-व्यवस्था समाजवादी आर्थिक व्यवस्था की दिशा में एक प्रकार की तैयारी और ठोस अभ्यास थी।

लेनिन जानता था कि रूस को पूँजीवाद की दोनों हासलों में गुजरना पडगा—निजी पूँजीवाद और राजकीय पूँजीवाद। निजी पूँजीवाद से राजकीय पूँजीवाद उत्पन्न होगा और राजकीय पूँजीवाद से समाजवाद। इस कार्य को नवीन आर्थिक नीति ने भली प्रकार पूरा किया।

नवीन आर्थिक नीति की विशेषताएँ

नवीन आर्थिक नीति वास्तव में एक पूँजीवादी नीति का ही सुधरा हुआ रूप था। रूस की सरकार देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहती थी, लेकिन वहाँ के गृह युद्ध व बाहरी हस्तक्षेप के कारण जनता में अशांति थी। समाजवाद लाने वाले नेता भी दो भागों में विभक्त थे। यद्यपि दोनों दलों ही देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे तथापि दोनों दलों की नीतियों में कुछ असमानताएँ थी। इस दशा में देश की सरकार के सामने एक ऐसी नीति बनाने का कार्य था जो कि पहले देश में शान्ति स्थापना में सहायक हो तथा बाद में देश को समाजवाद की ओर भी ले चले तथा इस बात का प्रत्येक व्यक्ति को आभास न हो। नई नीति में ये तमाम बातें शामिल हैं।

नवीन आर्थिक नीति के अनुसार देश में पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की कुछ बातों को शामिल किया गया तथा इसमें समाजवादी अर्थ-व्यवस्था की भी कुछ बातों का उल्लेख था। नई आर्थिक नीति की निम्नलिखित विशेषताएँ थी—

(1) पूँजीवाद के लक्षण—नई नीति के अनुसार कृषक अपनी उपज को बाजार में अपनी मर्जी के अनुसार बेच सकते थे तथा आवश्यक माल भी क्रय कर सकते थे। उद्योगों को भी इस प्रकार की छूट मिली हुई थी। वे भी स्वतन्त्रतापूर्वक बाजार में माल का क्रय-विक्रय कर सकते थे। इस नीति के कारण देश में खुदरा व थोक व्यापार की उन्नति हुई। अनेक सस्याएँ केवल व्यापार में ही लग गईं।

उद्योग के विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाई गई। अनेक सस्याओं में अर्थिक सघों द्वारा स्थापित कमिटी व बुराईयों को समाप्त किया गया। ट्रस्ट नाम की सस्याओं को मान्यता दी गई, जो कि हमारे देश की कम्पनियों के समान ही थे। इनका प्रबन्ध मालिक तथा श्रम सगठनों द्वारा सरकारी सस्या वेसेन्खा द्वारा किया जाता था, लेकिन फिर भी मालिकों का महत्त्व ट्रस्ट में अधिक समझा गया। दूसरे ट्रस्टों का एकीकरण भी किया जाने लगा। इससे बड़े पैमाने की उत्पत्ति को प्रोत्साहन मिला। ट्रस्ट यद्यपि ग्लोबकी से कई तरह से सादृश्य था तथापि ट्रस्ट पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का द्योतक था।

इस नीति के अनुसार अनेक वस्तुओं पर कर भी लगाए गए। शराब, स्प्रिट,

तन्हाफू, दियासलाई, चाम और बाँफो आदि पर उत्पादन कर लगाया गया। करारोपण की नवीन पद्धति निकाली गई जो कि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था की ही विशेषता है। इसके प्रतिरिक्त रुबल का प्रवमूल्यन भी किया गया ताकि इसी व्यापार अन्य देशों के साथ बढ सके। रुबल की स्थिरता को बढाने के लिए नया स्वतन्त्र विकास जिनमें अधिक स्वायत्तत्व था। मूल्यों में स्थिरता तथा मुद्रा-प्रसार को रोकने के लिए अनेक पूँजीवादी रीतियों का अवलम्बन किया गया।

रूस में वहाँ की जनता का सरकार पर से विश्वास हट रहा था जिसको बनाना जरूरी था। वहाँ की जनता देश में तमाम उद्योगों, कृषि आदि के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थी। इस कारण मार्च, 1922 के आदेशों के अनुसार अनेकों प्रकार के उद्योगों को उनके पुराने स्वामियों को लौटा दिया गया। इन सब बातों से सरकार चाहती थी कि जनता अपने नैराश्य को समाप्त कर एक विकासशील राष्ट्र की स्थापना में योग दे। इस नीति ने वास्तव में जनता का समर्थन प्राप्त कर लिया तथा सरकार के लिए लक्ष्य-प्राप्ति अथ उतना कठिन न रहा।

(2) समाजवाद की ओर कदम—देश में जनता सरकार के दिलकुल खिलाफ थी। लोग सरकारी नीतियों का पालन नहीं करते थे क्योंकि वे समाजवाद के खिलाफ थे। परन्तु नई नीति के कारण ऐसा लगने लगा मानो देश में पूँजीवाद की स्थापना हो जायगी तथा लोगों की दिक्कतें समाप्त हो जावेंगी। लेकिन सरकार ने मूल्य नियन्त्रण, अनेक बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, ट्रस्टों के प्रबन्ध में बेसेन्सता का हस्तक्षेप तथा भूमि कर की वस्तुओं के रूप में बस्ती आदि ऐसी बातें थीं जो साम्यवाद की ओर एक कदम कही जा सकती हैं। जनता तो अपनी नई स्थिति से ही नृष हो गई थी, कोई नहीं जानता था कि उन्हें किसी नई आर्थिक व्यवस्था का भी सामना करना पड सकता है। धीरे-धीरे सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन किया जिससे वहाँ के नागरिक अभ्यस्त हो गए तथा किसी ने इसका विरोध नहीं किया। पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा सरकार देश में अपनी अर्थ-व्यवस्था अच्छी बना कर लोगों को दिखाना चाहती थी कि समाजवाद का प्रयोग पूँजीवाद से अच्छा है। सरकार ने इस नई नीति के द्वारा दोनों नीतियों का एक साथ प्रयोग किया व इनके जरिए पूँजीवादी व्यवस्था की कमियों व कुराइयों का प्रदर्शन किया गया तथा दूसरी ओर इसके द्वारा समाजवाद के लाभ व गुण बताए। इससे जनता स्वतः ही सरकार के पक्ष में हो गई तथा समाजवाद को अच्छा समझने लगी।

(3) कृषकों तथा कारखानों की स्वतन्त्रता—इस नीति के अनुसार कृषकों तथा कारखानों व उनके मालिकों को छूट दी गई कि वे अपनी वस्तुएँ खुले बाजार में सखिद-बेच सकें, यह नीति पिछली दोनों आर्थिक नीतियों से भिन्न थी।

(4) ट्रस्टों का निर्माण—इस नीति के अनुसार उद्योगों के लिए ट्रस्ट स्थापित किए गए। ट्रस्टों के संचालन के लिए बड़े बॉर्डर ट्रस्टीज होना था। बर्डर को ट्रस्ट के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। केवल कुछ बातों के सम्बन्ध में

वेसेन्खा से इजाजत लेनी पड़ती थी। इन प्रकार स्वतन्त्र साहस, सगठन इस नीति की विशेषता है।

पूँजीवाद तथा समाजवाद का साथ-साथ रहना—नवीन नीति एक ओर तो पुरानी नीति की बुराइयों को दूर करती थी तथा पूँजीवादी नीति पर आधारित थी जबकि दूसरी ओर इस नीति का लक्ष्य था समाजवाद की प्राप्ति। ये दोनों उद्देश्य इस प्रकार मिले हुए थे कि एक-दूसरे उद्देश्य का एकदम पता नहीं लगाया जा सकता था। यही कारण है कि इस नीति का अधिक विरोध नहीं हुआ तथा इसके द्वारा सरकार ने लक्ष्य प्राप्ति की।

नवीन नीति द्वारा स्थापित आर्थिक प्रणाली—जब नवीन नीति लोगों के सामने आई तो लोगों ने समझा कि यह नीति सरकार के विरोधियों की जीत है तथा कहा गया कि सरकार ने समाजवाद का रास्ता छोड़ दिया है। कुछ लेखकों ने इसे विरोधी दृष्टिकोण शामिल करने वाली नीति कहा, परन्तु यह वास्तव में शान्तिकालीन वातावरण उत्पन्न करने की चेष्टा थी।

इस काल तक लगभग सभी बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। इससे राष्ट्रीय व्यवस्था का समाजवाद की ओर झुकाव था। कृषि पूरी तरह व्यक्तिगत उपक्रम थी कुछ थोड़े से बड़-बड़ सरकारी फार्मों को छोड़ कर कृषि छोटे-छोटे व्यक्तिगत कृषक भू स्वामियों के हाथ में थी। कृषि का अधिकांश भाग प्रायः कृषक के स्वर्च में चला जाता था। उद्योग तथा कृषि के बीच सम्बन्ध व्यापार द्वारा स्थापित होता था जिसमें व्यक्तिगत पूँजी के लिए पर्याप्त सम्भावना थी। इस व्यवस्था में व्यक्तिगत उपक्रम के विकास के लिए पर्याप्त सम्भावनाएँ थी। इस कारण इस व्यवस्था को किसी भी प्रकार समाजवादी नहीं कहा जा सकता था, परन्तु इसे पूँजीवादी व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि तमाम उत्पादन छोटे-छोटे कृषकों के हाथ में रहता है। इसका अध्ययन करने से केवल इतना कहा जा सकता है कि इस व्यवस्था से दुबारा पूँजीवाद के पतन की पूरी सम्भावनाएँ थी। लेनिन ने इसे ट्रेडिशनल मिश्रित प्रणाली कहा।

इस प्रणाली को मिश्रित इस कारण से कहा गया क्योंकि इसमें समाजवाद, पूँजीवाद तथा छोटे पैमाने के उत्पादन—क्षेत्रों का समावेश था। यह प्रणाली थोड़े से समय के ही लिए प्रयोग में रही।

यह व्यवस्था समाजवाद की प्राप्ति के लिए तैयारी मात्र थी तथा भागे चल कर उत्पादन का सामूहिकरण होना था। उत्पात्ति के साधनों का स्वामित्व व्यक्ति के पास न रह कर भविष्य में राज्य के पास रहना था।

2

प्रथम पंचवर्षीय योजना से पूर्व सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था

(Economic Situation on the Eve of the First
Five Year Plan)

“नवीन आर्थिक नीति को अपनाते वाला रूस समाजवादी बन कर रहे’ रूसी
समाज का रूप एक दफतर, एक फैक्ट्री का होगा।”

—लेनिन

सोवियत रूस ने नवीन आर्थिक नीति के दौरान आर्थिक क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की और राष्ट्रीय धन्य-व्यवस्था मुद्रा पूर्व के स्तर तक पहुँच गई, लेकिन निजी व्यापार तथा पूँजीवादी शक्तियों को अत्यधिक प्रोत्साहन देने के कारण 1925 से इस नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया तीव्र होने लग गई। आर्थिक क्षेत्र में जो विभिन्न संकट उपस्थित हुए, उनसे भी नवीन नीति के विरुद्ध असन्तोष की भावना जाग्रत हुई। लेनिन ने पूँजीवादी और समाजवादी तत्त्वों के बीच जिस संघर्ष की बल्बना की थी वह सामने आ गया। सोवियत नेताओं ने नवीन आर्थिक नीति को जारी रखने के सम्बन्ध में उग्र मतभेद उठ खड़े हुए। लेनिन की मृत्यु के उपरान्त स्टालिन के नेतृत्व में सन् 1928 तक, न्यूनधिक परिवर्तनों के साथ, यह नीति किसी न किसी प्रकार चलती रही, लेकिन इस नीति का परिणाम अपरिहार्य हो गया और स्टालिन ने देश के लिए नियोजित धन्य-व्यवस्था (Planned Economy) की नींव रखी। सन् 1928 में ही देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात करके रूस की सर्वांगीण समृद्धि की नींव रख दी गई। अब तक सोवियत रूस अपनी ही पंचवर्षीय, त्रिवर्षीय और सप्तवर्षीय योजनाएँ पूरी कर चुका है तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना (1976-1980) की पूर्ति की दशा में सफलतापूर्वक अग्रसर है। नियोजन की नीति के फलस्वरूप रूस आज हर क्षेत्र में इतनी प्रगति कर चुका है कि अमेरिका के बाद विश्व में उसका ही स्थान सर्वोपरि है। रूसी नेताओं का यह दावा है कि 1980 तक सोवियत संघ अमेरिका को पीछे छोड़कर विश्व का प्रथम श्रेणी का सर्वोपरि राष्ट्र बन जायेगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में आर्थिक स्थिति (Economic Situation on the Eve of the First Plan)

यह जानना रोचक होगा कि रूस में 1928 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना का समारम्भ किया गया तो रूस की आर्थिक स्थिति क्या थी—सारभूत रूप में सोवियत संघ की तत्कालीन आर्थिक स्थिति सामान्यतः 1915 के समकक्ष ही थी। औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से सन् 1913 में रूस का पाँचवाँ स्थान था, लेकिन सन् 1928 उसका स्थान छठवाँ हो गया। 1917 की क्रान्ति के उपरान्त रूस को घोर आर्थिक संकटों, गृह युद्ध की ज्वालाओं और विदेशी हस्तक्षेप का सामना करना पड़ा था। इन बाधाओं को भेद कर भी रूस 1928 में अपना जो औद्योगिक महत्त्व बनाये रख सका, वह कम आश्चर्य की बात नहीं थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात करने से ठीक पूर्व विभिन्न क्षेत्रों में रूस की आर्थिक दशा का दिग्दर्शन अग्रांकित वर्णन से स्पष्ट होगा—

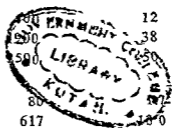
कृषि अवस्था—इस समय भी रूस एक कृषि प्रधान राष्ट्र था तथा उसकी श्रम शक्ति का लगभग 71 प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ था। 1917 की क्रान्ति के उपरान्त बड़ी-बड़ी जागीरों तथा भू-सम्पत्तियों को समानता के आधार पर छोटे-छोटे टुकड़ों में किसानों में विभाजित करने से यद्यपि भूमि के उप-खण्डों में काफी समानता आ गयी थी लेकिन छोटे-छोटे किसानों की सरया बहुत अधिक बढ़ गई थी। जहाँ 1914 में सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि का केवल 70 प्रतिशत भाग छोटे किसानों के पास था वहाँ 1928 में यह 96 प्रतिशत हो गया। राजकीय कृषि फार्मों के पास 30 से 40 लाख एकड़ भूमि थी जबकि गृह युद्ध की अवधि में उनके अधिकार में लगभग 50 लाख एकड़ भूमि थी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरम्भ करते समय रूस में कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 1 प्रतिशत भाग पर ही सरकारी और सामूहिक कृषि-फार्मों द्वारा खेती की जाती थी। सामूहिक खेत (Collective Farms) देश की कुल कृषि उपज का केवल 2 प्रतिशत भाग उत्पन्न करते थे। कृषि अधिकांशतः छोटे-छोटे किसानों द्वारा की जाती थी और सरकार इसी कृषि व्यवस्था पर कच्चे माल और साधान की उपलब्धि के लिए निर्भर थी। एक अध्ययन के अनुसार 1926-27 में कुल किसानों में से लगभग 3.9 प्रतिशत किसान 'कूलक' थे जो समस्त अन्न का लगभग 25.9 प्रतिशत भाग कर के रूप में लेते थे। मध्यवर्गीय किसान लगभग 62.7 प्रतिशत थे जिनसे कुल अन्न का लगभग 72.9 प्रतिशत भाग वसूल किया जाता था। निर्धन किसान लगभग 22.1 प्रतिशत थे जिनसे लगभग 1.3 प्रतिशत भाग कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। शेष 11.3 प्रतिशत किसान सर्वहारा वर्ग में से थे जिनसे कोई अन्न-कर वसूल नहीं किया जाता था।

नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत कृषि की प्रगति के लिए विभिन्न उपाय करने के बावजूद 1928 में कृषि-अर्थव्यवस्था की स्थिति चिन्ताजनक थी और अनाज

की गम्भीर समस्या विद्यमान थी। 1926-27 में युद्ध पूर्व की तुलना में अनाज के उत्पादन की जो स्थिति थी वह अग्रिमिक आंकड़ों से स्पष्ट होगी—

	कुल उत्पादन (10 लाख पुड)	प्रतिशत
युद्ध से पूर्व—		
भूमिपतियों द्वारा		12
कूलकों द्वारा		38
गरीब एवं मध्यवर्गीय किसानों द्वारा		
1926-27		
राजकीय तथा सामूहिक फार्मों द्वारा	80	
कूलकों द्वारा	617	130
गरीब तथा मध्यवर्गीय किसानों द्वारा	4052	853



सन् 1926-27 के उपरान्त कृषि उत्पादन में वृद्धि एक-सी गई तथा कृषि एवं औद्योगिक पदार्थों के मूल्यों का अनुपात किसानों के प्रतिकूल होता गया। कृषि की दशा शोचनीय हो गई और निराश होकर किसानों ने अन्न पैदा करना बहुत सीमित कर दिया जिससे 1927 का वर्ष समाप्त होते-होते देश में अन्न की मात्रा बहुत ही कम हो गई। विक्री के लिए बाजार में अनाज बहुत ही कम आने लगा। जहाँ युद्ध से पूर्व विक्री के लिए बाजार में उपलब्ध अनाज 1300 मि पुड था वहाँ 1926-27 में यह 630 मि पुड ही रह गया। खाद्यान्न की वसूली की स्थिति भी चिन्ताजनक हो गई। 1928 में मार्च की समाप्ति तक केवल 275 मि. पुड ही वसूली की गई, लेकिन अप्रैल और जून के मध्य केवल 100 मि. पुड की वसूली ही की जा सकी।

सन् 1928 में दुर्भाग्यवश विभिन्न क्षेत्रों में सूखा पड़ा जिससे फसलें नष्ट हो गईं और 1928-29 में कृषि की दशा और भी अधिक विगड़ गई। सरकार ने आर्थिक सहायता देकर कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं निकला। किसानों ने राज्य को निर्धारित मूल्यों पर खाद्य पदार्थ बेचने से मना कर दिया, पर सरकार को पुनः कठोर नीति अपनानी पड़ी। संप्रहित अन्न को जप्त करने के लिए विधेय किसानों की समितियाँ गठित की गईं और छोटे-छोटे बखरे खेतों के सामूहिकरण की नीति अपनाई गई। गहन खेती पर विशेष बल दिया जाने लगा। कूलकों और समृद्ध मध्यवर्गीय किसानों द्वारा असहयोग करने पर सरकार को कठोर दमनात्मक कार्यवाही भी करनी पड़ी। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते हुए असन्तोष और विद्रोही वातावरण से चिन्तित सरकार के लिए आवश्यक हो गया कि वह औद्योगिक विकास के माध्यम पर कृषि को सुसंगठित करते हुए पूर्ण आर्थिक नियोजन की नीति का आश्रय ले।

संक्षेप में, प्रथम योजना से पूर्व सोवियत कृषि की अवस्था बड़ी दयनीय थी और भयानक भ्रष्टाचार का सङ्कट मुँह बाएँ खड़ा था।

औद्योगिक अवस्था

प्रथम योजना की शुरुआत के पूर्व औद्योगिक दृष्टि से रूस की स्थिति सन्तोषजनक थी। नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र में, विभिन्न सड़कों के बावजूद, अच्छी प्रगति की गई। 1926-27 में उद्योग पर 800 मिलियन रूबल व्यय किए गए और 1927-28 में 1800 मिलियन रूबल से भी अधिक। फिर भी औद्योगिक क्षेत्र के कुछ पहलुओं के प्रति सरकार की नीति उदासीन-सी रही। औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को प्रभावशाली ढंग से नियन्त्रित नहीं किया जा सका। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मध्य पारस्परिक विनिमय की स्थिति में भी अपेक्षित सुधार नहीं लाया जा सका। औद्योगिक क्षेत्रों ने किसानों को घटिया वस्तुएँ बेचना जारी रखा। बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने विकास के प्रति आपरवाह रहे और कुछ प्रतिष्ठान तो कार्यशील पूँजी भी उपाजित करने में असमर्थ रहे। सरकार की अनिश्चित नीति के कारण निजी क्षेत्र ने औद्योगिक विकास के प्रति कोई रुचि नहीं ली। निजी क्षेत्र इस बात से आशंकित रहा कि पूँजी निर्माण और औद्योगिक प्रतिष्ठान के विकास के उपरान्त सरकार उस पर अपना कब्जा जमा लेगी। सरकार औद्योगिक ढाँचे तथा प्रबन्ध के विषय में भी कोई निश्चित नीति निर्धारित करने में असफल रही।

1917 की क्रान्ति के उपरान्त 1928 में प्रथम योजना आरम्भ होने पर सोवियत औद्योगिक उत्पादन में सन् 1913 के उत्पादन स्तर से लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मशीन निर्माण उद्योग ने लगभग 23 प्रतिशत अधिक मशीनों का उत्पादन किया। शक्ति-केन्द्र में क्रान्ति के पूर्व की तुलना में लगभग 2.5 गुना वृद्धि की गई। टूबटर, लारी, टैंक, हवाई जहाज आदि का निर्माण देश में ही होने लगा। 1927 में राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का भाग लगभग 42 प्रतिशत हो गया। और 1928 में कुल औद्योगिक उत्पादन में सामाजिक क्षेत्र का भाग 82.4 प्रतिशत तक जा पहुँचा। कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 17.6 प्रतिशत निजी कारखानों अथवा उपक्रमों द्वारा उत्पादित किया जाता था। प्रथम योजना लागू होने के बाद निजी उपक्रमों द्वारा उत्पादित माल का प्रतिशत और भी गिर गया तथा 1938 तक यह केवल 0.2 प्रतिशत ही रह गया।

नवीन आर्थिक नीति के अन्तर्गत 1927-28 से पूर्व के 3 वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करके भावी नियोजन की नीति के लिए आधारभूत तैयारी की गई। इसी अवधि में सर्वोच्च आर्थिक परिपद् वेसेन्का का दो बार पुनर्गठन किया गया। राजकीय उद्योगों के केन्द्रीय प्रशासन को समाप्त करके उद्योग की प्रत्येक शाखा के लिए पृथक् प्रशासन अथवा समितियों का गठन किया गया। इन विभिन्न प्रयासों के फलस्वरूप 1928 में स्थिति यह थी कि सोवियत औद्योगिक क्षेत्र का स्तर क्रान्ति के पूर्व के स्तर से कुछ ऊँचा उठ चुका था। फिर भी औद्योगिक विकास की गति में कोई सगल्कारिक वृद्धि नहीं हुई थी। साम्यवादी शासन अनवरत प्रयासों के बाद औद्योगिक क्षेत्र में लगभग वही स्थिति

पा सका था जो रूस ने 10-12 वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर ली थी। इसलिए, स्टालिन के नेतृत्व में, 1928-29 में यह निर्णय लिया गया कि औद्योगिकरण की नीति तीव्र की जाय तथा कृषि क्षेत्र की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में अधिक विनियोजन हो। अनेक दृष्टियों से औद्योगिक प्रगति करने के उपरान्त भी यातायात की स्थिति अनन्तोपजनक थी और विदेशी व्यापार उत्साहवर्द्धक नहीं था। कुल मिलाकर सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था सकारणिकालीन दशा में गुजर रही थी। 1928-29 में निजी उद्योग समाप्ति की ओर था और देश की औद्योगिक प्रगति में अवरोध शुरु हो गया था।

औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के समय रूस जिस स्थिति में था उसका एक अनुमान निम्नांकित तालिका से लगाया जा सकता है—

वर्ष	राष्ट्रीय आय	सकल औद्योगिक उत्पादन	सकल फार्म (कृषि) उत्पादन
1913	100	100	100
1921	38.8	—	—
1926	103.3	98.8	—
1929	137.6	158.6	116.7

नवीन आर्थिक नीति के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन विस्म में अवर्धित आ गई तथा उत्पादन लागत भी ऊँची हो गई।

यातायात तथा सन्देशवाहन की दशा

महायुद्ध और गृहयुद्ध के फलस्वरूप सम्पूर्ण यातायात-व्यवस्था के दिग्भ्रम हो जाने के बावजूद नवीन आर्थिक नीति के युग में यातायात और सन्देशवाहन के साधनों का काफी विकास किया गया। 1917 में रेलवे लाइन की लम्बाई 63,252 किलोमीटर से बढ़कर 1936 में 75,721 किलोमीटर हो गई। यूराल, साइबेरिया तथा मध्य एशिया में 1913 में रेलवे लाइन की लम्बाई 14,540 किलोमीटर थी जो 1926 में बढ़कर 23,062 हो गई। बोल्गा स्थित कर्जान से यूराल में स्थित सबलोवस्क तक 500 मील रेलवे लाइन पूरी की गई। मानविक जल परिवहन व्यवस्था का विकास किया गया और बसमार्गों द्वारा अधिक परिमाण में माल आने जाने लगा। फिर भी इस दिशा में प्रगति सन्तोपजनक नहीं थी। सड़क परिवहन व्यवस्था में विशेष प्रगति नहीं की जा सकी। समुद्री परिवहन व्यवस्था का भी यही हाल रहा। यातायात साधनों द्वारा माल ढोने के क्षेत्र में पूर्वापेक्षा अधिक प्रगति हुई। सन् 1929 में रेलों, नदियों तथा जहाजरानी द्वारा अन्न 1129,184 तथा 10.4 विलियन टन माल ढोया गया। सन्देशवाहन की सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। डाक तार और टेलीफोन व्यवस्था में सुधार किया गया तथा रेडियो प्रसार और शॉडकास्टिंग को अधिक प्रभावशाली बनाया गया। डाक एष तार की व्यवस्था अग्रान्त महासागर तक सम्पूर्ण देश में विकसित की गई।

राष्ट्रीय आय

क्रान्ति और गृह युद्ध के फलस्वरूप सोवियत रूस की राष्ट्रीय आय बहुत नीचे गिर गई थी, लेकिन नवीन आर्थिक नीति के दौरान उसमें लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1928-29 में राष्ट्रीय आय लगभग 1830 करोड़ रूबल हुई और अगले वर्ष अनुमानतः 2750 करोड़ रूबल तक जा पहुँची। प्रति व्यक्ति आय जहाँ 1921 में 29 रूबल थी वहाँ 1928 में लगभग 200 रूबल तक पहुँच गई। 1928-29 में शुद्ध निवेश राष्ट्रीय आय का लगभग 22½ प्रतिशत रहा। समाज में एक ओर आर्थिक सम्पन्नता व्याप्त थी तो दूसरी ओर भीषण गरीबी।

आर्थिक क्षेत्र की अन्य दशाएँ

प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होते समय देश में मूल्य स्तर में विपन्नता व्याप्त थी यद्यपि कच्ची सब्जियाँ टल गयी थी, लेकिन कृषि तथा औद्योगिक मूल्यों में पूरा साम्य स्थापित नहीं हो सका था। गजदूरी का स्तर भी असन्तोषजनक था। कृषि तथा वन क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों की औसत आय 1928 में क्रमशः 290 तथा 395 रूबल वार्षिक थी जबकि राजकीय कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों तथा निर्माण-कार्यों में सलग्न श्रमिकों की वार्षिक औसत लगभग 900 से 1000 रूबल थी। प्रथम योजना से पूर्व सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का औसत लगभग 700 रूबल था। कृषि-क्षेत्र में श्रमिकों की आय औद्योगिक श्रमिकों की तुलना में लगभग आधी ही थी। श्रमिक सघों का विकास सन्तोषजनक स्थिति में था। 1928 में इन सघों की सदस्य संख्या लगभग 11 करोड़ थी। श्रमिकों की उत्पादन कुशलता यूरोपीय श्रमिकों के मुकाबले बहुत कम थी क्योंकि कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में यन्त्रीकरण की दृष्टि से रूस बहुत पिछड़ा हुआ था। प्रशिक्षित कर्मचारियों की भारी कमी थी, अतः अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड से इन्जिनियरों और तकनीकी कर्मचारियों को बुलाया जाता था। 1928 में सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था में लगभग 116 करोड़ श्रमिकों और कर्मचारियों को रोजगार मिला हुआ था। नवीन आर्थिक नीति के अन्तिम वर्षों में लगभग 17-40 लाख व्यक्ति बेरोजगार रहे। विदेशी व्यापार में सरकार का एकाधिकार था। 1921 में विदेशी व्यापार केवल 18 करोड़ रूबल का था जो 1928 में 138 करोड़ रूबल तक पहुँच गया।

सारांशतः क्रान्ति के उपरान्त 10-11 वर्षों में रूस के लगभग सभी क्षेत्रों में आधारभूत परिवर्तन हो चुके थे तथा 1928 तक औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि बन चुकी थी। नवीन आर्थिक नीति का परित्याग करके नियोजन का मार्ग अपनाना तत्कालीन परिस्थितियों में सर्वथा श्रेयस्कर था। रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता ने नियोजन की साधकता सिद्ध कर दी और सभी से वर्तमान समय तक रूस समाजवादी नियोजन के मार्ग पर चल रहा है।

3

सामूहीकरण (Collectivisation)

सोवियत रूस में सामूहीकरण अथवा सामूहिक कृषि के आन्दोलन का सूत्रपात प्रथम पंचवर्षीय योजना से (जो प्रकृतबद्ध, 1928 से प्रारम्भ हुई) किया गया। 1937 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर सामूहीकरण का कार्य लगभग पूरा हो गया क्योंकि लगभग 93 प्रतिशत किसानों द्वारा इस पद्धति को अपना लिया गया। बचे-बुचे क्षेत्र को भी सामूहीकरण में लाने के लिए आगे समयानुकूल कदम उठाए जाते रहे और सामूहिक खेतों के एकीकरण का मशोघित-पुनर्संशोधित दौर जारी रहा। आज सोवियत संघ की सामूहिक कृषि-पद्धति विश्व के देशों के लिए अनुकरणीय है। रूसी भाषा में सामूहिक कृषि को 'कोलखोजी' (Kolkhozy) कहा जाता है। इसके स्वरूप का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व संकेत रूप में इतना जान लेना आवश्यक है कि सामूहिक कृषि के अन्तर्गत किसान आपस में मिलकर खेती-बाड़ी को अधिक उत्पादक-व्यवसाय बना लेते हैं और इसके लिए वे अपने सारे साधनों और श्रम-शक्ति को एक संगठित रूप में संचालित करते हैं। कृषि के समस्त प्रसाधन जैसे मवेशी, भवन एवं यन्त्रों का स्वामित्व सामूहिक रूप से किया जाता है। ये सभी चीजें सामूहिक कृषि सम्पत्ति बन जाती हैं। जिस भूमि पर सामूहिक फार्म के सदस्य खेती करते हैं उस पर राज्य का स्वामित्व होता है और यह सम्पूर्ण जनता की होती है।

सामूहिक कृषि के तीन प्रारम्भिक स्वरूप

(The Early Forms of Collective Farming, 1920-29)

क्रान्ति के बाद रूस में कृषि क्षेत्र में प्रगति के लिए विभिन्न प्रयास किए गए। 1920 से 1929 की अवधि में अनेक क्रान्तिकारी कदम उठाए गए। 1922 में भूमि पर सरकारी स्वामित्व की घोषणा की गई। नवीन माणविक नीति को सफल बनाने के लिए व्यक्तिगत कृषि को भी मान्यता मिली। 1920 से 1929 की अवधि में रूप में कृषि सहकारिता को विकसित किया गया। इस अवधि में प्रयोगात्मक तौर पर तीन प्रकार की सामूहिक कृषि प्रचलित रही—(1) टोज, (2) आर्टेल, एवं (3) कम्सून।

(1) टोज (Toz)—यह सयुक्त भूमि कृषि-पद्धति थी। इसका रूप एक प्रकार से उत्पादक कृषि सरकारी समिति का था जिसमें किसान भूमि पर खेती करने, मशीनें खरीदने और उनके उपयोग आदि के लिए परस्पर सयुक्त हो जाते थे, लेकिन अपनी अपनी भूमि, उपज, पशु तथा औजारों पर उनका व्यक्तिगत स्वामित्व बना रहता था। उत्पात्ति का वितरण भूमि के अनुपात में किया जाता था। इसे हम सयुक्त सहकारी कृषि के एक रूप की सजा दे सकते हैं।

(2) आर्टेल (Artel)—यह मध्यवर्गीय पद्धति थी जिसे आज सामान्य रूप से सारे रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तव में यही पद्धति आगे चलकर सामूहिक कृषि का रूप धारण कर सकी। इसे खेती-बाड़ी का सर्वाधिक व्यावहारिक और उपयोगी सहकारी तरीका पाया गया है। इसके अन्तर्गत अधिकांश उत्पादन सामूहिक रूप से किया जाता है और उत्पादन के अधिकांश साधनों पर सभी का नियन्त्रण रहता है। साथ ही प्रत्येक परिवार को कुछ व्यक्तिगत उत्पादन की अनुमति भी दी जाती है। उसके पास कुछ मवेशी, छोटे-मोटे औजार और दोड़ी भूमि रहती है फिर भी वह सामूहिक कार्य के उत्पादन में अपना भाग रखता है। किसान को इस प्रकार व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की आय उपलब्ध हो जाती है। इसका उपभोग वह और उसका परिवार स्वेच्छापूर्वक करते हैं। वास्तव में आर्टेल पद्धति में समाजवादी कृषि और व्यक्तिगत कृषि का सुन्दर सामन्वत्य रहता है। इस पद्धति को अर्थात् 'कोलखोजी' को आगे यथास्थान विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

(3) कम्यून (Commune)—यह वह पद्धति है जिसमें भूमिहीन किसान उत्पादन के लिए पूँजी, पशु, यन्त्र तथा अन्य साधनों के सामूहिक रूप से स्वामी होते हैं। वे सामूहिक रूप से उत्पादन करते हैं, साथ रहते हैं और साथ खाते हैं तथा साथ ही काम करके सामूहिक जीवन व्यतीत करते हैं। कम्यून पद्धति में निजी स्वामित्व के लिए किंचित मात्र भी स्थान नहीं होता।

सन् 1924 तक कृषि सहकारिता की पद्धति बड़ी धीमी रही। एक अनुमान के अनुसार लगभग 10 प्रतिशत कृषक ही इसमें सम्मिलित थे। सख्या की दृष्टि से कृषक सदस्य 25-30 लाख ही थे। 1928 तक यह संख्या लगभग 1 करोड़ तक पहुँच गई। अब परिस्थितियाँ ऐसी थी कि कृषि सहकारिता की टोज एव कम्यून पद्धति को अपनाता मुश्वल था। अतः आर्टेल पद्धति के आधार पर कृषि व्यवस्था की नीति अपनाने का निश्चय किया गया। स्टालिन कृषि क्षेत्र में सम्पन्न कृषि वर्ग (कुलक वर्ग) का उन्मूलन कर सामूहिक कृषि का विकास करने को कटिबद्ध था। अतः अक्टूबर, 1928 में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई तो कृषि के सामूहीकरण की नीति पर जोर-शोर से चलाया गया। छोटे-छोटे विशद खेतों का सामूहीकरण कर लिया अर्थात् सामूहिक खेत (Collective Farms) बना दिए गए।

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं और सामूहीकरण की पूर्ति

(First and Second Five Year Plans and Completion of Collectivisation)

नवीन आर्थिक नीति (New Economic Policy) के परित्याग के बाद देश के मुनियोजित आर्थिक विकास की दृष्टि से अक्टूबर, 1928 से प्रथम पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात किया गया। वैसे इस योजना को प्रारंभिक रूप से स्वीकृति अप्रेत, 1929 में साम्यवादी दल की 19वीं कांग्रेस द्वारा मिली। प्रथम योजना की अवधि 1 अक्टूबर 1928 से पांच वर्षों के लिए निश्चित की गई, लेकिन सरकारी तौर पर बाद में घोषित किया गया कि प्रथम योजना मवा चार वर्षों में ही प्रारंभ 31 दिसम्बर, 1932 तक पूरी कर ली गई।

रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में दो प्रधान उद्देश्य थे—

(1) खाद्यान्न के उत्पादन में 35 प्रतिशत की वृद्धि द्वारा कृषि-उत्पादकता को बढ़ाना, एवं

(2) सामूहिक खेती (Kolkhoz) तथा राजकीय खेतों (Sovkhoz) की पद्धति का विकास करके कृषि का समाजीकरण करना।

स्पष्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर सर्वाधिक बल देते हुए कृषि के सामूहीकरण (Collectivisation of Agriculture) का कार्यक्रम अपनाया गया। यह निश्चित किया गया कि छोटे-छोटे बिखरे खेतों को संयुक्त करके सामूहिक खेत बना दिए जाएं तथा समृद्धिशाली धनिक किसानों अर्थात् बुलक वर्ग को समाप्त करके समाजीकरण की दिशा में आगे बढ़ा जावे।

कृषि का सामूहीकरण (प्रथम योजना के दौरान)

(Collectivisation of Agriculture During the First Plan Period)

योजना के लागू होते ही कृषि के क्षेत्र में सामूहिक खेती (Collective Farming) के आन्दोलन का तेजी से सूत्रपात किया गया। अल्पकाल में ही इस क्षेत्र में आशातीत सफलता प्राप्त हुई। जहाँ सन् 1928 में सामूहिक कृषि के अन्तर्गत केवल लगभग 13 लाख 90 हजार हेक्टर भूमि जोती गई। दो-तीन वर्षों के अल्पकाल में ही यह उपलब्धि वास्तव में आश्चर्यजनक थी।

सामूहिक कृषि का आन्दोलन नित्य प्रति जोर पकड़ता गया और सामूहिक कृषि का प्रबन्ध करने वाली समितियों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई। यह आन्दोलन इतना तेज हो गया कि जहाँ पहले कुछ लोग मिलकर सामूहिक खेत बनाते थे वहाँ अब गांव-गांव और जिलों ने मिलकर सामूहिक कृषि करना आरम्भ कर दिया। यद्यपि धनी कृषकों अर्थात् कुलकों (Kulaks) द्वारा कृषि के सामूहीकरण का आरम्भ में तीव्र विरोध किया गया, किन्तु अन्ततः बाध्य होकर वे भी इस आन्दोलन में शामिल होते गए। इस प्रकार कृषि के सामूहीकरण का एक क्रान्तिकारी प्रभाव यह हुआ कि कृषि-क्षेत्र में पूंजीवाद का प्रभाव समाप्त हो गया। धन-शून्य कुलक वर्ग शक्तिहीन होकर प्रायः समाप्त हो गया। सोवियत सरकार ने भी कुलकों के विरुद्ध

बड़ी उग्र नीति अपनाई। सरकारी खर्चों से प्रोत्साहित होकर किसान कुलको अपनी जमीन, अपने जानवर, शेत, यन्त्र आदि बिना किसी रोक-टोक और सरका जाँच-पड़ताल के छुड़ाने लगे। इस तरह कुलक वर्ग और उनका प्रभाव पूरी तन्त्र नष्ट हो गया।

कृषि के सामूहीकरण में बड़ी जबरदस्ती की गई। कई बार ज्यादातर इतनी बड़ गई कि स्टालिन और बोल्शेविक दल की केन्द्रीय समिति को नियेधात्मक आदेश निकालने पड़े। सामूहीकरण इतनी तेजी से किया गया कि खेती के श्रोजा और अन्य साधनों की बहुत ही कमी पड़ गई। कुलको के पतन के साथ-साथ देश पशु धन की कमी आ गई। कुलको ने जमीन व चारे के अभाव में न केवल पशुओं को रखना बन्द कर दिया, बल्कि उनकी हत्या भी प्रारम्भ कर दी। फलस्वरूप देश का लगभग आधा पशु-धन विनष्ट हो गया और धी, दूध, मांस आदि की मात्रा कमी हो गई।

सामूहीकरण की प्रक्रिया के दौरान कृषि के यन्त्रीकरण के लिए सरकार प्रत्येक सम्भव तरीके अपनाए। सामूहिक खेतों को भारी मात्रा में ऋण प्रदान किए गए। सन् 1930 तक ही लगभग 55 प्रतिशत कृषक सामूहिक खेतों के अन्तर्गत आ गए। सामूहिक कृषि में क्षेत्र वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन में भी वृद्धि होने लगी जहाँ 1928 में सहकारी व सामूहिक खेतों से कुल मिलाकर 35 करोड़ पूड गन्ना पैदा हुआ था, वहाँ 1929 में ही लगभग 40 करोड़ पूड गन्ना पैदा होने लगा लेकिन बाद में प्रतिकूल मौसम व अन्य कारणों से उत्पादन में कमी आ गई।

प्रथम योजना काल में राजकीय फार्मों (State Farms) को भी प्रारम्भ किया गया जिनका प्रमुख उद्देश्य अनाज की पूर्ति को नियमित बनाना था। राजकीय फार्मों के क्षेत्रफल में सन् 1928 की तुलना में योजना काल में 8 गुणा वृद्धि हुई। 1932 तक कुल कृषि-भूमि का 10 प्रतिशत राजकीय फार्मों के अन्तर्गत आ गया।

पंचवर्षीय योजना की श्रवण समाप्त होते-होते रूस में कृषि का सामूहीकरण बहुत कुछ सम्पन्न हो गया। योजना के अन्त तक बाजार में लाए जाने वाले अनाज के लगभग 84 प्रतिशत भाग की पूर्ति सामूहिक कृषि फार्मों द्वारा की जाने लगी।

कृषि के सामूहीकरण के प्रभाव

(Effects of Collectivisation of Agriculture)

कृषि के सामूहीकरण के तात्कालिक प्रभाव अच्छे और बुरे दोनों ही हुए यद्यपि आगे चल कर सामूहीकरण के सुपरिणामों के फलस्वरूप ही रूस ने कृषि-क्षेत्र में भारी प्रगति की। सामूहीकरण के मुख्य प्रभाव ये हुए—

(1) कृषि उपज में कमी—प्रारम्भिक वर्षों में कृषि के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, किन्तु आगे चल कर उत्पादन की यह गति कायम नहीं रखी जा सकी। सामूहीकरण की नीति को बड़ी तीव्र गति से क्रियान्वित किया गया और किसानों की प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता का शिकार बनना पड़ा। फलस्वरूप उसमें अस्तन्तुष्ट व्याप्त हो गया और 1930 में अच्छे मौसम के बावजूद कृषि-उपज में बहुत कमी

हुई। उपज में कमी की प्रक्रिया आगे के वर्षों में भी चलती रही। सरकारी धाँकड़ों के अनुसार 1930 में 866 मिलियन क्विन्टल, 1931 में 695 मि० क्विन्टल और 1932 में 699 मिलियन क्विन्टल उपज कम पंदा हुई। यह कमी 1933 तक चलती रही। कुल मिलाकर 1929-1932 के बीच खाद्यान्न का जो उत्पादन हुआ, वह 1925-28 के बीच हुए औसत उत्पादन से भी कम रहा।

(2) पशु घन का विनाश—सामूहीकरण ग्रान्दोलन ने पशु घन का विनाश कर दिया। मध्यम वर्ग के असन्तुष्ट किसान कुलको के साथ मिल गए। कुलकों ने पशुओं को राजकीय और सामूहिक फार्मों को देने की अपेक्षा भार डालना अधिक अच्छा समझा, अतः बड़े पैमाने पर पशुओं का सहार किया गया। सन् 1929 की तुलना में सन् 1931 तक कुल पशुओं की संख्या में 1/3 कमी आ गई। कुछ अध्ययनों के अनुसार लगभग आधे पशुओं का नाश हो गया क्योंकि पशुओं की संख्या में कमी का क्रम 1933 तक जारी रहा। इतनी बड़ी संख्या में पशुओं को मारा गया कि सन् 1939 तक भी रूस में पशुओं की संख्या 1919 के स्तर तक नहीं पहुँच सकी।

(3) अनेक वस्तुओं की कमी—पशु सहार का यह स्वाभाविक परिणाम हुआ कि मांस, चमड़ा, दूध, मखन आदि वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई। खेती के लिए पशु इतने कम हो गए कि ट्रैक्टरों द्वारा भी उनकी पूर्ति नहीं हो सकी।

(4) कुलक वर्ग की समाप्ति—सामूहिक कृषि के विस्तार के साथ-साथ घनी कृषि का अर्थात् कुलको को भी इसमें शामिल होने को बाध्य होना पड़ा। सामान्य किसानों ने उनसे अपनी जमीनें, मवेशी, यन्त्र आदि छीन लिए। इस प्रकार कृषि-क्षेत्र में पूँजीवाद का प्रभाव विनष्ट हो गया। जहाँ 1928 में कुलको की संख्या लगभग 50 लाख थी वहाँ 1934 में यह केवल 15 लाख के आसपास रह गई और वह भी प्रभावहीन।

(5) बड़े खेतों का निर्माण और बृहद पैमाने का संगठन—सामूहीकरण की नीति के फलस्वरूप रूस में लगभग 2.5 करोड़ छोटे-छोटे खेतों को मिलाकर लगभग 2 लाख सामूहिक खेतों में परिवर्तित कर दिया गया। कृषि परिवारों का लगभग 60 प्रतिशत भाग और कृषि योग्य भूमि का लगभग 75 प्रतिशत भाग सामूहिक कृषि के अन्तर्गत आ जाने से कृषि में यन्त्रीकरण की प्रक्रिया सुगम हो गई। फलस्वरूप उत्पादन-वृद्धि की भाशाएँ प्रबल हो गईं।

(6) व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्त की समाप्ति—सामूहीकरण की नीति के फलस्वरूप धनिक कुलक वर्ग प्रभावहीन होकर लगभग समाप्त-सा हो गया और भूमि में निजी सम्पत्ति के सिद्धान्त का कोई महत्त्व नहीं रहा। स्टालिन के शब्दों में "पूँजीवादी देश सोवियत संघ में पूँजीवाद को पुनः प्रतिष्ठित करने का स्वप्न देख रहे थे, लेकिन उनकी अन्तिम आशा पर पानी फिर रहा है और वह नष्ट हो रही है। जिन किसानों को वे पूँजीवादी जमीन के लिए खाद समझते थे, वे सामूहिक रूप से 'व्यक्तिगत सम्पत्ति' का परित्याग कर सामूहिक कृषि और समाजवाद के मार्ग

को अपना रहे हैं। पूँजीवाद को रूस में प्रतिष्ठित करने की अन्तिम आशा भी क्षीण हो रही है।”

सामूहिककरण के कारण चाहे तत्कालीन अवस्था में किसानों की स्थिति बिगड़ गई, लेकिन कृषि भावी निर्माण की ओर अवश्य उन्मुख हो गई। धीरे-धीरे चल कर सामूहिककरण के सुपरिणाम निकले और कृषि की स्थिति प्रशंसनीय रूप से सुधर गई। कृषि का अधिकाधिक यन्त्रीकरण होने से वैज्ञानिक खेती को बल मिला।

सामूहिककरण के नियमों में ढिलाई

सामूहिककरण के फलस्वरूप जो प्रारम्भ में असन्तोष व्याप्त हुआ और पशुओं का सहान्द्रता, उससे स्टालिन व कुछ अन्य नेताओं ने यह अनुभव किया कि जबरदस्ती सामूहिककरण करना उचित नहीं होगा, अतः सामूहिककरण के नियम कुछ ढीले किए गए। सामूहिक फार्मों को भी कुछ सुविधाएँ दी गईं। फार्मों के सदस्यों को ऋण देने व औद्योगिक सुविधाएँ प्रदान करने में प्राथमिकता दी गई। सन् 1932 में फार्मों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे अपनी अतिरिक्त उपज खुले बाजार में बेच सकें। उत्पादन के प्रमुख साधनों और फार्मों पर बने मकानों को यद्यपि सामूहिक स्वामित्व के अन्तर्गत ही रखा गया लेकिन बगीचों रहने के मकानों, दुधारू पशुओं व मुर्गियों को व्यक्तिगत स्वामित्व के अन्तर्गत ही बने रहने दिया गया।

**द्वितीय योजना में सामूहिककरण का लगभग पूरा होना
(Almost Complete Collectivisation during the
Second Plan Period)**

कृषि के सम्बन्ध में द्वितीय योजना का प्रमुख उद्देश्य यह रहा कि अब तक जो लाभ प्राप्त हुआ है, उसे सुदृष्ट बनाया जाए। कृषि के सामूहिककरण आन्दोलन ने द्वितीय योजनाकाल में पूर्णता प्राप्त कर ली। लगभग 93 प्रतिशत किसानों ने सामूहिककरण पद्धति को अपना लिया और अनाज के कुल उत्पादन का 99 प्रतिशत भाग सामूहिक खेतों में पैदा किया जाने लगा। कृषि-भूमि का क्षेत्र 1913 में 105 करोड़ हेक्टर था जो 1937 में 135 करोड़ हेक्टर हो गया। 1913 में जहाँ किसान 48 अरब पूड गल्ला एकत्र करते थे वहाँ 1937 में यह उत्पादन 68 अरब पूड हो गया। सभी कुलक और किसान मिलकर जितने गल्ले का वितरण करते थे, 1937 में उससे 40 करोड़ पूड अधिक गल्ले का वितरण केवल सामूहिक कृषि द्वारा उत्पन्न गल्ले से किया जाने लगा।

सन् 1935 में, कृषि संगठन में समानता, एक रूपता और नियंत्रण लाने के लिए स्टालिन ने कृषि-आर्टेल के आदर्श नियम (Model Rules of the Agricultural Artel) बनाए। इन नियमों को स्टालिन की महत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक माना जाता है। आर्टेल कृषि सहकारिता की तरह थी। उनके अनुसार केवल मकान, बगीचे और भवशियों में निजी स्वामित्व होता था। कृषि औजार, यंत्र आदि सामूहिक स्वामित्व के अन्तर्गत थे। कृषि कार्य सामूहिक रूप से किए जाते थे। फसल का वितरण सदस्यों के बीच होता था। आर्टेल की भूमि को राजकीय सम्पत्ति घोषित किया गया जिस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार था।

आर्टेल अपने उद्देश्यों को पूर्ति में काफी सफल रहे। कृषि सम्बन्धी आदर्श नियमों के कारण सामूहिक खेतों के संगठन में काफी सुधार हुए। फलस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। पशु पालन के क्षेत्र में अपेक्षित सफलता नहीं मिली।

ग्रनाज को वसूली की प्रणाली में भी प्रभावशाली सुधार किए गए। अब प्रति एकड़ उत्पादन का एक पूर्व निश्चित ही ग्रन वसूली के अन्तर्गत किया जाने लगा। इससे किसानों को अविक उत्पादन करने में कोई रुकावट नहीं रही, साथ ही खुले बाजार में बेचने की स्वतन्त्रता से उन्हें बहुत राहत मिली। किसान अधिक कार्य करने लगे और उत्पादन काफी बढ़ गया। वास्तव में सोवियत अर्थ-व्यवस्था में सामूहीकरण के सुपरिणाम द्वितीय योजना-काल में ही प्रकट हो सके और किसानों ने शान्ति व सन्तोष का अनुभव किया। किसानों तथा ग्रमवासियों की आर्थिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हो गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद सामूहीकरण

(Collectivisation after Second Five Year Plan, 1938-1970)

(1) महायुद्ध की समाप्ति तक—सन् 1938 में रूस में तृतीय पंचवर्षीय योजना आरम्भ हुई, लेकिन द्वितीय महायुद्ध के विस्फोट से यह लगभग 3 वर्ष बाद तो स्थगित कर दी गई। सन् 1940 में स्थिति यह थी कि लगभग 192 लाख कृषक परिवार सामूहीकरण के अन्तर्गत आ चुके थे। महायुद्ध काल में रूसी कृषि पर बड़ा प्रतिफल प्रभाव पड़ा और सामूहिक खेतों का भारी विनाश हुआ। भारी सत्या में कृषि-यंत्र नष्ट हुए और कृषि का औसत उत्पादन 10 करोड़ टन से घट कर लगभग 5-7 करोड़ टन ही रह गया।

(2) महायुद्ध के बाद 1950 तक—महायुद्ध काल के बाद कृषि विकास पर पुन ध्यान केन्द्रित किया गया और भारी कठिनाइयों के बावजूद सामूहिक खेतों की सत्या में तेजी से वृद्धि हुई। 1947 में सामूहिक खेतों की सत्या लगभग 2 12 लाख थी जो 1950 में लगभग 2 54 लाख तक पहुँच गई। सामूहीकरण के प्रतीक 'एस्टोनिया' (Estonia) में 1948 में केवल 47 सामूहिक खेत थे जिनकी सत्या बढ़ कर 1949 की समाप्ति तक लगभग 3 हजार हो गई। बिनोप बात यह थी कि जहाँ महायुद्ध से पूर्व की अवधि में सामूहिक खेतों की सत्या में वृद्धि सरकारी दबाव के कारण हो रही थी वहाँ अब बिना किसी दबाव के सामूहिक कृषि की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। 1950 में स्थिति यह थी कि सामूहिक खेतों के अन्तर्गत कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 90 प्रतिशत भाग सम्मिलित था। और ये क्षेत्र कुल कृषि उत्पादन का लगभग 85 प्रतिशत भाग उत्पन्न कर रहे थे।

(3) 1950 से एकीकरण नीति सन् 1950 से सामूहिक खेतों के सन्दर्भ में एक सशोषित पद्धति लागू की गई। 1950 से पहले विभिन्न सामूहिक खेतों के प्रकार में बहुत अरिक्त असमानता थी। लगभग 20 प्रतिशत सामूहिक खेतों के पास जहाँ कृषि योग्य भूमि का लगभग 60 प्रतिशत भाग था वहाँ 30 प्रतिशत

सामूहिक खेतों के पास कृषि योग्य भूमि का केवल 6 प्रतिशत भाग ही था। सामूहिक खेतों के आकार की यह विषमता कृषि के विकास में बाधक थी। अतः 1950 से छोटे-छोटे खेतों में एकीकरण का आन्दोलन सरकारी मशीनरी और साम्यवादी दल द्वारा चलाया गया। छोटे सामूहिक खेतों का ऐच्छिक एकीकरण के लिए भी पूरा दबाव डाला गया। इस एकीकरण-नीति (Amalgamation Policy) का सुपरिणाम भी शीघ्र ही निकल आया। 1950 के आरम्भ में मास्को में सामूहिक खेतों की सख्या लगभग 6,069 से घट कर 1950 के माह जून में लगभग 1,368 ही रह गई। इसी प्रकार लेनिनग्राड प्रान्त में प्रथम चार माह में ही 2,000 छोटे सामूहिक खेतों को 600 बड़े खेतों में परिवर्तित कर दिया गया। और भी विभिन्न प्रान्तों तथा क्षेत्रों में तेजी से एकीकरण का यह कार्य सम्पन्न हुआ। सामूहिक खेतों के एकीकरण की प्रक्रिया तेजी से चलती रही। जहाँ 1950 में सामूहिक खेतों की सख्या लगभग 254 लाख थी वहाँ सितम्बर, 1953 तक यह सख्या केवल 94,000 ही रह गई न केवल छोटे-छोट सामूहिक खेतों का बरन् मध्यम आकार के सामूहिक खेतों का भी एकीकरण हुआ। 1953 में ख्रुश्चेव ने अपने एक बयान में बताया कि एकीकरण-नीति के फलस्वरूप प्रत्येक सामूहिक खेत के पास कृषि योग्य भूमि 1,500 एकड़ से बढ़कर लगभग 4,200 एकड़ हो गई।

एकीकरण की यह नीति कुछ विणिष्ट कारणों से अपनाई गई थी जो सशेष में ये थे— (1) कृषि-यन्त्रों के मितव्ययितापूर्ण उपयोग की दल मिले और उनकी कुशलता में वृद्धि हो, (2) प्रशासनिक व्यय में कमी आए, (3) पूँजी विनियोग क्षमता बढ़े तथा कुशल विशिष्टीकरण सम्भव हो सके, एवं (4) सामूहिक खेतों पर सरकारी तथा दलीय नियन्त्रण में अधिक मजबूती आए। इन उद्देश्यों की पूर्ति में सफलताएँ मिली, प्रशासनिक समस्याएँ पूर्वपिज्ञा अधिक जटिल हो गई। सामूहिक खेतों के आकार में भारी वृद्धि हो जाने से तथा अधिक सख्या में किसानों के इक्की परिधि में आने से समन्वय-कार्य अधिकाधिक कठिन होता गया। अधिक बड़े आकार के खेतों के लिए पूर्वपिज्ञा अधिक प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारियों की आवश्यकता अनुभव हुई। तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की माँग बढ़ी। यह कहा जाने लगा कि सामूहिक खेतों के अर्थस्य पर पर कृषकों की नियुक्ति न होकर तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए। इन विभिन्न बाधाओं और समस्याओं के फलस्वरूप एकीकरण की नीति अन्तिम रूप में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी। लेकिन इससे एकीकरण-नीति का परित्याग नहीं किया गया बरन् सामयिक संशोधनों के साथ वह जारी रही। एकीकरण-नीति के साथ-साथ ख्रुश्चेव ने दो और भी प्रस्ताव रखे—फॉर्म सिटीज का निर्माण प्रस्ताव और निजी व्यक्तिगत छोटे गाइडेंस को एक जगह रखने का प्रस्ताव। इन दोनों ही प्रस्तावों का दूसरे किसानों द्वारा भारी विरोध हुआ, अतः 1952 की 19वीं साम्यवादी पार्टी कांग्रेस में उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया।

सन् 1950 से सामूहिक कृषि के विस्तार की प्रक्रिया गतिमान रही। रूस

की छठी योजना जो 1956 से 1958 तक चली सामूहिक खेतों में अर्थिकाधिक मशीनी यन्त्रों की पूर्ति की दिशा में काफी सफल रही।

(4) सातवीं तथा आठवीं योजना में सामूहिकरण तथा वर्तमान स्थिति—
सन् 1958-1965 के दौरान सातवीं पंचवर्षीय योजना-काल में सामूहिक कृषि-फार्मों का पुनर्गठन किया गया। छोटे इकाइयों को बड़ी इकाइयों में मिला दिया गया तथा अत्यन्त मशीन ट्रेक्टर-मैशिन समाप्त करके उनकी मशीनों सामूहिक खेतों को दे दी गई। सामूहिक एवं राजकीय फार्मों (कोल-सोज) तथा सोव-सोज में एकत्रता लाने के प्रयत्न किए गए। सामूहिक फार्म-मंडलों को उन्नत बनाने के विभिन्न प्रयास किए गए। उनकी सम्पत्ति में वृद्धि की गई और उनके अर्थिक-आजीव्य कोष का उपयोग बिजली घर, नहर, स्कूल, अनाज भण्डार आदि कार्यों में करने की अनुमति प्रदान की गई। सामूहिक खेतों के राजकीय फार्मों के विलयन को प्रोत्साहन दिया गया। सम्पूर्ण योजना-काल में सामूहिकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए। अपने सम्पत्ति रूप में एकीकरण प्रक्रिया जारी रही और सामूहिक खेतों की संख्या 1953 में 94,010 से घट कर 1958 में लगभग 67,700 रह गई। सातवीं योजना की समाप्ति तक अर्थात् 1965 में यह संख्या और गिर कर 36,600 हो गई।

आठवीं योजना (1966-1970) के दौरान भी सामूहिक खेतों के राजकीय फार्मों में विलीनीकरण और छोटे-छाट सामूहिक खेतों के एकीकरण की प्रक्रिया जारी रही। पुनर्गठित खेतों में अर्थिक-आजीव्य मशीनीकरण और बैंगनीय पद्धतियों को प्रोत्साहन दिया गया। जहाँ 1965 में सामूहिक खेतों की संख्या 36,600 थी वहाँ 1969 में यह अनुमानित लगभग 25,000 हो रह गई। योजना की समाप्ति तक रूस के लगभग सभी कृषक परिवार सामूहिक कृषि के अन्तर्गत आ गए। रूस ने वस्तुतः कृषि-क्षेत्र में भारी प्रगति की। रूस की सामूहिकरण की कृषि-नीति का ही बहुत कुछ परिणाम था कि 1913 की तुलना में 1967 में कृषि-उत्पादन में लगभग 276 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

एकीकरण और विलीनीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामूहिक खेतों की संख्या घटकर 1977 में लगभग 23,000 रह गई। 1977 में सामूहिक फार्म कृषकों की कुल आय 24 अरब रूबल से भी अधिक थी। सामूहिक फार्मों में एक किसान-परिवार की समुक्त आयदानी 1965-77 की अवधि में 1.8 गुनी बढ़ गई।

सामूहिक खेतों का स्वरूप एवं संगठन

(Structure and Organisation of Collective Farms)

सामूहिक खेतों को रूस में कोलखोझी (Kolkhozy) कहा जाता है। यह बहुवचन शब्द है। किसी एक सामूहिक खेत को एकवचन में कोलखोज कहते हैं। रूस में सामूहिक कृषि के विकास आदि के विवेचन के सम्बन्ध में यह देखना उचित होगा कि सामूहिक खेतों का स्वरूप एवं संगठन क्या है।

संरचना—जैसाकि हम कह चुके हैं, सामूहिक खेतों अर्थात् कोलखोझी के अन्तर्गत किसान भाग्य में मिलकर कृषि को अधिक उत्पादक व्यवस्था बना लेते हैं।

इसके लिए वे अपने समस्त साधनों और सम्पूर्ण श्रम-शक्ति को संगठित रूप में संचालित करते हैं। कृषि के सभी प्रसाधनों का स्वामित्व सामूहिक रूप से किया जाता है और यह सभी चीजें अर्थात् मवेशी, भवन, यन्त्र आदि सामूहिक कृषि की सम्पत्ति बन जाती हैं। जिस भूमि पर सामूहिक खेत के सदस्य खेती करते हैं उस पर राज्य का स्वामित्व होता और यह सम्पूर्ण जनता की होती है।

प्रारम्भ में सामूहिक कृषि में, निजी सम्पत्ति और निजी स्वामित्व का कोई स्थान नहीं था पर 1935 में लागू की गई एक नई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक सदस्य कृषक परिवार को कुछ व्यक्तिगत उत्पादन की अनुमति भी दी जाती है। उसके पास कुछ मवेशी, छोटे-मोटे औजार और थोड़ी भूमि (प्रायः चौथाई से ढाई एकड़ तक) रहती है। पर सीमित मात्रा में इस निजी आय के साथ-साथ सदस्य परिवार सामूहिक कार्य के उत्पादन में अपना भाग यथापूर्व रखता है। दूसरे शब्दों में, सदस्य कृषक को व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की आय उपलब्ध हो जाती है। इसका उपभोग वह और उसका परिवार स्वेच्छापूर्वक करते हैं। कोई सदस्य यदि कोलखोज अर्थात् सामूहिक खेत से अलग होना चाहे तो उसको उसके द्वारा दी गई भूमि तो वापस नहीं लौटाई जाती हाँ उसका मूल्य चुकाया जा सकता है।

प्रबन्ध एवं श्रम कार—सामूहिक फार्म सरचना के अन्तर्गत सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को तथा फार्म की क्रियाओं के संगठन व प्रबन्ध के सिद्धान्तों को कृषि आर्टल के नियमों द्वारा परिभाषित किया जाता है। फार्म के कार्यों को इसके सदस्यों की सामान्य बैठक द्वारा निर्देशित किया जाता है। यह अपना एक प्रबन्ध मण्डल और सभापति चुनती है जिसके द्वारा उत्पादन का प्रबन्ध होता है। कानून सामूहिक फार्म के आधार के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहता। यह स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार भिन्नता रखता है। कुछ क्षेत्रों में कोलखोज अर्थात् सामूहिक खेत छोटे हैं तो कुछ में बहुत बड़े। वर्तमान में औसतन एक कोलखोज में 5 हजार से 50 हजार एकड़ भूमि और सम्मिलित कृषक परिवारों की संख्या 50 से 1,000 होती है।

भूमि-प्रयोग-व्यवस्था—सामूहिक फार्मों को भूमि का प्रयोग आवश्यक रूप से कृषि के लिए करना पड़ता है। वे भूमि से कोयला, तेल अथवा अन्य कोई महत्वपूर्ण खनिज निकालने की क्षमता नहीं रखते। सामूहिक फार्मों को उनकी भूमि के भील, तालाब या अन्य स्थानों के जल का प्रयोग केवल कृषि-उद्योगों के लिए करने की स्वीकृति होती है। अपनी भूमि के सभी जगहों पर इनका अधिकार होता है और वे इससे प्राप्त लकड़ी का प्रयोग अपने उपयोग के लिए कर सकते हैं। सिद्धान्त रूप से सामूहिक फार्मों के लिए भूमि निरन्तर प्रयोग हेतु दी जाती है, लेकिन राज्य को अधिकार है कि यह कभी भी औद्योगिक, खनिज अथवा राज्य फार्म की स्थापना के लिए उसे ले ले। ऐसा होने पर सामूहिक फार्मों पर काम करने वाले व्यक्ति राज्य के मजदूर बन जाते हैं।

उत्पादन-साधन तथा उत्पादन-कार्य—कोलखोज अर्थात् सामूहिक फार्म व्यावहारिक रूप से उत्पादन के समस्त साधनों पर नियन्त्रण रखता है। प्रत्येक

सामूहिक खेत अथवा कोलखोज के पास उत्पादन-कार्य के लिए बड़े बड़े कृषि-यन्त्रों के अतिरिक्त पशु साधारण उपकरण, फार्म भवन, वीज, पशुओं के लिए आहार, आटा मिलें, अन्य प्रोसेसिंग मशीनें आदि साधन होते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, सामूहिक खेत का सदस्य अर्थात् प्रत्येक कोलखोजनीकी (Collective Farmer) अपने निवास-स्थान, उद्यान क औजार, निजी मवेशियों क रहन क स्थान का व्यक्तिगत स्वामित्व कर सकता है, पर एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं।

प्रत्येक सामूहिक खेत को अपना काय-संचालन वार्षिक संचालन याजना (जा समूचे देश के लिए लागू की जाती है) के आधार पर करना होता है। योजना बनाते समय सरकार कृषि कार्यक्रम और योजना को ध्यान में रखा जाता है। फार्म या खेत के प्रायः सभी कार्य उसके सदस्यों द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। सामूहिक खेत-सम्पत्ति (कोलखोज सम्पत्ति) का सरक्षण, अधिकतम उत्पादन और साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किए जाने पर अत्यधिक बल दिया जाता है।

सामूहिक खेत अर्थात् कोलखोज में श्रम-संगठन—प्रत्येक सामूहिक खेत पर मजदूर अनेक श्रेणियों या ब्रिगेडों में अपनी सदस्यता संगठित करते हैं। प्रायः प्रत्येक ब्रिगेड में 50 से लेकर 100 सदस्य होते हैं जिन्हें उतने समय तक के लिए काम सौंपा जाता है जब तक फसल का काम चले। ब्रिगेड को अपने कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक पशु, मशीन एवं अन्य उपकरण दिए जाते हैं। कभी कभी इन ब्रिगेडों को उप-विभागों अर्थात् स्क्वैडों (Squads) में बाँट दिया जाता है जिन्हें Zveno or Link कहा जाता है। प्रत्येक विभाग में लगभग 12 से 15 सदस्य होते हैं। प्रत्येक ब्रिगेड में एक नेता होता है जो निर्धारित कार्य को पूरा करने में ब्रिगेड का नतृत्व अर्थात् संचालन करता है। काम से भी पुराने वालों और कार्य की अवहेलना करने वालों को दण्डित किए जाने की व्यवस्था होती है।

सामूहिक खेत में मजदूरी की गणना और भुगतान—सामूहिक फार्मों में श्रम को कार्य-दिवस (Working day) के आधार पर मापा जाता है। कार्य का दिन समय से नहीं बल्कि कार्य की प्रकृति के अनुसार निर्धारित किया जाता है उदाहरणार्थ यदि एक व्यक्ति एक एकड़ प्याज के खेत की सफाई करे तो उसे आधा दिन के काम का भुगतान दिया जाता है और यदि वह रूई के खेत पर दो एकड़ भूमि पर काम करे तो उसका काम द्वाइ दिन का माना जाता है। सन् 1948 के एक सुधार के अनुसार सभी विभिन्न कार्यों को 9 समूहों में वर्गीकृत कर दिया गया है। प्रत्येक कार्य के लिए एक निश्चित उत्पादन लक्ष्य होता है।

सामूहिक फार्म प्रणाली में श्रम का भुगतान सामूहिक फार्मों की सफलता पर निर्भर करता है। फार्म की आय जितनी अधिक होती है, कार्य के दिन की इकाई उतनी अधिक बन जाती है। प्रत्येक सामूहिक किसान अच्छा, अधिक और कुशल कार्य करना चाहता है ताकि सामूहिक फार्मों की उत्पादिकता को बढ़ाया जा सके क्योंकि तभी किसान को अधिक आय प्राप्त हो सकती है और उसके परिवार का जीवन स्तर ऊँचा उठ सकता है। सामूहिक फार्म की वार्षिक आय और उत्पादन को एक जटिल

तरीके से काम में लिया जाता है। जब ये फार्म अपने उत्पादको को वितरित करते हैं तो सबसे पहले ये अपने उत्पादन का एक भाग राज्य को बेचते हैं, उसके बाद कुछ भाग बीज-गोदामों में रखते हैं, मवेशियों के लिए चारे के रूप में देते हैं और जिस भाग का वितरण नहीं किया जाता उसे अक्षम व्यक्तियों के लिए तथा बीमा योजना के लिए धन की व्यवस्था करने में काम में लेते हैं।

सामूहिक किसानों की सामान्य बैठक में निर्णय लेने के बाद उत्पादक का एक भाग सामूहिक फार्म बाजार में बेच दिया जाता है। सामूहिक फार्मों में दिन-प्रतिदिन भुगतान के प्रायः नए तरीकों का प्रयोग किया जाने लगा है। वर्तमान समय में कृषि आर्टेल के लगभग 80 प्रतिशत भाग द्वारा अपने सामूहिक किसानों को कार्य के दिन के आधार पर मासिक या साप्ताहिक रूप से भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक फार्मों की प्रायः यह भी सिफारिश की जाती है कि वे व्यक्तिगत किसानों को उच्च उत्पादिकता के लिए अनुपूरक भुगतान करें। यह एक प्रकार से अतिरिक्त भौतिक प्रेरणा है।

उत्पादन का वितरण—सामूहिक फार्म व्यवस्था के अन्तर्गत वार्षिक उत्पादन और वितरण की व्यवस्था जटिल है। सबसे पहला दावा राज्य के भाग का होता है जो कई रूपों में हो सकता है, जैसे—वस्तु के रूप में कर। यह समस्त कर फार्म-उत्पादन पर लगाया जाता है। उत्पादित वस्तु का कितना भाग राज्य को दिया जाएगा, इस सम्बन्ध में राज्य के साथ समझौता कर लिया जाता है जो प्रायः 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के लिए होता है लेकिन व्यवहार में राज्य की क्रय-योजना के अनुरूप समझौते में वार्षिक समायोजन होता रहता है। राज्य के अतिरिक्त दूसरी सस्था मशीन ट्रेक्टर स्टेशन है जिसके लिए प्रत्येक सामूहिक फार्म को आवश्यक रूप से भुगतान करना पड़ता है। यह भुगतान उन समस्त मशीनों, वस्तुओं, सेवाओं और परामर्श के लिए होता है जो फार्मों द्वारा प्राप्त किया जाता है। सामूहिक फार्म थोड़ा बहुत भुगतान सरकार के लिए बीज, ऋणों तथा वस्तु के रूप में उधार ली गई चीजों के बदले करते हैं। सरकार को किए जाने वाले अधिकांश भुगतान कर के रूप में होते हैं और कुछ भाग अत्यन्त नीची कीमत पर उत्पादन की खरीददारी के रूप में भी होता है। कुल मिलाकर सामूहिक फार्मों के उत्पादन का 30 से 45 प्रतिशत तक भाग किसी न किसी रूप में राज्य को मिल जाता है। सरकार की माँग को सन्तुष्ट करने के बाद फार्म उत्पादन के विभिन्न भागों को बीज तथा चारे के लिए रख दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भविष्य में फसल असफल होने की स्थिति का सामना करने के लिए तथा वृद्धों व अपाहिजों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी उपज का कुछ भाग रखा जाता है।

इन सब भुगतानों को करने के बाद जो शेष बचता है वह सामूहिक फार्म के सदस्यों के बीच वितरित किया जाता है। सदस्यों को, कार्य के दिनों के आधार पर उनका यह भुगतान किया जाता है। सभी सदस्यों के वर्ष भर के कार्य के दिनों का

योग लगाकर उत्पादन में उनका भाग देकर यह मालूम कर लिया जाता है कि प्रत्येक प्रकार के उत्पादन के लिए कार्य के दिन का कितना भुगतान किया जाए।

घास का वितरण—घास का वितरण भी इसी प्रकार किया जाता है। वर्ष के अन्त में सामूहिक फार्म अपनी मौद्रिक घास वितरित करते हैं। प्रथम भुगतान राज्य के लिए घासकर के रूप में किया जाता है। यह वर्ष में चार बार होता है। अन्तिम वित्त घास 1 दिसम्बर को ली जाती है जो वर्ष के कुल-कर का लगभग 14 प्रतिशत होती है। कर की मात्रा छोट रूप में कुल घास या लगभग 14 प्रतिशत होती है। दूसरा भुगतान राज्य बीमा के लिए किया जाता है जो सभी भोजारों, साधनों और उत्पादनों से सम्बन्ध रखता है।

मौद्रिक घास का प्रयोग सामूहिक फार्म द्वारा उस भुगतान के लिए किया जाता है जो बाहर से ली गई थ्रम-सेवाओं और वस्तुओं के लिए किया जाना है। रोप मौद्रिक घास सामूहिक फार्म के सदस्यों के बीच उनके काम के दिनों की सख्या के अनुपात में वितरित कर दी जाती है।

सामूहिक खेत अर्थात् कोलखोज का सरकार से सम्बन्ध—प्रत्येक सामूहिक फार्म (कोलखोज) यद्यपि अपने आप में काफी स्वतन्त्रता का उपभोग करता है, लेकिन यह स्वतन्त्रता सरकारी और दलीय नियन्त्रण से पूरी तरह प्रभावित होती है। प्रत्येक कोलखोज की फसल-योजना (Crop-plan) राज्य द्वारा बनाई जाती है तथा प्रत्येक वस्तु का उत्पादन लक्ष्य भी राज्य द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। उत्पादक वस्तु का कितना भाग राज्य को दिया जाएगा इस सम्बन्ध में राज्य के साथ समझौता होता है जिसमें राज्य की इच्छा ही व्यावहारिक रूप में बाध्यकारी होती है। राज्य की क्य-योजना के अनुरूप समझौते में वार्षिक समायोजन होता रहता है। कोलखोज पर सभी यान्त्रिक कृषि-कार्य राजकीय ट्रैक्टर स्टेशनों द्वारा किया जाता है। बदले में प्रत्येक सामूहिक फार्म को आवश्यक रूप से भुगतान करना पड़ता है। अब यद्यपि बहुत से मशीन ट्रैक्टर स्टेशनों के उपकरण सामूहिक फार्मों को बेच दिए गए हैं तथा अनेक स्टेशन केवल मरम्मत-स्टेशनों के रूप में रह गए हैं। सामूहिक फार्मों द्वारा सरकार से बीज, श्रृणु आदि लेने के बदले भी काफी भुगतान किया जाता है। बंसा कि कहा जा चुका है, सरकार को किए जाने वाले अधिकांश भुगतान कर के रूप में होते हैं और कुछ भाग अत्यन्त नीची कीमत पर उत्पादन की सखीदशरी के रूप में भी होता है।

इस में राज्य फार्म और सामूहिक फार्म

मास्को के इर्दगिर्द कई राज्य फार्म हैं, उनमें मास्कोव्स्की भी एक है। ये वृषि प्रतिष्ठान राजधानी के लिए जिसको आबादी अस्सी लाख है, डेरी उत्पादन, सब्जियाँ, मांस, बेरी, भ्रडों और यहाँ तक कि फूलों की भी पूर्ति करते हैं।

मास्कोव्स्की फार्म सब्जियाँ उगाने में माहिर हैं। यह मास्को की सालभर ककड़ियों, सलाद और टमाटारों की पूर्ति करता है। अक्टूबर से मई तक काचधरो में सब्जियाँ उगायी जाती हैं। इसके अलावा फार्म में पशुशाला, फूल उगाने के लिए काचधर, कुकुमुत्ता बागान और बेरी उगाने के खेत हैं।

फार्म में सभी उत्पादन प्रक्रियाएँ अत्यधिक यन्त्रीकृत हैं। यहाँ गावों और बछड़ों के लिए प्रत्येक शेड में चारा जमा रखने की विशेष सुविधाएँ हैं।

मास्को स्की देश के बड़े राज्य फार्मों में है तथा काँचघर में पौधा उगाने में विशेषज्ञता हाँसिल कर रहा है। सोवियत सघ में 19,636 राज्य फार्म हैं। उनमें हर एक विशाल प्रतिष्ठान है तथा उनके पास औसतन 6000 हेक्टर जोत लायक जमीन, 55 ट्रेक्टर, 18 कम्बाइन हार्वेस्टर और 25 ट्रक हैं। 1976 में राज्य ने जितने परिमाण में कुल कृषि उत्पादन खरीदा उसमें उसने 51 प्रतिशत भवेशी, 45 प्रतिशत दूध, 56 प्रतिशत ऊन और 87 प्रतिशत अण्डे इन्हीं प्रतिष्ठानों से खरीदे।

महान अकनूबर समाजवादी क्रान्ति ने जमीन पर का निजी स्वामित्व खत्म कर दिया। 1917 के पहले दो प्रतिशत भूस्वामी जिसमें भूमिपति भद्र लोग, मठ और पूँजीपति शामिल थे, 60 प्रतिशत जमीन हथियाये हुए थे। जनसत्ता की घोषणा के तत्काल बाद किसानों को 1९ करोड़ हेक्टर से अधिक जमीन मिली। यह किसानों के बीच बाँटी गई ताकि हर एक को अपने परिवार का भरण-पोषण करने का अवसर मिले। किन्तु कई अत्यधिक यन्त्रीकृत और समृद्ध फार्म थे जिनका विभाजन अनुचित होता। इसी कारण लेनिन की भूमि सम्बन्धी आज्ञाप्ति में यह परिकल्पित है कि उन फार्मों के आधार पर आदर्श कृषि प्रतिष्ठान स्थापित किये जाने चाहिए और उन्हें राज्य को अथवा कृषक समुदायों को सौंप देना चाहिए।

प्रथम राज्य फार्म की स्थापना सोवियत राज्य के कायम होने के प्रथम महीने में, नवम्बर 1917 में हुई। इस प्रकार के प्रतिष्ठान शीघ्र सोवलोज के रूप में यानी वह फार्म जिसका स्वामी सोवियत हो, सर्वत्र विख्यात हुए।

अपने 60 वर्ष के जीवन काल में राज्य फार्मों ने लम्बा रास्ता तय किया है। किन्तु उनके कार्यकलाप को निर्देशित करने वाले बुनियादी सिद्धान्त एक ही रहे हैं। भवन और सरचनाएँ, मशीनें, बीज के भण्डार, भवेशी और राज्य फार्म के औजार के साथ ही वह हर चीज राज्य की है जिसका वे उत्पादन करते हैं। स्वामित्व का एक और रूप है, वह है सामूहिक स्वामित्व। राज्य फार्मों के प्रधान मनेजर होते हैं जिन्हें राज्य नियुक्त करता है जबकि सामूहिक फार्म का प्रबन्ध-संचालन सामूहिक फार्म के किसानों की धाम सभा द्वारा निर्वाचित बोर्ड करता है। सामूहिक फार्म के किसानों को अपने फार्म की आय का हिस्सा मिलता है जबकि राज्य फार्म के किसानों की राज्य द्वारा नियुक्त औद्योगिक मजदूरों की हैसियत होती है। वह वेतन पाता है तथा उसे वे सारी सुविधाएँ प्राप्त हैं जो शहरी मजदूर को मिलती हैं जिनमें काम के निश्चित घण्टे, छुट्टियाँ आदि शामिल हैं और शहरी मजदूरों के समान ही वह दक्षता उत्तम करता है तथा नयी प्रविधि में पारगता हाँसिल करता है। राज्य फार्म की दस्तियों में सारे देश में स्कूल, किन्डरगार्टन, बाहरी रोगियों का इलाज करने वाले क्लिनिक, अस्पताल, यामूदायिक केन्द्र, सार्वजनिक सेवाएँ, स्टेडियम, काफ़े रेस्तरा, और खाते बैसे ही हैं जैसे नगरों में होते हैं, किन्तु कुछ अन्तर होते हैं। यह गणना की गयी है कि चूँकि राज्य फार्मों के खाद्य उत्पादों की कीमत नगरों की

अपेक्षा कम होती है, इसलिए यदि केवल केन्टीनो, काफी और स्नेक-बार के जरिये बेची जाने वाली वस्तुओं की भी गणना की जाए तो सामान्यतया राज्य फार्म के मजदूरों ने वेतन में कुल 9 करोड़ 55 लाख रुबल की प्रतिवर्ष स्वतः 'वृद्धि' हासिल कर ली है।

इसके अलावा, सामान्यतया कृषि मजदूरों के पास जमीन का एक टुकड़ा होता है हालांकि उसके पास नौ मजिला इमारत में फ्लैट है पर वह उस जमीन में अपनी पसन्द की चीज उगा सकता है और जिस प्रकार चाहे उसे बेच सकता है।

आइए, हम अब सामूहिक और राज्य फार्म के सम्बन्धों की पड़ताल करें। सामूहिक फार्मों को व्यावसायिक भाव उत्पादित करने के अलावा यह कार्यभार दिया गया कि वे "प्रगतिशील, विज्ञान सम्पन्न रूप से प्रवृत्त, उच्च कार्यकुशलता और श्रम उत्पादकता के आर्थिक रूप से लाभदायक सामाजिक उत्पादन के नमूने के रूप में काम करें।"

राज्य फार्म सामूहिक फार्मों की नयी विधियाँ और प्राविधिक प्रक्रियाएँ विकसित करने, बीज का भण्डार सुदृढ़ करने और पशु प्रजनन उन्नत करने में मदद करते हैं। राज्य फार्म नयी प्रविधि के लिए "परीक्षण स्थल" का काम करते हैं। जहाँ तक विक्रय, कमियों के प्रशिक्षण, निर्माण सामग्रियों और फार्म मशीनों के वितरण और ऐसे अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है, जो प्रकटतया विवाद को जन्म दे सकते हैं, तो उन सभी का निर्धारण राज्य योजनाओं द्वारा किया जाता है। इस सिलसिले में उल्लेखनीय बात यह है कि राज्य और सामूहिक फार्म भी ऐसी योजनाओं का प्रारूप तैयार करने में भाग लेते हैं।¹

—

सन् 1954 से सोवियत कृषि-विकास

(Soviet Agricultural Development Since 1954)

रूस में कृषि-क्षेत्र में सामूहीकरण के तात्कालिक परिणाम भले ही विशेष सन्तोषजनक नहीं निकले, लेकिन आगे चल कर इसके कारण सोवियत रूस कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हाँसिल कर सका। सन् 1953 तक रूस ने कृषि के क्षेत्र में काफी प्रगति की, लेकिन प्रधानता औद्योगिक क्षेत्र को ही दी गई। सन् 1951 से 1955 तक जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित की गई, उसमें कृषि की स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही। योजना के प्रथम तीन वर्षों में कृषि-उत्पादन बढ़ने की अपेक्षा घट गया। मवेशियों की संख्या भी कम हो गई। अनाज के उत्पादन में केवल तीन या चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। मवेशियों की संख्या कम होने से दूध और मांस की स्थिति दयनीय हो गई। चुकन्दर और बपास के उत्पादन में भी नाममात्र की वृद्धि हुई। फलेस का उत्पादन तो बहुत ही घट गया।

इन सब कमियों के कारण कृषि उद्योग के विकास को अधिक महत्त्व देना आवश्यक हो गया। सन् 1953 में स्टालिन की मृत्यु हो गई। स्टालिन का दृष्टिकोण कृषि विकास पर उतना महत्त्वपूर्ण नहीं था जितना औद्योगिक विकास पर। स्टालिन की मृत्यु के बाद रूस के नए नेतृत्व ने कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देना आवश्यक समझा। अतः सन् 1954 से ही कृषि विकास के लिए विभिन्न नए कदम उठाए जाने लगे। इसी कारण रूस कृषि विकास के इतिहास में सन् 1954 से उसे एक नए युग का श्रागणेश माना जाता है और 1954 से रूसी कृषि विकास विशेष अध्ययन का पात्र है।

सन् 1954 से रूसी कृषि-विकास

स्टालिन के उपरान्त साम्यवादी दल ने सन् 1954 में कृषि-विकास के लिए प्रभावकारी कदम उठाए। लगभग साढ़े तीन लाख युवकों को वजर भूमि को आबाद करने के कार्य में नियोजित किया गया। लगभग दो लाख ट्रैक्टरों की सहायता से दो वर्षों की अल्प-अवधि में ही 33 मिलियन हेक्टर भूमि को कृषि योग्य बना दिया गया। परिणाम-स्वरूप पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में कृषि-उत्पादन में वृद्धि हो गई और मवेशियों की संख्या भी बढ़ गई। कृषि का यंत्रीकरण बड़े पैमाने

पर प्रारम्भ किया गया। अतः पंदावार 100 से 129 प्रतिशत तक बढ़ गई। इस प्रकार कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र में पाँचवी योजना की प्रगति सन्तोषजनक बन गई। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि (1956-1960)

छठी योजना में स्वाभाविक कृषि के विकास को विशेष महत्त्व दिया गया। कृषि की दृष्टि से योजना का उद्देश्य यह रखा गया कि कृषि-उत्पादन में तीव्र प्रगति से वृद्धि की जाए और इस हेतु लगभग 3 करोड़ हेक्टर नई पड़त भूमि का उपयोग किया जाए। साथ ही कृषि और यातायात के क्षेत्रों में विद्युत-शक्ति का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। कुल मिलाकर कृषि-उत्पादन में 38 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। योजना काल में कृषि-उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने सामूहिक कृषि फार्मों को 15 लाख 50 हजार ट्रेक्टर और 5 लाख 60 हजार ग्रोन कम्पाइन देने का निश्चय किया। छठी योजना में कुल मिलाकर 990 मिलियन डॉलर अर्थात् 9 लाख 90 हजार करोड़ डॉलर व्यय करने का प्रस्ताव रखा गया जिसमें से 120 मिलियन डॉलर कृषि विकास पर व्यय किए जाने थे।

छठी योजना भवधि में कृषि-क्षेत्र में इतनी प्रगति की गई कि पिछली योजनाओं में शायद ही कृषि में कभी इतनी प्रगति की जा सकी हो। इस योजना में 3 करोड़ हेक्टर नई भूमि को कृषि योग्य बना कर 150 करोड़ पूँज अनाज उत्पन्न किया गया, संकड़ों की सख्या में नए-नए राजकीय फार्म स्थापित किए गए, लेकिन यह सब कुछ लक्ष्य से नीचे था। अनाज का उत्पादन बढ़ाकर 1960 तक 18 करोड़ टन करने का आयोजन था जो नहीं हो सका। कपास के उत्पादन में 56 प्रतिशत और ऊन के उत्पादन में 82 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य रखे गए थे जो प्राप्त नहीं हो सके, लेकिन फिर भी कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन हुआ वह निराशाजनक नहीं था। लक्ष्यों को प्राप्त इसलिए नहीं किया जा सका कि वे अस्वाभाविक और बहुत ऊँचे थे। यदि अन्य योजनाओं से कृषि के विकास की तुलना की जाए तो छठी योजना की भवधि में कृषि विकास में जितनी प्रगति हुई, उतनी शायद ही अन्य योजनाओं में हुई हो।

सातवी सप्तवर्षीय योजना में कृषि (1959-1965)

छठी योजना की भवधि यद्यपि 1956 से 1960 तक की थी, लेकिन यह भवधि इस दृष्टि से पूर्ण नहीं हुई कि 1958 के अन्त में ही इसे समाप्त करके एक नई सप्तवर्षीय योजना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सातवर्षीय योजना का समय 1959 से 1966 तक का रखा गया। छठी योजना के अन्तिम दो वर्ष इसी योजना में शामिल कर दिए गए। यह सप्तवर्षीय योजना भी इस की एक दीर्घकालीन धार्मिक विकास की योजना का अंग कही जा सकती है। इसने 1960 से 1980 तक के लिए एक 20 वर्षीय योजना की घोषणा की है। अतः इसी सप्तवर्षीय योजना को इसी 20 वर्षीय योजना का एक अंग समझा जाना चाहिए।

कृषि की दृष्टि से सातवर्षीय योजना का उद्देश्य यह रखा गया कि कृषि के सभी क्षेत्रों में विवास किया जाए ताकि अधिक भोजन और कच्चे माल की पूर्ति की

जा सके। यह लक्ष्य रखा गया कि दूध का उत्पादन लगभग दुगुना, घीर रूई का उत्पादन 35 प्रतिशत से 45 प्रतिशत से भी अधिक किया जाए। चुकन्दर व पटसन में 32 प्रतिशत और तिलहन में 70 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। फलों की पैदावार दुगुनी की जाए तथा अगूर की पैदावार लगभग चौगुनी की जाए। आलू की फसल को 1965 तक 14 करोड़ 70 लाख टन कर दिया जाए। खाद्य-उत्पादन में कुल मिला कर लगभग 70 प्रतिशत वृद्धि का आयोजन किया गया। यह निश्चित किया गया कि सप्तवर्षीय योजना के बाद प्रतिवर्ष दस अरब से लेकर ग्यारह अरब पूँड अनाज पैदा किया जा सके।

सप्तवर्षीय योजना में जहाँ कृषि-उत्पादन में 70 प्रतिशत वृद्धि की सम्भावना थी वहाँ वृद्धि केवल 10 प्रतिशत की हुई। मार्च, 1965 में सोवियत साम्यवादी दल के प्रथम सचिव श्री ब्रेजनेव ने स्वीकार किया कि कृषि-उत्पादन की वार्षिक दर बहुत ही कम रही है और सोवियत संघ को बड़ी मात्रा में विदेशों से अनाज का आयात करना पडा है। योजना काल में कृषि-वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण और नियन्त्रण भी असन्तोषजनक रहा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में सातवी योजना असफल रही, जिसके कारण रूसी नेताओं में मत-भेद भी हो गए और भावी योजना में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने पड़े। कृषि-क्षेत्र में असफलता को मिटाने के लिए 1965-1970 की योजनाओं में कृषि-उत्पादन पर भरसक बल दिया गया।

बीस वर्षीय योजना (1961-81) में कृषि

सातवी सप्तवर्षीय योजना आरम्भ होने के दो वर्ष बाद ही अक्टूबर, 1961 में साम्यवादी दल की 22वी कांग्रेस में आर्थिक विकास का 20 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस 20 वर्षीय योजना में कृषि उत्पादन में साढ़े तीन गुना, दुग्ध उत्पादन में तीन गुना और खाद्यान्नों में दो गुना वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। निम्न तालिका यह प्रदर्शित करती है कि बीस वर्षीय योजना में कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980 तक का उत्पादन लक्ष्य रखा गया —

कृषि पदार्थों का उत्पादन (1960-1980)

मर्दें	1960	1970	1980
अनाज (10 लाख टन)	134	230	210
दूध (लाख टन)	61.7	1.5	170-180
मास (लाख टन)	8.7	29	30-32
अण्डे (अरब)	27.4	68	110-116
ऊन (000 टन)	357	800	1045-1055
आलू (लाख टन)	84.4	140	156
चुकन्दर (लाख टन)	57.7	86	98-108
सब्जी (लाख टन)	19.2	47	55
फल (लाख टन)	4.9	28	51
कपास (लाख टन)	4.3	8	10-11

विकास क्षेत्र	1965	1970	1975
1. औद्योगिक उत्पादन का विकास (प्रतिशत)	100	150	213-219
2. विद्युत् उत्पादन (हजार मि. किलोवाट)	507	740	1030-1070
3. तेल का उत्पादन (मि. टन)	243	353	480-500
4. गैस का उत्पादन (हजार मि. क्यू. मीटर)	129	200	300-320
5. इस्पात का उत्पादन (मि. टन)	91	116	142-150
6. फुटकर व्यापार टर्नओवर का विकास (प्रतिशत)	100	148	207
7. गृह-निर्माण (मि. स्क्वायर मीटर पत्तोर स्पेस)	490.6 (1961-65)	518 (1966-70)	565-575 (1971-75)
8. भाँस (श्रीसत बायिक) उत्पादन (मि. टन)	9.3 (1961-65)	11.6 (1966-70)	14.3 (1971-75)
9. भनाज (श्रीसत बायिक) उत्पादन (मि. टन)	130.3 (1961-65)	167.5 (1966-70)	195.0 (1971-75)
10. प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का विकास (प्रतिशत)	100	133	173
11. राष्ट्रीय आय का विकास (प्रतिशत)	100	141	193-196
12. विशेषज्ञों की ट्रेनिंग (मिलियन)	4.3 (1961-65)	7.1 (1966-70)	9.0 (1971-75)

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि 1975 तक सोवियत रूस आर्थिक प्रगति की बहुत ही उच्च स्थिति में पहुँच गया। रूस की द्रुत औद्योगिक प्रगति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहाँ 1913 से 1970 की अवधि में अमेरिका के औद्योगिक उत्पादन में आठ गुना, फ्रांस में तीन गुना, पश्चिमी जर्मनी में पाँच गुना और ब्रिटेन में तीन गुना वृद्धि हुई वहीं इसी अवधि में सोवियत सघ में लगभग अस्सी गुना वृद्धि हुई। 1971-75 की नवीं पंचवर्षीय योजना में ही औद्योगिक उत्पादन में लगभग 46 प्रतिशत वृद्धि हुई। सोवियत सघ ने औद्योगिक क्षेत्र में इतनी प्रगति की

है कि सम्पूर्ण विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का 20 प्रतिशत से भी अधिक भाग अकेला वह उत्पन्न करता है। सोवियत संघ में प्रति वर्ष 520 से 540 अरब रूबल मूल्य का औद्योगिक माल उत्पादित किया जाता है। सोवियत संघ में औद्योगिक उद्योगों की शाखाएँ 300 से भी अधिक हैं जिनमें विपुल धन राशि नियोजित है। 1913 में रूस का औद्योगिक उत्पादन विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का केवल 4 प्रतिशत ही था। 1913 में रूस का औद्योगिक उत्पादन समुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक उत्पादन का लगभग 12 से 13 प्रतिशत था जो अब बढ़कर 65 से 70 प्रतिशत हो गया है। 1960 से 1968 की अवधि में ही रूस की औद्योगिक उत्पादन में लगभग 95 प्रतिशत वृद्धि हुई। 1960 में लगभग 155 अरब रूबल मूल्य का औद्योगिक उत्पादन हुआ जबकि 1968 में लगभग 32 हजार करोड़ मूल्य का। यद्यपि रूस औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से अभी भी अमेरिका से पीछे है, लेकिन रूस का दावा है कि बीस वर्षीय कार्यक्रम की समाप्ति तक अर्थात् 1980 तक वह अमेरिका के समकक्ष हो जावेगा। रूस ने अनेक वस्तुओं के उत्पादन में तो चमत्कारिक प्रगति की है उदाहरणार्थ कोयले का उत्पादन 1913 में लगभग 3 करोड़ टन से बढ़ कर 1977 में लगभग 720 करोड़ टन हो गया। इस्पात 1913 में लगभग 4 मिलियन टन से कुछ ही अधिक था जो बढ़ कर 1977 में 150 मिलियन टन को स्पर्श करने लगा। खनिज तेल का उत्पादन 1913 में लगभग 9 मिलियन टन हुआ था जो बढ़ कर 1917 में लगभग 5000 मिलियन टन तक पहुँच गया। रूस की आठवीं योजना (1966-70) की तुलना में नवी योजना काल (1971-75) में औद्योगिक उत्पादन में 60 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई। जहाँ 1970 में लगभग 375 अरब रूबल मूल्य का औद्योगिक उत्पादन हुआ था 1977 में 500 अरब रूबल से भी अधिक हुआ। दसवीं पंचवर्षीय योजना (1976-80) की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में 35 से 40 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है और अम उत्पादकता में भी 30-से 35 प्रतिशत वृद्धि होने की पूरी सम्भावना है। दसवीं योजना काल में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत और उपभोक्ता माल में लगभग 30 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। यह आशा की गई है कि 1980 तक औद्योगिक उत्पादन का मूल्य 690 से 725 अरब रूबल तक पहुँच सकता है। विद्युत शक्ति का उत्पादन 1960 में लगभग 290 अरब किलोवाट हुआ जो 1980 तक लगभग 1830 अरब किलोवाट हो जाने की आशा है।

सोवियत रूस ने निरन्तर बड़ी तेजी से औद्योगिक प्रगति की है। 1960-से 1980 तक के लिए एक 20 वर्षीय कार्यक्रम बनाया गया है (वर्तमान पंचवर्षीय योजनाएँ उसी का अंग हैं) जिसके अनुसार वह न केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही बरन अन्य क्षेत्रों में भी सप्तरा का राष्ट्र-मन्वर एक बन जाने की आशा करता है। सन् 1960 से 1980 तक उसने औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन के जो लक्ष्य रखे हैं वे निम्न तालिका से स्पष्ट हो सकेंगे—

औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन (1960-80)

वस्तु	1960	1970	1980
कुल औद्योगिक उत्पादन (मिलियर्ड रूबल)	155	408	970-1000
पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन (मिलियर्ड रूबल)	105	287	720-740
उपभोग पदार्थ (मिलियर्ड रूबल)	50	121	250-260
विद्युत् शक्ति (मिलियर्ड किलोवाट)	292	900-1000	2700-3000
इस्पात (मिलियन टन)	65	145	250
तेल (मिलियन टन)	148	390	390-710
गैस (हजार क्यू. मी.)	47	310-385	680-720
कोयला (मिलियन टन)	513	700	1180-1200
सीमेन्ट (मिलियन टन)	45.5	122	233-235
सूती वस्त्र (मिलियर्ड वर्ग मीटर)	6.6	13.6	20-22
चमड़े के जूते (मिलियन जोड़े)	419	829	900-1000
घरेलू मशीनी सामान (मिलियर्ड रूबल)	5.9	18	60
कृत्रिम और सिंथेटिक वस्त्र (मिलियन टन)	0.2	8.35	31-33

रूस की इस 20 वर्षीय योजना में 1966 से 1980 तक की पधवर्षीय योजनाएँ भी सम्मिलित हैं। इसके पहले की सप्तवर्षीय योजना को भी इसी बीस वर्षीय योजना का एक अंग समझना चाहिए। रूसी नेताओं द्वारा यह आशा की गई है कि इस 20 वर्षीय कार्यक्रम के सफल सम्पादन के बाद रूस में पूर्णतः साम्यवादी समाज की स्थापना होने में बाकी सहायता मिलेगी।

तीव्र औद्योगीकरण की समस्याएँ

(Problems of Rapid Industrialization)

सोवियत रूस ने जो औद्योगिक प्रगति की है वह निश्चय ही बहुत उरसाह-वर्द्धक है। तीव्र औद्योगीकरण के जिन सन्ध्यों का निर्धारण रूस ने किया है वे उसकी पहुँच से सर्वथा बाहर हो, यह कहना भी भ्रामक होगा। लेकिन रूस औद्योगीकरण की दिशा में वांछित गति से तब तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि इस मार्ग में उपस्थित कुछ प्राधारभूत समस्याओं को हल न कर लिया जाए। रूसी आर्थिक संरचना मौलिक रूप में कुछ ऐसे दोषों और समस्याओं को छिपाए हुए है जिन्हें दूर

किए बिना रूस के भावी लक्ष्य महत्वाकांक्षी सिद्ध हो सकते हैं। रूसी औद्योगीकरण के और अर्थ-व्यवस्था के अनेक ऐसे पहलू हैं जो आधारभूत रूप से उतने ठोस नहीं हैं जितने प्रायः बाहर से दिखाई देते हैं। अतः हमें देखना चाहिए कि रूस के तीव्र औद्योगीकरण से सम्बन्धित कौन-सी प्रमुख समस्याएँ मौजूद हैं? ये सभी समस्याएँ एक-दूसरे से जुड़ी हैं तथापि विषय की स्पष्टता की दृष्टि से उन्हें अलग-अलग व्यक्त करना उपयुक्त होगा—

(1) सोवियत रूस में पूर्णतः राज्य-नियन्त्रित और केन्द्रीयकृत अर्थ-व्यवस्था है। वहाँ उत्पादन के लक्ष्यो, उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं आदि का निर्धारण राज्य द्वारा होता है। इस प्रकार उत्पादको के हितों को प्रमुखता नहीं दी जाती। उत्पादको को, मुक्त अर्थ-व्यवस्था की भाँति, इस बात का कोई उत्साह नहीं रहता कि वे कम से कम लागत पर अपनी इच्छानुसार वस्तुओं का उत्पादन करें। उत्पादन क्षेत्र में आधारभूत रूप से उत्साह की कमी रहने के फलस्वरूप औद्योगिक प्रगति उतनी ठोस नहीं हो पाती जितनी मुक्त अर्थ-व्यवस्था में होना सम्भव है।

(2) सोवियत अर्थ-व्यवस्था में कम से कम लागत-उत्पाद (Least Cost-out put) सम्भव नहीं है क्योंकि एक पूर्ण प्रतियोगितामय मुक्त अर्थ-व्यवस्था की तुलना में श्रमिकों को अधिक भुगतान करना पड़ता है जिससे वस्तुओं की उत्पादन-लागत अधिक बैठती है और फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के क्षेत्र में वे वस्तुएँ सुगमता से बाजार नहीं छीन सकती। यह स्थिति भी रूस के तीव्र औद्योगीकरण के मार्ग में बाधक है।

(3) सोवियत अर्थ-व्यवस्था में कीमत यन्त्र (Price-mechanism) प्रभाव-शील नहीं रहता। कीमत-यन्त्र का प्रभावशील न रहना तीव्र औद्योगीकरण के मार्ग में निम्न समस्याएँ पैदा करता है।

(4) सोवियत रूस में पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर ही अधिकाधिक ध्यान दिया जाता है जबकि उपभोक्ता-वस्तुओं की प्रायः उपेक्षा की जाती है। इस प्रकार आम जनता में निराशा और असंतोष का वातावरण पनपता है जो परोक्ष रूप में तीव्र औद्योगीकरण के लिए बड़ा घातक है।

(5) एक बड़ी समस्या यह है कि रूस की औद्योगिक योजनाओं में प्रायः उत्पादन की मात्रा (The Quantity of out put), लागतों में प्रतिशत कमी (Percentage Reduction in Costs) अथवा श्रम-उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि (Percentage increase in Labour-Productivity) में लक्ष्यो का निर्धारण कर दिया जाता है और इन लक्ष्यो की प्राप्ति को ही सफलता का सूचक माना जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जो अन्तर्निहित दोष विद्यमान हैं, उनकी प्रायः उपेक्षा कर दी जाती है या हो जाती है, उदाहरण के लिए हम 'उत्पादन की मात्रा' (The Quantity of out put) को ही लें। योजना प्रायः पूर्व सफलताओं पर आधारित होती है जिसमें 'प्रतिशत वृद्धि' (Percentage Increase) जोड़ दी जाती है। सम्बन्धित औद्योगिक संस्थान अथवा कारखाने व अधिकारीगण इसी बात के लिए

प्रयत्नशील रहते हैं कि निर्धारित मात्रा या उससे अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन निश्चित या उससे कम अवधि में कर दिखाया जाए। ऐसा करने में उनका ध्यान वस्तु की गुणात्मक वृद्धि पर बहुत कम अवधान गम्य रहता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी वस्तु का उत्पादन टनो में निर्धारित कर दिया गया है तो सम्बन्धित मस्यानो व व्यवस्थापको का प्रयत्न यही रहता है कि निर्धारित टनो का लक्ष्य पूरा कर दिया जाए, चाहे वस्तु गुणात्मक दृष्टि से कमजोर हो अवधान राष्ट्र के लिए आवश्यक, उस वस्तु का एक ही प्रकार निकाल दिया जाए, उसके विभिन्न प्रकारों के उत्पादन की परवाह न की जाए। इस प्रकार यदि किसी फ़ैक्ट्री को सीमेंट ब्लाक बनाने को कहा गया हो तो वह बड़े-बड़े ब्लाक बनाना अधिक पसन्द करेगी ताकि टनो के रूप में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की जा सके। वह इस बात का ध्यान नहीं रखेगी कि जिन इमारतों का निर्माण-कार्य चल रहा है उसमें छोटे सीमेंट ब्लाको की कमी से गतिरोध पैदा हो जाएगा। इस स्थिति को 'क्रोकोडिल' (Krokodil) नामक हास्य-यत्र ने एक वाटून के रूप में चित्रित किया था जिसमें एक फ़ैक्ट्री ने अपने पूरे महिने की कीलों के उत्पादन-कार्यक्रम को एक ही विशालकाय कील बना कर पूरा कर दिखाया था, क्योंकि उत्पादन-मात्रा टनो में जो दिखानी थी।

स्पष्ट है कि इस प्रकार की स्थिति तीव्र औद्योगीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। सोवियत रूस में हाल ही के वर्षों में सुधार की नई तकनीकें अपनाई जा रही हैं—और सम्भव है कि इस समस्या पर धीमे ही काबू पा लिया जाए।

(6) सोवियत रूस में तीव्र औद्योगीकरण के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा यहाँ के राजनीतिक ढाँचे की है जो आत्यधिक केन्द्रीयकरण प्रस्तुत करता है। योजना, उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्य नीतियों आदि का निर्धारण सर्वोच्च-स्तर पर होता है और यदि किसी विनियोग-नीति या तकनीकी तरीके में कोई परिवर्तन करना होता है तो भी निम्न अधिकारियों की उच्च अधिकारियों और उन उच्च अधिकारियों को अपने से उच्चतर अधिकारियों का मुख देखना पड़ता है। सर्वोच्च स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों प्रायः इतने व्यस्त रहते हैं कि वे समय पर आवश्यक निर्णय नहीं ले पाते। प्रायः निर्णय तभी किया जाता है जब नीति के नुकसान उसे अनिवार्य बना दें। इस प्रकार की स्थिति तीव्र औद्योगीकरण के मार्ग में एक गम्भीर बाधा है। फ़ैक्ट्रियाँ, कारखाने तथा अन्य उत्पादक मस्यान उत्पादन और उससे सम्बन्धित मामलों में प्रायः असमन्वित की स्थिति में पड़े रहते हैं क्योंकि वे आवश्यकता और समयानुसार अपनी निर्णायक बुद्धि से काम नहीं ले सकते।

(7) सोवियत रूस में प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में 'अभियान-बाजी' (Campaignology) का बोलबाला है। औद्योगिक क्षेत्र में यह दिनावटी अभियान-बाजी कई बार फलदायक सिद्ध नहीं होती। पहले तो उत्पादन ऊँचे-ऊँचे लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाते हैं और तब उन्हें पूरा करने के लिए इतने जोर-शोर से अभियान कार्यक्रम चलाया जाता है कि उत्पादन कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों व

व्यवस्थापकों को यह भय पैदा हो जाता है कि यदि लक्ष्यों को पूरा नहीं किया गया तो जनता के सामने उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, साम्यवादी दल का कोप-भाजन बनना पड़ेगा और प्रशासकीय अधिकारियों की नाराजगी का फल खलना पड़ेगा। नतीजा यह होता है कि वे किसी न किसी प्रकार उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं और इस प्रक्रिया में औद्योगिक असंतुलन पैदा हो जाता है तथा व्यवस्था भी फँस जाती है। जब चाह कर भी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता रहती है तो उच्च स्तरीय अधिकारी अपनी भूल को सुधारने के लिए एक नया अभियान (Campaign) शुरू कर देते हैं। पहले वी असफलताओं का दोष इधर-उधर सरकार और कई बार निरापराधियों के माथे डाल कर शीर्षस्थ अधिकारी अपनी नई अभियान-बाजी से जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लक्ष्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पुनः दिखाया जाता है और पिछली प्राप्तियों का भी विवरण प्रकट नहीं किया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाहियों से नियोजन और औद्योगिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा होती है। यह स्थिति प्रायः तीव्र औद्योगीकरण के मार्ग में सहायक नहीं होती।

(8) सोवियत रूस के तीव्र और ठोस औद्योगीकरण के मार्ग में लम्बी छलांगें (Big leaps) और औद्योगिक उत्पादन-वृद्धि के 'युद्ध कार्यक्रमों' ने भी बाधा पहुँचाई है। एक ही साथ आर्थिक छलांगें लगा कर बढ़ जाने की महत्वाकांक्षा में प्रायः नियोजन गड़बड़ा जाता है, साधनों का आवंटन कुशलतापूर्वक नहीं हो पाता, उत्पादन-वृद्धि की भोक में बाजार माँग पर समुचित ध्यान नहीं रह पाता और बड़ी मात्रा में साधन व शक्ति की बरबादी हो जाती है। प्रगति की रफ्तार में सन्तुलन नहीं रह पाता और एक क्षेत्र का पिछड़ापन अन्य क्षेत्रों पर भी प्रभाव डालता है या कुल मिलाकर उनकी उपलब्धियों के महत्त्व को कम कर देता है। यदि इतनी ही अवधि में विवेकपूर्ण ढंग से औद्योगिक नीतियों का संचालन किया जाए तो बिना साधनों और शक्ति की भारी बरबादी किए निर्धारित लक्ष्यों को अधिक अच्छे ढंग से प्राप्त किया जा सकता है।

(9) तीव्र औद्योगीकरण के लिए यह आवश्यक है कि देश में यातायात साधनों का जाल बिछा हो और औद्योगिक क्षेत्र देश भर में विकेंद्रित हो ताकि उन्हें स्थानीय लाभों से वंचित न होना पड़े। सोवियत रूस में रेलों का विस्तार अभी भी पर्याप्त नहीं है और उसमें काफी विस्तार की गुंजाइश है। औद्योगिक क्षेत्रों का विकेंद्रीकरण बहुत कुछ यातायात के साधनों के विकास पर ही निर्भर करता है। यद्यपि इस समस्या को काफी हद तक हल कर लिया गया है, किन्तु अमेरिका आदि देशों का मुकाबला करने के लिए अभी इस क्षेत्र में बहुत गुंजाइश बाकी है।

(10) सोवियत रूस औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में अभी तक तेजी से इसलिए भी प्रगति कर सका था क्योंकि सोवियत जनता से जीवन-स्तर की कीमत पर और उनकी इच्छा के बलिदान पर केवल पूँजीगत माल के उत्पादन पर ही अधिकाधिक जोर दिया जाता रहा था। लेकिन अब, विशेषकर 1960 के बाद से ही,

सोवियत जनता की बढ़ती हुई माँगों का दमन करना पहले जैसा आसान नहीं रहा। 1928 में पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने के बाद से ही सोवियत जनता ने जो भारी कठिनाइयाँ सही हैं और जो अमृतपूर्व बन्दिदान किए हैं, उनके बाद अब यह स्वाभाविक है कि वह समुचित उपभोक्ता वस्तुओं और सुविधाओं की माँग करे। अतः अब सोवियत सरकार को खाद्यान्न पदार्थों, गृह निर्माण और विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की ओर काफी ध्यान देना होगा जिससे तीव्र औद्योगीकरण की गति का मन्द होना सम्भव है।

(11) तीव्र औद्योगीकरण के मार्ग में एक बड़ी समस्या कुशल श्रम-शक्ति की कमी की है। पहले सोवियत सरकार ने लाखों बेकार लोगों को देहाती क्षेत्रों में बुला कर औद्योगिक उत्पादन में लगा दिया था। किन्तु अब देहाती क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों का औद्योगीकरण क्षेत्रों में आगमन आसान नहीं रहा है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में जिस प्रकार तकनीकी और कुशल श्रम की बहुलता है, वैसी बहुलता रूस में आज भी नहीं है। यह स्थिति भी औद्योगीकरण की दिशा में बाधक है। यद्यपि रूस श्रम-उत्पादकता में वृद्धि करके समस्या पर बाजू पाने की चेष्टा कर रहा है, किन्तु श्रम शक्ति की कमी केवल इसी से नहीं मिटाई जा सकती।

(12) कृषि क्षेत्र का पिछड़ापन सोवियत औद्योगीकरण पर अपना कुप्रभाव डालता रहा है। इस की अधिकांश योजनाएँ कृषि क्षेत्र में असफलता की बहानी हैं। अतः जब तक कृषि क्षेत्र पूर्णतः उन्नत नहीं होगा तब तक कच्चे माल के अभाव में और आर्थिक व्यवस्था में असंतुलन आदि के कारण तीव्र औद्योगीकरण का मार्ग समस्याग्रस्त ही रहेगा। इसी तथ्य को समझते हुए सोवियत रूस में विगत कुछ वर्षों से कृषि क्षेत्र पर काफी बल दिया जाने लगा है। 8वीं योजना की भी सचये बड़ी विशेषता यही है कि उपभोग वस्तुओं की उत्पादन दर में वृद्धि के साथ ही साथ कृषि उद्योग और उत्पादन मापनों की उत्पादन दरों में तेजी से वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया।

(13) सोवियत रूस में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति की समस्या भी इसी औद्योगीकरण की गति को धीमा कर सकती है।

अन्त में, यही कहना होगा कि तीव्र औद्योगीकरण के मार्ग में सोवियत रूस के समक्ष काफी विन्त समस्याएँ मौजूद हैं जिनका यथाशीघ्र निवारण करना होगा। रूस दिशा में आवश्यक कदम और सुधार कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों से निरन्तर उठाए जा रहे हैं। पर भारी कठिनाई यह है कि विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक कारणों से एक साथ सुधार कार्यक्रम लागू नहीं किए जाने और टुकड़ों-टुकड़ों में इन्हें लागू करने से औद्योगिक व आर्थिक क्षेत्र में असंतुलन तथा ग्रन्थ गडबडी की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर भी रूस ने जो औद्योगिक प्रगति की है वह कम आश्चर्यजनक नहीं है। विभिन्न बाधाओं, क्षतियाँ और भूलों के बावजूद सोवियत रूस औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और यदि वह तीव्र औद्योगीकरण के अपने भावी लक्ष्यों में सफल हो जाए तो विदोष आश्चर्य की बात नहीं होगी।

(14) यद्यपि सोवियत संघ न उत्पादन की वैज्ञानिक और तकनीकी विधियों में अनेक सुधार किए हैं तथापि अमेरिका और कई पश्चात्य देशों की तुलना में इस क्षेत्र में वह अभी पीछे है।

(15) संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेट ब्रिटेन आदि की तुलना में सोवियत संघ ने आज भी अत्यधिक कौशल प्राविधिक श्रमिकों का अभाव है। यद्यपि प्रशिक्षण व्यवस्था का यथा शक्ति प्रसार किया जा रहा है लेकिन वह अभी अपेक्षित स्तर और आकार की नहीं है। रूसी श्रमिकों की उत्पादन क्षमता अमेरिका के औद्योगिक श्रमिकों की क्षमता की तुलना में बहुत कम है।

(16) रूस का औद्योगिक क्षेत्र कच्चे माल के अभाव से पीड़ित है। औद्योगीकरण में पूरक और सहयोगी उद्योगों का आनुपातिक विकास नहीं हो पाया है और सीमेंट कागज गैस लोहा ईटो आदि की पूर्ति लक्ष्यों से कम रही है। उत्पादन विधियों के निम्न प्राविधिक स्तर कुशल प्राविधिक श्रमिकों की कमी श्रमिकों की उत्पादन क्षमता में कमी आदि के कारण रूस की औद्योगिक उत्पादन लागत अधिक है अतः रूसी औद्योगिक वस्तुएँ विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा में पिछड़ जाती हैं।

ऊपर जा समस्याएँ गिनायी गई हैं उनमें से अधिकांश ऐसी हैं जिनका रूस को प्रारम्भिक कुछ दशकों में भारी सामना करना पड़ा था किन्तु बाद में उनका बहुत कुछ समाधान कर लिया गया यद्यपि वे पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं। कुछ समस्याएँ ऐसी हैं जिनसे रूस आज भी काफी पीड़ित है। किन्तु सोवियत जनता अपनी कमियाँ को मिटाने के लिए कृत सकल्प है। तीव्र औद्योगीकरण के माग में उपस्थित विवट समस्याओं से रूस सफलतापूर्वक जूझ रहा है और वर्तमान दशक में सुधार के कार्यक्रमों का काफी अच्छा नतीजा निकला है। भारी कठिनाई यह है कि विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक कारणों से एक साथ सुधार कार्यक्रम लागू नहीं किये जाते और टुकड़ा टुकड़ों में इन्हें लागू करने से औद्योगिक व आर्थिक क्षेत्र में असंतुलन तथा अर्थ गडबडी की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर भी रूस ने जो औद्योगिक प्रगति की है वह कम आश्चर्यजनक नहीं है। विभिन्न बाधाओं क्षतियाँ और भूला के बावजूद सोवियत रूस औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है और यदि वह तीव्र औद्योगीकरण के अपने भावी लक्ष्यों में सफल हो जाए तो विशेष आश्चर्य की बात नहीं होगी।

6

नियोजन और आर्थिक विकास में आधुनिक प्रवृत्तियाँ

(Recent Trends in Planning & Economic Development)

हम देख चुके हैं कि सोवियत रूस वर्तमान आर्थिक उन्नति के शिखर पर नियोजन के मार्ग द्वारा पहुँचा है। पिछले लगभग 50 वर्षों में नियोजन-पद्धति द्वारा रूस ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में आश्चर्यजनक उन्नति की है। प्रो० डॉ० के शब्दों में 'ययेच्छाचारिता' (Laissez Faire) की परिस्थितियों के विपरीत एक राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के पक्ष-प्रदर्शन और नियंत्रण में पिछड़े हुए देश (रूस) ने व्यापक और अद्वितीय औद्योगिक प्रगति की है। इससे वह एशिया के देशों के भावी औद्योगिक विकास के लिए आदर्श बन गया है। सोवियत प्रशासकों ने नियोजन पद्धति का वैज्ञानिक ज्ञान अपनी मूल्य, त्रुटियों और उनकी खोज तथा उनके सुधार के उपाय से प्राप्त किया है। रूस में आज विकसित नियोजन पद्धति का जो आधुनिक स्वरूप दिखाई देता है वह "परीक्षण के प्रयोग-सुधार" का प्रतिफल है। इसलिए सोवियत नियोजन विधि "शक्त्यात्मक (Dynamic) है, न कि स्थिर (Static)।" परिवर्तनशील परिस्थितियों और विचारों के अनुरूप ढलने की उततमे क्षमता है। वह समय के साथ आज तक अपने में आवश्यक सुधार करता रहा है। सचीलेपन और अनुशासन की अपनी विशेषता को उतने कभी नहीं त्यागा। इसी नियोजन पद्धति के बल पर रूस आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर होता रहा है और 1980 तक सप्तर के समृद्धतम राष्ट्र तयुक्त राज्य अमेरिका से भी आगे निकल जाने या उसके समकक्ष हो जाने का दावा करने लगा है।

सोवियत रूस के आर्थिक विकास की रूपरेखा का चित्रण पिछले विभिन्न अध्यायों में किया जा चुका है। हम यह भी देख चुके हैं कि सन् 1928 के बाद निरन्तर पंचवर्षीय, सप्तवर्षीय आदि योजनाओं को अपनाकर रूस ने इतनी आर्थिक प्रगति की। प्रस्तुत अध्याय में हमारा विषय-क्षेत्र केवल यह देखने तक सीमित है कि सोवियत नियोजन और आर्थिक विकास की आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं। पर इन प्रवृत्तियों का अध्ययन करते समय यह तर्क नहीं भूलना चाहिए कि सोवियत रूस की सभी आर्थिक-राजनीतिक गतिविधियाँ "लौह आवरण" (Iron Curtain) में

छड़ी रहती है। इसीलिए प्रायः निश्चित रूप से यह कहना कठिन होता है कि सोवियत रूस में नियोजन व आर्थिक विकास की दृष्टि किन प्रवृत्तियों को पूरी तरह अपनाया जा चुका है अथवा किन्हीं अपनाने का पूर्ण निश्चय कर लिया गया है अथवा उनके सम्भव में मतभेदों की खाई कितनी चौड़ी है।

नियोजन के क्षेत्र में आधुनिक प्रवृत्तियाँ

(Recent Trends in Planning)

सोवियत रूस में आर्थिक नियोजन का यथार्थ रूप से सूत्रपात 1928 की प्रथम पञ्चवर्षीय योजना से हुआ था। इसके बाद रूस निरन्तर भटके खाते हुए भी, तेजी से आर्थिक विकास करता गया और आज वह विश्व के सर्वांग रूपेण उन्नत राष्ट्र समुदाय अमेरिका को भी चुनौती देने लगा है। नियोजन और आर्थिक विकास की इस यात्रा में समय-समय पर रूस ने अनेक परिवर्तन किए हैं। इस सम्पूर्ण अवधि में नई नई प्रवृत्तियाँ पनपती रही हैं। फिर भी आधुनिक प्रवृत्तियों का लेखा जोखा मुख्यतः रूस के सर्वोच्च माथल स्टालिन की मार्च, 1953 में मृत्यु के बाद से माना जाना चाहिए। स्टालिन की मृत्यु से रूस में एक ऐसे युग की समाप्ति हुई जो आज की अपेक्षा बहुत कम उदारवादी था। स्टालिन के युग में यह समझ न था कि रूस नियोजन और आर्थिक विकास के क्षेत्र में पूँजीवादी तत्वों तथा प्रवृत्तियों का प्रोत्साहन देता तथा केन्द्रीकरण को क्रमशः शिथिल करते हुए विकेन्द्रीकरण की तरफ अग्रसर होता। पर स्टालिन की मृत्यु के उपरान्त रूस में जो नया नेतृत्व कायम हुआ, उसने क्रमशः अनेक नई प्रवृत्तियों का मार्ग प्रशस्त किया।

1956-57 तक नियोजन प्रणाली

सोवियत रूस में नियोजन के क्षेत्र में जो आधुनिक प्रवृत्तियाँ दिखाई दी हैं, उनका वर्णन करने से पूर्व यह उपयुक्त होगा कि पृष्ठभूमि के रूप में 1956-57 तक की नियोजन प्रणाली को संक्षेप में जान लिया जाए।

रूस में नियोजन का वास्तविक सूत्रपात 1928 की प्रथम पञ्चवर्षीय योजना से हुआ। योजनाओं के निर्माण और निर्देशन का भार गोसप्लान आयोग तथा वेसेन्खा (सर्वोच्च आर्थिक परिषद्) पर था। 1929-30 में गोसप्लान और वेसेन्खा के संगठन में आवश्यक परिवर्तन किए गए। सन् 1932 में वेसेन्खा का अस्तित्व समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर तीन औद्योगिक लोक मंत्रालय (People's Commissariats or Ministries) स्थापित किए गए जिनकी सत्या 1946-48 में 32 तक पहुँच गई। स्टालिन की मृत्यु के बाद उनकी सख्या घटा कर 11 कर दी गई, लेकिन 1953 से यह सत्या पुनः बढ़ने लगी और 1956 में 31 हो गई।

गोसप्लान के कार्यों और उत्तरदायित्वों में भी समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन किए जाते रहे। सन् 1948-49 में गोसप्लान का पुनर्संगठन किया गया और उसका नाम राजकीय योजना आयोग (State Planning Commission) के स्थान पर राजकीय योजना समिति (State Planning Committee) रख दिया

गया। गोसप्लान का सामग्री वितरण और विभाजन का कार्य हटा लिया गया। उसके टेक्निकल एव केन्द्रीय सांख्यिकीय विभाग को भी उससे पृथक् कर दिया गया। इन विभागों को मंत्रिपरिषद् की समितियों के रूप में संगठित किया गया। स्पष्ट है कि गोसप्लान की स्टालिन की मृत्यु तक यही स्थिति बनी रही। स्टालिन के बाद गोसप्लान का फिर पुनर्संगठन हुआ और उसे वे सब अधिकार वापिस सौंप दिए गए जो 1948 से पहले उसके पास थे। केवल सांख्यिकीय विभाग मंत्रिपरिषद् का प्रग बना रहा।

बू कि गोसप्लान अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं के निर्माण का उत्तरदायित्व ठीक ढंग से नहीं निभा पाया था, अतः अब उसके दो भाग कर दिए गए—(1) राजकीय योजना आयोग अथवा गोसप्लान, तथा (ii) राजकीय आर्थिक आयोग (State Economic Commission)। योजना आयोग पर दीर्घकालीन योजनाएँ बनाने का और आर्थिक आयोग पर चालू योजनाएँ (Current Planning) बनाने का भार डाला गया। तकनीकी विभाग भी एक पृथक् संस्था के रूप में कार्य करने लगा। इसके प्रमुख कार्य नवीन तकनीकी विधियों को खोजने और प्रयोग में लाने का रखा गया। सन् 1956 तक योजना सम्बन्धी समस्त कार्य इन आयोगों व समितियों द्वारा किए जाते रहे, किन्तु सन् 1956 के अन्त में योजना प्रणाली की सम्पूर्ण विधि में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिए गए। दिसम्बर, 1956 में अर्थात् छठी पंचवर्षीय योजना (1956-60) के प्रारम्भिक वर्ष में ही गोसप्लान का एक बार फिर पुनर्संगठन किया गया। गोसप्लान के कर्मचारियों में परिवर्तन किए गए। सभी आर्थिक मन्त्रालयों को आर्थिक परिषदों के अधीन बना दिया गया। इन मन्त्रालयों के आर्थिक मन्त्री परिषद् के उप सभासद नियुक्त किए गए। पर इन सब परिवर्तनों के बावजूद गोसप्लान की आधारभूत स्थिति पहले ही के समान बनी रही। केवल चालू आर्थिक मामले ही आर्थिक परिषद् के साथ में केन्द्रित हुए।

खुश्चेव युग और बाद में लाए गए परिवर्तन

सन् 1957 में तत्कालीन प्रधान मन्त्री श्री खुश्चेव ने नियोजन प्रणाली में कुछ क्रान्तिकारी सुधारों का सूत्रपात किया और तब से ही सोवियत नियोजन पद्धति तथा संगठन अनेक नए-नए परिवर्तनों से गुजर रहा है। संक्षेप में ये इस प्रकार हैं—

(1) उद्योगों के प्रचण्ड में केन्द्रीकरण तथा बृहती व तिहरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समाप्त करके प्रत्येक क्षेत्र में समन्वित आर्थिक प्रशासन कायम करने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी है।

(2) आर्थिक विकेन्द्रीकरण की नीति का सूत्रपात हुआ। इसी दृष्टि से 1957 के बाद इस को 194 आर्थिक प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया तथा प्रत्येक इकाई के लिए एक आर्थिक परिषद् की स्थापना की गई। 1960 में कानून पास करके गणराज्यों में आर्थिक परिषद कायम की गई ताकि ये विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में समन्वय स्थापित कर सकें। इस नए परिवर्तन के फलस्वरूप सोवियत अर्थ व्यवस्था के केन्द्रीय प्रशासन के साथ-साथ गणराज्यों को भी पर्याप्त अवसर मिल

गया कि वे अपनी स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए आगे आ सकें। आर्थिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में यह एक अच्छा कदम था।

(3) उपरोक्त व्यवस्था में पुनः परिवर्तन लाया गया। सन् 1964 में ख्रुश्चेव के सत्ता-च्युत हो जाने के बाद नए प्रधान मंत्री कोसिगिन ने क्षेत्रीय आर्थिक परिपदों को समाप्त कर दिया। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं समझी गई कि पृथक्-पृथक् क्षेत्रीय आर्थिक प्रशासन को प्रोत्साहन मिले। अब पुनः केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति ने बल पकड़ा। धीरे-धीरे केन्द्रीय आर्थिक मंत्रालयों की स्थापना कर दी गई और आर्थिक प्रशासन का उत्तरदायित्व पुनः उन पर आ पड़ा। 1957 में क्षेत्रीय आर्थिक परिपदों को और 1960 में गणराज्यों की आर्थिक परिपदों को जो अधिकार दिए गए थे वे पुनः केन्द्रीय आर्थिक मंत्रालयों को सौंप दिए गए। इस प्रकार आर्थिक प्रशासन में विकेन्द्रीकरण की जो प्रवृत्ति और व्यवस्था घर करने लगी थी उसे समाप्त उद्योगों के प्रशासन में केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को फिर से थोप दिया गया।

(4) अब यह भय पैदा हुआ कि कहीं पृथक् औद्योगिक और उत्पादक इकाइयों के प्रबन्धकों की प्रबन्ध सम्बन्धी स्वतन्त्रता केन्द्रीकृत नौकरशाही की शिकार न बन जाए अतः स्थानीय प्रबन्ध और उत्पादन में विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था प्रारम्भ की गई। कोसिगिन प्रशासन ने एक ओर तो आर्थिक-प्रशासन का केन्द्रीयकरण किया और दूसरी ओर विभिन्न उपक्रमों के स्थानीय प्रबन्ध में विकेन्द्रीकरण का समावेश किया। इस प्रकार नियोजन के क्षेत्र में केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्तियाँ साथ-साथ प्रकट हुईं। स्थानीय प्रबन्धकों को अधिक स्वतन्त्रता दी गई ताकि वे उनके अधीन इकाइयों के प्रबन्ध में कुशलता ला सकें।

(5) उपक्रमों की सफलता के निर्धारण की कसौटी भी बदल दी गई। अब प्रवृत्ति यह रही कि उपक्रमों की सफलता का निर्धारण उत्पादन के आकार के साथ-साथ उत्पादित माल की श्रेष्ठ किस्म और लाभदायकता के आधार पर किया जाए। स्पष्ट है कि जहाँ पहले प्रवृत्ति उत्पादन के आकार को प्रधानता देने की थी वहाँ अब माल की किस्म और लाभदायकता पर भी बल दिया जाने लगा।

(6) स्थानीय प्रबन्ध और उत्पादन में विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति में अधिक जोर पकड़ा। स्थानीय प्रबन्धकों को इस बारे में अधिक स्वतन्त्रता दी जाने लगी कि वे उत्पादन की प्रक्रिया में तकनीकी सुधार लाएँ कच्चे माल की प्राप्ति का प्रयत्न करें, मजदूरों के वेतनमानों का निर्धारण करें और उपभोक्ताओं की माँग के अनुरूप माल उत्पादित करें अथवा माल के प्रकारों में परिवर्तन लाएँ।

(7) विकेन्द्रीकरण की उपरोक्त प्रवृत्ति को अप्रतिबन्धित नहीं छोड़ा गया। इस बात की पूर्ण व्यवस्था की गई कि विनियोगों के आकार के निर्धारण साधनों के आवंटन एवं उत्पादन के आकार-प्रकार के निर्धारण से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों और कार्यों का दायित्व केन्द्रीय मंत्रालयों पर ही रहे। वर्तमान प्रवृत्ति भी पूरी तरह यही है कि पूर्ण केन्द्रीकरण के दिग्दर्शन में आंशिक विकेन्द्रीकरण लाने का प्रयास किया जा रहा है।

(8) वर्तमान नियोजन पद्धति की एक अन्य पद्धति प्रत्येक उपक्रम के सामग्री संचालन की है। जो उपक्रम घाटे में चलते हों उन्हें सरकारी अनुदान प्रायः नहीं दिया जाता। इस यथार्थवादी प्रकृति ने सतोपजनक परिणाम निकले हैं क्योंकि औद्योगिक उत्पादन इकाइयों से लाभ बढ़े हैं। प्रत्येक औद्योगिक इकाई को यह प्रेरणा मिली है कि अपने विकास के लिए आवश्यक पूँजी स्वयं अपने साधनों से जुटाए तथा लाभ का एक अंश राष्ट्रीय विकास की दृष्टि से सरकार को दे। पहले आर्थिक नियोजन तथा सरकारी खर्च के लिए आवश्यक साधनों को प्रायः अप्रत्यक्ष करों द्वारा जुटाया जाना की प्रवृत्ति थी जबकि अब यह है कि सरकारी उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ से आर्थिक विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए।

स्पष्ट है कि सोवियत नियोजन से स्टालिन युग की तुलना में अनेक नए परिवर्तन हुए हैं और नई-नई प्रवृत्तियाँ पनपती जा रही हैं। वर्तमान नियोजन विश्व की तेजी से बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियों के अधिक अनुकूल है।

नियोजन के क्षेत्र में योजना आयोग के स्वल्प और ढाँचे को भी बदल दिया गया है। यद्यपि योजना आयोग की संरचना का नियोजन की प्रवृत्तियाँ से विशेष सम्बन्ध नहीं है तथापि प्रसंगवश उसे जान लेना अधिक उपयोगी होगा। इस में वर्तमान आर्थिक नियोजन का संगठन दो स्तरों पर है—केन्द्रीय स्तर पर एवं राज्य स्तर पर। दोनों स्तरों पर संगठन की रूपरेखा यह है—

(क) केन्द्रीय स्तर पर पाठों का प्रेस

(At Central Level) सर्वोच्च सोवियत

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल

(i) केन्द्रीय योजना आयोग (Gosplan)

(ii) सर्वोच्च आर्थिक परिषद्
(Supreme Economic Council)

(iii) विशिष्ट राज्य समिति
(Special State Committee)

(iv) केन्द्रीय सांख्यिकी मण्डल
(Central Statistical Board)

(ख) राज्य स्तर पर

(At State Level) राज्य मन्त्रिमण्डल

(i) राज्य योजना आयोग
(Union Republican Gosplans)

(ii) क्षेत्रीय नियोजन समितियाँ
(Regional Planning Committees)

(iii) जिला नियोजन समितियाँ
(District Planning Committees)

- (iv) विभागीय समितियाँ
(Departmental Committees)
- (v) औद्योगिक इकाइयों के नियोजन विभाग
(Planning Departments of Industrial Units)
- (vi) फार्म प्रबन्ध मण्डल
(Farm Management Boards)
- (vii) श्रम सघ समितियाँ
(Trade Union Committees)

सोवियत रूस एक सघात्मक राज्य है जिसमें सघ और राज्य के कार्य लेख निर्धारित हैं। राज्य में दो प्रकार की योजनाएँ (Projects) कार्यान्वित की जाती हैं—केन्द्रीय योजना एवं राज्य सरकार की योजनाएँ। राज्य सरकार द्वारा जो अपनी योजनाएँ बनाई जाती हैं वे न केवल अपनी आवश्यकताओं और साधनों के अनुरूप होती हैं बल्कि केन्द्र के सामान्य निर्देशन का भी उनमें पूरा ध्यान रखा जाता है। देश के विभिन्न राज्यों की जो योजनाएँ होती हैं उन्हें गोसप्लान आवश्यक परिवर्तनों सहित एकीकृत करता है और इस तरह सम्पूर्ण देश के लिए एक योजना बनाता है।

योजना निर्माण में चार सगठन बड़े प्रमुख भाग लेते हैं—गोसप्लान, विशिष्ट राज्य समिति, केन्द्रीय सार्विकीय मण्डल और सर्वोच्च आर्थिक परिषद्। गोसप्लान तो देश की प्रमुख योजना सस्था है। साम्यवादी दल की केन्द्रीय समिति और सरकार द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों व उद्देश्यों का पूरा ध्यान रखते हुए सम्पूर्ण देश के लिए यह आयोग (Commission) योजना तैयार करता है। योजना पद्धति में सुधार करना भी इसका प्रमुख कार्य है। राज्यों के जो योजना आयोग होते हैं वे इसी केन्द्रीय योजना आयोग के अधीन होते हैं। विशिष्ट राज्य समितियाँ उन आवश्यक वस्तुओं और प्राविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं जिनकी योजनाओं को क्रियान्वित करने की जरूरत होती है। केन्द्रीय सार्विकीय मण्डल का प्रधान कार्य सही आकड़े एकत्र करना है। देश के विभिन्न भागों में स्थित कम्प्यूटर सेन्टर्स (Computer Centres) इसी मण्डल के अधीनस्थ कार्य करते हैं। इस मण्डल का कार्य इतना व्यवस्थित होता है कि किसी भी प्रमुख वस्तु के उत्पादन के सम्बन्ध में आवश्यक आंकड़े यह तीन दिन की अल्पावधि में ही प्राप्त कर सकता है। सर्वोच्च आर्थिक परिषद् केन्द्रीय सरकार के निर्देशन में कार्य करती है। इसके प्रमुख कार्य केन्द्रीय योजना आयोग (Gosplan) राजकीय भवन समिति (USSR State Building Committee Gosstore) तथा राज्य परिषद् के कार्यों में समन्वय स्थापित करना है। सर्वोच्च आर्थिक परिषद् ही उद्योगों व निर्माण कार्यों, विभिन्न मन्त्रालयों, समितियों आदि को आवश्यक निर्देशन देती है। रूस में इस परिषद् का लगभग वही स्थान है जो भारत में राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद् का है। यह भी स्मरणीय है कि सोवियत रूस में नियोजनों के निर्माण में श्रम-सघ भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

सोवियत संघ में योजना की अवधारणा और कार्यान्वयन (1978)

सोवियत संघ में योजना की अवधारणा क्या है और योजना कार्यान्वयन कैसे होता है इस पर 1978 के उत्तराखंड में एक सोवियत लेखक ने जो प्रकाश डाला है, उससे हमें नवीनतम जानकारी प्राप्त होती है—

“योजना सोवियत जीवन पद्धति का अभिन्न अंग बन गयी है और योजनाएँ सामान्यतया हमारी आकांक्षाओं और उपलब्धियों का मापदण्ड है। हमारा आर्थिक विकास स्वतः स्फूर्त नहीं है। हम निश्चित रूप से जानते हैं कि कहाँ और कब, क्या चीज बनायी जाने वाली अथवा पुनर्निर्मित की जाने वाली है। हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 1978 में कितने जोड़े जूते, कितनी डिब्बा बन्द खाद्य सामग्रियाँ या ट्रांजिस्टरो का उत्पादन होगा, उन्हें कहाँ बेचा जायेगा और उनके दाम क्या होंगे। हम योजना के अनुसार काम करते हैं।

नियोजन की प्रक्रिया सम्भलने के लिए आइए हम सब इस बात का विश्लेषण करें कि 1977 की योजना किस प्रकार तैयार की गयी थी।

सबसे पहले इसकी जरूरत होती है कि निर्यातिक, मुख्य लक्ष्य निर्धारित किये जायें। उदाहरण के लिए बिजली को लें। 1977 के लिए इसका लक्ष्य था 11 खरब 60 अरब किलोवाट घटा। इसलिए यह पता लगाना आवश्यक था कि मौजूदा बिजलीघर किस हद तक उत्पादन की अपनी क्षमताएँ बढ़ा सकते हैं और उस वर्ष कितने नये बिजलीघर चालू करने की आवश्यकता होगी और सही-सही उनकी जरूरत किस समय होगी, बिजलीघरों को ईंधन और फालतू पुर्जों की अवाधित रूप में पूर्ति सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में स्थिति क्या थी और क्या उपभोक्ता बड़े हुए उत्पादित माल का उपयोग करने की स्थिति में थे? हर सैंक्टर में इसी प्रकार की गणनाएँ की जाती हैं और वे सर्वदा सरल नहीं होती।

इस विराट प्रक्रिया के पहले चरण का प्रारम्भ प्रत्येक आर्थिक सैंक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों से होता है जो आवश्यक तलमीना लगाने के बाद पेश किया जाता है, इसके बाद सैंक्टर से सम्बन्धित नियोजन निकाय रिपोर्ट करते हैं कि यदि उन सैंक्टरों को अमुक पदार्थ, अमुक परिमाण में मिले तो सम्बन्धित सैंक्टर अमुक मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं।

दूसरे चरण में प्रारम्भिक तलमीनो का और विभिन्न सैंक्टरों द्वारा प्रस्तुत योजना के प्रारूपों का तालमेल बिठाया जाता है। आर्थिक शब्दावली में इसे मुख्य उत्पादों के उत्पादन और उपभोग में सतुलन करना कहते हैं। सारणी के एक पक्ष में अपेक्षित सासाधनों को सूचीबद्ध किया जाता है और अनुरोधों को दूसरे में। अनुरोध हमेशा अपेक्षित सासाधनों से अधिक होता है, इसलिए सन्तुलन आवश्यक है। अर्थ-शास्त्रों उन अवसरों की तलाश करने में अत्यधिक परिश्रम करते हैं, गिनते कि उत्पादन बढ़ाया जाये ताकि निर्माण सामग्रियों और उपकरणों के आवश्यक सासाधन, और निस्सन्देह, वित्त के स्रोत खोजे जायें। स्वभावतया वे कुछ बचाने के अवसर के लिए अपनी आँखें खुली रखते हैं।

इस प्रकार के कई सन्तुलन तैयार किये जाते हैं। आइए हम कुछ मुख्य सन्तुलनों पर विचार करें :

(1) निर्माण कार्य का परिमाण और आवश्यक निर्माण सामग्रियों और उपकरणों की उपलब्धता।

(2) इंजीनियरी उद्योग के लिए लक्ष्य और धातु की उपलब्धता।

(3) कृषि उत्पादन के लक्ष्य और मशीनों, फालतू पुर्जों, उर्वरकों की पूर्ति, परिवहन सुविधाओं आदि की पूर्ति।

(4) उपभोक्ता मालों और कच्चे माल विधायित करने वाली इमारतों, रेफ्रिजरेटर, पैकेजिंग आदि की उपलब्धता।

(5) देश के ईंधन और ऊर्जा सन्तुलन यानी तेल, गैस, कोयला, पीट, शैल और जलाने की लकड़ी आदि का उत्पादन और उपभोग।

(6) श्रम शक्ति की कुल आवश्यकता सहित, श्रम शक्ति का सन्तुलन, वर्तमान आपूर्ति मांग और उस मांग की पूर्ति की सम्भावनाएँ।

(7) एक ओर मालभाड़े के कुल परिमाण सहित मालभाड़े का शेष तथा दूसरी ओर, माल की दूलाई कितनी दूर तक करनी है और इस बात का बँटवारा कि कितने माल की दूलाई रेलगाड़ी से होगी, कितनी मोटर परिवहन से, कितनी जहाजरानी से तथा कितनी हवाई जहाज से।

(8) नकद आमदनी और खर्च का सन्तुलन जिसमें एक ओर कुल वेतन, बोनस, पेन्शन, छात्रवृत्तियाँ, नकद इनाम आदि शामिल हैं तथा दूसरी ओर उनका खर्च और इस बात का तखमीना कि कितने परिमाण में किस किसके माल का उत्पादन करना है।

अब हम कुछ बातों पर विस्तार से विचार कर सकते हैं।

विजली का सन्तुलन तैयार करने में हमें यह निश्चित करना पड़ा कि विजली पैदा करने वाली कितनी इकाइयाँ कब चालू की जायें। इस प्रश्न का उत्तर दसवीं पंचवर्षीय योजना में मिला, क्योंकि वार्षिक योजना पंचवर्षीय योजना का अंग होती है। इसमें शक नहीं कि अमली रूप देते समय योजना में परिवर्तन किये जाते हैं परन्तु वार्षिक योजनाएँ कामोवेश पंचवर्षीय योजनाओं के ढाँचे के अन्तर्गत ही अमल में लायी जाती हैं।

योजना के हर मुद्दे का क्षेत्रीय पक्ष होता है। उदाहरणार्थ, देश के लिए ईंधन और ऊर्जा सन्तुलन सतोपजनक है परन्तु सोवियत संघ के यूरोपीय भाग के लिए यह थोड़ा अनिश्चित लगता है। इसलिए विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसी समस्याएँ योजना के कई हिस्सों में उठ सकती हैं। ऐसे मामलों में नये अप्रयुक्त ससाधनों की खोज की जाती है। कुछ लक्ष्यों का परित्याग कर दिया जाता है, दूसरे लक्ष्यों को घटा दिया जाता है परन्तु कामोवेश ऐसा सन्तुलन वायम करना आवश्यक है जो यह सुनिश्चित करे कि बुनियादी संकटों, क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों को सर्वोपरि

अक्सर मुहैया हो ताकि वे योजना की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्याओं को सरल ढंग से सुलझा सकें।

सोवियत योजनाओं में उत्पादन की सुनिश्चित परिधि बतलाना आवश्यक है क्योंकि उद्योगों को विशिष्ट आकार के बेलिन लोहे की जरूरत होती है और मांग के अनुसार उपभोक्ता मालों का उत्पादन करना होता है। उदाहरण के लिए, धुलाई की फासतू मशीनों रोबेदार टोपियों की मांग पूरी नहीं कर सकती हैं। इसलिए खुदरा व्यापार का न केवल मुद्रागत मूल्य महत्त्वपूर्ण है, बल्कि माल की किस्में भी।

अब उपभोक्ता माल का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम से सम्बद्ध आर्थिक समस्याओं के बारे में कुछ बातें कहना जरूरी है।

पहली बात, उद्योगों के लिए दीर्घकालीन आधार पर विज्ञान सम्मेलन लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। यह इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि नवीन से नवीनतर प्रतिष्ठान उपभोक्ता मालों का द्विनिर्माण करने लगे हैं। यदि प्रत्येक फैक्टरी यह स्वयं निर्धारित करेगी कि वह किस प्रकार के माल का उत्पादन करेगी तो हो सकता है कि कुछ मालों से बाजार पट जाये और दूसरे मालों की कमी रहे।

किन्तु मांग का पूर्वानुमान करना आवश्यक है जिससे कि लक्ष्य सही-सही निर्धारित किये जा सकें, जबकि मांग का अनेक अज्ञात कारणों के साथ समीकरण होता है।

विभिन्न शोध संस्थानों में हजारों विशेषज्ञ इन समस्याओं का अध्ययन करते हैं और उनका विशदीकरण करने के लिए नियमितताओं की तलाश करते हैं।

योजना तैयार करने में एक समस्या यह है कि क्या उपलब्ध पूंजी के मुकाबले मांग सन्तुलित करने में वचन बरना सम्भव है। इस आशय की गणना उपभोग के मानदण्डों पर आधारित है। स्वभावतया, इन मानदण्डों की अक्सर समीक्षा की जाती है क्योंकि वर्तमान वैज्ञानिक और प्राविधिक क्रान्ति वृद्धिरोध और इजाजत नहीं देती क्योंकि कल तक जो मानदण्ड था, वह हो सकता है कि आज पिछड़ा हुआ बन जाये।

भाइए अब हम लोग इस बात पर विचार करें जिसकी चर्चा प्रारम्भ में की गई थी। योजना तैयार करने में जुटे हजारों विशेषज्ञों को—जो राज्य योजना समिति से लेकर जिला योजना निहाय तक, मन्त्रालय के नियोजन विभाग से लेकर कारखाने के नियोजन विभाग तक इस काम में लगे हुए हैं, अपने तख्तीनों के प्रारम्भिक परिणामों का समग्रतया विद्वाना होता है। यह एक पेचीदा काम है क्योंकि प्रत्येक विशेषज्ञ अवश्यम्भावी रूप में अपने प्रतिष्ठान या विभाग की सीमाओं से घिरा होता है और इसलिए समस्या को अपने दृष्टिबिन्दु से देखता है। नियोजन निकायों के समक्ष बहुत अधिक अनुरोध, प्रस्ताव और विचार पेश किए जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि वार्षिक योजना का केवल एक प्रारूप तैयार करने में राज्य आयोजना

समिति को लगभग सत्तर लाख दस्तावेजों को विधायित करना पड़ता है जिनमें लगभग पाँच करोड़ सूचकांक होते हैं और केवल एक प्रारूप पर्याप्त नहीं होता।

अन्ततः जब सामञ्जस्य स्थापित करने का सारा काम समाप्त हो चुका होता है तथा उत्पादन परिमाण और मुख्य उपभोग कारकों को निर्धारित किया जा चुका होता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि देश के बजट पर नजर डाली जाये। क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं, प्रतिरक्षा और प्रशासन, विज्ञान और कलाओं के लिए पर्याप्त धन होगा? क्या नये निर्माण कार्यक्रम के लिए पर्याप्त कोष होंगे? क्या पर्याप्त सुरक्षित कोष होंगे?

अक्सर यह होता है कि बजट की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना में एक और संशोधन करना वाध्यनीय हो जाता है। उदाहरणार्थ अनुमान यह इंगित कर सकते हैं कि परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और नये औजार लगाने के फलस्वरूप हनके उद्योग अतिरिक्त मुनाफ़ा देंगे। ऐसे मामलों में कीमतें घटाने की सम्भावनाओं पर विचार किया जाता है। इसके लिए कई विस्म के मालों का अध्ययन करना जरूरी हो जाता है ताकि उन मालों की शिनास्त हो सके जिनकी कीमतें घटानी हैं।

जब सरकार योजना को स्वीकार कर लेती है तब उसे सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत के समस्त पक्ष किया जाता है। सिर्फ वही उसे स्वीकार कर सकती है और इस प्रकार इसे कानून का रूप प्रदान करती है। योजना में साथ ही साथ संघ जनतंत्रों के लिए भी सर्वाङ्गीण लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। जनतंत्रों के योजना निकाय सर्वाङ्गीण लक्ष्य निश्चित करते हैं और अपनी अपनी योजना के प्रारूपों की स्वीकृति के लिए अपनी अपनी सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशन में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद स्वायत्तशासी जनतंत्रों की सर्वोच्च सोवियतें अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन उद्योगों और प्रतिष्ठानों के लिए योजनाओं पर विचार-विमर्श करती हैं। आंचलिक, प्रादेशिक, जिला, नगर और ग्रामीण सोवियतें अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में प्रतिष्ठानों के लिए योजनाओं पर विचार-विमर्श करती हैं। मन्त्रालय अपनी ओर से सम्पूर्ण योजना के अनुसार अपने प्रतिष्ठानों के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं।

इस प्रकार सोवियत योजनाएँ अन्वयणों से लेकर कार्यान्वयन तक एक लम्बी और पेशीदा प्रक्रिया से गुजरती हैं, परन्तु यह एक सुनिश्चित मार्ग है। ये योजनाएँ यथार्थवादी हैं। यह बात इस तथ्य से सिद्ध होती है कि उनकी पूर्ति और यहाँ तक कि अतिपूर्ति नियमित रूप से सम्पूर्ण उद्योग करते हैं।

सोवियत जनता योजना के लक्ष्यों को सृजनात्मक, उत्साहपूर्ण और कुछ आलोचनात्मक रूप में देखती है। "आलोचनात्मक रूप" का तात्पर्य यह है कि वह अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को अपनी प्रतिभाओं और क्षमताओं के दृष्टिबिन्दु से देखती है। जो अर्थशास्त्री जितना समझते हैं उससे वही अधिक और विविधतापूर्ण हैं।

अभिनवीकरण, खोज और प्रविधि तथा उत्पादन तकनीक का उम्नयन वह अक्षय सुरक्षित शक्ति है जो बहुत दूद तक हमारी योजनाओं का समय से पहले पूरा किया जाना सुनिश्चित करती है। इस बात को पहले से नियोजित नहीं किया जा सकता। उदाहरणार्थ, केवल किनेव में विगत पंचवर्षीय योजनावधि (1971-75) में फ़ैक्टरी के कर्मियों और दफ्तर के कर्मचारियों इजीनियरों और तकनीशियनों ने संकटोद्धारो अभिनवीकरण प्रस्ताव किये जिनसे 29 करोड़ 30 लाख रूबल की बचत हुई।

10वीं पंचवर्षीय योजना के निरूपण के साथ ही 1990 तक के लिए दीर्घकालिक राष्ट्रीय आर्थिक विकास योजना भी तैयार की गयी।

ऐसी योजना की आवश्यकता का कारण यह तथ्य है कि नवीनतम प्रविधि का उपयोग करने वाले पेशीदा समुच्चयों के विकास के लिए समस्या को दीर्घकालिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।

निश्चित ही अनेक आर्थिक और प्राविधिक समस्याओं को सुलभाने के लिए दीर्घकालिक और विरतृत परिधि वाली योजनाओं की अपेक्षा मध्यम स्तर की योजनाओं की आवश्यकता होती है, परन्तु इसमें भी शक नहीं कि अधिकाधिक, विशेष रूप से पेशीदा समस्याओं पर दीर्घकालिक परिश्रेष्य में विचार करने की आवश्यकता है जो विभिन्न आर्थिक सेक्टरों और क्षेत्रों के बीच बढ़ते हुए एकीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं।

दर्जनों, यहाँ तक कि संकटो शोध कार्य करने वाले और आर्थिक निकायों के परिश्रमपूर्ण प्रयास के बाद विशिष्ट आंकः तैयार किये जा रहे हैं।

विज्ञान अकादमी और राज्य नियोजन समिति के शोध सत्यानों, मन्त्रालयों और प्रमुख प्रतिष्ठानों के सस्थानों और प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और उच्चतर अध्ययन के अन्य सस्थानों के सहायों और प्रयोगशालाओं ने सामान्य योजना पर काम शुरू कर दिया है।

इस समय योजना विशेषज्ञ नियोजन तकनीक, सूचकाँकों और मानदण्डों से अपने को सम्बन्धित कर रहे हैं, इसके बाद वे गणना करने में जुट जायेंगे। और इसमें शक नहीं कि इन सभी कार्यों के साथ-साथ बहुत भी होनी रहेगी, विचार-विमर्श हीमें और इष्टतम उत्तरो की खोज की जायेगी।”

रूस की पहली से दसवीं योजना के इतिहास और विकास पर

रूसी लेखक पावेल शारिकोव का लेख

सोवियत सघ की पहली से दसवीं योजना तक के इतिहास और विकास को नवम्बर 1978 की “सोवियत भूमि” में रूसी लेखक पावेल शारिकोव ने अपने एक लेख में संक्षिप्त प्रकाश डाला है। यह लेख न केवल रूसी योजनाओं के इतिहास और विकास पर प्रकाश डालता है बल्कि रूसी नियोजन के अनेक महत्त्वपूर्ण पहलुओं को भी स्पष्ट करता है—

पंचवर्षीय योजना (रूसी संक्षिप्त रूप “प्यातिलेत्स्वा”) की शब्दावली सोवियत

मृत की है। आज से 50 वर्ष पहले जब हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना का नियामकपत्र शुरू किया था, यह शब्दावली हमारे शब्द-भण्डार का तथा हमारी जीवन-पद्धति का एक अभिन्न अंग बन गयी। तब से एक के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजनाएं नियामकपत्र की गयीं। उन्होंने ऐसे ऊर्ध्वगामी कदमों का काम किया जिन्हें जरिये देश आज के शिखरों पर आरूढ़ हो सका है।

सोवियत अर्थतंत्र एक नियोजित अर्थतंत्र है। योजना के आधार पर विकास का वस्तुगत नियम है। जीवन ने दिखा दिया है कि केवल विज्ञान-प्राचरित नियोजन से ही आर्थिक विकास की स्थायी और गतिशील दर सुनिश्चित करना, एक अत्यधिक सजटिल राष्ट्रीय अर्थतंत्र में सतृप्त बनाये रखना, विशेषीकरण, और सहयोग संगठित करना तथा सामाजिक कर्तव्यों को हल करना—समाजवाद के अन्तर्गत सम्पूर्ण सामाजिक उत्पादन अन्तिम विश्लेषण में इन कर्तव्यों के अधीन हो जाते हैं—सम्भव है।

सोवियत संघ में तीन प्रकार की योजनाओं ने जो जीवन से उद्भूत तथा सम्पुष्ट हुई थी, रूप ग्रहण किया। दीर्घकालीन योजनाएं, मध्यकालिक (पंचवर्षीय) योजनाएं, तथा चालू (एक वर्षीय) योजनाएं। दीर्घकालिक योजनाओं की अवधि 10 से 15 वर्ष तक ही होती है। ये विकास की सामान्य दिशा की रूपरेखा बनाती हैं तथा उसका सकेत करती हैं, और मध्यकालिक योजनाओं की अपेक्षा कम निदेशात्मक और विस्तृत स्वरूप वाली होती हैं। दीर्घकालिक योजना का उद्देश्य है ठीक समय पर हमारे कर्तव्यों के स्वरूप और पैमाने को निर्धारित करना तथा उनकी पूर्ति पर हमारे समस्त प्रयासों को केन्द्रित करना, सम्भावित समस्याओं और कठिनाइयों को अधिक स्पष्टता से समझना, एक खास पंचवर्षीय अवधि से भी आगे जाने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं को तैयार करने तथा उन्हें पूरा करने के काम को सुयम बनाना।

लेनिन की गोएलरो योजना (रूस के विद्युतीकरण की राजकीय योजना का रूसी संक्षिप्त रूप) दीर्घकालिक नियोजन का श्रेष्ठ उदाहरण थी। यह 1920 में तैयार की गयी जो 10 से 15 वर्षों की अवधि के लिए अभिकल्पित थी। उसमें ऐसे 30 विजलीघरों के निर्माण का प्रावधान था जो उस समय के लिए बहुत बड़े विजलीघर थे।

पंचवर्षीय योजनाएं दीर्घकालिक योजनाओं में प्रारंभिक रूप में शामिल कर ली जाती हैं जो उनके नार्पों को विवक्षित करती और ठोस बनाती हैं। पांच साल की अवधि बड़े-बड़े प्रतिष्ठान और इमारतें बनाने के लिए, नये खनिज भण्डारों का विकास करने के लिए, बहुत से प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान-कार्य पूरा करने के लिए, उत्पादन में वैज्ञानिक उपलब्धियां लागू करने के लिए तथा महत्वपूर्ण सामाजिक कर्तव्यों का हल निकालने के लिए सर्वथा पर्याप्त होती है। अनुभव ने प्रमाणित कर दिया है कि पंचवर्षीय योजना अवधि दीर्घकालिक योजनाओं के लिए इष्टतम अवधि है।

पहली पंचवर्षीय योजना ने ही यह दिखा दिया कि इस अपेक्षाकृत अल्प समय में भी बहुत काम किया जा सकता है। केवल चार वर्षों और तीन महीने में ही (अर्थात् उतने ही समय में जितना कि सोवियत जनता को प्रथम पंचवर्षीय योजना को पूरा करने में लगा) 1500 बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्मित कर लिये गये तथा नये उद्योग ट्रैक्टर, मोटरगाड़ी, मशीन औजार, विमान, अल्युमीनियम, अत्यधिक ठोस मिश्रधातु, ऊँचे इर्ज के हस्पताल और अन्य-खड कर लिये गये। उसी अवधि में गोएस्वरो योजना में परिकल्पित विजलीघरों के निर्माण के कार्यक्रम की क्षतिपूर्ति भी गयी।

बाद की प्रत्येक पंचवर्षीय योजना पूर्ववर्ती प्रथम पंचवर्षीय योजना के मार्ग से आगे बढ़ी तथा उसने देश की आर्थिक क्षमता को सुदृढ़ किया और जनता में मंगल कल्याण को ऊँचा उठाया। किन्तु इनमें से प्रत्येक योजना की अपनी अद्वितीय सामाजिक विशेषताएँ थीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि (1933-37) देश के इतिहास में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की अवधि बन गयी, जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना (1946-50), प्रथम युद्धोत्तर पंचवर्षीय योजना ने युद्ध में तबाह हुए अर्थिक के पुनर्निर्माण का कार्य पूरा किया। यह उल्लेखनीय है कि हिटलरी आक्रान्ताओं ने सोवियत अर्थतंत्र को अपार क्षति पहुँचाई थी। उन्होंने 1,710 नगरों और वस्तियों को ध्वस्त कर दिया और लूट लिया, 70,000 गाँवों को जलाने दिया तथा लगभग 32,000 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को तहस-नहस कर दिया। किसी भी युद्ध में किसी भी राज्य को इतनी क्षति और विनाश नहीं हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के वर्षों में देश ने न केवल युद्धपूर्व के अपने औद्योगिक उत्पादन के स्तर को हासिल कर लिया बल्कि उससे भी आगे बढ़ गया। 6200 नये और पुनर्निर्मित समय, खानों विजलीघर और अन्य प्रतिष्ठान चालू किये गये।

छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1956-60) की विशेषता यह थी कि उसमें बहुत से नये उन्नत उद्योगों जैसे—औजार-निर्माण, रेडियो इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स और इसी तरह के अन्य उद्योगों का जन्म हुआ।

एक निश्चित अवधि तक औद्योगिक विस्तार की दृष्टि से देश आगे बढ़ा। सोवियत जनता पिछले वर्षों का लेखा-जोखा देश के औद्योगिक मानचित्र पर प्रकट हुए नये प्रतिष्ठानों की सख्या के जरिए लेती थी। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अपने प्रतीक थे। उदाहरणार्थ मॉस्को-गोर्कॉव धातुकर्म कारखाना तथा स्नीपर पनविजली घर (स्नेप्रोगेस) पहली पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रतीक थे। लियोनिद ब्रॉन्नेव ने अपनी पुस्तक पुनर्जन्म में एक छात्रों के निम्नलिखित शब्दों को उद्धृत किया है जो स्नीपर पनविजलीघर के महत्त्व को अत्यन्त सानदार ढंग से व्यक्त करते हैं, "हमारे देश में स्नेप्रोगेस का वही स्थान है जो साहित्य में एशिकन का, संगीत में त्वाइकोव्स्की का है। वोल्गा, घनारा और येनिसेई पर कितने ही विराट केन्द्र बनी न खड़े हो जाएँ, उनसे सोवियत विद्युत् इंजीनियरी के पितृमह का गौरव कम नहीं हो सकता।"

आइये, फिर प्रतीको की बात करें। यह कहा जा सकता है कि तोयलियाती मोटरगाड़ी कारखाना और येनिसेई पनविज्ञानीघर (क्रास्नोदास्क में) हमें नवीं पंचवर्षीय योजना के वर्षों की याद दिलाते हैं, जबकि वाम या एटममाश (यह वोल्गोग्राद में बन रहा है) वर्तमान दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अभिन्न रूप से जुड़े हैं।

यद्यपि औद्योगिक निर्माण जारी है और हम देखते हैं कि देश एक विशाल निर्माण-स्फल बना हुआ है किन्तु जोर अब निश्चित रूप से दूसरी चीजों पर दिया जाने लगा है। अधिकांशतः ध्यान सामाजिक उत्पादन वी कार्यकुशलता पर, पिछले वर्षों में अस्तित्व में आई उत्पादन क्षमताओं के अधिकतम उपयोग पर तथा उनके आधुनिकीकरण और तकनीकी पुनर्नवीकरण पर केन्द्रित किया जा रहा है। नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (1971-75) के दौरान अर्थतन्त्र की सभी शाखाओं में उद्योग में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा से तीव्र मोड़ आया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस बुनियादी लाइन को मजबूत तथा और विकसित किया जा रहा है। यह संयोग की बात नहीं है कि इसे कार्यकुशलता और गुण की पंचवर्षीय अवधि कहा जाता है। पहले ही की भाँति आठवें दशक में लाखों कार्यरत प्रतिष्ठानों को मानो नये सिरे से बनाया गया। करीब पाँच वर्षों में उद्योग की 40 प्रतिशत उत्पादन क्षमताओं का पुनर्नवीकरण किया गया।

कृषि भी पंचवर्षीय चरणों में विकसित होती जा रही है। यह सर्वविदित है कि सोवियत संघ की प्राकृतिक हालाँतें आदर्श कदापि नहीं हैं। देश की कृषि योग्य जमीन का काफी बड़ा भाग ऐसे इलाके में है जहाँ बराबर सूखा पड़ा रहता है या ऐसे इलाके में है जहाँ अधिक आर्द्रता रहती है। इसके बावजूद सोवियत सत्ताकाल में कृषि उत्पादन में साढ़े तीन गुनी वृद्धि हुई। इस सम्बन्ध में कृषि को मशीनों से सज्जित करने की निर्णायक भूमिका रही। जहाँ 1928 में पूरे देश में केवल दो अनाज कम्बाइन हार्वेस्टर थे, वहीं आज सामूहिक और राज्य फार्मों में कार्यरत ऐसी मशीनों की संख्या 6,92,000 है। कृषि उत्पादन बढ़ाने में अद्भुती धरती क विकास का तथा मिट्टी को सुधारने, खेती में रसायनों का प्रयोग शुरू करने और कृषि औद्योगिक समुच्चयों की स्थापना करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए कदमों का बहुत बड़ा महत्त्व था।

सोवियत संघ में केवल आर्थिक विकास की ही योजना नहीं बनाई जाती। विज्ञान भी योजना के आधार पर विकसित होता है। निम्नलिखित सुविदित तथ्यों का स्मरण कीजिए—सोवियत संघ अन्तरिक्ष उड़ान का श्रगुवा बना, गहरे समुद्र में नौबालन के इतिहास में वह सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पहुँचा, वह परमाणु के शान्तिपूर्ण उपयोग में अन्य देशों में प्रथम रहा है। जीवविज्ञान, इलेक्ट्रानिक्स तथा विज्ञान की बहुत-सी अन्य शाखाओं में सोवियत वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुई है। भू उपग्रह और अन्तरिक्षयानों का प्रक्षेपण, बाह्य अन्तरिक्ष में मानव की यात्रा तथा ऐसे अन्य कारनामों हाथ पर हाथ धरे सम्पन्न नहीं

किए जा सकते। उनके लिए लम्बी और योजनाबद्ध तैयारी की, अनेक बड़े-बड़े निकायो और सामूहिकों के प्रयासों के समन्वय की आवश्यकता होती है और यह सब विज्ञान-आधारित योजना के बिना हाँसिल नहीं किया जा सकता।

सुम्बक की सूई उतर की ओर झुकी रहती है, सोवियत पंचवर्षीय योजनाएँ मनुष्य की ओर सोवियत जनता के मंगल-कल्याण की सतत समुन्नति उसका मुख्य लक्ष्य था और आज भी है।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी 24वीं और 25वीं कांग्रेस में एक सर्वांगीण कार्यक्रम तैयार किया जिसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा रहा है। नवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में नये सामाजिक कार्यों के लिए जितनी धनराशि आवंटित की गई वह पिछली दो पंचवर्षीय योजना अवधियों में आवंटित की गई धनराशि के बराबर थी। सामाजिक उद्देश्यों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में त्रिपुल धनराशि आवंटित की गई है। इतना अधिक आवस निमाण पहले कभी नहीं हुआ था।

हर साल एक करोड़ दस लाख लोग नये फ़ैक्टो में प्रवेश करते हैं। जहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा में सुरुआत हुआ, वहीं आज देश में हमारे नौजवानों के लिए सार्वत्रिक अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा लागू की जा रही है।

योजना केवल राजकीय नियोजन निकाय ही नहीं बनाते बल्कि—और सर्वोपरि मजदूरों, किसानों और बुद्धिजीवियों के व्यापक हिस्से भी बनाते हैं। सामूहिक और राज्य फार्मों की योजनाओं तथा प्रतिष्ठानों की योजनाओं पर सम्बद्ध कार्य सामूहिक विचार-विमर्श करते हैं जिन्हें नये संविधान में उत्पादन तथा सामाजिक विकास के नियोजन में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। पाठकों ने सम्भवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सोवियत राजकीय योजनाओं को आज आर्थिक सामाजिक विकास की योजनाएँ कहा जाता है। यह बुनियादी परिवर्तन लेनिनवाद, स्टावरोपोल और अन्य नगरों के, जहाँ प्रतिष्ठानों के सामाजिक विकास कार्यक्रम तैयार किए गए थे, बहुत से औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कार्य सामूहिकों की पहल कदमी पर लागू किया गया। यह एक महत्वपूर्ण नवीन प्रक्रिया सिद्ध हुई तथा अब इस प्रक्रिया को राष्ट्रव्यापी पैमाने पर लागू किया जा रहा है।

हम कह सकते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएँ देश के जीवन का, प्रत्येक सोवियत नागरिक के जीवन का एक अभिन्न तत्व, उसके व्यक्तिगत मामलों का एक अभिन्न तत्व बन गई है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अवधि के अपने अमवीर थे, वे लोग जिन्होंने अन्य लोगों के लिए उदाहरण का काम किया।

एक के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजनाएँ सोवियत जनता के वारे में, उनकी राजनीतिक नेता कम्युनिस्ट पार्टी के वारे में, उसके उस शान्तिपूर्ण धर्म के वारे में

जो देश को बदल रहा है, साधारण मेहनतकश लोगों के जीवन को और अधिक समृद्ध बना रहा है। एक ही पुस्तक के विभिन्न अध्यायों के समान हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों की उपलब्धियाँ

1979 के लिए सोवियत सभ की योजना और वजट के प्रारूप पर विचार-विमर्श करने के लिए नवम्बर, 1978 में माल्को में सोवियत सभ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के अधिवेशन में श्री ब्रेझ्नेव ने दसवीं पंचवर्षीय योजना (1976-80) के तीन वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा—

“हमें यह कहने का पूरा अधिकार है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के तीन वर्षों में देश ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास की सभी दिशाओं में आभासीत प्रगति की है।”

लियोनिद ब्रेझ्नेव ने कहा कि दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि (1976-80) के तीन वर्षों में उत्पादन पिछली पंचवर्षीय योजना अवधि के तीन वर्षों के उत्पादन की तुलना में 450 अरब रुबल अधिक बढ़ गया। निश्चित उत्पादन परिसम्पत्ति 195 अरब रुबल बढ़ी। यह वदोतारी देश में सातवें दशक के प्रारम्भिक वर्षों की सम्पूर्ण निश्चित उत्पादन परिसम्पत्ति के लगभग बराबर ही है।

कृषि में प्रति मजदूर विद्युत शक्ति का अनुपात एक चौथाई से अधिक बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को 23 करोड़ टन से अधिक खनिज उर्वरकों की सप्लाई की गई। सिंचित अथवा जल-निष्कासित किए जाने के बाद उपलब्ध भूमि 45 लाख हेक्टर बढ़ गई। इस वर्ष अनाज की उपज 23 करोड़ 50 लाख टन थी और कपास का उत्पादन 80 लाख टन से भी अधिक हुआ।

इन तीन वर्षों के लिए जनसंख्या की नकद आमदनी बढ़ाने के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति पूर्ण रूप से उपलब्ध कर ली गई। दुबरा ध्यागार की विक्री 30 अरब रुबल से भी अधिक बढ़ गई। पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रारम्भ से लगभग 65 लाख नये फ्लेट लोगों को प्रदान किए गए। पाँच लाख की आबादी वाले नगर के लिए पर्याप्त आवास-व्यवस्था अब सोवियत सभ में एक महीने से भी कम समय में निर्मित की जाती है।

लियोनिद ब्रेझ्नेव ने कहा कि 1979 के लिए योजना “दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में एक और महत्वपूर्ण कड़ी बन जाएगी।” उन्होंने कहा कि नई योजना के अनुसार उपभोक्ता माल के समेत औद्योगिक एवं कृषि-उत्पादन की वदोतारी दरें भी बढ़ाई जाएंगी। श्रम-उत्पादकता और तेज गति से बढ़ेंगी। राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में विषम अनुपात को कम किए जाने के लिए कई बदन उठाने की परिकल्पना है, पूँजीनिवेश के वितरण में ई धन, ऊर्जा, धातुकर्म और परिवहन जैसी प्रमुख शाखाओं में विकास पर बल दिया गया है। देश की प्रतिरक्षा क्षमताओं को उचित स्तर पर कायम रखा जा रहा है।

शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सस्कृति तथा अन्य अनुत्पादक शाखाओं में काम करने वाले लोगों के वेतनों एवं पगारों को बढ़ाने का लक्ष्य 1979 में पूरा कर लिया

जाएगा। इसके फलस्वरूप 3 करोड़ से अधिक लोगों की आय दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बढ़ जाएगी। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध के सेवा निवृत्त व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभों की व्यवस्था की जाएगी।

आर्थिक विकास के क्षेत्र में आधुनिक प्रवृत्तियाँ (Recent Trends in Economic Development)

आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी स्टालिन की मृत्यु के बाद से ही नई-नई प्रवृत्तियाँ पनप रही हैं। स्टालिन के बाद के रूसी नेतृत्व का उद्देश्य मुरायात यह रहा है कि रूसी जनता को पूर्वपिछा अधिक उपभोक्ता-वस्तुएँ सुलभ की जाएँ, कृषि क्षेत्र में रूस की असफलता समाप्त हो जाए और औद्योगिक क्षेत्र में रूस कृषि क्षेत्र के साथ समन्वय करते हुए पूरी तेजी से आगे बढ़े। वर्तमान लक्ष्य यह है कि हर दृष्टि से रूस इतना समुन्नत होता जाए कि 1980 तक वह आर्थिक विकास के क्षेत्र में अमेरिका से आगे निकल जाए। हमें देखना चाहिए कि सोवियत सभ के आर्थिक विकास के क्षेत्र में आधुनिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं—

(1) राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय—सोवियत सभ अपनी राष्ट्रीय आय और प्रतिव्यक्ति आय में निरन्तर वृद्धि के लिए प्रयत्नशील है। रूस में आर्थिक विकास की दर सामान्यतः 7 प्रतिशत वार्षिक है। 1965 में रूस की राष्ट्रीय आय लगभग 840 अरब रूबल थी जो बढ़ कर 1977 में लगभग 1,420 अरब रूबल हो गयी है। 1965 में प्रतिव्यक्ति आय लगभग 182 रूबल थी जो 1977 में बढ़ कर 210 रूबल हो गयी।

(2) पूँजी विनियोग में तीव्र वृद्धि—सोवियत सभ अर्थ-व्यवस्था के कृषि, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों में पूँजी विनियोग तेजी से बढ़ रहा है। 1965-70 की अवधि में औद्योगिक क्षेत्र में पूँजी विनियोग लगभग 350 अरब रूबल था जो 1975 तक लगभग 500 अरब रूबल तक पहुँच गया। कृषि क्षेत्र में नवी योजना में लगभग 180 अरब रूबल विनियोग होने की आशा है अन्य विनियोगों में भी 30 से 40 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है।

(3) कृषि उत्पादन में वृद्धि पर बल—स्टालिन की मृत्यु के बाद से ही कृषि उत्पादन में वृद्धि पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। कृषि योग्य भूमि और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सामूहिक खेतों का पुनर्गठन किया जा रहा है। कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि का अनुमान इसी से लगता है कि 1956-60 में कृषि उत्पादन का औसत मूल्य लगभग 47 अरब रूबल था जो बढ़ कर 1970 में 70 अरब रूबल और 1975 में लगभग 117 अरब रूबल तक पहुँच गया। सामूहिक फर्मों की संख्या 1949 में लगभग 2.5 लाख से घट कर 1977 तक केवल 23 हजार रह गयी। कृषि का अत्यधिक आधुनिकीकरण और मशीनीकरण किया जा रहा है। 1975 के अन्त तक कृषकों के पास लगभग सात लाख ट्रैक्टर थे जो 1980 तक लगभग उन्नीस लाख हो जाने की आशा है। इसी प्रकार 1975 के अन्त तक कृषि क्षेत्र में ग्यान्हु लाख ट्रैक्टर थे जो 1980 तक 13 से 14 लाख हो जाने की

सम्भावना है। 1975 के अन्त तक कृषि में लगभग 17 अरब रूबल मूल्य के उपकरण थे जो 1980 तक लगभग 23 अरब रूबल मूल्य के हो जाने की आशा है। इस भारी प्रगति के बावजूद सोवियत सघ कृषि क्षेत्र में अभी अमेरिका से बहुत पिछड़ा हुआ है।

(4) उपभोक्ता वस्तुओं व विभिन्न सुविधाओं का विकास—सोवियत आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण आधुनिक प्रवृत्ति यह है कि उपभोक्ता-वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया जाए। सोवियत जनता लम्बे अर्से से इतना त्यागपूर्ण जीवन बिता चुकी है कि अब जीवन स्तर उन्नत करने और उपभोक्ता वस्तुओं की खपत बढ़ाने का मार्ग अपनाना सोवियत प्रशासकों के लिए अनिवार्य हो गया है। अतः अब इस विषय पर अधिकाधिक सोचा जाने लगा है और कुछ अमल भी किया जाने लगा है कि माँग के अनुरूप विभिन्न प्रकार का भाल उत्पादित किया जाए। अब प्रवृत्ति उपभोक्ता उद्योगों के विकास पर पर्याप्त जोर देने की है। 1966 में 1980 तक की नवीन पंचवर्षीय योजनाओं में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि जनसाधारण के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा किया जाए तथा इस दृष्टि से भोजन, वस्त्र, मकान और सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यक्रम की सुविधाओं का अधिकतम विकास किया जाए। 20 वर्षीय योजना में भी, जो विभिन्न भागों में 1980 तक समाप्त होगी, उपभोक्ता उद्योगों पर बहुत अधिक बल दिया गया है। वर्तमान प्रवृत्ति यही है कि पूँजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि की दूरी में अधिकाधिक लाया जाए।

(5) औद्योगिक क्षेत्र का तीव्र विकास और विस्तार—स्टालिन काल में रूसी सरकार ने पूँजीगत उद्योगों के विकास और विस्तार में उपभोग उद्योगों की उपेक्षा की थी किन्तु अब औद्योगिक क्षेत्र का सन्तुलित विकास किया जा रहा है। रूस का औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ रहा है। रूस का लक्ष्य है कि औद्योगिक उत्पादन में 1980 तक वह अमेरिका के समकक्ष हो जाए। औद्योगिक क्षेत्र को रूस ने कितनी प्रमुखता दी है इसका अनुमान कुछ उत्पादनों में लगाया जा सकता है। 1960 में कोयले का उत्पादन 51 करोड़ टन हुआ था जबकि 1977 में लगभग 720 करोड़ टन का हुआ। इस्पात का उत्पादन 1960 में लगभग 65 मिलियन टन से बढ़कर 1977 में लगभग 150 मिलियन टन हो गया। खनिज तेल के उत्पादन में तो आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। 1960 में लगभग 150 मिलियन टन खनिज तेल उत्पादित किया गया था जो बढ़कर 1977 में लगभग 5 हजार मिलियन टन हो गया। दसवी योजना (1976-80) की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में 35 से 40 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य है। जहाँ 1970 में लगभग 375 अरब रूबल का औद्योगिक उत्पादन हुआ था वहाँ 1975 में लगभग 520 अरब रूबल का हुआ और 1976 से 1980 की अवधि में लक्ष्य लगभग 960 से 725 अरब रूबल प्रतिवर्ष का है।

(6) रासायनिक उद्योगों का विकास—आर्थिक विकास के क्षेत्र में एक

आधुनिक प्रवृत्ति रासायनिक उद्योगों का विकास करने की है। यह विकास विभिन्न वस्तुओं के बदले प्लास्टिक के प्रयोग, कृषि के लिए खाद उत्पादन में वृद्धि, वस्त्र उद्योग के क्षेत्र प्राकृतिक रेशे के बदले कृत्रिम रेशे के प्रयोग आदि के लिए आवश्यक समझा गया और भी अनेक सरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। उदाहरणार्थ विगत कुछ वर्षों से ईंधन के रूप में कोयले के बदले तेल और गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इंजीनियरिंग उद्योग में स्वचालित यंत्रों के प्रयोग को बढ़ाया जा रहा है और पूर्वी साइबेरिया तथा कजाखस्तान जैसे सुदूर प्रदेशों के साधनों के विकास पर अधिकारिक बल दिया जा रहा है।

(7) एकीकृत उद्योग क्षेत्रों का निर्माण—भाज के युग की एक आर्थिक प्रवृत्ति एकीकृत उद्योग क्षेत्रों का निर्माण है। 9वीं पंचवर्षीय योजना (1971-1975) के निर्देशों में 'साम्ने सहायक उद्योगों, अन्य इंजीनियरी सुविधाओं और संचार साधनों पर आधारित कारखानों के निर्माण के चलन को बढ़ाने' की सिफारिश की गई है। आजकल देश के विभिन्न भागों में ऐसे दो सौ से अधिक उद्योग क्षेत्रों का निर्माण चल रहा है। इससे होने वाले लाभ कितनी से छिपे नहीं हैं, इस प्रकार से बनाए जाने वाले कारखानों की लागत में तीन से पांच प्रतिशत निर्माण कार्य में प्रयुक्त क्षेत्रफल में दस प्रतिशत और संचार साधनों की लम्बाई में बीस प्रतिशत की कमी होती है।

(8) प्राथमिक कौशल और श्रम उत्पादकता बढ़ाने का प्रयत्न—पिछले दशक से सोवियत संघ में निरन्तर प्रयास किया जा रहा है कि श्रम का प्राथमिक कौशल और इसकी उत्पादन क्षमता बढ़े। इसके लिए प्रशिक्षण व्यवस्था का प्रसार किया जा रहा है और कुछ क्षेत्रों में पाश्चात्य वैज्ञानिक एवं तकनीकी विधियों का आश्रय लिया जाने लगा।

(9) यातायात एवं संचार क्षेत्र का सुधार और विस्तार—सोवियत संघ में यातायात और संचार क्षेत्र में तीव्र तकनीकी सुधार और प्रसार का एक आन्दोलन या चलाया जा रहा है। 1958 में विद्युत तथा डीजल से चलने वाला रेलों का प्रतिशत लगभग 26 था जो 1965 तक ही 85 प्रतिशत हो गया और 1979 तक इसमें आशातीत विस्तार हुआ है। यातायात क्षेत्रों में क्षमता और लोचशीलता को बढ़ाया जा रहा है, फलस्वरूप हुलाई क्षमता में लगभग 35 से 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। रूस में यातायात और संचार साधनों का जाल विद्यमान जा रहा है, फिर भी देश की परिपक्व और संचार क्षमता कभी अमेरिका के समक्ष नहीं है। दसवीं योजना (1976-1980) का लक्ष्य लगभग तीन हजार किलोमीटर मय रेल मार्गों और 65,000 किलोमीटर नए सड़कों के निर्माण का है।

(10) व्यापार एवं वाणिज्य में तीव्र वृद्धि—सोवियत संघ का आन्तरिक और विदेशी व्यापार तीव्र गति से बढ़ा है। विदेशी व्यापार पर सरकार का एकाधिकार है। स्टालिन काल तक विदेशी व्यापार पर सरकार का कठोर नियंत्रण रहा किन्तु बाद में छुड़के युग में विदेशी व्यापार नीति नियंत्रणों को शिथिल बनाया गया और प्रवृत्ति निरन्तर विकासमान है। आज सोवियत संघ के भी से भी

अधिक राष्ट्रों से व्यापारिक समझौते हैं। 1971-75 की अवधि में ही विदेशी व्यापार में लगभग 30 से 35 प्रतिशत वृद्धि हुई। विदेशी व्यापार की एक मुख्य प्रवृत्ति समाजवादी राष्ट्रों के साथ व्यापार विस्तार में पहल करने और साथ ही विकासशील राष्ट्रों से विदेशी व्यापार को प्राथमिकता देने की है। विदेशी व्यापार की वृद्धि के लिए साम्राज्य सरकार औद्योगिक सगठनों तथा सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापारिक मेलों में भाग लेती है। वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि एक ओर तो उत्पादन को परिभारणात्मक रूप में बढ़ाया जाए और दूसरे गुणात्मक पक्ष पर भी अधिकाधिक ध्यान दिया जाए ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रूसी माल की प्रतिष्ठा बढ़े। 1980 तक विदेशी व्यापार में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि हो जाने की आशा है।

(11) साम्यवादी समाज की स्थापना की ओर तेजी—नियोजन और आर्थिक विकास की वर्तमान प्रवृत्ति यह है कि रूस में शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण साम्यवादी समाज की स्थापना कर दी जाए। इसी दृष्टि से वर्तमान बीस वर्षीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आर्थिक विकास और नियोजन की इस प्रवृत्ति के दर्शन हमें ख़ुश्चैब के इन शब्दों से होते हैं जो उन्होंने अक्टूबर 1961 में साम्यवादी दल की 22वीं कांग्रेस में कहे थे—“अपने सघर्ष में श्रमिक और उनके साम्यवादी दल को तीन ऐतिहासिक अवस्थाओं से गुजरना है—शोपको के शासन को बलपूर्वक समाप्त करके, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना, समाजवाद का निर्माण एवं साम्यवादी समाज की स्थापना। हमारा साम्यवादी दल और हमारे देशवासी इनमें से दो अवस्थाओं को पार कर चुके हैं। 20वीं शताब्दी साम्यवादियों की अपूर्व विजय की शताब्दी है। इसके पूर्वार्द्ध में समाजवाद ने हमारे देश में मजबूती से पैर जमाया है और अब इसके उत्तरार्द्ध में साम्यवाद अपने सुरङ्ग पर जमायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए साम्यवादी दल का यह अधिवेशन नवीन कार्यक्रम (20 वर्षीय कार्यक्रम) प्रस्तुत करता है।”

(12) श्रमिक कल्याण कार्यक्रमों में अभिवृद्धि—सोवियत संघ में श्रमिकों के कल्याण कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उन्हें पूर्वपिछा अधिक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दी जा रही है और उनके काम के घटों में कमी की जा रही है। अक्टूबर सन् 1977 के नए संविधान में रूसी श्रमिकों को नयी दिशा और नयी सुविधाएँ प्रदान की। काम के घटे 1970 तक प्रति सप्ताह 35 कर दिए गए जिन्हें 1980 तक घटा कर 30 कर दिया जाना है। श्रमिकों की मासिक आय में वृद्धि की गई है, उनके आवास गृहों के निर्माण में तेजी लाई गई है। सामूहिक फार्मों की कृषकों की आय में लगभग 30 से 35 प्रतिशत वृद्धि हुई है। आवास सुविधाओं में 1960 के मुकाबले 1980 तक लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य है। 1965 में आवास-गृहों की क्षमता लगभग 50 करोड़ वर्ग मीटर फर्शक क्षेत्र था जो 1976 तक लगभग 108 करोड़ वर्ग मीटर कर दिया गया जिससे करोड़ों लोगों की उत्तम आवास व्यवस्था हो सके। श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि का जो अभियान

चलाया गया है उससे पिछली पंचवर्षीय योजना में 28 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1976-80 की अवधि में 35 प्रतिशत तक वृद्धि की सम्भावना है।

(13) जन कल्याण सम्बन्धी सेवाओं का विस्तार—आर्थिक विकास व नियोजन के क्षेत्र में एक आधुनिक प्रवृत्ति जन-कल्याण सम्बन्धी सेवाओं के अधिकाधिक विस्तार की है। इसी दृष्टि से ये प्रयत्न किए जा रहे हैं कि 1980 तक रूसियों को निम्नलिखित सेवाएँ मुफ्त मिल सकें—(1) विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में सभी प्रकार की व्यवस्था मुफ्त मिले, (2) अयोग्य और अपाहिज लोगों की देखभाल समाज द्वारा की जाए, (3) सभी विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था हो, (4) सभी नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा और दवा दी जाए (5) मुफ्त आवास सुविधाएँ मिलें, (6) मुफ्त म्युनिसिपल यातायात सेवाएँ मिलें, (7) उद्योगों व संस्थानों में काम करने वाले लोगों और कृषि क्षेत्र में सभी सामूहिक कितानों को दिन का भोजन मुफ्त दिया जाए।

(14) सामाजिक सुरक्षा का विस्तार—एक आधुनिक प्रवृत्ति सामाजिक सुरक्षा योजना के अधिकाधिक विस्तार की है। इस दृष्टि से रूस आज विश्व का सबसे अग्रणी राष्ट्र है और रूसी बजट का लगभग 11-12 प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पर व्यय किया जाता है। सोवियत शासन को यह प्रवृत्ति सोवियत श्रमिकों में आत्म विश्वास और दृढ़ता की भावनाओं का विकास करने में प्रशंसनीय रूप से सहायक हुई है। इसके अतिरिक्त भय की उत्पादकता की वृद्धि और प्राविधिक उत्कृष्टता में सुधार करने पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है।

(15) भ्रम शिक्षा में नया अभियान और फैंक्ट्री विश्वविद्यालय—अन्तर विद्यालय अध्ययन-उत्पादन कम्बाइन (एस पी सी) एक दशक पूर्व मास्को में पहली बार प्रकट हुए। आज यह विश्वकूल स्पष्ट है कि ये कम्बाइन ऐसे नये प्रकार के विद्यालय बन गये हैं जो—सामान्य शिक्षा स्कूल और उद्योग, परिवहन, व्यापार तथा सेवा प्रतिष्ठानों में कार्यरत मजदूरों के स्कूलों के साथ-साथ स्कूली छात्रों की पोलिटेक्निकल और भ्रम-शिक्षा के अनेकानेक प्रश्नों का सफलतापूर्वक हल निकाल रहे हैं। मास्को के 80 प्रतिशत से अधिक मीनियर स्कूली छात्र ऐसे ही कम्बाइनों में अपना व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। 1980 तक नौवें और दसवें वर्ष के सभी छात्र इन कम्बाइनों में जाने लगेंगे।

फैंक्ट्री विश्वविद्यालय सोवियत संघ की उल्लेखनीय उपलब्धि है। फैंक्ट्री-विश्वविद्यालयों के आज के अधिकांश छात्र स्कूल छोड़ कर आने वाले लोग हैं। फिर भी प्रशिक्षण का सिद्धान्त उसी प्रकार है—बुने हुए रोजगार में उत्पादक कार्य के साथ संज्ञानात्मक प्रशिक्षण को आवश्यक रूप से सम्बद्ध करना जरूरी है। फैंक्ट्री विश्वविद्यालय का छात्र उद्योग-उद्योगों में ज्ञान संचित करता जाना है, क्रमिक रूप से वह एग्जिस्टेंस से तरक्की कर कर्मों, सहायक फोरमेन, टेक्नीशियन, प्राविधिक, डिजाइनर इत्यादि बनता है।

(16) नये प्रयोगों व परीक्षणों का विकास—आर्थिक विकास के लक्ष्यों की

पूति के लिए नए-नए प्रयोगों और परीक्षणों की प्रवृत्ति ने बल पकड़ा है। आर्थिक नीतियों, व्यावसायिक प्रवन्ध और प्रशासनिक रीतियों को अधिक लचीला व आधुनिक बनाया जा रहा है। आधुनिक प्राविधिकी के क्षेत्र में सैकड़ों नए प्रयोग चल रहे हैं ताकि नवीन मशीनीकृति और स्वचालित उत्पादन प्रक्रियाओं का अधिकतम विकास किया जा सके। आवश्यकतानुसार सामयिक और अविश्व निर्णय करने की सुविधा देने के लिए तथा केन्द्रीयकरण के दुष्प्रभाव को घटाने के लिए औद्योगिक कारखानों के प्रवन्धको को पूर्वापेक्षा अधिक स्वतन्त्रता दी जाने लगी है। इसके अलावा, औद्योगिक संस्थानों में लागत लेख एवं लाभ-सिद्धान्तों का समावेश किया जा रहा है।

(17) रहन सहन के स्तर में आश्चर्यजनक प्रगति—स्टालिन काल तक पूंजीगत उत्पादन-वृद्धि पर तो अत्यधिक बल दिया जाता रहा, किन्तु उपभोग-वस्तुओं के उत्पादन की उपेक्षा की गई जिससे जनता को भारी कष्ट सहने पड़े और भीतर ही भीतर जनता में असन्तोष भी पनपा। किन्तु स्टालिन की मृत्यु के बाद नये नेतृत्व ने वस्तु स्थिति को समझा और पूंजीगत तथा उपभोग उत्पादन को समतुलित महत्त्व देने की नीति अपनाई। फलस्वरूप रूसियों के जीवन स्तर में और उपभोग में प्रगति आश्चर्यजनक रही है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने बीसवीं कांग्रेस को सम्बोधित करते हुए कहा था कि अगले बीस वर्षों में सोवियत जनता का जीवन स्तर विश्व के सब देशों से अधिक हो जायेगा। 1960 से 1980 की अवधि में भोजन के उपयोग में 13 गुनी, उपभोग वस्तुओं में 5 गुनी और आवास व्यवस्था में दोगुनी वृद्धि की जाएगी। रूस ख्रुश्चेव के स्वप्न को साकार कर रहा है। उच्च जीवन-स्तर के लिए श्रमिकों की आय में वृद्धि पर विशेष बल दिया जा रहा है, क्योंकि रूस मुफ्त श्रमिकों का देश है 1965 में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय 180 रूबल से कुछ अधिक थी जो 1970 में 260 रूबल से अधिक हो गई और 1980 तक इसे बढ़ाकर लगभग 400 रूबल कर देने का लक्ष्य है। रूसियों के रहन-सहन के स्तर में वृद्धि का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले 1977 में रूस में लगभग 13 लाख कारों, 70 लाख टेलीविजन सैटों, 58 लाख रेफ्रिजरेटो और 35 लाख से भी अधिक घुलाई-मशीनों का निर्माण किया गया। जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार के लिए जो सामाजिक उपभोग कोष हैं, वह आश्चर्यजनक रूप में बढ़ा है। 1960 में इस कोष में लगभग 2450 रूबल थे जो बढ़कर 1980 तक लगभग 29500 करोड़ रूबल हो जाने की सम्भावना है जो कि रूस की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 50 प्रतिशत भाग होगा। इस बात के विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं कि 1980 तक सोवियत जनता को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त नगरीय यातायात, मुफ्त आवाता, दोपहर का भोजन और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए राज्य का योगदान अरबों रूबल बढ़ा दिया गया है।

(18) मूल्य-सूचियों का प्रकाशन—एक हाल की प्रवृत्ति मूल्य-सूचियों के

प्रकाशन की है। जनवरी, 1968 से ही प्रत्येक उद्योग के लिए मूल्य-सूचियों का प्रकाशन आरम्भ हुआ है। इन सूचियों को प्रतिवर्ष सशोधित रूप में प्रकाशन किया जाता है। इस नई व्यवस्था से अर्थात् मूल्यों के निर्धारण से कारखानों के लिए उत्पादन लागत कम करना तथा आय-व्यय का सही हिसाब रखना अधिक सुगम हो गया है।

(19) आयात नीति को उदार करना—हाल ही के वर्षों में सोवियत रूस ने अपनी आयात नीति को पूर्वपिछा अधिक उदार बनाया है और पूँजीवादी विश्व में उसका व्यापार बट रहा है। आम तौर पर अमेरिका से खाद्यान्न और अनेक वस्तुओं के आयात के समन्वय किए गए हैं। रूस की औद्योगिक क्षेत्र में यह नवीन प्रवृत्ति राजनीतिक क्षेत्र में सह-अस्तित्व की धारणा को प्रोत्साहन देने वाली है।

ये सभी तथ्य इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सोवियत संघ के आर्थिक विकास में नई प्रवृत्तियाँ तेजी से प्रदल होती जा रही हैं और फलस्वरूप रूस का आर्थिक विकास चमत्कारी ढंग से हो रहा है। औद्योगिक निर्माण जारी है और देश एक विशाल निर्माण-स्थल बना हुआ है, किन्तु जोर अब निश्चित रूप से दूसरी चीजों पर दिया जाने लगा है। अधिकांशतः ध्यान सामाजिक उत्पादन की कार्य-कुशलता पर, पिछले वर्षों में अस्तित्व में आई उत्पादन क्षमताओं के अधिकतम उपयोग पर तथा उनके आधुनिकीकरण और तकनीकी पुनर्नवीकरण पर केन्द्रित किया जा रहा है। नवी पंचवर्षीय योजना अवधि (1971-75) के दौरान अत्यंत ही सभी शाखाओं में उद्योग में गुणात्मक सुधार लाने की दिशा में तीव्र मोड़ आया। दसवीं पंचवर्षीय योजना में इसे बुनियादी लाइन की पंचवर्षीय अवधि कहा जाता है। पहले की ही भांति आठवें दशक में लाखों कार्यरत प्रतिष्ठानों को मानो नये सिरे से बनाया गया। करीब पाँच वर्षों में उद्योग की 40 प्रतिशत उत्पादन क्षमताओं का पुनर्नवीकरण किया गया। वृष्टि भी पंचवर्षीय चरणों में विकसित होनी जा रही है।

1977 के नये सोवियत संविधान में देश के सर्वांगीण जीवन को नई दिशा दी है इसमें नये प्राण फूँके हैं। जैसा कि श्री सुवर्ण बनर्जी ने लिखा है—किसी देश का संविधान न केवल मौजूदा सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक प्रणाली की पुष्टि करता है बल्कि उसके विकास की दीर्घकालिक सम्भावनाएँ भी व्यक्त करता है। इस प्रकार यह सामाजिक प्रगति और परिवर्तन का शक्तिशाली औजार है। उपलब्ध प्रगति के साथ तालमेल बैठाने के लिए समय-समय पर इसे सशोधित करने की भी आवश्यकता है। नया सोवियत संविधान उन्नत समाजवाद की उपलब्धियों को मान्यता देता है और कम्युनिज्म की स्थापना की सम्भावनाओं को व्यक्त करता है। यह व्यक्ति और समाज के समायोजन में इष्टतम हितों और कम्युनिज्म की स्थापना की सम्भावनाओं को व्यक्त करता है। यह व्यक्ति और समाज के समायोजन में इष्टतम हितों और कम्युनिज्म के भौतिक और प्राविधिक धारणार के निर्माण की प्रत्यक्ष माँगों के बीच समुचित सन्तुलन हासिल करता है। यह उत्पादन के समाजवादी मन्त्रणों को और अधिक उन्नत बनाने की, उपयुक्त अधिसंरचना के विकास की और स्वयं कम्युनिज्म के सामाजिक आर्थिक सम्बन्धों में उनके क्रमिक विकास की माँग करता है।

प्रश्नावली (University Questions)

अध्याय 1

1. रूसी सरकार ने सन् 1921 में नई आर्थिक नीति क्यों प्रारम्भ की? इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या थी? क्या यह नीति रूस की तत्कालीन आर्थिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत थी? (1978)

Why was the new economic policy introduced by the Russian Govt in 1921? What were the main features? Was it justified looking to the conditions prevailing then in Russia?

2. लेनिन ने नवीन आर्थिक नीति को दो कदम आगे बढ़ाने के लिए एक कदम पीछे हटने की सलाह दी। क्या आप इससे सहमत हैं? (1978)

Lenin described the New Economic Policy as a step backward to take two steps forward. Do you agree?

3. रूस की नवीन आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यह नीति रूस की तत्कालीन परिस्थितियों में उचित थी? (1978)

Describe briefly the salient features of the new economic policy of Russia. Do you agree with the view that it was justified under the economic conditions in Russia at that time?

4. सोवियत आर्थिक नीतियों व नियोजन में नवीन आर्थिक नीति की विवेचनात्मक व्याख्या कीजिए। (1978)

5. रूस में नवीन आर्थिक नीति के कारण तथा उद्देश्य बताइए तथा कृषि क्षेत्र में अपनाए गए कार्यक्रमों का विवरण दीजिए। साथ में इस नीति की कृषि में उपलब्धियों व असफलताओं का भी विवेचन कीजिए। (1977)

Explain the causes and objects of New Economic Policy in U S S R and describe the programmes adopted in the field of agriculture. Also discuss its achievements and failure in agriculture.

6. नई आर्थिक नीति "दो कदम आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटना कहा जा सकता है।" क्या आप सहमत हैं? कारण दीजिए। (1977)

The new economic policy can be described "as a step backward to take two steps forward". Do you agree? Give reasons.

- 7 नई आर्थिक नीति क्या थी ? यह किस सीमा तक सफल रही ? (1977)
 What was the new Economic Policy ? How far did it succeed ?
- 8 सोवियत रूस में कैंची संकट की व्याख्या कीजिए और इस संकट से मुक्ति पाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का विवरण दीजिए । (1977)
 Describe the Scissors Crisis in USSR and explain the methods adopted by the Govt to check the crisis
- 9 आयोजन काल के पूर्व सोवियत संघ में कैंची संकट के लिए उत्तरदायी कारणों की व्याख्या कीजिए । इसके प्रभाव क्या थे ? (1978)
 Describe the circumstances leading to the scissors crisis in the U S S R before the plan period What were its effects ?

अध्याय 2

- 10 सोवियत भूमि में प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय अर्थ-व्यवस्था की क्या स्थिति थी ? (1977)
 What was the economic condition of Soviet Union on the eve of First Five Year Plan ?
- 11 प्रथम योजना से पूर्व रूस की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति की समीक्षा कीजिए । (1977)
 Discuss the social, political and economic conditions of U S S R on the eve of the First Five Year Plan
- 12 सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए और बतलाइए कि नियोजन से इन परिस्थितियों में कहां तक सुधार हुआ है ? (1978)
- 13 प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ के समय रूस की अर्थ-व्यवस्था का परीक्षण कीजिए । (1978)
 Examine the conditions of Russian economy on the eve of First Five Year Plan

अध्याय 3

- 14 सोवियत संघ में सहकारी खेती का क्या स्वरूप है ? आप सामूहिक खेती और राजकीय खेती में कैसे भेद करेंगे ? (1977)
 What is the nature of Co-operative Farming in Soviet Union ? How would you distinguish between collective farming and state farming ?
- 15 रूस में प्रथम योजना काल में कृषि के सामूहिकरण के प्रभावों का विवेचन कीजिए और कालखोज (सामूहिक खेत) के कार्य में आई बाधाओं पर प्रकाश डालिए । (1977)

90 सोवियत रूस का आर्थिक विकास

Discuss the effects of collectivisation on agriculture during First Five Year Plan in U S S R and throw light on the obstruction put forth in the working of Kolkhoz (collective farms) in U S S R.

अध्याय 4

16 सन् 1954 से सोवियत सघ में कृषि विकास कार्यक्रमों की 20 सफलताओं तथा असफलताओं का परीक्षण कीजिए ।

17 हाल के वर्षों में सोवियत सघ की कृषि और औद्योगिक नीतियों में क्या परिवर्तन हुए हैं ? (1977)

What changes have been brought about in the agricultural and industrial policies of Soviet Union during recent years ?

18 सोवियत सघ में पिछले पच्चीस वर्षों में जो कुछ कृषि विकास के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए । (1978)

अध्याय 5

19 सोवियत सघ में तीव्र औद्योगीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए और विकास की नई प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए ।

20 रूस में प्रारम्भिक तथा वर्तमान समस्याओं का विवेचन कीजिए जिनका सामना द्रुतगति से औद्योगीकरण के दौरान किया गया । (1977)

Discuss the basic and present problems faced by U S S R during rapid industrialization

21 क्या यह कहना उपयुक्त है कि सोवियत सघ में तीव्र औद्योगीकरण राज्य की आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका के कारण हुआ है ? (1978)

It is correct to say that rapid industrialization in the Soviet Union is due to the active role of the state in the process of development

22 तीव्र औद्योगीकरण के प्रारम्भिक काल में रूस द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों के विषय में आप क्या जानते हैं ? इन्हें किस प्रकार सुलझाया गया ? (1978)

What do you know of the difficulties faced by the U S S R in the initial period of rapid industrialization ? How did she solved them ?

अध्याय 6

23 रूस की नियोजन तथा आर्थिक विकास प्रणाली की आधुनिक प्रवृत्तियों पर एक टिप्पणी लिखिए । (1978)

Write a short note on the recent trends in planning and economic development of U S S R

24 सोवियत सघ ने आर्थिक विकास के क्षेत्र में क्रान्तिकारी सफलता प्राप्त की है। इस कथन के सन्दर्भ में नियोजन की आधुनिक प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए । (1978)

(1978)